

राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jd.hort@rajasthan.gov.in)

क्रमांक: एफ.5 (5) आ.उ./PDMC-MI/GL/2026-27/

दिनांक: .05.2026

संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड समस्त।
उप निदेशक उद्यान, समस्त।

विषय:- 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के वर्ष 2026-27 हेतु क्रियान्वयन दिशानिर्देश

प्रसंग:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में जारी मूल दिशानिर्देश पत्रांक 15920780 दिनांक 13.06.2025

राज्य सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र में सिंचाई जल के दक्षतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम के आकार में वृद्धि करते हुए इसके सुगम वृहत क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन के मध्यनजर वर्ष 2025-26 में प्रासंगिक पत्र द्वारा क्रियान्वयन दिशानिर्देश जारी किये गए थे। चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान आगामी आदेशों तक यही दिशा निर्देश लागू रहेंगे।

अतः क्षेत्र में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए कार्यक्रम का समय पर सफल क्रियान्वयन संलग्न दिशानिर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(श्वेता चौहान)
आयुक्त उद्यानिकी

क्रमांक: एफ.5 (5) आ.उ./PDMC-MI/GL/2026-27/

दिनांक: .05.2026

1. संयुक्त सचिव, RFS/RKVY कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सहायक, जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी.....
6. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
7. अतिरिक्त निदेशक कृषि खण्ड.....
8. मुख्य लेखाधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
9. संयुक्त निदेशक कृषि शष्य, जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय, जयपुर
10. संयुक्त निदेशक उद्यान, मुख्यालय/सीएसएस/नर्सरी/अनुसंधान/विस्तार/कीट, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
11. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद.....
12. उप निदेशक उद्यान शष्य/एनएचएम/नर्सरी/सांख्यिकी/विस्तार, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
13. आहरण वितरण अधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
14. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार).....
15. उप निदेशक सांख्यिकी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

आयुक्त उद्यानिकी
Signature Not Verified

Digitally signed by Shweta Chauhan
Designation : Commissioner
Date: 2026.05.14 15:39:56 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22200357

M e-Sign



राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdih.ext.hort@rajasthan.gov.in)

क्रमांक: एफ.5 (5) आ.उ./PDMC-MI/GL/2025-26/

दिनांक: .06.2025

संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड समस्त।

उप निदेशक उद्यान, समस्त।

विषय:—‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’ योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के वर्ष 2025-26 हेतु क्रियान्वयन दिशानिर्देश व वार्षिक कार्ययोजना जारी करने बाबत।

राज्य सरकार द्वारा कृषि बजट 2025-26 के बिन्दू 103 के अनुसार कृषि क्षेत्र में सिंचाई जल के दक्षतम उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु आगामी वर्ष में विभिन्न सिंचाई योजनाओं के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई के लिए एक लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में प्रावधान करने के साथ-साथ 3 लाख 50 हजार हेक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रिंकलर संयंत्रों के अनुदान पर 1250.00 करोड़ रुपये व्यय किये जाने प्रस्तावित किये गये हैं। इस क्रम में सूक्ष्म सिंचाई कार्यक्रम के वृहत क्षेत्र में प्रभावी क्रियान्वयन के मध्यनजर प्रचलित दिशानिर्देशों को अद्यतन करते हुये वर्ष 2025-26 हेतु नवीन दिशानिर्देश संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं जोकि जारी होने की दिनांक से लागू होंगे।

दिशानिर्देशों में निम्नानुसार मुख्य **नीतिगत निर्णयों** (बिन्दू स-7.2) का समावेश किया गया है—

1. कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु सूक्ष्म सिंचाई **निर्माता ही** बिल जारी करने/कृषक की ओर से अनुदान प्राप्ति हेतु **मान्य होंगे** तथा
2. कार्यक्रम को पूर्ण डीबीटी मोड पर ले जाने की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य के 10 अग्रणी जिलों में ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर के **20 प्रतिशत प्रकरण आवश्यक रूप से डीबीटी के माध्यम से सीधे कृषकों के पक्ष में सम्पन्न** करवाये जाने हैं। डीबीटी के प्रकरणों में **अनुदान भुगतान प्राथमिकता के आधार पर** किया जावेगा। ये 10 जिले जैसे जालोर, जयपुर, अलवर, झालावाड़, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, नागौर एवं सिरोही हैं।

पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजनान्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना के साथ-साथ सहयोगी योजना यथा ऑटोमेशन, फर्टीगेशन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान सलाह, दम्पति प्रशिक्षण तथा गुणवत्ता नियंत्रण हेतु नमूने आहरण व निर्माता पंजीकरण के प्रचलित दिशानिर्देशों को भी सम्महित किया गया है। अतः क्षेत्र में योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करते हुए कार्यक्रम का समय पर सफल क्रियान्वयन संलग्न दिशानिर्देशानुसार किया जाना सुनिश्चित करावें। **‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’** योजनान्तर्गत **सूक्ष्म सिंचाई** योजना वर्ष **2025-26** की वार्षिक कार्ययोजना भी संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : **संयुक्त उद्यानिकी**
Date: 2025.06.13 20:20:20 IST
Reason: Approved



क्रमांक: एफ.5 (5) आ.उ./PDMC-MI/GL/2025-26/

दिनांक: : .06.2025

1. संयुक्त सचिव, RFS/RKVY कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली
2. निजी सचिव, शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी, शासन सचिवालय, जयपुर
3. निजी सचिव, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर
4. निजी सचिव, आयुक्त उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर
5. निजी सहायक, जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष, जिला हार्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी.....
6. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
7. अतिरिक्त निदेशक कृषि खण्ड.....
8. मुख्य लेखाधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
9. संयुक्त निदेशक कृषि शष्य, जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय, जयपुर
10. संयुक्त निदेशक उद्यान, मुख्यालय/सीएसएस/नर्सरी/अनुसंधान/विस्तार/कीट, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
11. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार), जिला परिषद.....
12. उप निदेशक उद्यान शष्य/एनएचएम/नर्सरी/सांख्यिकी/विस्तार, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
13. आहरण वितरण अधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
14. समस्त उप निदेशक कृषि (विस्तार).....
15. उप निदेशक सांख्यिकी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर

आयुक्त उद्यानिकी

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2025.06.13 20:20:20 IST
Reason: Approved

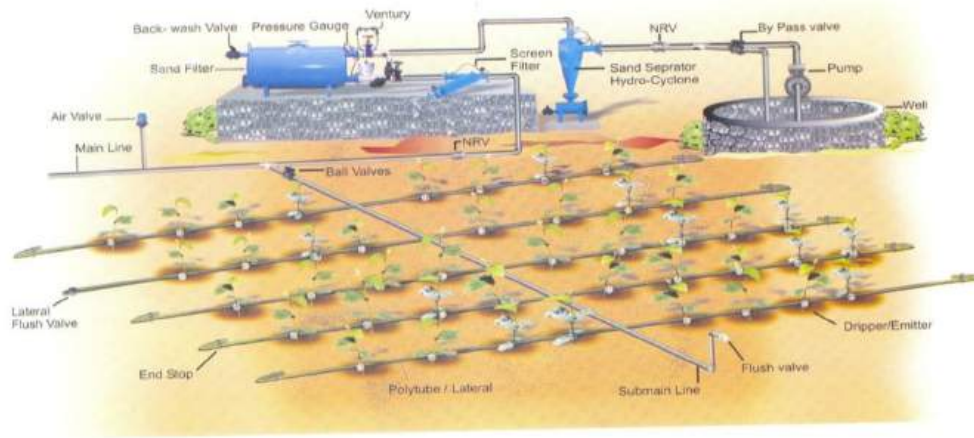
राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन

Per Drop More Crop

Under the umbrella of RKVY

कार्यक्रम क्रियान्वयन मार्गदर्शिका

2025-26



Layout of Drip Irrigation System

उद्यान आयुक्तालय राजस्थान
पंत कृषि भवन, जयपुर

अनुक्रमणिका		
क.सं.	विवरण बिन्दू	पृष्ठ संख्या
1	योजना परिचय	1-3
2	योजना के सामान्य निर्देश	4-5
3	अनुदान की पात्रता	5-8
4	आवेदन एवं निस्तारण की प्रक्रिया कृषक चयन पंजीकरण एवं आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण तकनीकी-आर्थिक सर्वे आवेदन अनुमोदन, प्रशासनिक स्वीकृति एवं कृषक हिस्सा राशि संग्रहण अनुबंध एवं संयंत्र स्थापना भौतिक सत्यापन अन्तिम भुगतान संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रशिक्षण, संचालन व नक्शा सुपुर्दगी	9-14
5	अनुदान की सीमा एवं भुगतान	14-15
6	निर्माता पंजीकरण एवं आपूर्तिकर्ता दायित्व	15-16
7	गुणवत्ता नियंत्रण व प्रशिक्षण	16
8	अन्य बिन्दू	17-19
Annexures		
1	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर देय अनुदान	20
2	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की सांकेतिक इकाई लागत	21
2 a & b	अनुदान गणना	22-23
3	वैकल्पिक घटकों के सांकेतिक मूल्य	24
4	आवेदन पत्र	25
5 & 5 a	भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रपत्र	26-27
6	त्रि-पार्टी अनुबंध प्रपत्र	28-29
7	प्रशासनिक स्वीकृति प्रपत्र	30
8	वित्तीय स्वीकृति प्रपत्र	31
9 & 9 a	बिल/इनवॉइस प्रपत्र	32-33
10	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना के लिए जल और विद्युत उपलब्धता के मूल्यांकन हेतु प्रश्नावली	34-35
11	विभिन्न फसलों के लिए सुझाया गया प्रणाली चयन	36
12	क्लोगिंग से संबंध में जल की गुणवत्ता का मापदंड	37
13	शपथ-पत्र	38
14	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों हेतु डिजाईन	39
14 (I)	निर्माता के इंजीनियर/एग्रोनॉमिस्ट के द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्रपत्र	40-41
14 (II)	भौतिक सत्यापन हेतु चेक लिस्ट	42
15	भारत सरकार द्वारा जारी पीडीएमसी योजना 2024 के दिशानिर्देश	
16	ऑटोमेशन, फर्टीगेशन एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान परियोजना 2024-25 दिशानिर्देश	
17	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र निर्माता पंजीकरण दिशानिर्देश	
18	कृषक दम्पति प्रशिक्षण हेतु दिशानिर्देश	
19	सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु जारी दिशानिर्देश	
20	सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत वर्ष 2025-26 हेतु जिलेवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का आंशिक	

राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन

प्रति बूंद ज्यादा फसल—Per Drop More Crop (PDMC)—2025—26

राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना

परिचय

राज्य में उपलब्ध जल की कमी तथा सिंचाई दक्षता के मध्यनजर कृषि/उद्यान विभाग द्वारा किसी न किसी केन्द्रीय/राज्य योजनान्तर्गत वर्ष 1990-91 से फव्वारा व ड्रिप सिंचाई तकनीक को बढ़ावा देने हेतु कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजना के रूप में जनवरी 2006 से सूक्ष्म सिंचाई योजना (MIS) शुरू की गई जिसका उन्नयन क्रमशः राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (NMMI-June 2010), ऑन फार्म वॉटर मैनेजमेन्ट (OFWM-NMSA-April 2014), प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY-PDMC-MI-April 2015) तथा प्रति बूंद ज्यादा फसल—Per Drop More Crop (PDMC)— राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना (अप्रैल 2022) के रूप में किया गया।

जहां तक फव्वारा सिंचाई कार्यक्रम को राज्य के कृषकों द्वारा अपनाये जाने का प्रश्न है, राज्य के किसानों द्वारा अत्यधिक रुचि दिखाई गई है। फव्वारा सिंचाई तकनीक द्वारा जल बचत के अतिरिक्त राज्य की भौगोलिक, आर्थिक—सामाजिक एवं कृषि जलवायु स्थितियां प्रबल रूप से सहायक रही हैं। वास्तविक रूप से इसके परिणाम आकर्षित करने वाले रहे व इसी आधार पर सम्पूर्ण देश में राजस्थान राज्य फव्वारा तकनीक के तहत सिंचित क्षेत्र (मार्च 2025 तक लगभग 17 लाख हैक्टेयर) दृष्टि से शीर्ष स्थान पर है।

कालान्तर के बूंद-बूंद सिंचाई के अनेकानेक फायदे होने के बावजूद इसके प्रगति परिणाम तुलनात्मक दृष्टिकोण से वांछित नहीं रहे हैं परन्तु विगत वर्षों में इसकी उपयोगिता व तकनीक की जानकारी के प्रसार के फलस्वरूप इसकी मांग व स्थापना में प्रभावी वृद्धि दर्ज की गई है। अन्य राज्यों जैसे— आंध्रप्रदेश, कर्नाटक, गुजरात और महाराष्ट्र में बूंद-बूंद संयंत्र स्थापन क्षेत्र की बजाय राजस्थान का क्षेत्र तुलनात्मक रूप से कम है तथा मार्च 2025 तक लगभग 6.00 लाख हैक्टेयर क्षेत्र ही बूंद-बूंद सिंचाई तकनीक के तहत सिंचित किया जा सका है। मंहंगे संयंत्र, जागरूकता की कमी, कम बागान क्षेत्र, तकनीकी जानकारी का अभाव, तकनीकी रूप से सुदृढ़ आपूर्ति नेटवर्क की कमी तथा संयंत्र रख-रखाव की जानकारी का अभाव आदि बूंद-बूंद सिंचाई की न्यून प्रगति के प्रमुख कारण रहे हैं।

राज्य में सीमित सिंचाई जल संसाधन एवं इसके दक्षतम उपयोग के महत्व के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों के बजट में इस तकनीक को प्रोत्साहित किये जाने हेतु **राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन** की घोषणा करते हुए इस हेतु विशिष्ट प्रावधान किये हैं तथा राज्य बजट वर्ष 2022-23 के बिन्दू 133(1) के तहत आगामी तीन वर्षों के दौरान वृहत स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई तकनीक को क्रियान्वित करने हेतु रुपये 1705.00 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित करने के साथ-साथ संभागीय स्तर पर सूक्ष्म सिंचाई उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित करने प्रस्तावित किये गये हैं। वर्ष 2023-24 के बजट भाषण बिन्दू 166 में 25 ब्लॉक्स/क्लस्टर में सम्पूर्ण सूक्ष्म सिंचाई आच्छादन तथा बजट प्रतिउत्तर 60, 69 में न्यू जनरेशन टेक्नोलॉजी यथा ऑटोमेशन/फर्टीगेशन को बढ़ावा व धौलपुर लिफ्ट कवरेज तथा वर्ष 2024-25 बजट प्रतिउत्तर बिन्दू 44 में 2.50 लाख हैक्टेयर में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना प्रस्तावित की गई। वर्ष 2025-26 के बजट बिन्दू 103 के तहत कृषि क्षेत्र में जल दक्षता बढ़ाने हेतु 3.50 लाख हैक्टेयर में ड्रिप एवं स्प्रींकलर ईरीगेशन सिस्टम के लिए अनुदान दिया जाना प्रस्तावित किया गया है।

आधुनिक सिंचाई संयंत्रों के माध्यम से सिंचाई जल के समुचित एवं दक्षतम उपयोग सुनिश्चित किया जाकर राज्य की वर्तमान सिंचाई दक्षता में प्रभावी वृद्धि किया जाना संभव है। बूंद-बूंद सिंचाई प्रणाली जो कि जल बचत एवं अधिक उत्पादन प्राप्ति के दृष्टिकोण से सूक्ष्म सिंचाई

योजना की अति उपयोगी एवं वैज्ञानिक तकनीक है, के क्षेत्रफल में व्यापक रूप से वृद्धि पर अधिसक्रिय आधार पर कार्य की आवश्यकता है। सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों को बढ़ावा देने के साथ-साथ उत्पादन एवं इसकी गुणवत्ता में प्रभावी वृद्धि हेतु उच्च उद्यानिकी तकनीक यथा फर्टीगेशन एवं ड्रिप ऑटोमेशन को भी बढ़ावा दिया जाना अवश्यम्भावी है। राज्य में सूक्ष्म सिंचाई से सम्पूर्ण आच्छादन की अवधारणा पर विभिन्न ब्लॉकस/क्लस्टरस पर कार्य प्रारम्भ किया गया है। जिसे वृहत स्तर पर प्रसारित करते हुए जिलेवार सम्पूर्ण सूक्ष्म सिंचाई आच्छादन किया जाना दृष्टिगत है। इसके साथ ही अधिक जल मांग की फसलों यथा धान, गन्ना, कपास, मूंगफली आदि पर आवश्यक रूप से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापित किये जाने आवश्यक है।

सूक्ष्म सिंचाई के घटक

(अ) बूंद-बूंद सिंचाई पद्धतियाँ:

1. **ड्रिप सिंचाई:** ड्रिप सिंचाई में पाईपों के नैटवर्क (मेन, सबमेन तथा लेटरल) पर लगे उत्सर्जक (एमिटर) के माध्यम से पौधों की जड़ वाले क्षेत्र में सिंचाई की जाती है। उत्सर्जक डिवाइस में ड्रिपर, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी-स्प्रिंकलर, माइक्रो-जेट, मिस्टर्स, फैन-जेट, माइक्रो-स्प्रेयर, फोगर्स आदि हो सकते हैं जो निर्धारित मात्रा में पानी प्रवाह के लिए तैयार किए जाते हैं। विभिन्न उत्सर्जक (एमिटर) का उपयोग विशिष्ट जरूरत पर निर्भर करता है जो फसल-दर-फसल अलग-अलग होता है। जल आवश्यकता, पौधे की आयु, पौधों की परस्पर दूरी, मृदा की किस्म, जल गुणवत्ता तथा उपलब्धता आदि कुछ ऐसे घटक हैं जो उत्सर्जन (एमिटिंग) प्रणाली के विकल्प को निर्धारित करते हैं। ड्रिप सिंचाई प्रणाली की यूनिट लागत पौधे की दूरी तथा जल स्रोत के स्थान पर अलग-अलग होती है। ड्रिप सिंचाई पद्धति का मुख्य रूप से सब्जियों, फल-बगीचों तथा नकदी फसलों यथा कपास आदि में प्रचलन है तथापि इस तकनीक की न्यून अन्तराल ड्रिप का उपयोग फसल चक्र में अधिकांश फसलों में किया जा सकता है।
2. **सूक्ष्म (माइक्रो) स्प्रिंकलर (3 मीटर त्रिज्या तक की दूरी तक प्रवाह):** सूक्ष्म स्प्रिंकलर का उपयोग ज्यादातर पत्तेदार सब्जियों, उद्यानिकी पौधों को ठोस व मजबूत करने तथा कुछ चुनी सब्जियों के लिए सिंचाई हेतु किया जाता है। सिंचाई प्रदान करने के अलावा सूक्ष्म स्प्रिंकलर से पौधे के नजदीक की सूक्ष्म जलवायु को परिवर्तित करने में मदद मिलती है। सूक्ष्म स्प्रिंकलर का त्रिज्या क्षेत्र कम होता है तथा स्प्रिंकलर के बहाव की त्रिज्या 3 मीटर तक जाती है। सूक्ष्म स्प्रिंकलर का बहाव 20 से 150 ली./घण्टा होता है। सूक्ष्म स्प्रिंकलर का चयन फसल, मृदा की किस्म आदि पर निर्भर करता है। इस तकनीक का उपयोग मुख्यतः हरी पत्तेदार सब्जियों व जलवायु संवेदनशील फसलों में किया जाता है।
3. **मिनी स्प्रिंकलर (3 – 10 मी. त्रिज्या दूरी तक प्रवाह):** मिनी स्प्रिंकलर एक मध्यम दूरी की स्प्रिंकलर प्रणाली है जिसकी त्रिज्या 3 मी. से 10 मी. के बीच है। इन स्प्रिंकलरों से प्रवाह 150 से 600 ली./घण्टा के बीच होता है। निकट उगाई जाने वाली फसलों में इसका सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है जैसे मूंगफली, आलू, प्याज, अदरक, चारा फसले आदि। मिनी स्प्रिंकलर पाले से बचाव के लिए भी उपयुक्त है।

सूक्ष्म स्प्रिंकलर और मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली ड्रिप प्रणाली से अलग है क्योंकि इसकी उत्सर्जन प्रणाली राईजर एवं स्टेक्स की मदद से जमीन के उपर लगी होती है। इसका उत्सर्जन काफी ज्यादा होता है और इसकी परिधि में आने वाली सभी खड़ी फसलों की इससे सिंचाई की जा सकती है। तदनुसार, ड्रिप सिंचाई प्रणाली की ईकाई लागत की तुलना में सूक्ष्म स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली की लागत काफी ज्यादा होती है। अतः सामग्री के बिल के साथ-साथ खेत में स्थापित उपकरण की जांच के द्वारा ड्रिप

सिंचाई, सूक्ष्म तथा मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए अनुदान क्रियान्वयन करते समय क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा पूर्ण सावधानी बरतना बहुत जरूरी है।

(ब) फव्वारा सिंचाई पद्धतियों: (12–18 मी.)

फव्वारा सिंचाई में पानी को उच्च घनत्व वाली पॉलीथलीन (एचडीपीई) पाईप में लगी नोजल्स के द्वारा हवा में दबाव के साथ छोड़ा जाता है। यह स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली फसलों की सिंचाई के लिए उपयुक्त है जहां पौधों की सघनता काफी ज्यादा होती है। अनाज, दाल, बीज, मसाला तथा अन्य फील्ड फसलों के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है।

- 1. पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली:** पोर्टेबल स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में एचडीपीई पाईप का उपयोग किया जाता है जिसे एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। इस प्रकार की स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में पानी को 12 मी. से 18 मी. तक फेंका जा सकता है इसमें 1200 से 1800 ली./घण्टा प्रवाह होता है। इसका उपयोग मैदानी तथा लहरदार दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है।
- 2. अर्ध-स्थायी स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली:** इस प्रकार की स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में मेनलाईन तथा लैटरल लाईन के पाईप नैटवर्क को लैटरल लाईन पर लगे राईजर के साथ लगा दिया जाता है। स्प्रिंकलर नॉजल को प्रत्येक राईजर पाईप पर लगाया जाता है और इसे फसल को पानी जरूरत के अनुसार सिंचाई वाले जरूरी स्थान में एक जगह से दूसरी जगह आसानी से ले जाया जा सकता है।
- 3. अधिक घनफल वाली स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली (रेनगन):** अधिक घनफल वाली स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली (रेनगन) का उपयोग वहां किया जाता है जहां एक या दो स्प्रिंकलर से विशाल क्षेत्रों की सिंचाई की जाती है। इन स्प्रिंकलरों के बहाव की दूरी 10,000 से 32,000 ली./घण्टा और पानी फेंकने की त्रिज्या 24 मीटर से 36 मीटर होती है। चूंकि इस प्रणाली में विशाल क्षेत्र शामिल होता है। अतः इन्हें चलाने के लिए उच्च दबाव तथा उच्च बहाव वाले पाईप तथा पम्प की जरूरत होती है। इनके इस्तेमाल से कम समय में विशाल क्षेत्रों में फैली फसल की सिंचाई की जाती है।

सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान हेतु क्रियान्वयन दिशा-निर्देश वर्ष 2025-26

अ. सामान्य

- वर्ष 2005-06 जून 2006 से प्रारम्भ की गई केन्द्रीय प्रवर्तित "सूक्ष्म सिंचाई योजना" का उन्नयन क्रमशः राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई मिशन (NMMI-Jun 2010), On Farm Water Management (OFWM-NMSA 1 April 2014), PMKSY-April 2015 बढ़ाकर इसे 12 वीं योजना अवधि में वर्ष के दौरान "प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) के तहत सूक्ष्म सिंचाई योजना (MIS)" के नाम से क्रियान्वित किया जा रहा था जिसे अप्रैल 2022 से 'पर ड्रॉप मोर क्रोप' (PDMC) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के दायरे में संचालित किया जा रहा है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जारी PDMC के अन्तर्गत सूक्ष्म सिंचाई योजना की परिचालन मार्ग-दर्शिका (2024) वेबसाइट pdmc.da.gov.in/Revised_PDMC_Guideline_2024.pdf पर उपलब्ध है।

सूक्ष्म सिंचाई योजना का ढाँचा

- राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन व प्रबोधन संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक प.6(14) प्र.सु./अनु-3/2014/1 दिनांक 30.05.2014 के द्वारा राज्य स्तर पर मिशन के संचालन, पर्यवेक्षण, क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी के अध्यक्ष अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव कृषि है।
- योजना जिला स्तर पर संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार (अनु.-3) विभाग शासन सचिवालय जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक प.6(14) प्र.सु./अनु-3/2014/II दिनांक 30.05.2014 के द्वारा जिला स्तर पर मिशन के संचालन, पर्यवेक्षण, क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना में जिला मिशन कमेटी का गठन किया गया है। संबंधित जिले के जिला मिशन कमेटी के अध्यक्ष जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद होंगे।
- जिला मिशन कमेटी द्वारा जिला कार्य योजना, योजना क्रियान्वयन हेतु वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण हेतु समन्वयन, भौतिक/ वित्तीय प्रगति की निगरानी व समीक्षा, उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुतीकरण तथा प्रत्येक माह की प्रगति भिजवाना आदि कार्य किया जाना सुनिश्चित किया जावे। जिला मिशन कमेटी की बैठक प्रत्येक माह में एक बार होगी। जिला मिशन कमेटी द्वारा ब्लॉक और ग्राम स्तर पर योजना का विभिन्न माध्यमों के द्वारा व्यापक प्रचार किया जायेगा।
- राज्य स्तरीय कार्य योजना के संकलन के लिये राज्य स्तरीय कमेटी (SLC) को जिला मिशन कमेटी (DMC) द्वारा जिला वार्षिक कार्य योजना (निर्धारित प्रपत्र में) ऑनलाईन पोर्टल/MIS पर अग्रेषित की जावेगी जिसे कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय को भेजा जाएगा।

कार्यक्रम क्रियान्वयन

- योजना का समस्त क्रियान्वयन कोष कार्यालय/IFMS /PD Account/ (Additional subsidy) व SNA SPARSH (CA+SS) (यथास्थिति अनुसार) के माध्यम से अनुदान राशि का भुगतान दिशा-निर्देशानुसार जिले के उप निदेशक उद्यान द्वारा किया जावेगा।
- कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिये फसल चयन, प्राथमिकता क्षेत्र चयन, लाभार्थी चयन तथा नीतिगत निर्णयों हेतु पंचायती राज संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जावे। लाभार्थी के चयन में पूर्ण पारदर्शिता रखी जावे।

8. संबंधित क्षेत्र के खण्ड स्तरीय अधिकारी कृषि/उद्यान योजना के सम्पूर्ण पर्यवेक्षण व समन्वयन हेतु जिम्मेदार होंगे। सम्भाग स्तर पर उद्यान विभाग के अधिकारी इस कार्यक्रम क्रियान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होंगे।
9. राज्य स्तर पर उद्यान विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता फर्मों से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाने पर ही कृषक को अनुदान दिया जा सकेगा।
10. जिले के केन्द्रीयंश वार्षिक परिव्यय की प्रतिशत राशि तक जिला स्तर पर DMC के अनुमोदन पर उप निदेशक उद्यान द्वारा योजना की मॉनिटरिंग/मिशन मैनेजमेंट/प्रबोधन कार्य हेतु काम में ली जा सकेगी तथा प्रतिशत राशि राज्य स्तर पर उक्त कार्यों के लिए उपयोग में ली जावेगी।
11. ड्रिप व फव्वारा सिंचाई पद्धति कृषक की आवश्यकतानुसार सभी प्रकार की फसलों में लगाई जा सकती है तथापि, फव्वारा सिंचाई प्रणाली के लिये सहायता सिर्फ उन फसलों के मामलों में दी जायेगी जहां ड्रिप सिंचाई किफायती नहीं होती है।
12. योजना के तहत फव्वारा संयंत्रों तथा ड्रिप संयंत्रों मिनी/माइक्रो स्प्रींकलर पर अनुदान देय होगा।
13. सूक्ष्म सिंचाई योजना के प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के दृष्टिगत योजना का समन्वय सूक्ष्म सिंचाई से सम्बन्धित निम्न योजनाओं के साथ किया जायेगा।
 - माइक्रो ईरिगेशन फंड (MIF) कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय द्वारा नाबार्ड के माध्यम से वित्त पोषित ऋण
 - अटल भू-जल योजना (भू-जल विभाग के माध्यम से भारत सरकार एवं विश्व बैंक वित्त पोषित)
 - कृषक कल्याण कोष (राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के माध्यम से)
 - राजस्थान जल क्षेत्र आजीविका सुधार मिशन (RWSLIP) जल संसाधन विभाग के माध्यम से जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन ऐजेन्सी (JICA) से वित्त पोषित
 - राजस्थान जल क्षेत्र पुर्नसंरचना परियोजना रेगिस्तानी क्षेत्र (RWSRPD) जल संसाधन विभाग के माध्यम से न्यू डवलपमेंट बैंक (NDB) से वित्त पोषित
 - अन्य समन्वय (Convergence) योग्य योजनाएँ जिनका समय-समय पर समावेश किया जा सकेगा।
 - ऑटोमेशन व फर्टीगेशन योजना
 - कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित समाधान
 - राष्ट्रीय बागवानी मिशन-फल बगीचा विकास, संरक्षित खेती व जल संग्रहण ढांचा
 - सौर उर्जा आधारित पम्प परियोजना
 - कृषि विभाग द्वारा के.प्र.यो. व राज्य योजना के तहत संचालित फार्म पौण्ड व डिग्गी निर्माण

ब. अनुदान की पात्रता

1. कृषकों को फव्वारा/ड्रिप संयंत्र पर अनुदान नकद या बैंक से ऋण लेकर क्रय करने पर दोनों ही स्थिति में देय होगा।
2. जिन कृषकों के नाम पर भूमि का स्वामित्व है तथा कुएं, नलकूप या अन्य जल स्रोत पर विद्युत/डीजल/ सौर /ट्रैक्टर चालित पम्प सैट है वे अनुदान के पात्र होंगे। सामलाती जल स्रोत पर अलग-अलग पम्प सैट होने पर या पम्प सैट सामलाती होने पर भी यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग फव्वारा/ड्रिप पर अनुदान की मांग करते हैं तो अलग-अलग अनुदान देय होगा परन्तु भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना आवश्यक है। अविभाजित भूमि के हिस्सेदार किसान (Notaional Share Farmer) को हिस्सेदार मानकर अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा। अविभाजित/सामिलाती भूमि में

- नोशनल शेयर के आधार पर खसरा विशेष में यदि कृषक के पास कुल क्षेत्र कम है परन्तु कृषक उस पर काबिज है तथा समस्त सामिलात कृषकों द्वारा सहमति प्रदान की जाती है तो कृषक को तत् क्षेत्र हेतु अनुदान प्रदान किया जा सकेगा।
3. जो क्षेत्र राज्य सरकार द्वारा नहर/बांध से पम्प सैट द्वारा पानी लिफ्ट करके सिंचाई करने हेतु अधिसूचित है उन क्षेत्रों में भी सिंचाई हेतु फव्वारा/ड्रिप पर अनुदान देय होगा। नहरी क्षेत्रों में खाले (Water course)/डिग्गी तथा अन्य क्षेत्रों में फार्म पौण्ड, व्यक्तिगत/सामुदायिक जल स्रोत, जल संग्रहण ढांचे से सिंचाई हेतु भी फव्वारा/ड्रिप संयंत्र पर अनुदान देय होगा।
 4. जिस लाभार्थी के पास स्वयं का जल का स्रोत नहीं है, तब पड़ोसी लाभार्थी से सिंचाई के स्रोत की साझेदारी हेतु जल करार जिनसे वह पानी लेने का इच्छुक है, प्रस्तुत करना होगा।
 5. सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर **न्यूनतम 0.2 हैक्टेयर** तथा अधिकतम 5 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी की सीमा में अनुदान सीमित रखा जायेगा। जिन कृषकों ने 5 हैक्टेयर से कम क्षेत्र हेतु पूर्व में अनुदान लिया है उन्हें 5 हैक्टेयर तक की सीमा में विस्तार हेतु अनुदान दिया जा सकता है। कृषक के यहां पूर्व में स्थापित हैड यूनिट या स्वयं मापदण्ड अनुरूप द्वारा स्थापित हैड यूनिट के प्रकरण में संयंत्र विस्तार के प्रकरणों में भी अनुदान देय होगा। अनुदान गणना हेतु हेड कंट्रोल यूनिट की अनुमानित ईकाई रुपये 8000 लागत मानी जावेगी।
 6. कतिपय प्रकरणों में पूर्व स्थापित मैन/सब-मैन पाईपलाईन अगर निर्धारित डिजाइन के अनुरूप व तकनीकी रूप से संयंत्र के उपयोग योग्य हो तो पुनः नवीन पाईप लाईन स्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे प्रकरणों में 63, 75 व 90 मिमी पाईप की अनुमानित लागत क्रमशः रुपये 90, 120 व 170 प्रति मीटर मानते हुए ईकाई लागत में से कटौती करते हुए अनुदान की गणना की जावे।
 7. जिन किसानों ने सूक्ष्म सिंचाई के लिये राज्य/केन्द्रीय अनुदान लाभ 5 हैक्टेयर की सीमा में पहले ही ले लिया है वह उसी भूमि पर सिंचाई प्रणाली की अनुमानित आयु अर्थात् 7 वर्ष की समाप्ति के बाद ही अनुदान प्राप्त करने के पात्र होंगे।
 8. जिन कृषकों ने पूर्व में ड्रिप/फव्वारा पर अनुदान ले रखा है एवं क्षेत्र विस्तार के तहत अनुदान हेतु आवेदन किया है ऐसे कृषकों के लिए इस वर्ष की देय अनुदान राशि से ही गणना की जानी है। अनुदान वांछित मॉडल हेतु देय अनुदान के अनुसार ही देय होगा।
 9. कृषक के यहां पूर्व में स्थापित हैड यूनिट या स्वयं द्वारा स्थापित हैड यूनिट के प्रकरण में संयंत्र विस्तार के प्रकरणों में भी अनुदान देय होगा।
 10. कृषक द्वारा नियत क्षेत्र सीमा में फव्वारा कार्यक्रम के तहत अनुदान लिये जाने के पश्चात् ड्रिप संयंत्रों पर अनुदान मांगे जाने पर वांछित क्षेत्र पर फव्वारा हेतु पूर्व में देय अनुदान की राशि ड्रिप हेतु देय अनुदान राशि में से घटाते हुए अनुदान जारी किया जा सकेगा।
 11. कतिपय प्रकरणों में सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के आवेदन के समय कृषकों द्वारा संयंत्र क्रय कर कोटेशन की बजाय आवेदन में बिल प्रस्तुत किया जाता है। कृषकों को समय पर इन संयंत्रों को सुलभ कराया जाने व व्यवहारिक स्थिति के मध्यनजर जिस वित्तीय वर्ष में आवेदन किया गया हो उसी वित्तीय वर्ष के संयंत्र क्रय बिल होने की स्थिति में पात्र कृषकों को अनुदान देय होगा। ऐसे प्रकरणों में योजना प्रावधान/आकार में कमी या योजना मापदण्डानुसार संयंत्र न होने की स्थिति में अनुदान देयता से अमान्य किये जाने की जिम्मेदारी स्वयं कृषक/आपूर्तिकर्ता की होगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदन व संयंत्र क्रय/स्थापन पर कृषक अनुदान प्राप्ति का अधिकार नहीं है।

12. कृषक/संस्थान जिन्होंने लीज/अनुबंध पर कृषि हेतु भूमि ली है वे भी ऐसी भूमि पर यदि कृषि हेतु सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाना चाहते हैं तो उनको भी नियमानुसार अनुदान देय होगा किन्तु यह लीज एग्रीमेंट कम से कम सात वर्ष के लिये होना आवश्यक है।
13. कृषकों के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद/राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और सरकार से संबंधित भूमि को एवं साथ ही सहकारी समिती/स्वयं सहायता समूह/निगमित कम्पनियों/पंचायतीराज संस्थान/गैर सरकारी संगठन/ट्रस्ट/उत्पादक समितियों को भी योजनान्तर्गत अनुदान उपलब्ध करवाया जा सकता है।

लाभार्थी श्रेणी

14. योजना में सभी वर्ग के कृषक अनुदान के पात्र होंगे लेकिन कम से कम 50 प्रतिशत कृषक लघु, सीमान्त एवं महिला श्रेणी के अन्तर्गत होने चाहिए, जिसमें 30 प्रतिशत महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जावे। महिला लाभार्थियों हेतु कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान आवश्यक होगा। कुल आवंटन का 16.2 प्रतिशत एससीपी तथा 8 प्रतिशत टी एस पी के लिये निर्धारित किया जायेगा। अनु. जाति/ अनु. जनजाति किसानों का आवंटन जिले की जनसंख्या में इनके अनुपात के अनुसार किया जावे। विकलांग आवेदकों की स्वीकृतियां प्राथमिकता से जारी की जावे।
15. लघु और सीमान्त किसान के मापदण्डों का सख्ती से अनुसरण किया जाएगा अर्थात् सीमांत (1.0 है. क्षेत्र तक भूमि स्वामित्व) तथा लघु (1.0 से 2.0 है. क्षेत्र तक भूमि स्वामित्व)। लाभार्थी /किसान की होल्डिंग के आकार का निर्धारण या प्रमाणन स्वयं के संज्ञान/प्राधिकृत स्थानीय राजस्व कार्मिकों द्वारा की जायेगी। शंका/विवाद की स्थिति में लघु/सीमान्त कृषक का निर्धारण सक्षम स्तर के राजस्व कार्मिकों (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के अनुसार ही मान्य होगा।

तकनीकी मापदण्ड

16. (a)-कृषकों द्वारा बी.आई.एस. मार्का सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र राज्य में पंजीकृत निर्माता अथवा उसके अधिकृत विक्रेता से निर्धारित मापदण्ड के संयंत्र क्रय करने एवं अपने खेत पर सफलतापूर्वक स्थापित करने पर ही अनुदान देय होगा। बी.आई.एस. मानकों की सूची संलग्न है। लाभार्थी किसी भी पंजीकृत निर्माता अथवा उसके अधिकृत विक्रेता से सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र खरीद के लिए स्वतंत्र होंगे।
- (b)- डीलर/अधिकृत विक्रेता द्वारा जारी किये गये बिल पर निर्माता कम्पनी के द्वारा जारी बिल क्रमांक मय दिनांक एवं कम्पनी अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- (c)- भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के सांकेतिक बीओक्यू में प्रतीकात्मक कम्पोनेंट दर्शाये जाने के मध्यनजर क्षेत्र विशेष में तकनीकी आवश्यकता के मध्यनजर विभिन्न फव्वारा मॉडल में 50, 63, 75, 90 तथा 110 मिमी. के पाइप पर अनुदान अनुमत किया जा सकेगा। क्षेत्र की मांग के मध्यनजर 50 व 110 मिमी. संयंत्र भी अनुमत होंगे। यह स्पष्ट किया जाता है कि 110 मिमी. प्रकरणों में अनुदान की गणना छोटे आकार यथा 75/90 मिमी. हेतु देय अनुदान के अनुसार की जावे जिससे अतिरिक्त वित्तीय भार न हों। उदारणार्थ 0.4-1.0 हैक्टेयर 75 मिमी. मॉडल इकाई लागत रुपये 24194 है अतः अगर कृषक 90/110 मिमी. पर अनुदान चाहा जा रहा हो तो अनुदान की गणना इसी इकाई लागत से की जावे तथा अतिरिक्त राशि का वहन लाभार्थी द्वारा किया जावे।

- (d)- ड्रिप व मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्रों के स्थापन में प्रतीकात्मक कम्पोनेंट पीवीसी मैन/सब मैन लाइन के स्थान पर तकनीकी आवश्यकता के मध्यनजर एचडीपीई पाइप (आईएस: 4984/आईएस:17425) को भी अनुमत किया जा सकेगा।
- (e)- ऑटोमेशन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए योजना के कुल लक्ष्यों का 5 प्रतिशत आवंटन ऑटोमेशन कार्यक्रम हेतु निर्धारित किया जावे।
- (f)- योजना का क्रियान्वयन कलस्टर आधारित रखा जावे तथा कुल लक्ष्यों का 5 प्रतिशत क्रियान्वयन FPO,s के माध्यम से किया जावें।
- (g)- योजना का क्रियान्वयन PPP Mode से भी किया जावें।
- (h)- KVKs/ICAR केन्द्रों पर सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों के प्रदर्शन लगाये जावें।
- (i)- सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर QR Code अंकित हो।
- (j)- रेनगन फव्वारा सिंचाई संयंत्रों के BOQ का भारत सरकार के दिशानिर्देश 2024 के परिशिष्ट 9 के अनुसार क्रियान्वित किया जावें।
17. ड्रिप सिंचाई प्रकरण में ड्रिप के आवश्यक घटकों यथा फिल्टर, उर्वरक टैंक/पम्प/वेंचुरी के अभाव में अनुदान देय नहीं होगा।
18. फव्वारा संयंत्र द्वारा < 0.4 , $> 0.4-1$, $> 1-2$, $> 2-3$, $> 3-4$ व $> 4-5$ हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने हेतु क्रमशः 0.4, 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 व 5.0 हैक्टेयर मॉडल के फव्वारा संयंत्र की आवश्यकता होती है। अतः उक्त उल्लेखित भू-स्वामित्व के कृषकों को उसके अनुरूप वांछित फव्वारा संयंत्र पर अनुदान दिया जा सकेगा।
19. ड्रिप संयंत्रों में तकनीकी रूप से वांछित/वैकल्पिक घटक यथा ड्रिप लाइन वाइडर, उर्वरक टैंक, सेण्ड फिल्टर/मीडिया फिल्टर एवं हाईड्रोसाईक्लोन फिल्टर स्थापित करने पर भी नियमानुसार अनुदान देय होगा।
20. विभिन्न सिंचाई प्रणाली हेतु जारी सांकेतिक घटकों की संख्या/मात्रा में खेत व सिंचाई स्रोत के मध्यनजर बदलाव आ सकता है। उदाहरण के तौर पर फव्वारा के सांकेतिक घटकों में बैण्ड/एंडकैप निर्धारित संख्या दो के स्थान पर तीन या एक क्रय करने पर भी अनुदान देय होगा। इसी प्रकार ड्रिप संयंत्र प्रणाली हेतु मैन/सबमैन पाइप लाइन व लेटरल की लम्बाई में बदलाव आ सकता है। तथापि, सांकेतिक घटक में पांच प्रतिशत से अधिक बढ़ोतरी/कमी की स्थिति में सम्बन्धित निर्माता के तकनीकी कर्मी (अभियन्ता/शष्य विज्ञानी) के स्तर से स्पष्ट तकनीकी कारणों का खुलासा संयंत्र डिजाइन डॉक्यूमेंट्स में किया जावेगा।
21. न्यून अंतराल फसलों में अधिकाधिक प्रकाश संश्लेषण के मध्यनजर यथासंभव ड्रिप लेटरल का ओरियेंटेशन उत्तर-दक्षिण रखा जावें।
- ड्रिप संयंत्रों की ईकाई लागत संयंत्रों के अंतराल के अनुसार तय की गई है। फल बगीचों में स्थापित होने वाले ड्रिप संयंत्रों के प्रकरणों में पौध अन्तराल के बीच अंतराक्षय या दो संयंत्र लेटरल (अगर तकनीकी रूप से तर्क संगत हो) सिंचाई के प्रकरणों में वास्तविक संयंत्र अंतराल पर अनुदान देय होगा।

डाक्यूमेंटेशन

22. राज्य स्तर पर पंजीकृत निर्माताओं एवं उनके द्वारा अधिकृत किये गये डीलर्स की सूची आयुक्तालय द्वारा विभागीय वेबसाइट व राजकिसान साथी पोर्टल पर अपलोड की जावेगी एवं आवेदन हेतु पोर्टल पर भी उपलब्ध होगी तथा अनुदान हेतु वही मान्य होगी।
23. पंजीकृत निर्माताओं द्वारा उनके पास शेष रहे गत वर्ष के दौरान निर्मित सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की सूचना विभाग को सूचित की जावे।
24. अनुदान हेतु वांछित बिल में कार्यान्वयन एजेन्सी द्वारा वैधानिक व्यावसायिक विवरण अर्थात् बिल पर छपी क्रम संख्या, जीएसटी, सीएसटी/आरएसटी/टीआईएन संख्या

- आदि के साथ उचित इनवॉइस सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली निर्माता के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रति हस्ताक्षर कर लाभार्थी को जारी किया जायेगा।
25. बिल में बैच नम्बर (जिसमें निर्मित वर्ष का उल्लेख हो) का अंकन अनिवार्य होगा। बिल में सभी कम्पोनेंट्स जिनके बीआईएस नम्बर हैं, पृथक-पृथक अंकित होना आवश्यक हैं। संयंत्र के प्रत्येक अवयवों पर बैच नम्बर/बीआईएस नम्बर का स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य है।
26. बिल/इनवाइस में आपूर्तिकर्ता द्वारा फिटिंग्स एवं एसेसरीज का स्पष्ट खुलासा किया जाना आवश्यक होगा। ड्रिप संयंत्रों की में एकरूपता हेतु सांकेतिक प्रपत्र के अनुसार तथा फव्वारा संयंत्रों की बिलिंग भी सांकेतिक प्रपत्र पर है।
27. ऑनलाईन अनुदान पत्रावलियों हेतु आवश्यक दस्तावेज—
- अ: ऑनलाईन आवेदन के समय
- जनाधार के माध्यम से ऑनलाईन राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदन
 - भूमि की नवीनतम जमाबंदी /राजस्व रिकॉर्ड की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व)/ऑनलाईन राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति में सीधे ही पोर्टल से फैंच की जा सकेगी।
 - बिजली का बिल/पम्प सैट क्रय बिल (वर्षों पुराने पम्प सैट से सिंचाई कर रहा हो तो स्वयं/विभागीय कार्मिक का प्रमाण-पत्र मान्य होगा)/ जल करार (सिंचाई जल स्रोत)
 - पंजीकृत निर्माता या अधिकृत डीलर का संयंत्र प्रोफार्मा इनवाइस/क्रय बिल मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट एवं डिजाइन (केवल ड्रिप संयंत्र हेतु)
- ब: वित्तीय स्वीकृति जारी करने से पूर्व आवश्यक दस्तावेज
- कृषक द्वारा कृषक हिस्सा राशि निर्माता को जमा करवाने की रसीद।
 - पंजीकृत निर्माता/अधिकृत विक्रेता द्वारा जारी संयंत्र क्रय बिल
 - संयंत्र स्थापन की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए सैट को बेचान/दान/उधार अथवा खुर्द-बुर्द नहीं करने एवं स्थापन के पश्चात् पाँच वर्ष के दौरान कृषि/उद्यान/अन्य राजकीय विभाग के किसी अधिकारी द्वारा सैट के सत्यापन/निरीक्षण की सहमति बाबत सादे कागज पर शपथ-पत्र/अंडर टेकिंग।
 - इस आशय का प्रमाण पत्र कि उसे अथवा उसके परिवार में किसी सदस्य (यदि अलग नहीं है) को राज्य/भारत सरकार की किसी योजना के तहत प्रस्तावित भूमि पर पात्र समयावधि 7 वर्ष में 5 हैक्टेयर सीमा में ड्रिप/स्प्रिंकलर के लिये वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई गई है।
 - स्थापित संयंत्र के अनुरूप बनाया गया नक्शा।
 - लघु/सीमान्त/SC/ST का प्रमाण-पत्र (अगर लागू हो)।
 - यदि उसके पास अपना /अपने खेत /प्लाट, जिसके लिए वित्तीय सहायता ली जा रही है, में जल का स्रोत नहीं है, तब पड़ोसी लाभार्थी से सिंचाई के स्रोत की साझेदारी हेतु 5 साल का जल करार जिनसे वह पानी लेने का/की इच्छुक है।
 - त्रि-पार्टी अनुबंध 500/-रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर।
28. लाभार्थी/ आपूर्तिकर्ता द्वारा आवश्यक रूप से पूर्ण दस्तावेजों के साथ राजस्थान सरकार के राजकिसान साथी पोर्टल पर स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करना होगा।

अन्य

29. **ड्रिप रेपर (Drip Line Winder)** — फसल कटाई उपरांत अन्तःशस्य कार्य हेतु ड्रिप लेटरल को लाभार्थी द्वारा इकट्ठा किया जाता है। उचित जानकारी एवं उपकरण के

- अभाव में एकत्रित ड्रिप लेटरल में कट लगने के कारण इसकी आयु कम हो जाती है।
अतः 2 हैक्टेयर से अधिक स्थापित न्यून अन्तराल ड्रिप संयंत्रों के साथ ड्रिप रेपर मशीन की आपूर्ति सुनिश्चित की जावे।
30. ड्रिप संयंत्रों पर प्रेशर गेज आवश्यक रूप से स्थापित किया जावें। डिजाइन की आवश्यकता अनुसार ऐयर प्रेशर रिलीज वाल्व भी स्थापित किये जावें।
31. न्यून अन्तराल ड्रिप संयंत्रों में डिस्क फिल्टर अनिवार्य रूप से स्थापित किया जावें।

स. आवेदन एवं निस्तारण की प्रक्रिया

1. कृषक चयन

- 1.1 उद्यान/कृषि विभाग के अधिकारी, संयंत्र आपूर्तिकर्ता तथा अन्य संबंधित संस्थाएँ उप निदेशक उद्यान के माध्यम से अपने क्षेत्र में अधिसक्रिय (Proactive) रूप से प्रगतिशील व संभाव्य कृषकों का चयन करेंगे।
- 1.2 पंजीकृत संयंत्र निर्माताओं द्वारा उनके नेटवर्क के माध्यम से संभाव्य कृषकों से सम्पर्क किया जाकर आवेदन पत्र राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाइन तैयार कराये जायेंगे। (Annexure -4)
- 1.3 कृषि पर्यवेक्षक/सहायक कृषि अधिकारी, सहायक निदेशक उद्यान/कृषि, बैंक, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा संयंत्र आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का प्रचार-प्रसार उप निदेशक उद्यान सुनिश्चित करेंगे।
- 1.4 उद्यान/कृषि विभाग के कार्मिकों/पंजीकृत फव्वारा/ड्रिप निर्माताओं द्वारा कृषकों के ऑनलाइन आवेदन तैयार कराये जाने में सहायता दी जायेगी व ऑनलाइन स्वीकृति की कार्यवाही की जावेगी।

2. पंजीकरण एवं आवेदन पत्रों का सूक्ष्म परीक्षण

- 2.1 कृषक द्वारा आवेदन हेतु आवश्यक समस्त कागजात जैसे- भू-स्वामित्व, सिंचाई स्रोत का प्रमाण-पत्र, जल उपयोग सहमति इत्यादि ऑनलाइन अपलोड किया जावेगा।
- 2.3 ऑनलाइन/राजकिसान साथी पोर्टल पर प्राप्त आवेदन का कृषि अधिकारी या अधिकृत प्राधिकारी द्वारा प्राथमिकता से सूक्ष्म परीक्षण (जांच) किया जावेगा।
- 2.4 सही पाये गये पूर्ण आवेदन प्रशासनिक स्वीकृति हेतु अग्रेषित एवं अपूर्ण आवेदन बैंक टू सिटीजन तथा अपात्र आवेदन निरस्त किये जायेगे।

3. तकनीकी-आर्थिक सर्वे

- 3.1 उद्यान विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के निर्देशन में संबंधित संयंत्र आपूर्तिकर्ता के एग्रोनोमिस्ट द्वारा Annexure 14 अनुरूप खेत का तकनीकी सर्वेक्षण, मृदा-जल का परीक्षण तथा स्थापित किये जाने वाले संयंत्र का रूप-रेखा (डिजाइन) तैयार किया जावेगा।
- 3.2 कृषक की आवश्यकता तथा रूप-रेखा (डिजाइन) के आधार पर निर्माता द्वारा लागत अनुमान तैयार किये जावेंगे। इसके पश्चात् तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन तैयार किया जावेगा तथा पात्र प्रकरण में संबंधित कृषक की सहमति प्राप्त की जावेगी।
- 3.3 संयंत्र आपूर्ति कर्ता जल गुणवत्ता के आधार पर यथोचित फिल्टर चुनाव कर डिजाइन में समावेश सुनिश्चित करेंगे।
- 3.4 संयंत्रों की ईकाई लागत वर्ष 2024 में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित ईकाई लागत के अनुसार मान्य होगी।
- 3.5 उक्त दस्तावेज राजकिसान साथी पोर्टल पर अपलोड किये जायेगे।

4. आवेदन अनुमोदन, प्रशासनिक स्वीकृति एवं कृषक हिस्सा राशि संग्रहण

- 4.1 राजकिसान साथी पोर्टल पर आवेदित समस्त सूक्ष्म सिंचाई पत्रावलियों के पात्र प्रकरण उप निदेशक उद्यान द्वारा निस्तारित किये जायेंगे।
- 4.2 ऑनलाईन पूर्ण दस्तावेज प्राप्त होने पर बिना हार्ड कॉपी का इंतजार किये उप निदेशक उद्यान द्वारा नियमित समयावधि में अविलम्ब सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापन हेतु लक्ष्यों की सीमा में ऑनलाईन प्रशासनिक स्वीकृति "पहले आओ पहले पाओ" के सिद्धान्त पर जारी की जावेगी।
- 4.3 प्रशासनिक स्वीकृति की सूचना तत्पश्चात् पोर्टल द्वारा संबंधित आपूर्तिकर्ता तथा कृषक को प्रेषित की जावेगी ताकि निश्चित समयावधि के दौरान संयंत्र स्थापन की मॉनीटरिंग की जा सके।
- 4.4 कृषक हिस्सा राशि का संग्रहण सीधे ही आपूर्तिकर्ता फर्म द्वारा किया जा सकेगा। कृषक हिस्सा राशि कृषक द्वारा सीधे जिला कार्यालय में या आपूर्तिकर्ता फर्म में जमा करा सकेगा। आपूर्तिकर्ता फर्म को जमा कराने की दशा में फर्म द्वारा दो प्रतियों में रसीद तैयार की जाकर एक प्रति कृषक एवं दूसरी प्रति जिला कार्यालय में प्रेषित की जायेगी।
- 4.5 न्यून अंतराल ड्रिप सिंचाई संयंत्रों पर बड़ी अनुदान राशि जारी की जाती है। 2 हैक्टेयर से अधिक न्यून अंतराल ड्रिप स्वीकृति प्रकरणों का निस्तारण तर्क संगत आधार पर किये जाने के मध्येनजर समस्त स्टेक होल्डर्स (यथा लाभार्थी, आपूर्तिकर्ता, तकनीकी अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी) का शपथ पत्र/संस्तुति/अनुमोदन निर्धारित प्रपत्र (Annexure 13) पर प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
- 4.6 ऑनलाईन आवेदन से संयंत्र स्थापना की समस्त प्रक्रिया निर्धारित समयावधि में सम्पन्न करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रशासनिक स्वीकृति निरस्ती की कार्यवाही की जायेगी। निर्धारित समयावधि संलग्न फ्लो चार्ट में दर्शित है।
- 4.7 ऑनलाईन आवेदन के समय कृषक द्वारा ड्रॉपडाउन लिस्ट में से पंजीकृत निर्माता/आपूर्तिकर्ता का चयन किया जायेगा तथा ड्रिप/मिनी स्प्रींकलर प्रकरणों में अनुदान स्वयं या आपूर्तिकर्ता को किये जाने की अनुशंसा की जावेगी।
- 4.8 सम्बन्धित निर्माता द्वारा राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाईन भुगतान निर्माता/अधिकृत विक्रेता को किये जाने की अनुशंसा की जावेगी।

5. अनुबंध एवं संयंत्र स्थापना

- 5.1 प्रशासनिक स्वीकृति उपरान्त उप निदेशक उद्यान, संयंत्र आपूर्तिकर्ता तथा संबंधित कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर त्रि-पार्टी अनुबंध संपन्न किया जावेगा।
- 5.3 प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के पश्चात् निर्धारित समयावधि में संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा संयंत्र सामान की आपूर्ति की जाकर संयंत्र स्थापन के पश्चात् ऑनलाईन ऐप के माध्यम से जियो टैगिंग की जायेगी।
- 5.4 एक माह की अवधि से ज्यादा विलंब की स्थिति में संबंधित कृषक किसी अन्य अनुमोदित आपूर्तिकर्ता से संयंत्र स्थापन करवाने के लिए स्वतंत्र होगा। विलंब अवधि की गणना प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने के दिवस से की जायेगी।
- 5.5 विलम्ब के लिए उत्तरदायी आपूर्तिकर्ता की प्रशासनिक स्वीकृति निरस्त करते हुए सूचना अविलम्ब आयुक्तालय उद्यानिकी, फर्म एवं कृषक को दी जायेगी।
- 5.6 कृषक द्वारा खुदाई व अन्य निर्माण संबंधित कार्य सम्पन्न करवाये जायेंगे।
- 5.7 संयंत्र स्थापन कार्य पूर्ण होने पर आपूर्तिकर्ता द्वारा तत्काल ऑनलाईन पोर्टल व्यवस्था द्वारा सूचित किया जावेगा।
- 5.8 प्रायः हेड कन्ट्रोल यूनिट की पक्की फाउण्डेशन नहीं की जाती है। संयंत्र की लम्बी आयु हेतु पक्के फाउण्डेशन आवश्यक है। अतः ड्रिप संयंत्रों के स्थापन में लाभार्थी स्तर से पक्का

फाउन्डेशन कार्य अनिवार्य होगा। हैड कन्ट्रोल यूनिट के चारों तरफ यथा संभव तारबन्दी की जावे ताकि जानवरों इत्यादि से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके।

6. भौतिक सत्यापन (मोबाइल ऐप के माध्यम से)

यथा संभव विभागीय अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन किया जावेगा तथापि थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन एजेंन्सी (Third Party Inspection Agencies) का भी प्रावधान करते हुये जिला विशेष की तर्क संगत आवश्यकता अनुसार इनकी सेवाएं ली जावेगी। थर्ड पार्टी के साथ भौतिक सत्यापन के दौरान कृषि पर्यवेक्षक/सहा.कृषि अधिकारी अवश्य रहे। थर्ड पार्टी का चयन आयुक्तालय के स्तर पर निविदा/अभिव्यक्ति की अभिरुचि (Expression of Interest) द्वारा किया जावेगा तथा भुगतान पीडीएमसी योजना के प्रशासनिक मद से किया जायेगा।

विभागीय भौतिक सत्यापन निम्न प्रकार सम्पन्न कराया जावें:-

क्र.सं.	पद भौतिक सत्यापन कर्ता		
	अनुदान राशि (रूपये लाख)	फव्वारा / रेनगन / ड्रिप / मिनि स्प्रिंकलर	
1	1.50 लाख तक	कृ.प. + स.कृ.अ. या ऊपर	
2	1.50 लाख से अधिक	कृ.प. / स.कृ.अ + कृ.अ. या ऊपर	

उक्त कार्मिक कृषि/उद्यानिकी विभाग से होंगे। जिसकी भौतिक सत्यापन हेतु मैपिंग जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा की जायेगी।

- 6.1 थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन की दशा में भौतिक सत्यापन का कार्य विभाग द्वारा जारी अभिव्यक्ति की अभिरुचि (Expression of Interest) के माध्यम से अनुमोदित थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसीज (Third Party Inspection Agencies) द्वारा सम्पन्न करवाया जावेगा।
- 6.3 भौतिक सत्यापनकर्ता द्वारा भौतिक सत्यापन व प्रायोगिक परीक्षण निर्धारित अवधि में ऐप के माध्यम से पूर्ण करना होगा।
- 6.4 थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसीज (Third Party Inspection Agencies) द्वारा भौतिक सत्यापन के प्रकरणों में रेण्डम आधार पर कम से कम 20 प्रतिशत पुनः भौतिक सत्यापन कृषि अधिकारी से निम्न विभागीय अधिकारियों द्वारा करना होगा।
- 6.5 संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि भौतिक सत्यापन के दौरान खोदी गई खाई उक्त कार्य हेतु निर्दिष्ट स्थानों पर खुली रखी जावे। भौतिक सत्यापन व प्रायोगिक परीक्षण के दौरान स्वयं की संतुष्टि हेतु संबंधित कृषक स्वयं उपस्थित रहेगा। कृषक के खेत पर लगाया गया संयंत्र भारत सरकार के दिशा-निर्देशों में उल्लेखित कम्पोनेन्ट के अनुसार होना चाहिए। प्रायोगिक परीक्षण पश्चात् संबंधित कृषक द्वारा संयंत्र अपने कब्जे में लिया जावेगा तथा निर्धारित प्रपत्र में कार्यपूर्ण प्रमाण-पत्र संबंधित संयंत्र आपूर्तिकर्ता को जारी किया जाकर अपलोड किया जायेगा।
- 6.6 (अ) भौतिक सत्यापन रिपोर्ट में आवेदन पत्र पर मौके पर ही रिपोर्ट में भौतिक सत्यापन कर्ता का नाम, पदनाम, निरीक्षण दिनांक, फव्वारा/ड्रिप सैट में प्रयुक्त होने वाले कम्पोनेन्ट्स के मैनुफैक्चरिंग बैच नम्बर, कम्पनी का ISI मार्का नम्बर, सी.एम.एल. नम्बर, कम्पनी का ब्रांड नाम/मेक तथा कृषक द्वारा पूर्व में फव्वारा/ड्रिप संयंत्र पर अनुदान नहीं लिये जाने का प्रमाण पत्र अंकित कर आवेदन पत्र ऑनलाईन अपलोड किया जायेगा।
(ब) आपूर्तिकर्ता द्वारा भौतिक सत्यापन पूर्व संयंत्र की सामग्री की चैकलिस्ट उपलब्ध करायी जावेगी (संलग्न प्रपत्र 14 (II) अनुसार)। भौतिक सत्यापन के दौरान भौतिक सत्यापनकर्ता थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसीज (Third Party Inspection Agencies) द्वारा

मौके पर संयंत्र का फोटो लेकर जीयो-टैगिंग किया जावेगा एवं इसी साफ्टवेयर में उपलब्ध भौतिक सत्यापन प्रपत्र को भरकर अपलोड किया जावेगा।

- 6.7 भौतिक सत्यापन का वास्तविक उद्देश्य यह सत्यापित करना है कि लाभार्थी द्वारा वास्तव में फव्वारा/ड्रिप संयंत्र स्थापित कर लिया गया है तथा अनुदान का पात्र है। अतः भौतिक सत्यापन उद्देश्य पूरक होना चाहिए न कि प्रक्रियात्मक। सत्यापन के दौरान कम से कम चार फोटो किसान एवं भौतिक सत्यापन कर्ता अधिकारी के साथ अलग-अलग कोण से लिये जाकर अपलोड किये जायेंगे।
- 6.8 6.10 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् संबंधित खण्ड स्तरीय अधिकारियों द्वारा कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित करके रेन्डम आधार पर 2 से 5 प्रतिशत संयंत्रों का पुर्नभौतिक सत्यापन करवाया जावेगा। यह कार्यवाही 10 मई तक पूर्ण करनी होगी।
- 6.11 संबंधित खण्ड स्तरीय कृषि/उद्यान विभाग द्वारा भी रेन्डम आधार पर अपने क्षेत्र के कम से कम 5 से 10 प्रतिशत संयंत्रों का पुर्नभौतिक सत्यापन किया जावेगा।
- 6.12 रेन्डम आधार पर किये गये पुर्नभौतिक सत्यापन के दौरान कार्यक्रम क्रियान्वयन के सम्बन्ध में पायी गयी अनुकूल/प्रतिकूल स्थितियों की टिप्पणी सम्बन्धित खण्ड स्तरीय अधिकारी कृषि/उद्यान द्वारा उद्यान आयुक्तालय को प्रेषित की जावेगी।
- 6.13 उद्यान आयुक्तालय स्तर पर गठित दल द्वारा कार्यक्रम का आवश्यकतानुसार समय-समय पर आकस्मिक निरीक्षण किया जावेगा।
- 6.14 भौतिक सत्यापन अधिकारियों द्वारा भौतिक सत्यापन के समय आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रस्तुत डिजायन मैप आवश्यक रूप से साथ रखा जावे तथा मैप में इंगित अनुसार समस्त आईटम फील्ड में पाया जाना सुनिश्चित किया जावे। ड्रिप स्थापन के वर्क मैनशिप (हेड कन्ट्रोल यूनिट/कन्ट्रोल वॉल्व/प्लस वॉल्व की उचित फिटिंग, ट्रेन्च पूरी तरह मिट्टी से पुनः भरा जाना) पर विशेष ध्यान दिया जावे।
- 6.15 डिजाइन मैप तैयार करने का कार्य निर्माता के अधिकृत एग्रोनोमिस्ट या इंजिनियर द्वारा ही तैयार किया जाना अनिवार्य है। डिजायन पर सम्बन्धित डिजायनकर्ता का नाम मय योग्यता (eg. MSc Ag. Agro./ B tech Ag. Etc.) अंकित की जावे। डिजाइन हेतु प्राधिकृत इंजीनियर/एग्रोनोमिस्ट के प्रमाणित हस्ताक्षर निर्माता स्तर से जिला ईकाई को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे। डिजाइन चार्ट/मैप में एकरूपता लाये जाने के मध्येनजर विभाग द्वारा अग्रेषित सैम्पल डिजायन मैप (Annexure 14) के अनुसार समस्त आपूर्तिकर्ता डिजायन मैप प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करे।

7. अंतिम भुगतान (ऑनलाईन)

- 7.1 स्थापित फव्वारा संयंत्र का ऑनलाईन भौतिक सत्यापन करने के पश्चात् संबंधित क्षेत्र के जिला अधिकारी उद्यान द्वारा उपलब्ध बजट सीमा में वित्तीय स्वीकृति जारी कर अनुदान राशि का भुगतान कृषक के खाते में ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा जारी किया जावेगा।
- 7.2 ड्रिप / मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्रों के प्रकरणों में संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक को जारी कार्यपूर्ण प्रमाण-पत्र, तथा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ विधिवत प्रमाणित/अंतिम भुगतान बिल अपलोड किया जावेगा। उप निदेशक उद्यान द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर सम्बंधित कृषक/संयंत्र आपूर्तिकर्ता निर्माता को अऋणी प्रकरणों में शेष देय अनुदान राशि का भुगतान ऑनलाईन किया जावेगा। कृषक द्वारा संयंत्र का पूर्ण भुगतान करने की स्थिति में अनुदान राशि कृषक के खाते में किया जायेगा। कृषक द्वारा आंशिक भुगतान व आपूर्तिकर्ता द्वारा अनुदान राशि सम्बंधित कृषक से नहीं लिये जाने की स्थिति में कृषक की अनुशंसा पर उसे देय अनुदान का भुगतान आपूर्तिकर्ता निर्माता के खाते में ऑनलाईन किया जा सकेगा। ऋणी प्रकरणों में उप निदेशक उद्यान द्वारा कृषक की अनुशंसा पर संबंधित बैंक में शेष अनुदान राशि का भुगतान ऑनलाईन किया जावेगा।

कार्यक्रम को पूर्ण डीबीटी मोड पर ले जाने की दिशा में कदम उठाते हुए राज्य के 10 अग्रणी जिलों में ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर के 20 प्रतिशत प्रकरण आवश्यक रूप से डीबीटी के माध्यम से सीधे कृषकों के पक्ष में सम्पन्न करवाये जाने हैं। डीबीटी के प्रकरणों में अनुदान भुगतान प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा। ये 10 जिले जैसे जालोर, जयपुर, अलवर, झालावाड़, बाड़मेर, जोधपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, नागौर एवं सिरोंही हैं।

- 7.3 ड्रिप/मिनी/माइक्रो स्प्रिंकलर संयंत्रों की ऑनलाईन व्यवस्था से जनरेट प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति संबंधित जारीकर्ता कम्पनी एवं आयुक्तालय उद्यान को ऑनलाईन व्यवस्था से संप्रेषित की जायेगी।
- 7.4 सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की स्थापना उपरान्त अधिकृत विक्रेता द्वारा जारी किये जाने वाले बिल पर निर्माता कम्पनी द्वारा जारी किये गये बिल (इनवॉइस) का नम्बर मय दिनांक अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 7.5 सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर अनुदान हेतु वित्तीय स्वीकृति जारी करने के पूर्व भौतिक सत्यापन दस्तावेजों के साथ संयंत्र निर्माता से कृषक हिस्सा राशि की रसीद भी अपलोड कराई जानी होगी।
- 7.6 भुगतान से पूर्व भौतिक सत्यापन सम्बन्धी समस्त प्रक्रिया की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जावे। बिलिंग क्षेत्र सीमा से कम क्षेत्र में (5 प्रतिशत अन्तर के अलावा) भौतिक सत्यापन के दौरान संयंत्र स्थापन पाये जाने की स्थिति में अनुदान भुगतान न किया जावे तथा सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावे तथा संबंधित निर्माता कम्पनी के विरुद्ध विभाग द्वारा पंजीयन निरस्तीकरण/अमानत राशि की जब्ती आदि की कार्यवाही संबंधित फर्म को आयुक्त उद्यान/अध्यक्ष आरएचडीएस के समक्ष सुनवाई का अवसर देने के बाद उनके द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार अमल में लायी जावेगी। 5 प्रतिशत तक बिलिंग क्षेत्र सीमा में भौतिक सत्यापन कम पाये जाने पर भुगतान में अनुपातिक कटौती कर भुगतान किया जायेगा।
- 7.7 भुगतान लाभार्थी/आपूर्तिकर्ता को भुगतान एसएनए स्पर्श/पे-मैनेजर प्रक्रिया के माध्यम से किया जावे।
- 7.8 योजनान्तर्गत दी जाने वाली अनुदान राशि बैंक में जमा होने की सूचना एसएमएस (SMS)/ई-मेल के माध्यम से तथा लिखित में लाभार्थी कृषक तथा निर्माता कम्पनी दोनों को आवश्यक रूप से संप्रेषित किया जाना सुनिश्चित करावे।

8. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रशिक्षण, संचालन व नक्शा सुपुर्दगी

(i) संयंत्र आपूर्तिकर्ता कम्पनी द्वारा कृषक को खेत में स्थापित संयंत्र के अनुरूप बनाया गया नक्शा सुपुर्द किया जावेगा। नक्शों में हैड कंट्रोल यूनिट, जल धारक व वितरण प्रणाली, पाईप लाईन, विभिन्न वाल्व की स्थिति, जोड़ व अन्य अवयवों की पूर्ण स्थिति दर्शाई जावेगी। इसके साथ-साथ सिंचाई व उर्वरकीकरण समय-सारणी, सभी फसलों जिनके लिए डिजाईन तैयार की गई है उनकी तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन की प्रति एवं संयंत्र के रख-रखाव समय-सारणी का साहित्य भी संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक को उपलब्ध कराया जावेगा। उक्त नक्शे व अन्य कागजात का व्यय संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा वहन किया जावेगा।

(ii) कृषक से इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जावे कि संयंत्र स्थापना, उपयोगिता व संचालन की पूर्ण जानकारी आपूर्तिकर्ता/कृषि विभाग के क्षेत्रीय अधिकारी/कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई है।

(iii) संयंत्र स्थापना के बाद आपूर्तिकर्ता कम्पनी के तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कृषकों एवं कृषि विभाग के अधिकारी/कर्मचारी के समक्ष संयंत्र का संचालन कर उपयोग की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाये। माह दिसम्बर में निर्माता द्वारा संयंत्र संधारण रिपोर्ट प्रस्तुत की जावेगी।

द. अनुदान की सीमा एवं भुगतान :-

1. संयंत्रों की ईकाई लागत वर्ष 2024 में कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित ईकाई लागत के अनुसार मान्य होगी।
2. ड्रिप, मिनि स्प्रिंकलर तथा स्प्रिंकलर संयंत्र पर देय अनुदान

सिंचाई संयंत्र का नाम	कृषक श्रेणीवार अनुदान (ईकाई लागत का)	
	लघु सीमान्त कृषक / एससी / एसटी / महिला	अन्य कृषक
ड्रिप एवं मिनि स्प्रिंकलर	75 प्रतिशत	70 प्रतिशत
स्प्रिंकलर	75 प्रतिशत	70 प्रतिशत

राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत (RKVY/PDMC) सूक्ष्म सिंचाई योजना 2025-26 के दौरान सिंचाई संयंत्रों पर देय अनुदान

क.सं	सिंचाई संयंत्र का नाम	कृषक श्रेणी	कुल देय अनुदान प्रतिशत में	केन्द्रीय/राज्यांश प्रतिशत में	राज्यांश प्रतिशत में	अति.राज्यांश प्रतिशत में
1	ड्रिप, मिनि स्प्रिंकलर एवं स्प्रिंकलर	लघु एवं सीमान्त कृषक	75	33	22	20
		SC/ ST/ Woman	75	33 / 27	22 / 18	20 / 30
		अन्य कृषक	70	27	18	25

3. सूक्ष्म सिंचाई स्वचालन (ऑटोमेशन) हेतु समस्त श्रेणी कृषकों को 75 प्रतिशत अनुदान देय होगा। जिसमें के.प्र.यो. द्वारा देय रुपये 40000 प्रति हैक्टेयर से अधिक की देय राशि अतिरिक्त अनुदान/राज्य संसाधन मद से देय होगा।
4. RWSLIP व RWSRPD या अन्य परियोजना क्षेत्र में विभागीय योजना में देय अनुदान पर अतिरिक्त टॉपअप का प्रावधान रहेगा जिसके निर्देश समय-समय पर जारी किये जायेंगे। अटल भूजल योजना के तहत चयनित ब्लॉक्स (तालिका) हेतु विशिष्ट प्रावधान समय-समय पर सूचित की जावेगी।
5. RWSLIP/MIF/Automation व अटल भू-जल योजना हेतु समय-समय पर जारी दिशानिर्देश तत् समय लागू होंगे।

य. निर्माता पंजीकरण एवं आपूर्तिकर्ता दायित्व

निर्माताओं का पंजीकरण राज्य स्तर पर विभाग द्वारा किया जावेगा। योजना क्रियान्वयन हेतु संयंत्र की आपूर्ति सीधे ही निर्माता या उनके अधिकृत डीलर द्वारा किया जावेगा। जिला उप निदेशक उद्यान द्वारा जिले में कार्य कर रहे निर्माताओं की सूची का संधारण पंजिका में किया जावेगा।

निर्माता /कंपनी द्वारा प्रणाली लगाई जाएगी और किसान की संतुष्टि के अनुसार इसे आरम्भ किया जाएगा और निम्नलिखित बिन्दुओं को सुनिश्चित किया जाएगा:-

1. फसल के अनुसार फसल की पानी की आवश्यकता की आंकलन करना जिसके लिए सिंचाई प्रणाली प्रदान की जानी है।
2. फसल की जल आवश्यकता के अनुसार प्रणाली का डिजाइन तैयार करना।
3. लागत का आंकलन तैयार करके इसे क्रियान्वयन एजेंसी को ऑनलाइन पोर्टल पर प्रस्तुत करना जिसमें स्पष्ट रूप से किसान के खेत में प्रणाली स्थापित करने की समय सीमा दर्शायी गई हो।
4. किसानों के खेतों में बेहतर गुणवत्ता वाले बीआईएस प्रमाणित उपकरण लगाए जाएंगे और भुगतान करते समय क्रियान्वयन एजेंसी आपूर्ति किए गए उपकरणों के बीआईएस मानकों को सुनिश्चित करेगी। संयंत्र की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु फील्ड एवं निर्माता इकाई से रेण्डम आधार पर नमूने लिये जाकर समय समय पर जाँच करवायी जावे। नमूने की जांच का व्यय योजना के प्रशासनिक मद से भुगतान किया जावे।
5. स्थापित प्रणाली फसल की जल जरूरत के अनुसार प्रासंगिक होनी चाहिए।
6. जिला स्तर पर ड्रिप/स्प्रिंकलर सिंचाई के साथ फसल की सिंचाई के लिए अनुसरण की जाने वाली कृषि क्रियाओं हेतु किसानों को आवश्यक नवीनतम यथा फर्टीगेशन, ऑटोमेशन, एसिड ट्रीटमेंट जानकारी तथा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कृषकों में जागरूकता एवं आवेदन प्रोत्साहन हेतु व्यापक स्तर पर अभियान भी समय-समय पर चलाये जावें।
7. ड्रिप तथा स्प्रिंकलर या दोनों सिंचाई प्रणालियों हेतु किसानों के पास प्रणाली को चलाने तथा इसके रख-रखाव के लिए उपयोगकर्ता हिन्दी में मैनुअल तथा उचित वारंटी होनी चाहिए।
8. लाभार्थी से प्रणाली को सफलतापूर्वक संस्थापित/आरंभ करने का प्रमाण-पत्र लिया जाए।
9. निर्माता द्वारा कम से कम पाँच वर्ष बिक्री के बाद निशुल्कसेवा प्रदान की जायेगी। विक्रय पश्चात् सेवा के तहत निर्माताओं द्वारा अपने एग्रोनोमिस्ट फ़िल्ड में समय-समय पर भिजवाये जाना सुनिश्चित किया जावें। इसका प्रमाण पत्र 5 वर्ष तक प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में निर्माता को देना होगा। आपूर्तिकर्ता द्वारा स्थापित ड्रिप संयंत्रों में तकनीकी आवश्यकता के मध्यनजर Acid treatment करवाया जावे।
10. आपूर्ति किये गये सामान के बारे में उत्पन्न किसी तरह के विवाद की जिम्मेदारी स्वयं निर्माता की होगी।
11. बिक्री पश्चात् सेवा केन्द्रों/कार्यालयों की सूची जिसमें पूरा पता/टेलीफोन नंबर/ई-मेल, टोल फ्री नम्बर आदि का व्यापक रूप से प्रचार किया जायेगा।
12. पंजीकृत निर्माता द्वारा पंजीकरण के तत्काल पश्चात् सम्बन्धित जिला इकाइयों को अधिकृत मूल्य सूची से अवगत कराना होगा।
13. आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रति 250 हैक्टर या इसके अंश ड्रिप स्थापन प्रति वर्ष पर कम से कम एक तकनीकी कार्मिक (एग्रोनोमिस्ट/कृषि अभियन्ता) रखा जावेगा। क्षेत्रवार तकनीकी कार्मिकों की सूची आयुक्तालय के साथ-साथ सम्बन्धित उप निदेशक उद्यान को भी प्रेषित की जावेगी। तकनीकी कर्मियों द्वारा संयंत्रों की तकनीकी डिजाइन के अलावा संयंत्र रख-रखाव तथा फसल उत्पादन सम्बन्धि जानकारीयां प्रदान की जायेगी। तकनीकी कार्मिकों की सूचना जिलेवार मुख्यालय, जयपुर को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

14. निर्माता फर्म द्वारा तकनीकी कर्मियों के माहवार भ्रमण प्रतिवेदन सम्बन्धित उप निदेशक उद्यान को प्रस्तुत किया जावें।
15. निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संयंत्र स्थापना व विक्रय पश्चात सेवाओं का निर्वहन न करने की स्थिति में आपूर्तिकर्ता कम्पनी की जिम्मेदारी तय की जाकर सम्बन्धित के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जा सकेगी। गम्भीर अनियमितता की स्थिति में सम्बन्धित की भुगतान प्रक्रिया रोकी जाकर काली सूची में डालने की कार्यवाही आयुक्त उद्यान/अध्यक्ष आरएचडीएस के निर्देशानुसार की जा सकेगी एवं अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी।
16. ऑनलाईन, नो रिलेवेनसनिर्माता/अधिकृत डीलर्स द्वारा बिल में GSTIN, CML, ISI, BIS Batch No. का अंकन किया जावें। आपूर्तिकर्ता द्वारा यथासंभव कम्प्यूटराइज्ड बिल व डिजाईन ले-आउट प्रस्तुत किया जावें।
17. आपूर्तिकर्ताओं के पंजीकरण शर्तों का विस्तृत विवरण संलग्नक 17 पर स्थित है।

र. गुणवत्ता नियंत्रण व प्रशिक्षण

1. निर्माता द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री बेहतर गुणवत्ता तथा बीआईएस प्रमाणित होनी चाहिए एवं लगाए गए उपकरण पंजीकरण के दौरान निर्माता द्वारा घोषित मानकों के अनुरूप होना चाहिए। इसके साथ ही समय समय पर फील्ड से नमूना लेकर गुणवत्ता की जाँच हेतु सीपेट जयपुर को भिजवाया जावें।
2. ड्रिप लेटरल तथा उत्सर्जक का वितरण फसल अंतराल के अनुरूप होना चाहिए जिसमें यह सुनिश्चित हो कि पौधों का जड़ वाला क्षेत्र गीला होगा।
3. लेटरल पर प्रथम तथा अंतिम उत्सर्जक के बीच पानी का प्रयोग समान होना चाहिए (10 प्रतिशत विविधता के तहत)।
4. ड्रिप सिंचाई की स्थापना और सिंचाई प्रबन्धन प्रणाली से कृषक सन्तुष्ट होना चाहिए।
5. किसानों के पास प्रणाली लगाने वाले संबंधित निर्माता की उपभोक्ता पुस्तिका (यूजर्स मैनुअल) होनी चाहिए।
6. मुख्य लेटरल में घर्षण शीर्ष नुकसान मुख्य लेटरल के 1 मी./ 100 मी. से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
7. आपूर्तिकर्ता के स्तर से लाभार्थियों को समय-समय पर प्रशिक्षण प्रदान किया जावें।
8. योजना में उपलब्ध प्रावधान के तहत समय-समय पर कृषक/कार्मिक/अधिकारी प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे (दम्पति प्रशिक्षण के दिशानिर्देश संलग्न)।

ल. अन्य बिन्दू

1. स्वीकृत प्रकरणों का संधारण जिला स्तर पर किया जायेगा जो लाभान्वित कृषकों की ग्रामवार सूची वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक को उपलब्ध कराई जावेगी, जिससे सहायक कृषि अधिकारी व कृषि पर्यवेक्षक का रिकॉर्ड आदिनांक हो जाए तथा अगले वर्ष में भौतिक सत्यापन करने में कोई कठिनाई नहीं आए। जिला मिशन समिति(DMC) द्वारा समय-समय पर बैठक आयोजित कर कार्ययोजना व व्यय का अनुमोदन तथा प्रगति की समीक्षा की जावेगी।
2. एमआईएस योजनान्तर्गत किये गये व्यय का उपयोगिता प्रमाण-पत्र भी निर्धारित प्रपत्र में हर त्रिमाही के अंत में भिजवाया जाना आवश्यक होगा। वित्तीय वर्ष के अंत में समेकित उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजा जावेगा। खण्ड स्तरीय अधिकारी, उद्यान द्वारा समय-समय पर लाभार्थियों की सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना उपरान्त उत्पादकता, गुणवत्ता एवं आर्थिक स्तर के बदलाव का सर्वेक्षण किया जावे। चिन्हित लाभार्थियों की सफलता की कहानी कम से

कम 5 कृषक प्रति जिला आवश्यक रूप से मय फोटोग्राफ तथा सीडी के राज्य स्तर को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सिंचाई प्रणाली के माध्यम से आर्थिक स्तर में आये बदलाव का पूर्ण विवरण अंकित हों।

3. राज्य में पंजीकृत निर्माताओं के निर्माण परिसर एवं कार्यालयों का मुख्यालय के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर निरीक्षण कर उनकी कार्य प्रणाली, तकनीकी एवं उत्पादन क्षमता का अवलोकन किया जावेगा।
4. कृषकों को उच्च गुणवत्ता के सिंचाई संयंत्रों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ड्रिप संयंत्र/मिनि फव्वारा संयंत्रों के नमूने निर्माता के निर्माण स्थल से एवं कृषक खेतों पर संयंत्र स्थापना उपरान्त रेन्डम आधार पर लेकर गुणवत्ता की जाँच अधिकृत संस्थानों से करवायी जावे।
5. भारत सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश के पैरा 14.13 के अनुसार प्रत्येक आपूर्तिकर्ता कम्पनी का स्वयं का प्राइसिंग सिस्टम होगा जो कि पंजीकरण के समय और जब भी दरों में संशोधन हो, विभाग को सूचित किया जावेगा। जबकि अनुदान गणना हेतु भारत सरकार द्वारा कम्पोनेन्टवार/मॉडलवार इकाई लागत जारी की गई है। इकाई लागत या आपूर्तिकर्ता दर जो भी कम हो, उस पर अनुदान गणना की जाती है। अतः किसानों में इकाई लागत व बिल दर के आधार पर अनुदान देयता का संशय समय-समय पर होने वाले प्रशिक्षणों व अभियानों के माध्यम से किया जावे।

व. ऑन-लाइन क्रियान्वयन

सूक्ष्म सिंचाई योजना के तहत समस्त पत्रावलियां राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाईन प्राप्त की जावेगी तथा समस्त निस्तारण ऑनलाईन प्रक्रिया के माध्यम से सम्पन्न किया जावेगा। ऑनलाईन पत्रावलियों की विभाग द्वारा हार्ड कॉपी करना आवश्यक नहीं है। जिससे भविष्य में समस्त कार्य राजकिसान ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से एण्ड टू एण्ड डिजिटल इजेशन सर्विस के माध्यम से सम्पन्न किया जा सकें।

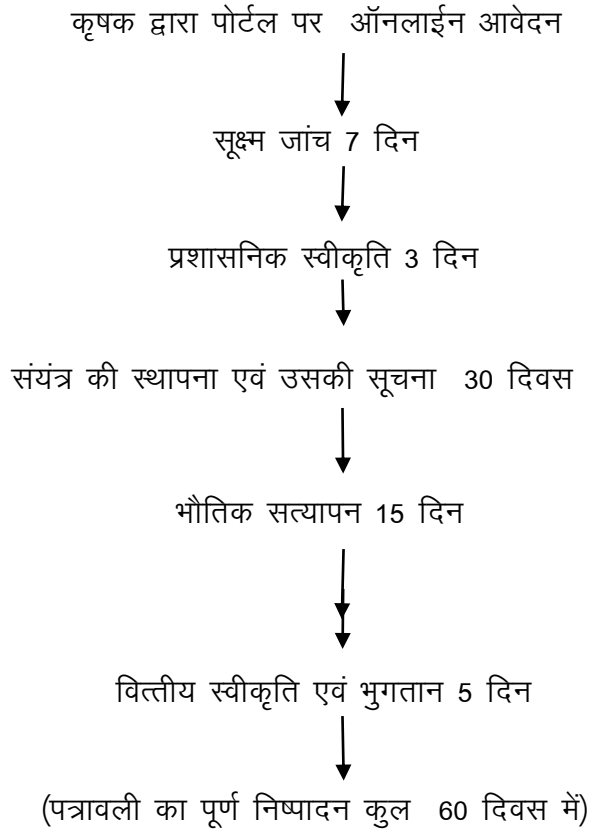
वर्ष के दौरान संयंत्रों की स्थापना हेतु कृषकों द्वारा ऑनलाईन आवेदन माह जनवरी तक ही स्वीकृत किये जावें ताकि वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक समस्त पत्रावलियों का निस्तारण किया जा सके। वित्तीय वर्ष के दौरान जनवरी के पश्चात प्राप्त ऑनलाईन आवेदन पत्रावलियों का निस्तारण उपलब्ध लक्ष्यों व बजट प्रावधान के मध्यनजर ही किया जा सकेगा। राजकिसान पोर्टल का पूर्ण विवरण पोर्टल पर उपलब्ध है तथा सुलभ संदर्भ हेतु संक्षिप्त विवरण संलग्नक 31 पर स्थित है।

राजकिसान साथी पोर्टल पर सभी हितधारकों की आवश्यकता व सुगमता के मध्यनजर समय-समय पर अपडेट किये जायेंगे।

प्रबोधन एवं मूल्यांकन (M&E)

1. राज्य स्तर व जिला स्तर पर मासिक समीक्षा बैठक आयोजित कर निरन्तर प्रगति समीक्षा की जावेगी।
2. आवश्यकतानुसार समय-समय पर योजना का मूल्यांकन व अध्ययन आवश्यकतानुसार कराया जायेगा।
3. अच्छे परिणामों के प्रकरणों की सफलता की कहानी जिला/राज्य स्तर पर तैयार की जावेगी।
4. खण्ड स्तरीय अधिकारी, उद्यान द्वारा समय-समय पर लाभार्थियों की सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र स्थापना उपरान्त उत्पादकता, गुणवत्ता एवं आर्थिक स्तर के बदलाव का सर्वेक्षण किया जावे। चिन्हित लाभार्थियों की सफलता की कहानी कम से कम 5 कृषक प्रति जिला आवश्यक रूप से मय फोटोग्राफ तथा सीडी के राज्य स्तर को भिजवाना सुनिश्चित करें, जिसमें सिंचाई प्रणाली के माध्यम से आर्थिक स्तर में आये बदलाव का पूर्ण विवरण अंकित हों।

कृषक द्वारा सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र हेतु पत्रावली के आवेदन से पत्रावली के निष्पादन की निर्धारित अवधि का फ्लो चार्ट:-



Annexure-1

सूक्ष्म सिंचाई योजना 2025-26 के दौरान सिंचाई संयंत्रों पर देय अनुदान

क्र.सं	सिंचाई संयंत्र का नाम	कृषक श्रेणी	कुल देय अनुदान प्रतिशत में	केन्द्रीयांश प्रतिशत में	राज्यांश प्रतिशत में	अति.राज्यांश प्रतिशत में
1	ड्रिप, मिनि स्प्रिंकलर एवं स्प्रिंकलर	लघु एवं सीमान्त कृषक	75	33	22	20
		SC/ ST/ Woman	75	33 / 27	22 / 18	20 / 30
		अन्य कृषक	70	27	18	25

सूक्ष्म सिंचाई में ऑटोमेशन हेतु समस्त श्रेणी के कृषको हेतु 75 प्रतिशत अनुदान देय है।

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना 2025-26 (सांकेतिक इकाई लागत)

अन्तराल (मी.)	मि.मी.	बूंद-बूंद (ड्रिप) सिंचाई संयंत्र स्थापन हेतु सांकेतिक इकाई लागत (As per PDMC-MI Operational Guidelines 2024) क्षेत्रफल (हैक्टेयर) वार संयंत्र की सांकेतिक इकाई लागत रुपये में						
	क्षेत्रफल	0.20	0.40	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Close Space Drip								
1.2x0.6 or lower spacing	16	31436	57241	127501	242422	366950	495055	619326
1.5x0.6	16	28003	50116	109531	207860	313909	425189	530905
1.8x0.6	16	24569	42992	91560	173298	260868	355323	442484
2.5x0.6	16	20201	35000	71733	131824	201464	279770	343433
1.5x1.5	16	28106	46995	97245	185324	276767	382246	470306
Wide Space Drip								
2.0x2.0	16	23932	41303	83085	161263	234280	325469	399494
2.5x2.5	16	19516	35393	68234	124216	189724	266274	325233
3.0x3.0	12	15792	26190	47751	82654	127306	160103	200455
4.0x4.0	12	14602	24326	41534	72799	113560	148684	176964
5.0x5.0	12	13144	23486	39378	67199	97110	123409	165815
6.0x6.0	12	12400	21693	34687	57987	93688	113618	142566
8.0x8.0	12	11330	19711	28777	47314	73272	92615	117529
9.0x9.0	12	11091	19114	27304	44469	68853	86606	110024
10x10	12	10854	18652	26181	42226	65487	82025	104292
12x12	12	10526	18009	24586	39098	60704	75521	96166
Mini Sprinkler								
8x8	32		47528	103873	187929	290935	380031	469890
10x10	32		45694	94134	176766	268422	345497	423236
Micro-Sprinkler								
3x3	16/20		38263	74259	133821	191078	263852	321462
5x5	16/20		32713	65102	114426	164937	222721	281557
फव्वारा मॉडल (है.)	मि.मी.		एल्युमिनियम व एचडीपीई दोनों के लिए					
			फव्वारा सिंचाई संयंत्र स्थापन हेतु सांकेतिक इकाई लागत (As per PDMC-MI Operational Guidelines 2024)					
			<0.4	>0.4 - 1.0	>1.0 - 2.0	>2.0-3.0	>3.0 - 4.0	>4.0 - 5.0
Sprinkler	50		10485	17133	24736	NA	NA	NA
	63		13211	21588	31167	NA	NA	NA
	75		NA	24194	34657	NA	NA	NA
	90		NA	0	0	46779	58995	66789
Rain-gun	63		NA	31684	NA	NA	NA	NA
	75		NA	38127	48370	NA	NA	NA
	90		NA	NA	NA	62767	72751	79894

सामान्य कृषकों हेतु अनुदान गणना

अन्तराल (मी.)	मि.मी.	बूंद-बूंद (ड्रिप) सिंचाई संयंत्र स्थापन हेतु अनुदान गणना 70 % (As per PDMC-MI Operational Guidelines 2024)						
		क्षेत्रफल (हैक्टेयर) वार संयंत्र पर अनुदान ईकाई लागत का 70 प्रतिशत						
	क्षेत्रफल	0.20	0.40	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Close Space Drip								
1.2x0.6 or lower spacing	16	22005	40069	89251	169695	256865	346539	433528
1.5x0.6	16	19602	35081	76672	145502	219736	297632	371634
1.8x0.6	16	17198	30094	64092	121309	182608	248726	309739
2.5x0.6	16	14141	24500	50213	92277	141025	195839	240403
1.5x1.5	16	19674	32897	68072	129727	193737	267572	329214
Wide Space Drip								
2.0x2.0	16	16752	28912	58160	112884	163996	227828	279646
2.5x2.5	16	13661	24775	47764	86951	132807	186392	227663
3.0x3.0	12	11054	18333	33426	57858	89114	112072	140319
4.0x4.0	12	10221	17028	29074	50959	79492	104079	123875
5.0x5.0	12	9201	16440	27565	47039	67977	86386	116071
6.0x6.0	12	8680	15185	24281	40591	65582	79533	99796
8.0x8.0	12	7931	13798	20144	33120	51290	64831	82270
9.0x9.0	12	7764	13380	19113	31128	48197	60624	77017
10x10	12	7598	13056	18327	29558	45841	57418	73004
12x12	12	7368	12606	17210	27369	42493	52865	67316
Mini Sprinkler								
8x8	32		33270	72711	131550	203655	266022	328923
10x10	32		31986	65894	123736	187895	241848	296265
Micro-Sprinkler								
3x3	16/20		26784	51981	93675	133755	184696	225023
5x5	16/20		22899	45571	80098	115456	155905	197090
फव्वारा मॉडल (है.)	मि.मी.		एल्युमिनियम व एचडीपीई दोनों के लिए					
			फव्वारा तथा रेनगन हेतु अनुदान 70 % (As per PDMC-MI Operational Guidelines 2024)					
				<0.4	>0.4 - 1.0	>1.0 - 2.0	>2.0-3.0	>3.0 - 4.0
Sprinkler	50		7340	11993	17315	—	—	—
	63		9248	15112	21817	—	—	—
	75		—	16936	24260	—	—	—
	90		—	—	—	32745	41297	46752
Rain-gun	63		—	22179	—	—	—	—
	75		—	26689	33859	—	—	—
	90		—	—	—	43937	50926	55926

लघु, सीमान्त, अजा.,अजजा. एवं महिला कृषकों हेतु अनुदान गणना

अन्तराल (मी.)	मि.मी.	बूंद-बूंद (ड्रिप) सिंचाई संयंत्र स्थापन हेतु अनुदान गणना 75 % (As per PDMC Operational Guidelines)						
		क्षेत्रफल (हैक्टेयर) वार संयंत्र पर अनुदान ईकाई लागत का 75 प्रतिशत						
	क्षेत्रफल	0.20	0.40	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00
Close Space Drip								
1.2x0.6 or lower spacing	16	23577	42931	95626	181817	275213	371291	464495
1.5x0.6	16	21002	37587	82148	155895	235432	318892	398179
1.8x0.6	16	18427	32244	68670	129974	195651	266492	331863
2.5x0.6	16	15151	26250	53800	98868	151098	209828	257575
1.5x1.5	16	21080	35246	72934	138993	207575	286685	352730
Wide Space Drip								
2.0x2.0	16	17949	30977	62314	120947	175710	244102	299621
2.5x2.5	16	14637	26545	51176	93162	142293	199706	243925
3.0x3.0	12	11844	19643	35813	61991	95480	120077	150341
4.0x4.0	12	10952	18245	31151	54599	85170	111513	132723
5.0x5.0	12	9858	17615	29534	50399	72833	92557	124361
6.0x6.0	12	9300	16270	26015	43490	70266	85214	106925
8.0x8.0	12	8498	14783	21583	35486	54954	69461	88147
9.0x9.0	12	8318	14336	20478	33352	51640	64955	82518
10x10	12	8141	13989	19636	31670	49115	61519	78219
12x12	12	7895	13507	18440	29324	45528	56641	72125
Mini Sprinkler								
8x8	32		35646	77905	140947	218201	285023	352418
10x10	32		34271	70601	132575	201317	259123	317427
Micro-Sprinkler								
3x3	16/20		28697	55694	100366	143309	197889	241097
10x10	32		24535	48827	85820	123703	167041	211168
फव्वारा मॉडल (है.)	मि.मी.		एल्युमिनियम व एचडीपीई दोनों के लिए					
			फव्वारा तथा रेनगन हेतु अनुदान 75 % (As per PDMC-MI Operational Guidelines 24)					
				<0.4	>0.4 - 1.0	>1.0 - 2.0	>2.0-3.0	>3.0 - 4.0
Sprinkler	50		7864	12850	18552	—	—	—
	63		9908	16191	23375	—	—	—
	75		—	18146	25993	—	—	—
	90		—	—	—	35084	44246	50092
Rain-gun	63		—	23763	—	—	—	—
	75		—	28595	36278	—	—	—
	90		—	—	—	47075	54563	59921

वैकल्पिक घटकों के सांकेतिक मूल्य				
क्र. सं.	वैकल्पिक घटक		आईएस सं.	लगभग मूल्य रु. में
1	बैकवॉश एसेंबली वाला सैंड फिल्टर			
	ए	10 घन मी. / घंटा x 1.5"	14606	9775
	बी	20 घन मी. / घंटा x 2"	14606	13225
	सी	25 घन मी. / घंटा x 2"	14606	16100
	डी	30 घन मी. / घंटा x 2.5"	14606	18400
2	हाइड्रोसाईक्लोन फिल्टर			
	ए	20 घन मी. / घंटा x 2"	14743	4025
	बी	25 घन मी. / घंटा x 2"	14743	4600
	सी	30 घन मी. / घंटा x 2.5"	14743	6325
3	एसेम्बली के साथ उर्वरक टैंक			
	ए	30 लीटर	उपलब्ध नहीं	3220
	बी	60 लीटर	उपलब्ध नहीं	5750
4	वाइन्डर			
	ड्रिप लाईन वाइन्डर			2000

**उद्यान विभाग से पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना 2025-26 के तहत
कृषक परिवार के मुखिया द्वारा अनुदान हेतु**

कृषक का
पासपोर्ट
साइज फोटो

आवेदन पत्र

1. लाभार्थी का नाम	2. पिता/पति का नाम
3. जाति	4. कृषक श्रेणी (लघु/सीमांत/अन्य) :
5. गांव	6. ब्लॉक/कस्बा
7. जिला	8. आवेदक के नाम भूमि (हैक्टेयर)
9. खसरा नम्बर जिसमें संयंत्र स्थापित किया जाना है (भू-राजस्व की प्रति संलग्न करें)	
10. पिछले निकटतम समय में कृषक ने या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा माइक्रो इरीगेशन के तहत भारत सरकार की किसी भी योजना से कोई अनुदान प्राप्त किया गया है अथवा नहीं?	
11. अगर हां तो विवरण दीजिये- सिंचाई के लिए प्रयुक्त प्रणाली :	
अ. क्षेत्र हैक्टेयर में	ब. फसलान्तर्गत क्षेत्र (हैक्टेयर) स. स्थापना वर्ष
12. फसल जो लगानी है	13. संयंत्र का प्रकार जिसकी आवश्यकता है {ड्रिप (in/online)/फव्वारा (HDPE/Allm.) 63/75/90 m.m.}
14. फसल जिसके लिए संयंत्र की आवश्यकता है	15. क्या संयंत्र प्लान्टेशन फसल के लिए मांगा गया है या अन्तराशस्य के लिए:-
16. अन्तराशस्य फसल का नाम	17. माइक्रो इरीगेशन के तहत कुल क्षेत्र
18. पानी के स्रोत	19. कुएं का प्रकार खुला अथवा नलकूप
20. जल का स्तर (माप मीटर में)	21. सिंचाई जल की गुणवत्ता की रिपोर्ट संलग्न करें
22. कुएं में प्रतिदिन उपयोग समय	
23. यदि सिंचाई नहर द्वारा की जा रही है तो क्या पानी के संग्रहण हेतु व्यवस्था उपलब्ध है? यदि हां तो पोण्ड का आकार (लम्बाई x चौड़ाई x उंचाई)	
24. अन्य कोई फार्म पोण्ड यदि हां तो आकार	
25. यदि पानी का स्रोत उपलब्ध नहीं है तो क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गयी ?	
26. विद्युत की उपलब्धता (घण्टों में)	
27. विद्युत उपलब्धता का समय	
28. पम्प की क्षमता (हॉर्स पावर में)	
29. डीजल इंजिन का हॉर्स पावर में यदि उपलब्ध है तो	
30. भूमि का आकार	31. भूमि की विश्लेषण रिपोर्ट संलग्न करें
32. भूमि की गहराई	33. भूमि में जल स्तर की गहराई
34. कृषक बीमा कराने का इच्छुक है या नहीं	
35. लाभार्थी/आपूर्तिकर्ता के बैंक अकाउंट विवरण	
खाताधारी का नाम	खाता नंबर
बैंक का नाम	आरटीजीएस – इसीएस कोड
बैंक दूरभाष नंबर	

आवेदक का नाम मय दूरभाष नंबर

आवेदक के हस्ताक्षर

ड्रिप/मिनि/माइक्रो फव्वारा संयंत्रों की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2022-23 में कृषक श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नि
 ग्राम पं. सं.तहसील जिला ...
के खेत पर मेरे द्वारा ड्रिप संयंत्र का भौतिक सत्यापन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम -
2. पदनाम -
3. भौतिक सत्यापन करने की दिनांक -
4. कम्पनी का ब्राण्ड व मैक -
5. मौके पर मेरे द्वारा संयंत्र के भौतिक सत्यापन के पश्चात् निम्न विवरण पाया गया:-

क्र. सं.	अवयव का नाम	मौके पर मौजूद अवयवों की मात्रा/संख्या	आई. एस. मार्क, सी. एम. एल. नम्बर व बैच नम्बर
1.	Screen Filter		
2.	Ventury & manifold		
3.	PVC pipe 90mm, class II; 4kg/cm ²		
4.	PVC pipe 75mm, class II; 4kg/cm ²		
5.	PVC pipe 63mm, class II; 4kg/cm ²		
6.	Plain lateral		
7.	Emmitting pipe / Lateral 32mm /16mm /12mm		
8.	Nozzle		
9.	Micro tube		
10.			
11.			

1. ड्रिप संयंत्र स्थापना का क्षेत्र जिसमें अनुदान दिया जाना है
2. कृषक द्वारा ड्रिप संयंत्र स्थापित करने का वर्ष माह (कृषक से पूछताछ कर भरा जावे)
3. अवयवों की मात्रा एवं ड्रिप संयंत्र स्थापित क्षेत्र के अनुसार कृषक को कितना अनुदान देय है
4. क्या कृषक द्वारा पूर्व में ड्रिप/फव्वारा संयंत्र पर अनुदान लिया गया है? हां नहीं
6. मौके पर बोयी गई फसलों का विवरण
7. संयंत्र को मौके पर चलाकर प्रायोगिक परीक्षण किया गया व संतोषजनक पाया गया।
8. अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु जो मौका निरीक्षण के दौरान देखा गया है.....

कृषक के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी

आपूर्तिकर्ता के हस्ताक्षर

भौतिक सत्यापन करने वाले
 अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
 मय नाम, पदनाम व दिनांक

फव्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट

प्रमाणित किया जाता है कि वर्ष 2022-23 में कृषक श्री/श्रीमतीपुत्र/पुत्री/पत्नि
..... ग्राम पं. सं.तहसील जिला ...
.....के खेत पर मेरे द्वारा फव्वारा संयंत्र का भौतिक सत्यापन किया गया जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. भौतिक सत्यापन करने वाले अधिकारी का नाम -
2. पदनाम -
3. भौतिक सत्यापन करने की दिनांक -
4. कम्पनी का ब्राण्ड व मैक -साईज 63/75/90 एम.एम.
5. मौके पर मेरे द्वारा संयंत्र के भौतिक सत्यापन के पश्चात् निम्न विवरण पाया गया:-

क्र. सं.	अवयव का नाम	मौके पर मौजूद अवयवों की मात्रा/संख्या	आई. एस. मार्क, सी. एम. एल. नम्बर व बैच नम्बर
1.	HDPE QCPE Pipe आई.एस. 14151 पार्ट- 2 (6 मीटर)		
4.	Sprinkler Nozzles (1.7 to 2.8 kg/cm ²) :IS 12232 part I Brass		
5.	कपलर के साथ फुट बटन एसेम्बली		
6.	जी.आई. राईजर पाईप 20 m.m. X 75 c.m.		
7.	कपलर के साथ बैंड		
8.	पम्प जोड़ने वाला कपलर		
9.	टी कपलर सहित		
10.	एण्ड प्लग		

1. फव्वारा संयंत्र स्थापना का क्षेत्र जिसमें अनुदान दिया जाना है
2. कृषक द्वारा फव्वारा संयंत्र स्थापित करने का वर्ष माह (कृषक से पूछताछ कर भरा जावे)
3. अवयवों की मात्रा एवं फव्वारा संयंत्र स्थापित क्षेत्र के अनुसार कृषक को कितना अनुदान देय है
4. क्या कृषक द्वारा पूर्व में ड्रिप/फव्वारा संयंत्र पर अनुदान लिया गया है? हां नहीं
5. यदि हां तो वर्ष कम्पनी का ब्रांड क्षेत्रफल
6. मौके पर बोयी गई फसलों का विवरण
7. संयंत्र को मौके पर चलाकर प्रायोगिक परीक्षण किया गया व संतोषजनक पाया गया।

अन्य कोई महत्वपूर्ण बिन्दु जो मौका निरीक्षण के दौरान देखा गया है.....

आपूर्तिकर्ता कम्पनी के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

भौतिक सत्यापन करने वाले
अधिकारी/कर्मचारी के हस्ताक्षर
मय नाम, पदनाम व दिनांक

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना देय अनुदान पर ड्रिप स्थापन हेतु अनुबंध

(100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल शपथ-पत्र पर)

प्रपत्र

(कृषक द्वारा वहन किया जावे)

त्रि-पार्टी अनुबंध

(ऋणी/अऋणी कृषक)

अनुबंध डीड का क्रियान्वयन आज दिनांक 202..., स्थान....., जिला....., को एच.डी.एस.....
.....(प्रतिनिधि श्री), कृषक श्री/श्रीमती....., गाँव.....तहसील.....जिला.....
..... राजस्थान एवं ड्रिप/मिनि फव्वारा संयंत्र निर्माता /अधिकृत विक्रेता मैसर्स(प्रतिनिधि श्री ..
.....), के बीच सम्पन्न किया गया जिसमें निम्न शर्तें संबंधित पार्टी द्वारा स्वीकार की जाती हैं।

1. कृषक अनुदान पर सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगाने का इच्छुक है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाये गये हैं। अनुदान राशि का भुगतान संयंत्र आपूर्तिकर्ता कम्पनी को करने के लिये कृषक सहमत है।
2. कृषक संयंत्र स्थापन हेतु आवश्यक खुदाई व सिविल निर्माण कार्य स्वयं के व्यय पर निश्चित समयावधि में पूर्ण करने हेतु सहमत हैं।
3. कृषक द्वारा सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र निर्माता कम्पनी के सामान रखने के लिए यथोचित स्थान उपलब्ध करायेगा।
4. कृषक अपने स्वयं के खर्च पर पम्पिंग शीट, संयंत्र के चलाने हेतु प्रोपर वोल्टेज का कनेक्शन अपने खर्च पर उपलब्ध करायेगा।
5. संयंत्र निर्माता द्वारा प्रफोर्म इनवॉइस प्रस्तुत करने व त्रिपक्षीय अनुबंध सम्पन्न होने के पश्चात कृषक /एच.डी.एस. द्वारा कृषक हिस्सा राशि का अग्रिम भुगतान किया जावेगा।
6. कृषक द्वारा ऐसी फिटिंग सामग्री, पार्ट जो कि गारन्टी के अधीन नहीं आते एचडीएस की अनुमोदित दर/ वास्तविक दर के अनुसार ऐसे अवयवों का भुगतान संयंत्र आपूर्तिकर्ता को जल्द से जल्द जैसे ही रख रखाव कार्य समाप्त हो बिल का भुगतान किया जावेगा।
7. एचडीएस द्वारा भौतिक सत्यापन एवं प्रायोगिक परीक्षण के दौरान कृषक अपनी संतुष्टि के लिये वहां उपस्थित रहेगा।
8. संयंत्र स्थापना के बाद कृषक द्वारा बकाया/देय राशी संयंत्र आपूर्तिकर्ता को चुकाई जावेगी।
9. सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र लगने के 7 वर्ष की अवधि तक कृषक द्वारा स्थल /डिजाइन में बदलाव (विभागीय अनुमति के बिना), संयंत्र हटाना या किसी को बेचान व खुरद-बुरद नहीं करेगा। ऐसा करने की स्थिति में वैधानिक कार्यवाही के साथ-साथ संबंधित कृषक से अनुदान राशि वसूल योग्य होगी।
10. संयंत्र निर्माता कम्पनी द्वारा कृषक की माँग पर खेत का तकनीकी सर्वेक्षण, मृदा-जल का परीक्षण तथा स्थापित किये जाने वाले संयंत्र की रूप-रेखा (डिजाइन) तैयार किया गया है। कृषक की आवश्यकता तथा रूप-रेखा (डिजाइन) के आधार पर निर्माता द्वारा लागत अनुमान तैयार किये गये हैं। इसके पश्चात् तकनीकी-आर्थिक प्रतिवेदन तैयार किया जाकर पात्र प्रकरण में संबंधित कृषक की सहमति प्राप्त की गई है। डिजाइन में किसी भी तरह की तकनीकी खामी (Over/Under design) के लिये आपूर्तिकर्ता जिम्मेदार होगा।
11. सूक्ष्म सिंचाई निर्माता कम्पनी अग्रिम राशि प्राप्त होने के 7 दिवस में माल की सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगी।
12. संयंत्र निर्माता कम्पनी द्वारा 30 दिन की समयावधि में ड्रिप स्थापना का कार्य पूर्ण करना होगा।
13. संयंत्र निर्माता कम्पनी एचडीएस को लिखित रूप में ड्रिप स्थापना की सूचना देगी जिससे कि एचडीएस/अधिकृत संस्था 7 दिवस में संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर सके।
14. संयंत्र निर्माता कम्पनी यह सुनिश्चित करेगी कि यथोचित दूरी पर नाली खुली रखी जावे ताकि भौतिक सत्यापन और प्रायोगिक परीक्षण एचडीएस/अधिकृत संस्था द्वारा की जा सके।
15. भौतिक सत्यापन एवं प्रयोगिक परीक्षण के उपरांत संयंत्र निर्माता कम्पनी संयंत्र को कृषक के सुपुर्द कर देगा उसके लिये कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्ति रसीद देनी होगी।
16. एचडीएस द्वारा अनुमोदित संयंत्र आपूर्तिकर्ता एक माह के भीतर संयंत्र नहीं लगाता है तो ऐसी स्थिति में कृषक के अन्य सप्लायर के चुनने की स्वतंत्रता होगी, विलम्ब की तिथि त्रिपक्षीय अनुबन्ध की तिथि से गिना जावेगा।
17. संयंत्र आपूर्तिकर्ता द्वारा, कृषक द्वारा जारी कार्यपूर्ण प्रमाण-पत्र, अनुदान दावा (क्लेम) प्रपत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ अंतिम भुगतान बिल प्रस्तुत किया जावेगा।
18. एचडीएस या संयंत्र निर्माता कृषक की त्रुटि से संयंत्र के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।

19. संयंत्र निर्माता द्वारा अनुबन्धित समयावधि में कोई बनावट संबंधी विकार या अन्य बनाते समय रही कमी में कलपुर्जों को बिना किसी शुल्क के बदलना होगा।

20. संयंत्र निर्माता कम्पनी को रिपेयर, बदलने हेतु 7 कार्य दिवस का समय देना होगा, यह शिकायत लिखित में किसान की ओर से एचडीएस को प्राप्त होगी। संयंत्र निर्माता कम्पनी द्वारा सामान बदलने का कार्य 7 दिवस में करना होगा ताकि सिंचाई पर कोई विपरीत असर नहीं पड़े।

21. संयंत्र निर्माता कम्पनी कृषक के संयंत्र लगाने का रेखांकन ले-आउट कार्य उपलब्ध करायेगा, जिसमें सिंचाई अवधि उर्वरक देने की अवधि तकनीकी व आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट (फसलवार) संयंत्र के रख रखाव संबंधी जानकारी का साहित्य भी उपलब्ध कराया जावेगा।

22. संयंत्र निर्माता कम्पनी फसल बुआई के समय से पूर्व तथा फसल कटाई से पूर्व सीजन में स्वयं उपस्थित होकर प्रशिक्षण आयोजन की व्यवस्था करेगा, वर्ष में कुल 4 प्रशिक्षण कार्य होंगे।

23. संयंत्र निर्माता कम्पनी द्वारा एच.डी.एस. प्रभारी अन्य विशेषज्ञ मुख्यालय से/तथा विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण कार्य हेतु बुलाये जावेंगे।

24. प्रशिक्षण अवधि के दौरान संयंत्र निर्माता कम्पनी निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन देगी।

I. नई फसल प्रजाति/संकर बीज, ऊतक संवर्धन द्वारा तैयार पौध, कलगी (ग्राफ्ट्स) इत्यादि, बूंद-बूंद सिंचाई अन्तर्गत पौधरोपण पर मार्गदर्शन।

II. बूंद-बूंद सिंचाई सिद्धान्त एवं जल प्रबंध, परियोजनान्तर्गत प्रस्तावित विभिन्न फसलों हेतु सिंचाई समय सारणी, कम गुणवत्ता के सिंचाई जल का प्रबन्ध एवं विभिन्न जल स्रोतों व सूखा प्रबन्ध।

III. उर्वरकीकरण विधियां, मिश्रित उर्वरकों का सही चयन, पोषक तत्वों का शोषण।

IV. बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्र रखरखाव-फिल्टर क्रिया, पलश क्रिया, बहाव मूल्यांकन, अम्लीकरण, क्लोरोनीकरण आदि।

V. व्यवसायिक सघन खेती के सुरक्षा उपाय, सावधानियां इत्यादि।

VI. कृषक के खेत पर विशेषज्ञों के भ्रमण आयोजित कराना, कृषि आदान निर्माता, बैंक ऋण प्रदाता, बीमा कम्पनियों व निरीक्षण संस्था के प्रतिनिधियों का समावेश करते हुये प्रशिक्षण आयोजित कराना।

25. एच डी एस/ जिला अधिकारी द्वारा पात्र प्रकरणों पर अविलम्ब प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावेगी।

26. विभाग / एच डी एस द्वारा संयंत्र स्थापन की सूचना प्राप्ति के सात दिवस में भौतिक सत्यापन सुनिश्चित किया जावेगा।

27. डी.एच.डी.एस. द्वारा पात्र प्रकरणों में निर्धारित समयावधि वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर अऋणी प्रकरणों में सम्बन्धित कृषक/अधिकृत विक्रेता या संयंत्र निर्माता कम्पनी को शेष रही अनुदान राशि का भुगतान कृषक सहमती आधार पर किया जावेगा। ऋणी प्रकरणों में एच.डी.एस./संबन्धित बैंक द्वारा शेष अनुदान/कृषक हिस्सा राशि का भुगतान किया जावेगा।

28. विभाग संयंत्र स्थापना के बाद कभी भी संयंत्र का भौतिक सत्यापन कर सकता है। संयंत्र नहीं पाये जाने पर/चालू नहीं रहने पर जाँच में कृषक की गलती पाई जाती है तो अनुदान की रिकवरी की जा सकती है।

29. संयंत्र निर्माता कम्पनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा बिल जारी किये जाने की स्थिति में कृषक की सहमति एवं निर्माता कम्पनी द्वारा बिल को प्रमाणित करने एवं अधिकृत विक्रेता को भुगतान की अभिशंषा एवं प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकृत विक्रेता को बिल का भुगतान किया जा सकेगा। यह प्रत्येक केस/प्रकरण में अलग अलग होगा।

30. संयंत्र स्थापना में पायी गयी किसी भी प्रकार की अनियमितता की स्थिति में संबंधित संयंत्र निर्माता कम्पनी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी

एच.डी.एस प्रतिनिधि

संयंत्र निर्माता कम्पनी/अधिकृत विक्रेता प्रतिनिधि

कृषक

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना अनुदान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति आदेश

कमांक:

दिनांक:

“पर ड्रॉप मोर क्रॉप”—सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका तथा कृषि/उद्यान आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 202...-2.... के दौरान इस योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना में निम्न कृषकों द्वारा प्रेषित दस्तावेजों के आधार पर ड्रिप/फव्वारा सिंचाई संयंत्र स्थापित करने की प्रशासनिक स्वीकृति निम्न शर्तों पर एतद् द्वारा प्रदान की जाती है:—1. विभागीय व योजना दिशानिर्देशों के अनुसार पात्र कृषकों को कार्य पूर्णता पर ही अनुदान देय होगा। 2. संयंत्र की स्थापना निर्धारित अवधि में करनी होगी। 3. विभाग द्वारा पंजीकृत निर्माता या उनके अधिकृत डीलर से संयंत्र क्रय कर स्थापना करने पर ही अनुदान देय होगा।

S. No.	Reg. No.	Reg. Date	Name of farmer & father/husband	Village	Panchayat at Samiti/B lock	Cast	Category	Gender	Crop	Subsidy amount received during past years	Area of MI System during past years	Name of Manufacturer	Brand	Name of Dealer	Subsidy transfer (To Whome)	Spacing/ Size	Area	Subsidy Amount	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			
8																			
9																			
10																			
Total																			

उप निदेशक उद्यान

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना अनुदान हेतु वित्तीय स्वीकृति आदेश

कमांक:

दिनांक:

“पर ड्रॉप मोर क्रॉप”—सूक्ष्म सिंचाई योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शिका तथा कृषि/उद्यान आयुक्तालय राजस्थान जयपुर द्वारा वर्ष 202...-2.... के दौरान इस योजना हेतु जारी दिशा-निर्देशों की पालना में निम्न कृषकों को ड्रिप/फव्वारा संयंत्र स्थापित करने, मौका निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रशासनिक स्वीकृति आदेश के आधार पर निम्नानुसार/फर्मस को उनके नाम के आगे अंकित अनुदान राशि जारी करने की वित्तीय स्वीकृति निम्नानुसार एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

S. No.	Reg. No.	Reg. Date	Name of farmer & father/ husband	Village	Cast	Spacing/Size	Area	Name of Manufacturer	Brand	Name of Dealer	Subsidy transfer (To Whome)	AS No.	AS Date	Bill Amount (Rs.)	Subsidy (Rs)				GST Amount (Rs.)	TDS Amount (CS, SS & Add. Topup)	Net Subsidy Amount	Remarks
															CSS	State Share	Addl Drip Subsidy	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1																						
2																						
3																						
4																						
5																						
6																						
7																						
8																						
9																						
10																						
Total																						

अक्षरे राशि रुपये.....

पर ड्रॉप मोर क्रॉप-सूक्ष्म सिंचाई योजना					
CA	SF	Total	GST Deduction	TDS Deduction	Pay Amount

State Top-up	TDS Deduction	Pay Amount

Subsidy Receiver Summary						
S No	Payee Name	Bank Branch Id	Acc No.	GSTIN No	Gross Amt	Net Amt

उपरोक्त राशि निम्नानुसार बजट मद से आहरित की जावेगी।

उपरोक्त राशि निम्नानुसार बजट मद से आहरित की जावेगी।

इस वित्तीय स्वीकृति में समस्त तथ्यों एवं अनुदान राशि की जांच मेरे द्वारा कर ली गयी है।

उप निदेशक उद्यान

TIN No.

Contact:

M/s

VAT INVOICE/ DELIVERY CHALLAN

No.
Name of the farmer **Sh.**
Village
Panchayat samiti
Tehsil
District
Tel./ Cell contact

Date
System
Crop
Area (ha)
Crop spacing
Lateral spacing
Brand

S. NO.	Particular of Items	CM/L No.	Size	Unit	Qty	Unit Cost (in Rs.)	Amount (In Rs.)
A	Head Control Unit						
	Screen/ Disc Filter						
	Hydrocyclone/Sand Filter .						
	Fertilizer Tank						
	Fertigation/ ventury Manifold						
	NRV						
	By Pass Assy						
	Throttle valve						
	Air Release Valve						
	Pressure Gauge						
SUB TOTAL							
B	Water Carrier System						
	PVC for Main (...kg/cm2)						
	PVC for Sub Main (...kg/cm2)						
	Control Valve						
	Flush Valve						
SUB TOTAL							
C	Water Distribution System						
	Plain Lateral ... kg/ cm2, Cl ...						
	Inlinhe Lateral Cl ...						
	Dripper/Emitter/ Nozzel						
	Fogger / Micro jet						
	Grommet						
	Take off / Start Connector						
	Nipple/ Joiner						
	End Cap						
	Mini valve/ lateral cock						
	Poly Joiner						
SUB TOTAL							
D	Others:Fittings & Accessories						
SUB TOTAL							
Gross Amount (A+B+C+D)							
VAT							
Round off							

Amount in words Rs.

Manufacturer's invoice no.

Date:-

Details of optional Item Sand Fillter / Hydrocyclone Fillter/ Fertilizer Tank

Signature of Farmer

Authorised Signatory

Authentication by representative of
Manufacturer
signature with date:-
Name:-
Seal:-

TIN No.

Contact:

M/s

VAT INVOICE/ DELIVERY CHALLAN

No.

Name of the farmer Sh.

Village

Panchayat samiti

Tehsil

District

Tel./ Cell contact

Date

System

Crop

Area (ha)

Size

Make

Brand

Sprinkler/ Raingun

50/63/ 75/ 90 mm

HDPE/ Alluminium

S. NO.	Particular of Items	CM/L No.	Size	Unit	Qty	Unit Cost (in Rs.)	Amount (In Rs.)
A	Water Carrier System						
	HDPE Pipes with Quick Coupled (Pipe of class 2; 3.2 kg / cm ² IS:17425 Part II 63mm diameter & 6m long)						
	HDPE Pipes with Quick Coupled (2.5 kg/cm ² IS:17425 Part II, 75mm diameter & 6m long)						
B	Water Distribution System						
	Sprinkler Nozzels (1.7 to 2.8 kg/ cm ²) IS 12232 Part I						
C	Others:Fittings & Accessories						
	Quick Coupled HDPE 75mm Foot batten Assembly						
	GI Riser Pipe 3/4" diameter x 75 cm long						
	Quick Coupled HDPE Bend with Coupler 90° (75mm)						
	Quick Coupled HDPE Pump Connecting Nipple 75mm						
	Quick Coupled HDPE End Plug 75mm						
	Quick Coupled HDPE Tee with Coupler 75mm						
Gross Amount (A+B+C)							
VAT if any							
Round off							

Amount in words Rs.

Authorised Signatory

ड्रिप/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापना के लिए जल और विद्युत की उपलब्धता के मूल्यांकन हेतु खेत स्तरीय प्रश्नावली		
क. सं.	आवेदक का नाम	
1		
2	आवासीय पता	
3	फार्म का पता/ स्थान (क. सं. का उल्लेख किया जाए)	
4	फार्म / प्लॉट का क्षेत्रफल (है.)	
5	ड्रिप/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के तहत सिंचाई के लिए प्रस्तावित कुल क्षेत्र	
6	फसल	प्लॉट 1 प्लॉट 2 प्लॉट 3 प्लॉट 4
	फसल के तहत कुल क्षेत्रफल (है.)	
	पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे के बीच अंतराल (मी.)	
	पौधों की कुल संख्या	
	मृदा की किस्म (स्पष्ट करें)	
7	लाभार्थी द्वारा किस जल स्रोत का प्रयोग करने का प्रस्ताव है	खुला कुआ
		ट्यूब वेल/ बोर वेल
		सतही प्रवाह
		अन्य (स्पष्ट करें)
		भंडारण टैंक
8	खुला कुआ	
ए.	जल तालिका की गहराई (मी. में)	
बी	दिनांक और मौसम जिसके दौरान मूल्यांकन/ सर्वेक्षण किया गया था।	
सी	ड्रा-टाउन मीटर में (कृपया अनुबंध देखें)	
डी	भू-तल से उपर निकास पाईप की उंचाई	
ई	जल उपलब्धता का मूल्यांकन (लीटर प्रति सैकण्ड में)	
एफ	स्रोत में जल उपलब्धता निर्धारित करने हेतु विधि	
जी	कुल अवधि जिसके दौरान पंप चलाया गया अथवा कुल खेत/ प्लॉट के लिए प्रभावी पंपिंग के घंटे	
एच	पंपिंग की अवधि जिसके बाद स्थिर जल स्तर प्राप्त हुआ (घंटे/ मिनट)	
आई	प्रयुक्त पंपिंग/ निर्माता का उल्लेख करें (बिजली/ डीजल)	
जे	प्रयुक्त पंप की हॉर्स पावर	
के	निकास पाईप का व्यास	
9	ट्यूब वेल/ बोर वेल	
ए.	जल तालिका की गहराई (मी. में)	
बी	दिनांक और मौसम जिसके दौरान मूल्यांकन/ सर्वेक्षण किया गया था।	
सी	ड्रा-टाउन मीटर में (कृपया अनुबंध देखें)	
डी	भू-तल से उपर निकास पाईप की उंचाई	
ई	जल उपलब्धता का मूल्यांकन (लीटर प्रति सैकण्ड में)	
एफ	जल उपलब्धता निर्धारित करने हेतु विधि (आयतनमापी/ समन्वय/ कोई अन्य)	
जी	कुल अवधि जिसके दौरान पंप चलाया गया	
एच	पंपिंग की अवधि जिसके बाद स्थिर जल स्तर प्राप्त हुआ	
आई	प्रयुक्त पंपिंग/ निर्माता का उल्लेख करें (बिजली/ डीजल)	
जे	प्रयुक्त पंप की हॉर्स पावर	
के	निकास पाईप का व्यास	
10	सतही प्रवाह/ पहाड़ी क्षेत्रों में धारा	
ए.	खराब (लीन) मौसम के दौरान जल-प्रवाह दर (लीटर/ सैकण्ड में)	
बी	जल-प्रवाह दर के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त विधि	
सी	क्या भंडारण टैंक उपलब्ध है	
डी	यदि हां., भंडारण टैंक की क्षमता	
ई	जल के भंडारण टैंक में मोड़ने के लिए प्रयुक्त ढांचा	

ड्रिप/ स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली स्थापना के लिए जल और विद्युत की उपलब्धता के मूल्यांकन हेतु खेत स्तरीय प्रश्नावली		
क. सं.	आवेदक का नाम	
11	नहर के पानी के प्रयोग से भंडारण टैंक	
ए.	नहर के वितरण स्रोत से लाभार्थी के खेत की दूरी	
बी	भंडारण टैंक बनाया गया है अथवा लाभार्थी द्वारा बनाए जाने का प्रस्ताव है	
सी	यदि हां., भंडारण टैंक की क्षमता ६	
डी	भूमि के स्तर से भंडारण टैंक की उंचाई	
ई	“बारी” प्रणाली के अनुसार नहर में पानी की उपलब्धता (सप्ताह/ पखवाड़ा/ माह की संख्या)	
एफ	नहर से भंडारण टैंक तक जल ले जाने हेतु लाभार्थी के पास उपलब्ध पंप (बिजली/ डीजल) (निर्माता का उल्लेख करें)	
जी	पम्प की हॉर्स पावर (एचपी)	
12	पम्प का ब्यौरा	
ए.	क्या लाभार्थी के पास पंप है	
बी	यदि हां., किस निर्माता का है ६ (कृपया स्पष्ट करें)	
सी	पंप की हॉर्स पावर (एचपी) कितनी है ६	
डी	बिजली पंप के मामले में प्रतिदिन घंटों की संख्या जिस दौरान सामान्यतः बिजली उपलब्ध होती है	
ई	डीजल पंप के मामले में, निकटतम डीजल स्टेशन का नाम बताएं	
एफ	क्या लाभार्थी का नया पंप खरीदने का प्रस्ताव है (यदि हां. निर्माता और एचपी बताएं)	
जी	लाभार्थी के पास अन्य फार्म मशीनरी (जैसे ट्रैक्टर, कृषक हल, रैसर आदि हां. निर्माता और एचपी बताएं)	
13	निकटवर्ती ड्रिप स्टेशन	
ए	इस गांव में कितनी ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाई गई है	
बी	इन सीपनाओं में लगभग कितना क्षेत्र है	
सी	मौजूदा ड्रिप सिंचाई प्रणाली में किस समस्या को सामना करना पड़ रहा है	
14	एजेंसी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जल और विद्युत उपलब्धता का विश्लेषण	
ए.	ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत लाभार्थी द्वारा कवर किए जाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र के लिए जल की कुल आवश्यकता (लीटर प्रति दिन/ पौधा पौधों की कुल संख्या अथवा लीटर प्रति है. में कुल जरूरत कुल क्षेत्रफल)	
बी	जल की कुल उपलब्धता	
सी	ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत लाए जाने के लिए सिफारिश किया गया क्षेत्रफल (है.)	
डी	उपलब्ध पंप की हॉर्स पावर (एचपी)	
ई	अपेक्षित पंप की हॉर्स पावर (एचपी)	
एफ	ड्रिप सिंचाई प्रणाली के तहत कवर किए जाने के लिए क्षेत्रफल संबंधी सिफारिशें (यदि आवश्यक हो, पम्पिंग क्षमता में बढ़ोतरी संबंधी सिफारिश भी दें)	
जी	सिफारिशें	

विभिन्न फसलों के लिए सुझाया गया प्रणाली चयन

फसल	प्रणाली
अनाज जैसे गेहूं, मक्का, बाजरा, ज्वार	स्प्रिंकलर
मूंगफली	स्प्रिंकलर/मिनी स्प्रिंकलर/ड्रिप
आलू	मिनी स्प्रिंकलर/ड्रिप/स्प्रिंकलर
केला	ड्रिप
गन्ना	ड्रिप
गन्ना पंक्तिबद्ध रूप में अंतः फसल के साथ	मिनी स्प्रिंकलर/ड्रिप
अन्य फसल के साथ उद्यान (आर्किड) फसलें	ड्रिप/मिनी स्प्रिंकलर
प्याज/लहसुन/धनियां और अन्य छोटी संतृप्त फसलें	मिनी स्प्रिंकलर
सब्जियां जैसे टमाटर, बैंगन, भिंडी आदि और करेले ज्यादा अंतराल जैसे खीरा और अंगूर	ड्रिप
कपास/अरहर/अरंड आदि	ड्रिप
नर्सरियां	माइको स्प्रिंकलर/मिनी स्प्रिंकलर
छोटे और सीमांत भूमि/किसान	स्प्रिंकलर/ड्रिप
पहाड़ी और जनजातीय क्षेत्र	ड्रिप
लवणीय जल और अधिक फास्फोरस वाला जल	ड्रिप

क्लोगिंग से संबंध में जल की गुणवत्ता का मापदंड

परम्परागत सिंचाई के लिए जल की गुणवत्ता के मापदंड ड्रिप के जरिये सिंचाई के मापदंडों से भिन्न है। पानी की विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता के क्लोगिंग खतरे नीचे दिए गए हैं:

सिंचाई जल में पानी की गुणवत्ता के आधार पर क्लोगिंग की सीमा

पानी की गुणवत्ता	क्लोगिंग का खतरा		
	अति अल्प	सामान्य	गंभीर
तैरते हुए ठोस पदार्थ (पीपीएम)	<50	50-100	>100
पीएच	<7.0	7.0-8.0	>8.0
टीडीएस (पीपीएम)	<500	500-2000	>2000
मैंगनीज (पीपीएम)	<0.1	0.1-1.5	>1.5
लौह (पीपीएम)	<0.1	0.1-1.5	>1.5
कैल्शियम और मैगनेशियम (पीपीएम)	<20	20-40	>40
हाइड्रोजन सल्फाइड (पीपीएम)	<0.5	0.5-2.0	>2.0
जीवाणुओं की सुख्या (सं./मिली)	<10000	10000-50000	>50000

**2 हैक्टेयर से अधिक न्यून अन्तराल ड्रिप संयंत्रों पर अनुदान प्राप्त करने हेतु विभिन्न स्तर से
शपथ पत्र / संस्तुती/ अनुमोदन
कृषक/ लाभार्थी शपथ पत्र**

मैं/हम शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ / करते हैं कि –

1. मुझे मेरे/हमें हमारे खेत पर वर्ष भर नियमित रूप से(फसल का उल्लेख करें) फसलें ड्रिप पर उत्पादन करने हेतु हैक्टेयर में ड्रिप संयंत्र की आवश्यकता है।
2. उक्त ड्रिप संयंत्र मेरे द्वारा नियमित रूप से फसल सिंचाई एवं फर्टिगेशन हेतु काम में लिया जावेगा।
3. मैं/हम भली भाँती जानता हूँ / जानते हैं कि कि सीमित जल संसाधन के इष्टतम उपयोग तथा कृषक की आमदनी में वृद्धि के मध्येजनर केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा ड्रिप संयंत्रों पर अनुदान दिया जाता है। स्थापित ड्रिप संयंत्र का नियमित रूप से उपयोग न होने की स्थिति में इस हेतु किया गया राजकीय व्यय निष्फल व्यय की श्रेणी में आयेगा। अतः संयंत्र के नियमित रूप से काम में न लेने की जानकारी अगर विभाग को मिलती है तो उक्त संयंत्र हेतु दिये गये अनुदान की वसूली हेतु विभाग स्वतंत्र होगा।

लाभार्थी/कृषक के हस्ताक्षर

आपूर्तिकर्ता निर्माता की तरफ से तकनीकी संस्तुती

प्रमाणित किया जाता है कि –

पर्याप्त है।

2. कृषक द्वारा प्रस्तुत फसल चक्र वर्ष पर्यन्त नियमित रूप से ड्रिप संचालन हेतु तकनीकी रूप से उपयुक्त है।
3. कृषक द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र सहमति योग्य है।

निर्माता एग्रोनोमिस्ट/कृषि अभियन्ता

विभागीय संस्तुती/अनुमोदन

प्रमाणित किया जाता है कि कृषक शपथ पत्र व निर्माता संस्तुती पर संतुष्टी तथा कृषक से उसके खेत में सम्पर्क करने व सन्तुष्टि के आधार पर कृषक द्वारा आवेदित क्षेत्रहैक्टेयर/आवेदित क्षेत्र की बजाय.....हैक्टेयर पर न्यून अन्तराल ड्रिप दिया जाना संस्तुतित है।

सहायक कृषि अधिकारी/कृषि अधिकारी/कृषि अनुसंधान अधिकारी

उक्त संस्तुती पर सहमति प्रदान की जाती है।

सदस्य सचिव, डीएचडीएस

है।

उप निदेशक, उद्यान/कृषि

Description		Unit	Details		
Crop			Crop-I	Crop-II	Crop-III
Net Irrigation Area	Ha.	-	-	-	-
Flow to Farm Spacing	Mtr.	-	-	-	-
Net to Farm Spacing	Mtr.	-	-	-	-
Flow Direction	-	-	-	-	-
Total No. of plants	No.	-	-	-	-
Type of Irrigation System	-	-	-	-	-
Emitter Type	-	-	-	-	-
Emitter per plot	No.	-	-	-	-
Emitter Discharge	LPH	-	-	-	-
Lateral Spacing	Mtr.	-	-	-	-
Emitter Spacing	Mtr.	-	-	-	-
No. of lateral per row	No.	-	-	-	-
Application Rate	mm/day	-	-	-	-
Daily Peak Water requirement	m ³ /day	-	-	-	-
Daily Peak Water requirement	Ltr/s/day/ha	-	-	-	-
Irrigation level	Days	-	-	-	-
Duration of one shift	Hr.	-	-	-	-
No. of Shifts	-	-	-	-	-
Maximum Daily Duration	Hr.	-	-	-	-
Electricity available per day	Hr.	-	-	-	-
Maximum Discharge variation	%	-	-	-	-
Existing Pump Flow (at G.L.)	m ³ /hr	-	-	-	-
Existing Pump	HP	-	-	-	-
Pump Head Required	Mtr.	-	-	-	-
Pump Flow required	m ³ /hr	-	-	-	-
Minimum Discharge per Shift	m ³ /hr	-	-	-	-
Water Source	-	-	-	-	-
Water Source Depth	m	-	-	-	-
Delivery Size of Pump	mm	-	-	-	-
Placement unit - Hydroponics/Bed a /Pouch/Dac /Bw.....	m ² /hr	-	-	-	-
Placement Unit - Fertigation /Injector /Fertigation tank/Fertigation Pumps.....(Sai)	Inches / Liters	-	-	-	-

NAME OF THE FIRM:		CUSTOMER	
ADDRESS:		VILLAGE :	
		PANCHAYAT :	
		DISTRICT :	
		STATE :	
		SYSTEM :	
		CROP :	
		EMITTER TYPE :	

DATE		SCALE	
00/00/0000		A4 1:1000	
DESIGN BY		NAME: XXXX	
QUALIFICATION:		XXXX	
APPROVED BY		AREA (Ha.)	
XXXX		1.00	

SCHEME OF OPERATION				
Slack No.	Valve No	Valve Area (Ha.)	Slack Area (m ² /hr)	Irrigation Time (Hrs)
1	V1	0.25	16.7	1.05
2	V2	0.25	16.7	1.05
3	V3	0.25	16.7	1.05
4	V4	0.25	16.7	1.05
TOTAL				4.20

All Main Pipe PVC/HDPEkg/cm ²	
All Submain Pipe PVC/HDPEkg/cm ²	

LEGEND	
WATER SOURCE	
PUMPING UNIT	
HYDRO UNIT	
CONTROL VALVE	
PUSH VALVE	
MAIN PIPE	
SUBMAIN PIPE	
PIPELINE	
AIR VALVE	
ELEVATION	

**PHYSICAL VERIFICATION REPORT OF MIS SYSTEM BY AUTHORIZED
ENGINEER / AGRONOMIST OF MANUFACTURER**

Date:

नाम कम्पनी नाम अधिकृत इंजिनियर/ एग्रोनोमिस्ट.....
 मो. नं. नाम कृषक पिता/ पति...
 ग्राम..... ग्राम पंचायत..... पं.सं.....
 तह..... विधानसभा क्षेत्र जिला राज. के खेत
 पर हमारी कम्पनी/ कम्पनी के अधिकृत डीलर द्वारा..... है. में फव्वारा/ मिनि/ ड्रिप
 संयंत्र स्पेशिंग में स्थापित किया है। दिनांक को मेरे द्वारा कृषक
 के खेत में स्थापित संयंत्र को चालू करके निरीक्षण किया गया। संयंत्र पूर्ण रूप से चालू पाया गया
 एवं सभी उपकरण सुचारु रूप से काम कर रहे थे। संयंत्र का भौतिक सत्यापन किया गया जो
 निम्नानुसार है—

(A)	GEOTAGGING	AS PER REGISTERED MAUFACTURER ENGINEER/ AGRONOMIST		VERIFICATION BY DEPARTMENT OFFICIAL / AUTHORIZED		REMARKS
		LATITUDE	LONGITUDE	LATITUDE	LONGITUDE	
1	WATER SOURCE					
2	HEAD UNIT					
3	FIELD NW CORNER -A					
	ANY OTHER CORNER - B					
	ANY OTHER CORNER - C					

**(B) VERIFICATION BY MANUFACTURER AUTHORIZED ENGINEER / AGRONOMIST PRIOR TO
SUBMISSION OF FILE FOR DEPARTMENT PHYSICAL VERIFICATION**

S. No.	NAME COMPONET	BRAND & Manufacturer	NOS. / LENGTH IN MTR.	YEAR OF MANUFAC TURE	BIS Number	CM/L Number	BATCH Number
1	Screen / Disc Filter (capacity.....CuM)						
2	Hydrocyclone/ Sand Filter (capacityCuM)						
3	Ventury/ Ferti. Tank/ Pump.....capacity						
4	PVC Pipe 75mm						
5	PVC Pipe 63mm						
6	Plain lateral 16mm / 32mm						
7	Emmitting pipe						
8	Control Valve						
9	Flush Valve						
10	Nozzle / Dripper						

Undertaking given by authorized Engg./ Agronomist this is certified that the-

- 1 Design made according to departmental guideline, pressure of irrigation water, water availability, field & soil type, topography etc
- 2 System installed according to design made by me.
- 3 Pressure of irrigation water in system and driper flow capacity checked by me.
- 4 All components used in system installation are according to registration list given by department as well as per ISI standard and registration of component list attached with file.
- 5 Head unit is safely protected by c.c foundation and complete drip line cut & installed in field according to design and bill submitted in department.

Enclosures- PV photo with system

FARMER Signature
NAME OF FARMER WITH FATHER/HUS.
ADRESS-
CONTACT NO OF FARMER-

ENGG/ AGRONOMIST SIGN.
NAME
QUALIFICATION
Contact Number
ANY OTHER

भौतिक सत्यापन हेतु चैक लिस्ट

क्र.सं.	विवरण दस्तावेज	पैज नम्बर
1	अनुदान दावा (क्लेम) प्रपत्र	
2	कम्पनी के अधिकृत अधिकारी/अभियंता द्वारा प्रमाणित संयंत्र बिल	
3	निर्धारित प्रपत्र में संयंत्र का डिजाईन मैप (ड्रिप)	
4	तकनीकी आर्थिक प्रतिवेदन प्रपत्र (ड्रिप)	
5	कृषक की हिस्सा राशि प्राप्ति रसीद	
6	कार्य पूर्ण प्रमाण-पत्र कृषक द्वारा।	
7	कार्य पूर्ण प्रमाण-पत्र डीलर/निर्माता द्वारा	
8	अनुदान भुगतान बाबत कृषक का सहमति-पत्र	
9	कम्पनी का वारण्टी पत्र	
10	डीलर का कम्पनी द्वारा ओथोराइजेशन प्रमाण-पत्र की प्रति	
11	त्रिपार्टी अनुबंध-पत्र (500/-)	
12	संयंत्र भौतिक सत्यापन रिपोर्ट कम्पनी के अधिकृत कर्मी द्वारा	
13	संयंत्र की कृषक एवं भौतिक सत्यापनकर्ता के साथ फोटो	
14	फार्म नं. -27 (2.0 है0 से अधिक)	
15	कृषक/डीलर/ निर्माता कम्पनी के राष्ट्रीयकृत बैंक का खाता नं0 मय IFSC Code का विवरण (कॉन्सिल चैक/पास बुक की फोटो प्रति)	
16		

F. No.17-38/2020-RFS-III
Government of India
Ministry of Agriculture and Farmers Welfare
Department of Agriculture and Farmers Welfare
(RFS Division)

Krishi Bhawan, New Delhi
Date: 28th May, 2024

The Principal Secretary/Agriculture Production Commissioner
(Agriculture/Horticulture)

Government of Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Manipur & Sikkim, Tripura, Andaman & Nicobar, Puducherry, Jammu & Kashmir and Ladakh.

Subject: Revised Operational Guidelines of Per Drop More Crop (PDMC) scheme regarding.

Sir/Madam,

I am directed to inform that the Operational Guidelines of Per Drop More Crop (PDMC) scheme have been revised for implementation of the scheme in effective manner. A copy of the revised Operational Guidelines of the scheme is herewith attached for implementation from the date of issue of this letter.

This issue with the approval of Competent Authority.

Encl: As above

Yours faithfully,



(Asha Sota)
Director (RFS)

Copy to:

Director (Agriculture/Horticulture)

Government of Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Goa, Gujarat, Haryana, Himachal Pradesh, Jharkhand, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Odisha, Punjab, Rajasthan, Tamil Nadu, Telangana, Uttarakhand, Uttar Pradesh, West Bengal, Arunachal Pradesh, Assam, Mizoram, Meghalaya, Nagaland, Manipur & Sikkim, Tripura, Andaman & Nicobar, Puducherry, Jammu & Kashmir and Ladakh.

Operational Guidelines of Per Drop More Crop



2024

**Government of India
Ministry of Agriculture & Farmers Welfare
Department of Agriculture & Farmers Welfare**

Contents

Sl. No	Particulars	Page No.
	Salient Features of the Scheme	1
1	Introduction	3
2	Per Drop More Crop	3
3	Scheme Architecture	3
4	Nodal Department	4
5	District and State Irrigation Plans (DIPs & SIPs)	4
6	Objectives of Per Drop More Crop	4
7	Scheme Strategies	5
8	Operational Aspects	14
9	Drip Irrigation System for states where it has been well accepted by farmers and good infrastructure is available	16
10	Drip Irrigation System in states with low penetration	18
11	Drip Irrigation System for North Eastern and Himalayan States	19
12	Sprinkler Irrigation	21
	Portable Sprinkler Irrigation System	21
	Micro Sprinklers (up to 3 m radius of throw)	22
	Mini Sprinklers (more than 3 m up-to 10 m radius of throw)	22
	Semi-Permanent Sprinkler Irrigation System	23
	Large Volume Sprinkler Irrigation System (Raingun)	23
13	Optional Components	24
14	Key Administrative requirements	25
15	Registration of manufacturing companies	28
16	After sales services & campaigns	29
17	Violations & Penalties	31
18	Quality Control	32
19	Human Resource Development and Media	33
20	Pattern of Assistance & funding pattern	34
21	Monitoring and Evaluation	35
22	Release of Funds	36
23	Administrative Expenses and Contingencies	37

Annexures

Annexure I	Recommended norms for use of treated sewage quality for specific activities at point of use
Annexure II	Format for Annual Action Plan– Per Drop More Crop (PDMC)
Annexure III a	Format for Physical Progress Monitoring Report for Per Drop More Crop (Micro Irrigation)
Annexure III b	Format for Financial Progress Monitoring Report for Per Drop More Crop (Micro Irrigation)
Annexure IV a	Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 0.2 ha
Annexure IV b	Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 0.4 ha
Annexure IV c	Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 1.0 ha
Annexure IV d	Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 2.0 ha
Annexure IV e	Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 3.0 ha
Annexure IV f	Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 4.0 ha
Annexure IV g	Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 5.0 ha
Annexure IV h	NEH States -Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 0.2 ha
Annexure IV i	NEH States -Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 0.4 ha
Annexure IV j	NEH States -Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 1.0 ha
Annexure IV k	NEH States -Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 2.0 ha
Annexure IV l	NEH States -Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 3.0 ha
Annexure IV m	NEH States -Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 4.0 ha
Annexure IV n	NEH States -Drip Irrigation Technology-Indicative Bill of Quantities 5.0 ha
Annexure V	Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Portable Sprinkler Irrigation System
Annexure VI	Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Micro Sprinkler Irrigation System
Annexure VII	Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Mini Sprinkler Irrigation System
Annexure VIII	Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Semi Permanent Sprinkler Irrigation System
Annexure IX	Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Rain-gun Sprinkler Irrigation System
Annexure X	Water Quality Criteria In Relation To Clogging
Annexure XI	Guidelines for Selection of Filter
Annexure XII	Indicative Price of Optional Components
Annexure XIII	Other Interventions to be provided as optional, if and only if a farmer opted to install micro-irrigation System in his/her field
Annexure XIV	Gazette Notification
Annexure XV	List of BIS Standards

Abbreviations	
AC&FW	Agriculture Cooperation & Farmers Welfare
AIBP	Accelerated Irrigation Benefit Programme
ATMA	Agriculture Technology Management Agency
BIS	Bureau of Indian Standards
CIPET	Central Institute of Plastics Engineering and Technology
CST	Central Sales Tax
DAC&FW	Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare
DBT	Direct Benefit Transfer
DIP	District Irrigation Plan
DLIC	District Level Implementation Committee
DoLR	Department of Land Resources
DONER	Development of North Eastern Region
DPR	Detailed Project Report
DRDA	District Rural Development Agency
GoI	Government of India
HDPE	High Density Polyethylene
HP	Horse Power
HRD	Human Resource Development
ICAR	Indian Council of Agricultural Research
ICT	Information Communication Technology
IDWG	Inter Departmental Working Group
IMD	Indian Meteorological Department
IPPE	Intensive Participatory Planning Exercise
ISRO	Indian Space Research Organisation
IWMP	Integrated Watershed Management Programme
KVK	Krishi Vigyan Kendra
MGNREGA	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
Mha	Million Hectare
MI	Micro Irrigation
MIS	Micro Irrigation System/Management Information System
MLALAD	Member of Legislative Assembly Local Area Development
MoA	Ministry of Agriculture
MoRD	Ministry of Rural Development
MoJS	Ministry of Jal Shakti
MPLAD	Member of Parliament Local Area Development
NABARD	National Bank for Agriculture & Rural Development
NABCONS	NABARD Consultancy Services
NCPAH	National Committee on Precision Agriculture and Horticulture
NEC	National Executive Committee
NEH	North Eastern & Himalayan States
NGO	Non-Governmental Organisation
NRAA	National Rain-fed Area Authority
NRM	Natural Resource Management
NSC	National Stewardship Council

PFDCs	Precision Farming Development Centres
PMKSY	Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana
PRI	Panchayati Raj Institutions
PVC	Poly Vinyl Chloride
RIDF	Rural Infrastructure Development Fund
RKVY	Rashtriya Krishi Vikas Yojana
SAC	Space Application Centre
SAGY	Sansad Adarsh Gram Yojana
SAU	State Agricultural university
SC	Schedule Caste
SCP	Special Component Plan
SIP	State Irrigation Plan
SLNA	State Level Nodal Agency
SLSC	State Level Sanctioning Committee
S&MF	Small & Marginal Farmers
ST	Schedule Tribe
GSTIN	Goods & Service Tax Identification Number
TSP	Tribal Sub – Plan
UC	Utilization Certificate

Salient Features of the Scheme

- i. Per Drop More Crop (PDMC) is a Centrally Sponsored Scheme implemented by the Department of Agriculture and Farmers Welfare (DA&FW) from the year 2015-16 to promote micro irrigation in the Country to benefit the farmer community. As a part of the restructuring/rationalization of the schemes of DA&FW, PDMC Scheme is being implemented under Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) from the year 2022-23.
- ii. At the State level, PDMC has a three-tier structure with State Level Sanctioning Committee (SLSC) of RKVY under the Chairmanship of Chief Secretary, Inter-departmental Working Group (IDWG) under the Chairmanship of Secretary, Deptt. of Agriculture/Agriculture Production Commissioner (APC)/Development Commissioner; and District Level Implementation Committee (DLIC) under the Chairmanship of District Collector/Magistrate.
- iii. District Irrigation Plans (DIP) is the cornerstone for planning and implementation of PDMC which identifies gaps in irrigation chain after taking into consideration currently available resources and resources that would be added from ongoing schemes, both State and Central.
- iv. The Annual Action plans is to be drawn from District Irrigation Plans
- v. State irrigation plan focuses on cluster based approach and integrated development of different components in the irrigation chain.
- vi. The scheme is to be implemented through the mechanism of Direct Benefit Transfer (DBT). Aadhaar details of the beneficiary are required to avail the benefit of the programme. Aadhaar details need to be linked through a web based registration process. States/UTs should ensure disbursement of subsidy in a time bound manner.
- vii. The scheme will be monitored through web-portal of PDMC. Physical and Financial progress achieved during the preceding month is required to be uploaded by states on the web-portal of PDMC.
- viii. More focus be given on promotion of micro irrigation in rainfed areas and also for water intensive/guzzling crops to minimize water requirement.
- ix. The pattern of assistance payable to the beneficiary under the micro irrigation scheme will be 55% for small and marginal farmers and 45% for other farmers which will be met by both Central Government and State Government in the ratio of 60:40 for all states except the North Eastern and Himalayan States. In the case of these states, ratio of sharing is 90:10. For the Union Territories, funding pattern is 100% grant by the Central Government.

- x. The subsidy payable to the beneficiary will be limited to an overall ceiling of 5 hectare per beneficiary. Those beneficiaries, who have already availed subsidy benefits for his /her farm, would be eligible for subsidy again for the same land only after the end of projected life of the micro irrigation system which is 7 years.
- xi. The subsidy payment will be limited to the unit costs specified in the Operational Guidelines of the scheme. 25% higher amounts will be taken into calculation of subsidy for the North Eastern, Himalayan States and UTs of JK & Ladakh and 15% higher for States with low penetration of Micro Irrigation.
- xii. Only BIS marked systems/components can be supplied under the scheme.
- xiii. The registration of manufacturers/companies under the scheme will be for a period of 5 years. The registration will be open round the year. The registration will, however, be subject to satisfactory performance by the company. In case of violations, penalty provisions have been specified in the guidelines. Repeated failures will lead to de-registration of the company with the approval of SLSC.
- xiv. The company will provide free service after sales to the beneficiary for a period of at least three years from the date of installation of the system. If it fails to provide free after sales service, action as appropriate similar to other consumer products may be initiated.
- xv. In case the company intends to supply imported components, it shall be eligible for subsidy under the scheme subject to indigenization of manufacturing of the component within the country in a period of two years.
- xvi. Human resource development is an important component of the scheme and suitable provisions have been made in the guidelines for creating awareness, organizing training programs, Skill development and exposure visits etc.
- xvii. The general framework of the Guidelines of the RKVY shall also be applicable for PDMC.

1. Introduction:

Water is becoming scarce commodity these days due to competitive demand and also due to the change in climatic behaviour, particularly the erratic nature of rainfall. More than 80% of the available water resource in the country is used in Agricultural sector for the purpose of irrigation. The country has been able to cover just 50% of the net sown area under irrigation. Hence, promoting efficient use of the available water through technological interventions is one of the priorities in agriculture. Micro irrigation is one such initiative for enhancing water use efficiency in Agriculture Sector. The Government of India has been implementing Centrally Sponsored Scheme on Micro Irrigation with the objective to

enhance water use efficiency in the agriculture sector by promoting appropriate technological interventions like drip & sprinkler irrigation technologies and encourage the farmers to use water saving and conservation technologies. The Ministry is making efforts to bring two million ha area under micro irrigation per year.

2. Per Drop More Crop:

Per Drop More Crop (PDMC) focuses on enhancing water use efficiency at farm level through Micro Irrigation viz. Drip and Sprinkler irrigation systems.

3. Scheme Architecture

Per Drop More Crop will adopt the following institutional set up and architecture of overall RKVY framework as given in the General Guidelines of RKVY.

3.1 National Stewardship Council(NSC): National Stewardship Council(NSC)under the Chairmanship of Secretary (DA&FW) with the following members will be constituted to provide strategic direction for guidance and planning for effective implementation of the scheme;

- i. Secretary, Department of Agriculture &Farmers Welfare: Chairman
- ii. Additional Secretary & Financial Advisor: Member
- iii. Additional Secretary, DA&FW: Member
- iv. Representative from Ministry of Water Resources: Member
- v. Representative from Ministry Rural Development: Member
- vi. Representative from Department of Agricultural Research & Education: Member
- vii. Representative from Department of Land Resources: Member
- viii. Joint Secretary (INM): Member
- ix. Joint Secretary (Crops): Member
- x. Joint Secretary(RKVY): Member
- xi. Technical Expert of National Rainfed Area Authority (NRAA): Member
- xii. Director, Water TechnologyCenter (WTC), ICAR: Member
- xiii. Joint Secretary (NRM & RFS):Member Secretary

Representative from three State Implementing Departments/Agencies; One representative from Precision Farming Development Centres (PFDC); One Micro Irrigation System Manufacturer/Industry; President/Representative of the Irrigation Association of India(IAI) and representative from two FPOs/farmers' cooperatives may be invited as special invitees.

3.2 At the State level, an Inter Departmental Working Group (IDWG) under the Chairmanship of Agriculture Production Commissioner/ Development Commissioner with Secretaries of line departments as members to be constituted to coordinate at the State level, the planning and implementation of the scheme. States may take

the advice/input of MI manufacturers by inviting representative from manufacturers/Micro Irrigation Industries /Irrigation Association of India (IAI) as special invitee in such Committees.

- 3.3 District Level Implementation Committee (DLIC) under the Chairmanship of Collector/District Magistrate/CEO of Zila Parishad/ PD DRDA, Joint Director/Deputy Director of line departments in the district and progressive farmers, representative of MI industry, and leading NGO as members to oversee implementation of the scheme and inter-departmental coordination

4. Nodal Department

PDMC focuses on enhancing water use efficiency at farm level and thereby enhancing agricultural production & productivity. Therefore, State Agriculture/Horticulture Department may be the Nodal Department for implementation of Per Drop More Crop scheme. However, States are free to identify the nodal Department based on the established institutional set up and mandate of the Department. All communication between Department of Agriculture & Farmers Welfare, GoI and State Government would be preferably with and through the Nodal Department.

5. District and State Irrigation Plans (DIPs & SIPs)

- 5.1 District Irrigation Plans (DIPs) are the cornerstone for planning and implementation of different schemes related to irrigation which will identify gaps in irrigation infrastructure after taking into consideration the District Agriculture Plans (DAPs) vis-à-vis irrigation infrastructure currently available and resources that would be added from ongoing schemes, both State and Central.
- 5.2 DIPs present holistic irrigation development perspective of the district outlining medium to long term development plans integrating three components viz. water sources, distribution network and water use applications.
- 5.3 The annual action plans for Per Drop More Crop will be drawn from DIPs and implemented in conjunction with the water sources created under convergence with other State/Central schemes.

6. Objectives of Per Drop More Crop

The main objectives of Per Drop More Crop are as under:

- 6.1 Increase the area under Micro Irrigation technologies in agriculture to enhance water use efficiency.
- 6.2 Increase productivity of crops and income of farmers through precision water management.
- 6.3 Promote micro irrigation technologies in water intensive/consuming crops like sugarcane, banana, cotton, paddy etc. and give adequate focus to extend coverage of field crops under micro irrigation technologies.

- 6.4 Make potential use of micro irrigation systems for promoting fertigation.
- 6.5 Promote micro irrigation technologies in water scarce, water stressed and critical ground water blocks/districts
- 6.6 Link tube-well/river-lift irrigation projects with micro irrigation technologies for best use of energy both for lifting and pressurized irrigation as far as possible.
- 6.7 Establish convergence and synergy with activities of on-going programmes and schemes, particularly with created water source for its potential use, integration of solar energy for pressurised irrigation etc.
- 6.8 Promote, develop and disseminate micro irrigation technology for agriculture and horticulture development with modern scientific knowledge.
- 6.9 Support the initiatives of reuse of waste water in Agriculture/peri-urban Horticulture through micro irrigation systems.
- 6.10 Create employment opportunities for skilled and unskilled persons, especially unemployed youth for installation and maintenance of micro irrigation systems.

7. Scheme Strategies

- 7.1 Priority should be given for promoting micro irrigation technologies in rainfed areas. More focus should be given to water scarce, water stressed and critical ground water blocks/districts to conserve water and get extended coverage in terms of area and time period for life saving irrigation.
- 7.2 It is desirable to make potential use of the available water for sustained growth in agriculture sector. Preference should be given to adopt Micro Irrigation technology in water guzzling crops like sugarcane, cotton, banana etc. and the state implementing agencies should take suitable steps like publicity campaigns, policy provisions & sharing responsibilities with the Micro Irrigation industry so that adoption of technology is initiated in such crops. Industry related to the specific crops like sugar factories should be actively involved in promotion of micro irrigation to their farmers through incentivisation and technical supervision. Apart from horticulture and water guzzling crops, cereals and pulses may also be brought under the ambit of Micro irrigation.
- 7.3 In all the new irrigation commands where hydraulic heads are available, drip irrigation systems need to be encouraged as it can be operated without additional energy support.
- 7.4 Facilities of micro irrigation is under utilized if it is not used for fertigation. States should encourage the use of liquid fertilizers using micro irrigation systems. Availability of liquid fertilisers, awareness among farmers on the benefits of fertigation need to be given desired attention for promoting fertigation.
- 7.5 Efforts may be made for integration of micro irrigation with solar pumping units. A solar water pump has a mini power house at its heart and consists of a calibrated and matching solar array of modules – tuned with the equivalent power of pump

for that particular application. The solar water pumping system is capable of running all types of electrical water pumps with applications varying from irrigation to household demands. Irrigation pumps such as submersible, surface or deep well can also be coupled with drip irrigation systems to enhance the returns from this configuration. A 2000 Watt Peak (WP) solar water pump is capable of drawing and pumping approximately 80,000 litres of water per day from a source that is up to 10 meters deep. This is sufficient to irrigate about 1 ha of land with regular crops.

- 7.6 The available water sources or the new sources those are being created need to be used in best possible manner to fulfil the vision of “Har Khet Ko Pani” through efficient water conservation (Jal Sanchaya) and water management (Jal Sinchan) practices. It is, in this context, more vital to link most of the water sources with micro irrigation to get extended coverage for a longer duration.
- 7.7 PDMC focuses on micro irrigation for enhancing water use efficiency. States may take up sources creation activities as Other Interventions (OI) under the scheme and must be linked with Micro Irrigation to make potential use of the available funds for higher water use efficiency. These activities should be based on actual requirement and as per the needs of the farmer who adopts the Micro irrigation system.
- 7.8 The amount for OI activities must be restricted to 20% of the total allocation for States/UTs and 40% for North East States, Himalayan States & UTs of Jammu Kashmir and Ladakh.
- 7.9 Assistance for installation of micro irrigation system is limited to five hectares per beneficiary. The land holding of a beneficiary to be covered under drip/sprinkler system could be located in one contiguous area or at different locations, but the financial assistance will be limited to the overall ceiling of five ha.
- 7.10 Those beneficiaries, who have already availed subsidy benefits for his /her farm, can not avail the assistance for the next seven years. A beneficiary if availed the benefit of subsidy for micro irrigation for a particular farm would be eligible for subsidy again for the same land only after the end of projected life of the micro irrigation system which is seven years. However, the beneficiary may be allowed to avail effective differential subsidy in case he intends to install Drip Irrigation System on the same plot/field from the existing Sprinkler Irrigation System at least after three years to promote crop diversification irrespective of seven years subsidy cycle.
- 7.11 The unit cost/BoQs of the MI systems given in the Guidelines are indicative. The beneficiary will be allowed to opt to make his choice for items/components etc. In case any deviation from the BoQ, the differential cost shall be borne by the beneficiary subject to ceiling of unit cost.

- 7.12 Sometimes beneficiaries may not be able to contribute the requisite amount to adopt micro irrigation technologies. States/UTs may involve financial institutions like NBFC/Bank/NABARD to fill the upfront credit gap faced by the farmers for micro-irrigation adoption. States may facilitate credit facility to farmers (such as enabling subsidy component as State guarantee).
- 7.13 In view of the continuous modernization of agriculture resulting into evolving ways to improve productivity and sustainability, crops spacings keeps on changing. Financial assistance for installation of Micro irrigation systems will be based the indicative cost of MI systems for different spacings and plot sizes provided in the guidelines. In case of crops with plant spacing other than those mentioned in the Guidelines, the amount of assistance could be calculated on pro rata/average basis of the nearest plant area.
- 7.14 Beneficiaries/Institutions that have opted for contract farming or taken land on lease are also eligible for obtaining financial assistance under the scheme. However, to become eligible, the beneficiary/institution shall have to produce lease agreement for a minimum period of 7 years from the date of approval of application by the MI implementing agency.
- 7.15 ICAR, PFDCs, CIPET, ATMA etc may be involved in planning, implementation, demonstration, training and evaluation under the scheme. The implementing agency at the district level will ensure convergence of activities under the programme with the activities of various departments on water management to get the desired output.
- 7.16 Raw material price of polymers & other costs varies a lot because of fluctuation in national/international prices. Accordingly, periodic review of pricing may be carried out by the DA&FW, GoI.
- 7.17 States must include all Aspirational Districts identified by NITI Aayog in their Annual Action Plan (AAP) for coverage of Micro Irrigation under the Scheme in these Districts. Further, priority may be given to Namami Gange Districts/Gram Panchayats (GPs) along the stretch of river Ganga basin to be included in AAP for Micro Irrigation coverage.
- 7.18 Climate Change is known to have adverse impact on agriculture. Irrigation has been an effective tool in addressing climatic aberrations like drought, heat wave causing that is responsible for enormous loss to agriculture. States/UTs must ensure coverage of MI in dark zones and climatically vulnerable areas. The MI coverage should also be given priority to the areas under NICRA program of ICAR-CRIDA to promote climate resilient technologies.
- 7.19 Micro Irrigation is an important component of various Centrally Sponsored Schemes, such as, National Mission of Edible Oils – Oilseeds (NMEO-OS), MIDH, NFSM, NMEO-OP. States/UTs should ensure that installation of Micro Irrigations

systems under these schemes be dovetailed with PDMC. The Annual Action Plan must be prepared accordingly and progress of Micro Irrigation activity to be reported under the PDMC scheme.

- 7.20 States may encourage Automation in the Micro Irrigation Systems for ease of operation with minimal or no manual intervention thereby achieving greater efficient use of Micro Irrigation Systems by the beneficiaries. The Automation unit may be linked with solar energy wherever possible at the farm. It is desirable that States should target 5% of Micro Irrigation coverage under the scheme with Automation. The cost of automation may vary with the type of Automation adopted by the beneficiary. For adoption of Automation in the Micro Irrigation system under the scheme, the financial assistance to the beneficiary will be restricted on the existing rate of subsidy to the indicative cost of Rs. 40000/ha.
- 7.21 Preference for installation of micro irrigation will be given to farmers adopting crop diversification to enhance the production and their income substantially.
- 7.22 The Guidelines for implementation of Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha evam Utthan Mahabhiyan (PM KUSUM) Scheme, Ministry of New and Renewable Energy gives preference to farmers using Micro irrigation systems. Accordingly, PDMC be converged with PM-KUSUM for promoting use of solar energy with MI systems. States/UTs to ensure that all solar pump beneficiaries under PM-KUSUM adopt micro irrigation system.
- 7.23 The Atal Bhujal Yojana (ABY) focuses on sustainable management of ground water through participatory approach. The PDMC Scheme may be converged with ABY to achieve the objectives of the schemes.
- 7.24 The Guidelines for New Generation Watershed Development Projects (WDC-PMKSY 2.0) envisage convergence of watershed projects with PDMC. Accordingly, priority may be given to areas under WDC-PMKSY 2.0 to integrate activities, particularly, creation of water sources with that of micro irrigation. Similarly, water sources created under MGNREGS may be integrated with micro irrigation for their potential use.
- 7.25 Department of Water Resources, River Development & GR is implementing Command Area Development & Water Management (CADWM) program. CADWM envisages the modernization of Irrigation Command Area i.e. providing Pressurized Piped Irrigation Command (PPIC) for use of Surface Water combined with other sources of water which provides network of established water source to farm gate for farmer to adopt micro irrigation in the farm to improve the Water use Efficiency at farm level. The States/UTs must ensure that the source/infrastructure created under the scheme shall be utilized for Micro Irrigation in coordination with WRD/CAD agencies. CADWM program shall be dovetailed with PDMC and it shall be ensured that Water user Societies covered under modernized CADWM program should be necessarily part of PDMC for adoption of MI systems. Such convergence

shall make it possible to aggregate large areas under micro irrigation which enable better implementation, cost effective, maintenance & services and better market linkage of produce.

7.26 Soil Health Card scheme was launched in 2015 to provide Soil Health Cards to all the farmers in the country. Soil Health Card provides information to farmers on soil nutrient status of their soil and recommendation on appropriate dosage of nutrients to be applied for improving soil health and its fertility. Further, the Ministry is promoting Kisan Credit Card (KCC) scheme with a view to provide easy access to concessional institutional credit to farmers. While implementing PDMC scheme, States/UTs should facilitate the beneficiary of PDMC scheme to avail Soil Health Card and Kisan Credit Card under the respective programs.

7.27 Cluster Approach:

7.27.1 States/UTs should prioritize implementation of MI through Cluster approach to have effective integration of sources, connectivity, distribution and application. The size of cluster may be 50 ha. & above in mainland states and 20 ha. in NE & hilly states. Water User Associations/Groups, Farmer Producer Organizations, Cooperative societies, Self-Help Groups, Growers' Associations etc. shall be encouraged to adopt Micro Irrigation in a cluster. In such cases the beneficiary will be entitled to avail financial assistance through their respective organizations / bodies. The total financial assistance available to the individual beneficiary in the group would be 55% under the scheme. The land holding of the beneficiary should be located in one contiguous area. Such farmers groups/organizations may be allowed to avail an administrative/institutional charges @ 3% of the cost of the Cluster.

7.27.2 The States/UTs may encourage FPOs to take up micro irrigation at community level. States/UTs may ensure at least 5% micro irrigation target is implemented through FPOs.

7.27.3 States/UTs may enable such farmers' groups to access capital from NBFC/Bank/NABARD so that such cluster implementation could be taken up through banks with Joint Liability Group (JLG).

7.28 Public Private Partnership (PPP-MI) approach:

States/UTs may take up projects with PPP mode of implementation. The framework for PPP-MI would be as follows:

7.28.1 Public Private Partnership (PPP) approach in Project mode may be an important step for increasing MI coverage for the benefit of farming community. State Governments/UTs may take up projects in PPP approach involving farmer groups, private partners and concerned Departments in the State. Such projects should focus on improving water use efficiency, productivity, income of farmers, access to market and positive environment outcomes.

7.28.2 Objectives:

- a. Implementation of Micro-Irrigation in an aggregated manner achieving better coverage, efficiency in water and fertilizer use.
- b. Convergence of various ongoing Central and State Government schemes and programs to deliver better outcomes.
- c. Availability of private capital and technology partnership;
- d. Access to functional and technical efficiency of private entities.
- e. Active involvement of farmer groups through participatory approach.
- f. Creating employment opportunities for skilled/unskilled persons, especially unemployed youth.
- g. Achieve better products and market linkage.

7.28.3 Rationale:

Judicious use of water is important to expand the agricultural area under irrigation. Micro irrigation promotes adopting optimum cropping pattern and efficient water application, that utilizes available water resources in an efficient manner. Saving of water will not only help in extending irrigation coverage but also in enhancing productivity and improving farmland ecosystem. The water use efficiency in irrigated areas as well as non irrigated areas is presently at low level. In future there could be huge stress on water availability for agriculture as a result of negative impact of climate change. Very few farmers in irrigated commands are adopting micro irrigation system. Micro-irrigation system is cost intensive and technical with maintenance requirements. Capital investment in agriculture is still largely insufficient. Micro irrigation penetration to small and marginal farmers especially in most rural areas is still lagging. There is also a need to ensure equitable access of water availability to tail end farmers. Better market linkage opportunities of farm produce would help in enhancing farmers income. In this regard, collaborative efforts between the Government and Private partners in promotion of micro irrigation shall open new opportunities for the benefit of the farming community.

7.28.4 Strategy of PPP- Micro Irrigation:

- a) Public Private Partnership for integrated Project on Micro Irrigation can be executed through an agreement between State Government and private partners. The arrangement would involve a whole-lifecycle with a predetermined period where the private partners can extend support for both implementation (installation, construction etc.) and operation of the MI systems.
- b) State /UT Governments may prepare projects involving Corporate/Private Partners/Other Entities, farmers groups and concerned Institutions/ Departments in the State. Under the project, allowed activities of PDMC

scheme may be taken up through the scheme following the operational Guidelines. The other activities of the project would be converged from other schemes/investments from entities of the project. The proposals shall clearly indicate the interventions being made by the entities, the scale of the project, approx. number of farmers involved and the expected outcomes in terms of farmers benefits.

- c) Various Agri retail business companies may be involved for facilitating market linkages of farm produce in the project area.
- d) The aim is to set up PPP based projects wherein entities (eg. FPO/ Farmers Groups, Private Companies, Concerned Departments of the State etc.) may invest in creation of Common Infrastructure i.e. Water sources, pressurized pipe networks till farm end gate from canal /reservoir along with sumps/storages, lifting/pumping facility and the on-farm Micro irrigation system. Convergence with various related Government schemes may be made for effective utilization of available resources in the project area. Corporate/Industries shall be encouraged to participate in the project through their Corporate Social Responsibilities (CSR) outreach.
- e) The PDMC scheme would be dovetailed with such PPP projects.
- f) Project document will have clearly marked out convergence of other Centrally Sponsored Schemes of Ministries as well as State Schemes.
- g) Transparency of complementary investments of non-Government entities and visibility of public-domain infrastructure created shall be ensured.
- h) IT based solutions, use of advanced technologies of Micro Irrigation such as solar energy, Automation, use of AI, IoT etc. should be given priority for effective implementation & monitoring. Technologies that are complimentary to micro irrigation in reducing water losses or evaporation, improve soil water holding capacity etc. should be promoted along with MI.
- i) PPP projects should explore carbon market potential which will deliver additional income to farmers.

7.28.5 Procedure for Approval and Implementation:

- a) The project on PPP should include information on geography & climate, potential of agriculture development, available irrigation infrastructure, potential for micro irrigation, strategy for development and plan of action proposed to be taken. The document should focus on adoption of aggregation/cluster approach for coverage of micro irrigation and linking with available infrastructure, or to be created. Willingness of the farmers to be a part of the proposed project should also be included.
- b) The project should reflect the whole-lifecycle with a predetermined period. The project shall clearly indicate the interventions/responsibilities/role of the

entities, the scale of the project, approx. number of farmers involved and the expected outcomes in terms of farmers benefits and the way forward.

- c) Growers/farmers/farmers group under the project would be entitled for assistance under other schemes of DA&FW/other Departments. The project implementing agency or the private partner should collect the data and required documentations of all farmers in the project and facilitate to access the assistance available under the PDMC scheme.
- d) The State Nodal Department/Agency of PDMC of the State may call for proposals from entities interested in carrying out the project and short list them based on applicant's experience. State can set up a committee to select and finalize the projects.
- e) Proposals shall be submitted to State Governments. The State Government will examine the project proposal from the viewpoint of suitability to need of the area. If found suitable, the proposal should be included in the Annual Action Plan of the State to be approved by the SLSC.
- f) Project should be implemented after approval of SLSC.

7.28.6 Monitoring of the Projects:

In order to ensure transparency & accountability, robust technology based monitoring system must be ensured. Assets created under the project will be geo tagged and land area also be geo referenced. Payment to the beneficiary should be through DBT. Information related to the Project, cluster, funds provided etc. will be available in the public domain. An independent monitoring agency will be appointed by the State Government to closely track the performance of the projects including the quality aspects as well as benefits accruing to the farmers.

7.29 Pilot Projects on Micro Irrigation in Irrigation Command Areas.

Agriculture consumes the largest share of groundwater in India-the biggest user of ground water in the world. The past few decades have witnessed an alarming depletion of groundwater resources in the Country. It is observed that the water source for Micro Irrigation under PDMC Scheme is mostly ground water. Micro irrigation systems has not been sufficiently linked to surface water. On the other hand, the conventional flooding method of Irrigation is still largely used by farmers under command area which is highly inefficient. It is important to encourage the use surface water for Micro Irrigation for enhancing water use efficiency. Ministry of Jal Shakti has been given the goal of increasing the water use efficiency in India by 20%. For efficient use of surface water available under command area, Ministry of Jal Shakti and MA&FW have decided to promote network of Pressurized Piped Irrigation Command (PPIC) with assured supply of water at outlet provided at the farm gate in a cluster. This outlet will be linked to micro irrigation systems for use by the farmers. The initiative will be supported

under PDMC Scheme of Ministry of Agriculture. The Water User Society of the cluster will be strengthened with other schemes of the MoAFW to convert into an Economic Entity. The Economic Entity will sustain the created infrastructure on their own, relieving the Governments of burden of subsequent maintenance and subsidy.

As a joint effort, Ministry of Jal Shakti and MoAFW have decided to jointly work on a pilot project under PDMC funds. The PPIC will be created along with the micro irrigation systems (drip/sprinkler) in a pilot project. The pilot projects will cover an area of about 500 hectare or more with close proximity to achieve visible impact of the program and encourage local participation and market linkage of produce. The pilot project will emphasizes on adoption/promotion on latest technologies in MI, such as sensor based MI, use of AI, IoT etc. Water User Societies/FOPs/SHGs/ Farmers Cooperatives should be actively involved in such pilot projects and shall be given the responsibility of managing/maintenance of the MI systems. NABARD may assist in mobilizing FPOs in providing market support to the farmers. Further, convergence with flagship schemes/Missions like, RKVY, Marketing, NFSM, MIDH, Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme MGNREGS, Integrated Watershed Management Programme (IWMP) etc. will be emphasized which will enable better implementation outcome. These projects will help in training, capacity building and demonstrations on adoption of Micro Irrigation technologies to farmers and for future replication of the model in larger areas.

All the State/UTs/ICAR/Central Agencies are eligible to implement the pilot projects under PDMC. The proposals of pilot projects will be come through Ministry of Jal Shakti by the implementing agencies for funding under Head Quarter Budget of PDMC scheme within the budget limits. The total approved cost of the project will be provided to implementing agency as a 100% assistance during the project period. Assistance will be extended for adopting activities such as Pressurized Piped Irrigation Command (PPIC), Solar Power, Micro Irrigation systems and Water Use Efficiency applications for efficient delivery, distribution and monitoring of water. Efforts will be made for development of the cluster Water User Society into an FPC, once the project is handed over to Water User Society. The projects will be monitored by Ministry of Jal Shakti as per their standard operating Procedures. An MoU may be executed between Commissioner CADWM, MOJS, JS (NRM), MoAFW, State level Implementing Agency and the Water User Society for successful implementation of the Pilot Projects.

7.30 Micro Irrigation Demonstration plots in KVKs/ICAR Centers.

Micro irrigation is generally perceived as technology intensive; hence, its acceptance by farmers needs much persuasion as well as capacity building. Extension services/on field demonstration of MI systems for the farmers/farmers groups is important to achieve the desired results. Demonstration plots for micro irrigation may be set up in KVKs and ICAR institutes across the country where demonstration of MI systems shall be conducted with underlying objectives of

collating, creating and imparting knowledge useful for the farmers to address the issues like administration processes and practices adopted, effectiveness, crops wise impact, effect of water/ energy, labour saving, income and employment generation etc. Such plots will also carry out demonstration of new technologies such as automation, solar based MI systems, AI/IoT based MI systems etc. and develop database. KVKs will coordinate with the State Implementing agencies/Agriculture/Horticulture Departments for training farmers/farmers groups on MI technology through these demonstration plots. The information and experience gain will also be an important asset for future research purposes.

Low MI penetration States/UTs, Vibrant Villages, Aspirational Districts shall be given priority for developing such water smart plots. The proposals for developing such plots will be submitted by the concerned/implementing ICAR/KVKs to the Ministry for funding under Head Quarter Budget of PDMC scheme within the budget limits. The total approved cost of the proposal will be provided to the ICAR/KVK as a 100% central assistance.

8. Operational Aspects:

- 8.1 The Implementing Agency need to widely publicize the importance of the scheme at block and village levels through its existing networks to create awareness among the farmers. Organize District Level Seminars/Workshops involving MI Manufactures/Companies. Further, the State Agriculture Extension Units should organize camps and Trainings in collaboration with MI Manufactures/Companies to explain system components and their functions, type of micro irrigation for crop, post installation services and frequency of maintenance etc. Trainings/camps to target the family, not individual beneficiary. The MI manufacturer / company may provide irrigation schedule to farmers, make efforts for linkage to agronomic practices.
- 8.2 Dedicated Implementing Agency/Special Purpose Vehicle (SPV): States/UTs with good micro irrigation coverage have shown that dedicated Implementing Agency/Special Purpose Vehicle (SPV) can accelerate the scheme success with overall efficiency. Therefore, States/UTs should setup a dedicated Implementing Agency/Special Purpose Vehicle (SPV) at the state level with dedicated manpower to ensure that the needed attention is given in the implementation of the scheme.
- 8.3 Dedicated portal for implementation: States having dedicated portal for implementation have performed better with high level of transparency. Hence, all States/UTs should develop their own portal dedicated for the implementation of the scheme. Government of India will also develop a reference portal for use of States. States using its own portals should make data available to the Government of India portal through APIs.

- 8.4 All level of implementation including receipt of applications, work order, work completion, verification, payment release, monitoring, feedback etc. shall be captured by the State portal developed for the purpose. Also, the Portal should have online workflow, mapping all levels of implementation to ensure effective monitoring.
- 8.5 The States/UTs shall adopt bio-metric/facial authentication enabled Aadhar based registration of applicant developed by DA&FW. The details of the applicant, such as, Name, Gender, Date of Birth, Identifier Name (Father/Spouse Name), etc should be captured as per the Aadhar eKYC. The assistance should be transferred to the Aadhar seeded and DBT enabled active bank account of the beneficiary through DBT. In case it is given in kind through Companies, the intimation should be conveyed as SMS to the beneficiary on his mobile phone with details of assistance. The States/UTs should ensure that disbursement of subsidy is made a time bound activity
- 8.6 All land based interventions should be Geo Tagged/Geo Fenced. Krishi Mapper/Mobile App developed by DA&FW shall be used for Geo Tagging/Geo Fencing of farmers' field. The data captured by the App will automatically link with the State MIS portal through API.
- 8.7 The State Implementing Agency will engage Third Party Inspection Agencies (TPIAs) for conducting inspection/physical verification of the installed Micro Irrigation Systems at every farmer field. The installed site will be verified by these agencies for material supplied and also conduct Trial Run at the site. TPIAs should capture and upload photographs/videos/report of the MI installation at site which should be made available in the State portal. States/UTs should ensure timely installation and third party verification of MI installation. The Implementing Agencies must complete the timely inspection/physical inspection of the MI systems to avoid delay. Ideally, the physical inspection should be completed within 60 days of installation. Due penalty should be imposed on supplier if any delay in installation is observed. States/UTs must also ensure timely release of subsidy/top-up to the beneficiaries.
- 8.8 All scheme related information including progress and achievements should be captured by State portal which may be integrated with the National portal through API to ensure seamless flow of information.
- 8.9 The beneficiary shall be free to choose MI equipment from any MI manufacturer out of the approved list of registered manufacturers and also to choose the type of MI system to be installed as per the system design compatible with his/her cropping pattern.

- 8.10 The State Implementing Agency/ SPV should conduct inspections at the factory site of the Supplier(s) through Third Party technical agencies such as Central Institute of Plastics Engineering and Technology (CIPET), ICAR Institutes, State Agriculture Universities etc. However, if any State/UT has already conducted such inspection of a supplier, the inspection report (of the supplier) may be considered by other States/UTs also.
- 8.11 All the Micro Irrigation Systems will be QR Coded. The QR code of the system will be linked to Unique application no./Sanction ID of the farmer on installation of the system.
- 8.12 The MI manufacturer/supplier should necessarily generate e-invoice for micro irrigation system supplied with details of all its components and the e-invoice shall be captured by the State Portal.
- 8.13 A module/hand book may be devised by the Implementing Agency/SPV for the benefit of the farmers with basket of services which includes Farmer Education & Training (Agronomy services), maintenance & operating Micro Irrigation Systems etc.
- 8.14 The MI supplier Agency should provide necessary services to farmers after installation trial run of the system for at least three years free of cost. The List of service centers/offices/offices of authorized distributors with full address/telephone numbers/e-mail should be widely published (Inspection/repair/replacement).
- 8.15 A toll free customer care number will be provided by the State implementing agency for providing information related to Micro Irrigation Systems. Also grievance redressal and feedback system of the beneficiaries should be provided.
- 8.16 To ensure strict adherence to quality standards in the use of MIS Components, the Implementing Agency of the State will ensure the BIS standards of supplied equipment.
- 8.17 States to develop modules on several aspects; fertigation schedule, acid treatment, issue of salts/salinity in water, linkage to agronomic practices, selection of the right system etc. Further, States to conduct trainings and best practices demonstrations for the beneficiaries as well as officials/staff for better learning.

9. Drip Irrigation System for states where it has been well accepted by farmers and good infrastructure is available

- 9.1 The scheme is well accepted by the farmers and substantial coverage has been made under micro irrigation system compared to other parts of the country with

required infrastructure and service facilities in the States namely Andhra Pradesh, Delhi, Gujarat, Haryana, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan, Tamil Nadu and Telangana. These states are considered to be category "A" States with comparatively better penetration of micro irrigation technologies.

- 9.2 Drip Irrigation technology involves irrigating root zone through emitters fitted on a lateral tube as well as inserted within the tubing as emitting pipe. The use of different emitters will depend upon specific requirements, which may vary from crop to crop.
- 9.3 Fertigation is important for getting maximum benefits out of the micro irrigation technology. Therefore, it is mandatory to use a fertigation device by the farmers such as venturi injector or fertilizer tank on which the subsidy is available.
- 9.4 Water requirement, age of plant, plant to plant spacing, soil type, water quality and availability etc are some of the factors which decide the choice of emitting system. The indicative cost of drip irrigation systems (assuming peak water requirement with source of water at the corner of plot), for different lateral spacing and plot sizes has been provided in the guidelines. An indicative list of system components required for installing a drip irrigation system in the areas ranging from 0.2 ha to 5 ha is at **Annexure-IV a to g**, on the basis of which subsidy will be calculated as per Table 1:

Table 1: Indicative cost of Drip Irrigation System for calculation of subsidy
(Cost in Rs.)

Spacing (mxm)	0.2 ha	0.4 ha	1 ha	2 ha	3 ha	4 ha	5 ha
12x12	10526	18009	24586	39098	60704	75521	96166
10x10	10854	18652	26181	42226	65487	82025	104292
9x9	11091	19114	27304	44469	68853	86606	110024
8x8	11330	19711	28777	47314	73272	92615	117529
6x6	12400	21693	34687	57987	93688	113618	142566
5x5	13144	23486	39378	67199	97110	123409	165815
4x4	14602	24326	41534	72799	113560	148684	176964
3x3	15792	26190	47751	82654	127306	160103	200455
2.5x2.5	19516	35393	68234	124216	189724	266274	325233
2x2	23932	41303	83085	161263	234280	325469	399494
1.5x1.5	28106	46995	97245	185324	276767	382246	470306
2.5x0.6	20201	35000	71733	131824	201464	279770	343433
1.8x0.6	24569	42992	91560	173298	260868	355323	442484
1.5x0.6	28003	50116	109531	207860	313909	425189	530905
1.2x0.6 (or lower spacing)	31436	57241	127501	242422	366950	495055	619326

- 9.5 In case of crops with plant spacing other than those mentioned in above table, the amount of assistance could be calculated on pro rata/average basis of the nearest plant area (Row to row x plant to plant spacing in metre). The example is given below.

- a. If a subsidy has to be calculated for 1.5 x 1.5m spacing i.e. between 1.0 ha (₹97245) and 2.0 ha (₹185324), the cost would be : ₹97245 + [(₹185324-₹97245) / (2.0 ha-1.0ha) x (1.5ha-1.0ha)].
 - b. If a subsidy has to be calculated for 1.0 ha and 3.5 x 3.5m spacing i.e. between 4.0x4.0m (₹41534) and 3.0x3.0m (₹47751) the cost would be: ₹41534+[(₹47751-₹41534)/(4.0x4.0-3.0x3.0)X(4.0x4.0-3.5x3.5)].
- 9.6 The unit cost of Drip Irrigation system varies with respect to plant spacing and location of the water source. The farmer can avail other interventions as per **Annexure-XIII** as per specific requirement of the field in which micro-irrigation system is to be installed.
 - 9.7 Assistance under the scheme is available for all types of drip irrigation systems such as on-line & in-line drip irrigation systems.
 - 9.8 As small farm holdings may not have individual source of water, it would be preferable to encourage a group of farmers to avail the benefits of drip irrigation through a common water source.
 - 9.9 A beneficiary having farms located at different places and having different water source may avail the subsidy as per the guidelines. However, a beneficiary cannot split area at one location into small pockets of the same crop for claiming assistance under the scheme. If a beneficiary has more than one crop with different crop spacing being grown separately in his/her land holding, assistance will be available for installing the drip irrigation system as per the individual crop spacing, the combined area of which will not exceed 5 ha per beneficiary.
 - 9.10 In case of inter-cropping, assistance will be available for the prescribed plant spacing/ area, subject to the condition that the assistance will be provided only for one crop as per the farmers' choice.

10. Drip Irrigation System in states with low penetration

- 10.1 Based on the prevailing coverage and acceptance by farmers, states namely Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Odisha, Uttar Pradesh, West Bengal, Goa, Punjab and Union Territories have been identified as states with low penetration of micro irrigation technology. These states are considered as category "B" in terms of implementation of micro irrigation. The cost of drip system is likely to be higher in these states due to various factors such as lesser presence of manufacturing companies in these states leading to higher cost of transportation, the companies will have to make considerable efforts in making the farmers ready for adoption of technology, and higher cost involved in providing after sales service in these states etc. Thus, 15% higher cost has been taken in consideration while working out the unit cost

of drip system in the table below for these states for the purpose of subsidy calculation as per indicative list of system components given at **Annexure-IV a to g**.

Table 2: Indicative cost of Drip Irrigation System for calculation of subsidy in the states where penetration level is low

(Cost in Rs.)

Spacing (mxm)	0.2 ha	0.4 ha	1 ha	2 ha	3 ha	4 ha	5 ha
12x12	12105	20710	28274	44962	69810	86849	110591
10x10	12482	21450	30109	48560	75310	94329	119935
9x9	12755	21981	31399	51139	79181	99597	126527
8x8	13030	22667	33094	54412	84263	106507	135159
6x6	14260	24947	39890	66685	107741	130661	163951
5x5	15115	27009	45285	77279	111676	141921	190687
4x4	16792	27975	47765	83719	130594	170987	203508
3x3	18161	30119	54913	95052	146402	184119	230523
2.5x2.5	22444	40702	78469	142848	218183	306215	374018
2x2	27522	47498	95547	185453	269421	374289	459418
1.5x1.5	32322	54044	111832	213122	318282	439583	540852
2.5x0.6	23231	40250	82493	151597	231684	321735	394948
1.8x0.6	28255	49441	105295	199293	299998	408621	508857
1.5x0.6	32203	57634	125960	239039	360995	488967	610541
1.2x0.6 (or lower spacing)	36151	65827	146626	278786	421992	569313	712224

- 10.2 In case of crops with plant spacing other than those mentioned in above table, the amount of assistance could be calculated on pro rata/average basis of the nearest plant area (Row to row x plant to plant spacing in metres) similar to example given in 9.5.
- 10.3 The assistance will be available for all types of drip irrigation systems; on-line and in-line drip irrigation systems.
- 10.4 In case of inter-cropping, assistance will be available for the prescribed plant spacing/area, subject to the condition that the assistance will be provided only for one crop as per the farmers' choice.

11. Drip Irrigation System for North Eastern and Himalayan States

- 11.1 The coverage of MI system in North Eastern and hilly region is much low due to poor infrastructure and difficult terrain. The states namely Assam, Arunachal Pradesh, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, Sikkim, Jammu & Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand are considered under category "C". In the Hilly states, following points need to

be kept in mind while designing a drip irrigation system keeping in view the sloppy and terraced land:

- It is difficult to lay PVC main and sub-main lines below the ground surface and therefore HDPE pipes are required in place of PVC.
- The undulating and vertical slopes would lead to comparatively larger length of pipes.
- To maintain uniform pressure and to irrigate upper most terrace of land, control valve should be provided at sub-main/main lines at 4m vertical drop. Accordingly, the number of flush valves will also increase.

11.2 The cost of drip system is likely to be higher in North Eastern & Himalayan states because of the terrain, higher transport cost, lesser presence of manufacturing companies etc. Therefore, unit cost of micro irrigation systems is taken 25% higher in these states for the purpose of subsidy calculations and is given in table below (including 25%) for the indicative list of system components is at **Annexure-IV h to n**.

Table 3: Unit cost for NE&H states

(Cost in Rs.)

Spacing (mxm)	0.2 ha	0.4 ha	1 ha	2 ha	3 ha	4 ha	5 ha
12x12	13157	22511	30733	48872	75881	94402	120207
10x10	13567	23315	32727	52783	81859	102531	130365
9x9	13864	23893	34130	55586	86066	108258	137530
8x8	14163	24638	35971	59143	91590	115768	146912
6x6	15500	27116	43358	72484	117110	142023	178207
5x5	16430	29357	49223	83999	121387	154262	207269
4x4	18252	30408	51918	90999	141950	185855	221205
3x3	19740	32738	59688	103318	159132	200129	250569
2.5x2.5	24395	44242	85292	155270	237156	332842	406542
2x2	29915	51628	103856	201579	292849	406836	499367
1.5x1.5	35132	58744	121556	231655	345959	477807	587883
2.5x0.6	25251	43750	89666	164780	251830	349712	429292
1.8x0.6	30712	53740	114451	216622	326085	444153	553106
1.5x0.6	35003	62645	136914	259825	392386	531486	663631
1.2x0.6 (or lower spacing)	39295	71551	159377	303028	458687	618819	774157

11.3 In case of crops with plant spacing other than those mentioned in above table, the amount of assistance could be calculated on pro rata/average basis of the nearest plant area (Row to row x plant to plant spacing in metres) similar to example given in 9.5.

12. Sprinkler Irrigation

- 12.1 In sprinkler irrigation, water is discharged under pressure in the air through a set of nozzles attached to a network of High Density Poly Ethylene (HDPE) pipes, simulating the rainfall. Sprinkler irrigation systems are suitable for irrigating crops where the plant density is very high. It is widely used for cereals; pulses; seeds; spices; and field crops.
- 12.2 Financial assistance would be restricted as per the cost of High Density Poly Ethylene (HDPE) pipes used in sprinkler irrigation systems, even though, the beneficiaries may use aluminium pipes as well. The sprinkler irrigation systems may be portable, mini sprinklers, micro sprinklers, semi-permanent sprinklers and large volume sprinkler systems (Rain-guns). Additional 25% and 15% on the indicated unit cost may be considered for calculation of subsidy for Hilly states including NE region and low penetrating State respectively.

12.3 Portable Sprinkler Irrigation System

- 12.3.1 In portable sprinkler irrigation systems the HDPE pipes are used for mains and sub-mains which can be shifted from one place to another as per the irrigation schedule with respect to design layout. These can be used in both, plains as well as in undulating terrains.
- 12.3.2 The indicative number of components required for various area range of sprinkler irrigation system is annexed. Financial assistance will be provided based on the number of pipes procured by the beneficiary for the area under reference. An indicative list of system components required for installing portable sprinkler irrigation system is at **Annexure-V** on the basis of which subsidy will be calculated. The indicative cost for various area ranges and pipe sizes is given below in Table 4 below:

Table 4: Indicative Cost of Portable Sprinkler Irrigation System
(Cost in Rs)

Area	Pipe Dia. (mm)		
	63	75	90
Upto 0.4 ha	13211	NA	NA
1 ha	21588	24194	0
2 ha	31167	34657	0
3 ha	NA	NA	46779
4 ha	NA	NA	58995
5 ha	NA	NA	66789

- Note: i) In case of area other than those mentioned in above table, the amount of assistance could be calculated on pro rata/average basis of the nearest area.
ii) In case of low penetrating states and hilly states including NE region, 15% and 25% higher indicative cost respectively may be taken for calculation of subsidy.

12.4 Micro Sprinklers

- 12.4.1 Micro Sprinklers are mostly used for irrigating leafy vegetables, nurseries, hardening of seedlings and a few vegetables. Apart from providing irrigation, the micro sprinkler also helps in changing the micro climatic conditions near the plant. Micro sprinklers are low radius sprinklers. The selection of micro sprinklers depends on the type of crop, soil, types etc.
- 12.4.2 An indicative list of system components required for installing a micro sprinkler system is at **Annexure-VI**. The indicative cost of Micro Sprinkler irrigation system at different lateral spacing & area is given in **Table5**:

Table 5: Indicative cost of Micro Sprinkler Irrigation System

Area(ha)	(Cost in Rs)	
	Spacing (mxm)	
	5 x 5	3 x 3
0.4	32713	38263
1	65102	74259
2	114426	133821
3	164937	191078
4	222721	263852
5	281557	321462

- Note: i) In case of area other than those mentioned in above table, the amount of assistance could be calculated on pro rata/average basis of the nearest area.
ii) In case of low penetrating states and hilly states including NE region, 15% and 25% higher indicative cost respectively may be taken for calculation of subsidy.

12.5 Mini Sprinklers

They are commonly used for close growing crops like groundnut, potato, onion, ginger, short statured fodder crops, etc. Mini sprinklers are also suitable for frost protection. An indicative list of system components required for installing a mini sprinkler irrigation system is enclosed at **Annexure VII**. The indicative cost of Mini Sprinkler irrigation system at different lateral spacing and area is given below in **Table 6**below:

Table 6:- Indicative Cost of Mini Sprinkler Irrigation System

Area (ha)	(Cost in Rs)	
	Spacing (mxm)	
	10 x 10	8 x 8
0.4	45694	47528
1	94134	103873
2	176766	187929
3	268422	290935
4	345497	380031
5	423236	469890

- Note: i) In case of area other than those mentioned in above table, the amount of assistance could be calculated on pro rata/average basis of the nearest area.
ii) In case of low penetrating states and hilly states including NE region, 15% and 25% higher indicative cost respectively may be taken for calculation of subsidy.

12.6 Semi-Permanent Sprinkler Irrigation System

- 12.6.1 In Semi-Permanent Sprinkler System, the piping network for main line and lateral lines are permanently buried with risers fitted on the lateral lines. The sprinkler nozzles are fitted on each riser pipe and can be easily shifted from one place to another to irrigate the required area in shifts as per the irrigation schedule or the crop water requirement.
- 12.6.2 The indicative number of components required for various area ranges of semi-permanent sprinkler irrigation systems is enclosed at **Annexure VIII**
- 12.6.3 The estimated unit cost for various area ranges is given below in Table 7 below:

Table 7: Indicative Cost of Semi-Permanent Sprinkler System

Area (Ha)	Cost (in Rs)
0.4	24919
1	40440
2	77113
3	104083
4	132997
5	161345

Note: i) In case of area other than those mentioned in above table, the amount of assistance could be calculated on pro rata/average basis of the nearest area.
ii) In case of low penetrating states and hilly states including NE region, 15% and 25% higher indicative cost respectively may be taken for calculation of subsidy.

12.7 Large Volume Sprinkler Irrigation System (Raingun)

- 12.7.1 Large volume sprinkler irrigation systems (Rain guns) are used where larger areas are to be covered with one or two sprinklers. These sprinklers have a discharge ranging from 10,000 lph to 32,000 lph and radius of throw from 24 m to 36 m. These systems require high pressure and high discharge pipes & pumps to operate them. These are preferred for irrigating crops spread over large areas in short time. The indicative list of components is enclosed at **Annexure IX**.
- 12.7.2 Pivot Irrigation system is used for a much larger area & are not suitable for the beneficiaries targeted under PDMC. However, if some beneficiary is interested, may avail financial assistance as per unit cost norms of rain-gun system. The estimated unit cost for various area is given in Table 9:

Table: 9 Indicative Cost of Large Volume Sprinklers(Rain-gun)*(Cost in Rs)*

Area (Ha)	Pipe Dia. (mm)		
	63	75	90
1	31684	38127	NA
2	NA	48370	NA
3	NA	NA	62767
4	NA	NA	72751
5	NA	NA	79894

Note: i) In case of area other than those mentioned in above table, the amount of assistance could be calculated on pro rata/average basis of the nearest area.
 ii) In case of low penetrating states and hilly states including NE region, 15% and 25% higher indicative cost respectively may be taken for calculation of subsidy.

13. Optional Components

13.1 The use of optional components depends upon the agro climatic conditions of the place & requirement of the beneficiary. The provision is kept to provide the said component on the then existing rate of subsidy to the beneficiary; if required & provided. These components are:

- i. Fertilizer tank - to increase fertilizer use efficiency, fertilizer tanks have been included in the list of equipment eligible for financial assistance. The beneficiary can opt for either fertilizer tank or venturi system or automated dosing system equipment and financial assistance will be provided for either of those components.
- ii. Sand filters/media filters- to remove organic matter and inorganic contaminants from water sources like rivers, tanks and open wells. Sand/media filters have been included the financial assistance.
- iii. Hydro Cyclone Filters/Sand Separators - to remove particles of the size of 75 microns (200 mesh) which have a higher density than water, hydro cyclone filters/sand separators have been introduced as an optional item for which financial assistance will be provided. These equipments require minimum maintenance and are useful for cleaning river water, canal water and tube well water which may contain sand.
- iv. Drip Line Winder- for wrapping the drip laterals has been included for financial assistance.

13.2 States may take up sources creation -Other Interventions (OI) activities under the scheme and must be linked with Micro Irrigation to make potential use of the available funds for higher water use efficiency. These activities should be based on actual requirement and as per the needs of the farmer who adopts

the Micro irrigation system. The details of eligible OI activities for financial assistance and cost Norms is provided at **Annexure XIII**.

13.3 The detailed guideline for water quality & filters selection is provided at **Annexure X&XI** respectively. The indicative cost of optional components such as sand filters, hydro cyclone filters and fertilizer tanks is annexed at **Annexure XII**

13.4 Optional items if any other than above may be allowed. However, cost of these items will be borne by the beneficiary.

14. Key Administrative requirements

14.1 The unit cost norms indicated in the guidelines for various technologies/ specifications are for the purpose of calculating subsidy ceiling amount only i.e. it can be less but not more than the indicated amount if the cost is more. The actual cost of the system, however, would vary as per design of the field and other agro climatic conditions. It is to be ensured that all compulsory system components are provided to the farmer. The BOQ given in the table is indicative & may vary case to case.

14.2 An individual eligible to receive the benefits under the scheme is required to furnish proof of possession of Aadhaar Number or undergo Aadhaar registration. If one individual is eligible but do not possess the Aadhaar number she/he can get enrolled visiting the Aadhaar enrolment centre. State Government/Union Territories Administration is required to offer Aadhaar registration facilities to the beneficiaries who are not enrolled and in case no Aadhaar enrolment centre is available in certain blocks/ taluka/ tehshil, the nodal department through its implementing agency is required to provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the Registrars of UIDAI. Till the time Aadhaar is assigned to individual, she/he can avail the benefit of the scheme on production of the following documents Aadhaar enrolment ID slip/ Copy of request for Aadhaar enrolment and Voter Identity Card/ PAN/ Passport/ Ration Card /Employee Govt. ID/Passbook of bank or post office/MGNREGS card/ Kissan photo passbook/ Driving License/ any other document as specified by State/UT.

14.3 Aadhaar details need to be linked through a web based registration process. The assistance if given in cash, need to be transferred to the bank account of the beneficiary and in case it is given in terms of kind through Companies, the intimation be conveyed as SMS to the beneficiary mobile phone with details of assistance. It should be ensured that no eligible beneficiary suffers for want of Aadhaar and it would be the responsibility of implementing agency to ensure that Aadhaar enrolment of such beneficiaries is carried out on priority. The notification issued in this respect is given at **Annexure-XIV**

14.4 It must be ensured that at least 50% of the allocation is utilised for small, marginal farmers of which, at-least 30% should be women beneficiaries/farmers. Further, 16.5% and 8.5% of the total allocation or in proportion of SC/ST population in the district should be utilised for Special Component Plan (SCP) & Tribal Sub Plan (TSP) respectively.

14.5 Transparency in beneficiary selection – It should be ensured that the Implementing Agency follows uniform procedures and full transparency in selection of beneficiaries and release of assistance to the beneficiaries in an efficient manner. Enlisting of the beneficiaries should be open round the year facilitating submission of applications by beneficiaries any time for availing the benefit of financial assistance under the scheme. The state implementing agency need to adopt a web based IT model for implementation of the scheme. Implementing Agency should ensure that selection of beneficiaries is done as per details included in the Annual Action Plan for the component for the year which has been derived from the DIP.

14.6 All level of implementation shall be in the State portal platform developed for the purpose. The Portal should have online workflow, mapping all levels of implementation to ensure effective monitoring.

14.6.1 Pre-installation activities

- i. The Implementing Agency need to widely publicize the scheme at the block and village levels through its existing networks.
- ii. Appoint a nodal officer who is responsible for coordination of the scheme implementation with the Districts.
- iii. Disseminate the list of suppliers and rate list approved by SLSC to the farmers.
- iv. Organize at least one District Level Seminar/Workshop with the participation of Industry.
- v. Compile the application submitted by the farmers and scrutinize, codify and forward the same to the company's/Manufacturer's local office indicated by the farmer.
- vi. The beneficiary share may be deposited with manufacturer/their representative or the state nodal agency as per the practices to be adopted by the state with the approval of SLSC.
- vii. The beneficiary shall be free to purchase MI equipment from any MI manufacture out of the approved list of registered manufacturers.

14.6.2 The manufacturer/company will do/provide the following:

- i. Assess the crop water requirement as per the crop for which the system is to be provided.
- ii. Design the system as per the crop water requirement.
- iii. Prepare an estimate of cost and submit it to Implementing agency duly

indicating the time frame in which the system will be installed in the farmer's field once work order is issued.

- iv. The Implementing agency will approve the estimate, issue work order and ensure installation
- v. Efforts will be made by the MIS Supplier to ensure coverage of MI in the water scarce, stressed area, critical ground water districts/blocks and in potential & untapped area of the State.

14.6.3 The Company will install the system and commission it to the satisfaction of the beneficiary duly ensuring that:

- i. Quality components having BIS marking are installed in the farmer's field, and while making payment the implementing agency will ensure the BIS standard of supplied equipment, whichever the BIS standard exists.
- ii. The date of manufacturing should be printed on the components as per prevailing statutory norms.
- iii. Implementing agency will ensure that MI system installed in each field bears separate QR code.
- iv. The installed system should match the water requirement of the crop.
- v. Necessary orientation and training is given to the beneficiary on the system maintenance & irrigating the crop with drip/sprinkler irrigation.
- vi. Proper warranty and a user's manual for running & maintenance of the system - whether drip or sprinkler or both- as the case may be is provided to the beneficiary.
- vii. A certificate towards successful installation/commissioning of the system is obtained from the beneficiary.

14.6.4 Disbursement of assistance post installation.

- i. Financial assistance to the beneficiary will be limited to the prescribed subsidy as per unit cost as prescribed under the guidelines or the actual Bill of Quantities (BoQ) whichever is less. On physical verification of satisfactory installation of the system & a certificate to that effect from the beneficiary, Implementing Agency will release payment to the beneficiary electronically in his/ her bank account.
- ii. The Implementing Agency shall ensure proper invoice with statutory commercial details i.e. Serial number, GSTIN number etc. printed on it and countersigned by the authorized representative of the MI System manufacturer is issued to the beneficiary & subsidy released on the same.
- iii. The manufacturer will install the system as per the agreement with the state nodal agency and the procedure for payment as decided by the SLSC may be adopted. Electronic mode of payment is required to be followed for most of the transactions for implementation of the programme. In case the amount is placed with manufacturers/ companies/financial institutions on

behalf of beneficiary, the consent of beneficiary is required and the transaction details need to be conveyed to him over SMS immediately and subsequently in writing too.

- 14.7 Micro irrigation system may be insured for the period of its expected life and the premium may be borne by beneficiary/state government based on the decisions to be taken by States.

15 Registration of manufacturing companies

- 15.1 Registration of micro irrigation system manufacturers shall be done with the approval of SLSC for a period of five years. The registration will be open round the year and a company can apply at any time. Only those manufacturing companies, which have all the facilities to ensure supply of quality product as per BIS standards and can provide prompt after sales services will be registered. The registration will be subject to the satisfactory performance of the company as assessed by the state implementing agency and repeated failures will lead to the de-registration by SLSC.
- 15.2 The companies willing to participate in the scheme should be manufacturing below mentioned components and own BIS in their name:
- 15.3 In the case of drip irrigation, company must manufacture at least laterals and emitting devices as specified conforming to BIS standards. For online drip irrigation systems the company should be manufacturing lateral tubing as well as drippers as per BIS and for inline drip irrigation systems, the company should be a manufacturer of inline emitting pipe.
- 15.4 In the case of portable sprinkler irrigation system the company should manufacture coupled HDPE pipes or sprinklers and should possess respective BIS.
- 15.5 In the case of other sprinkler irrigation systems viz. Mini, Micro, Semi-permanent sprinkler irrigation systems the company should manufacture either of HDPE/PVC/PE pipes/nozzles and should possess respective BIS.
- 15.6 In the case of large volume sprinkler irrigation system (rain gun sprinklers) the company should manufacture HDPE pipes or nozzle and should possess respective BIS.
- 15.7 The company must provide guarantee of quality assurance of other components which are not manufactured by them in various technologies covered under the scheme.

- 15.8 The company must provide free after sales service to the farmers for three years from the date of installation of system. Moreover, they should set up service centres for providing technological support at the grass root level.
- 15.9 The registration under the scheme should be open throughout the year to enable maximum flexibility and open participation.
- 15.10 The company will supply only BIS marked material. The list of relevant BIS components is given at **Annexure XV**.
- 15.11 In case the company intends to supply imported components, it shall be eligible for subsidy under the scheme subjected to indigenization of manufacturing of the component within a period of two years. In case of imported equipment, the techno- economic analysis report will be provided by NCPAH after proper examination and verification and submit report to DA&FW.
- 15.12 The material should be supplied directly by the manufacturer or their authorized distributors/dealers. In all cases, the manufacturer should authenticate the invoices. Such manufacturers shall furnish a Bank Guarantee of quantum of which will be prescribed by SLSC valid for the period of registration.
- 15.13 Each company may have its own pricing system. However, the company would be required to submit the same to the Registering Authority/SLSC at the beginning of the year and as and when the prices are revised by the company.

16 After sales services & campaigns

- 16.1 Operation and Maintenance of the system requires adequate training of beneficiaries for system operation etc. The manufacturers should have required network for providing training and after sales service in their areas of operation. The manufacturers should provide detailed operational and maintenance manual in the local vernacular language at the time of installation of the system. The beneficiaries should be advised to follow the instructions provided by the manufacturers for the operation and maintenance of drip/sprinkler irrigation systems.
- 16.2 Service centres and / or offices of drip / sprinkler system manufacturers / authorised distributors should have facilities to provide technical guidance on system maintenance schedules, supply spare parts and ensure satisfactory performance of the system during the warranty period. The manufacturer must also operate a toll free customer care number where beneficiaries can register their complaints. List of service centres/offices/offices of authorised distributors with full address/telephone numbers/e-mail should be widely published.

- 16.3 After sales service should be provided by the manufacturer/authorized distributor, free of cost for at least a period of three years. The company shall repair or replace any components/instruments of the MI system free of cost within warranty period, if they are found to have manufacturing defects or workmanship defects.
- 16.4 Due to normal wear and tear, if any parts/components require repairing/replacement, the company shall supply the same and recover the cost from the beneficiary after the free period is over. The company or its authorised representatives shall provide acid/chlorine treatment to drip system once during the first year of operation of the system. However, the company should provide training to the beneficiary on this aspect to enable him to do further treatment by himself.
- 16.5 If any system manufacturer fails to provide such service, the same should be brought to the notice of district level committee and SLSC. The manufacturer would be responsible for any dispute arising from the supply of their product/component directly or through their authorised distributors/dealers. The Implementing Agency/ SLSC of each State shall evolve a process and modus operandi to redress the disputes, if any. In cases where product quality related complaints from beneficiaries are received due sampling process mentioned in the guidelines shall be followed.
- 16.6 The SLSC may take measures against erring companies or their authorized dealers, as well as their own staff after due hearing in order to safeguard the interests of farmers/beneficiaries and to ensure effective utilization of public funds. However, before initiating any action, principle of natural justice should be followed.
- 16.7 There could be extension campaigns by the MI companies at a centralized location having area nodal officials, farmers & other related officials. Various aspects of system maintenance, acid treatment, fertigation etc. could be covered. The technical support group NCPAH would maintain a data appropriately to monitor these activities.
- 16.8 The State agencies ensure the campaigns by companies should cover all beneficiaries under warranty period & could be asunder:
- | | |
|--|-------------|
| More than 5000 ha area coverage in the state | 6 campaigns |
| 1000-5000 ha area coverage in the state | 4 campaigns |
| Less than 1000 ha area coverage in the state | 2 campaigns |
- 16.9 The States should develop a grievance redresser system for farmers with a unique toll free number to assist the farmers for their queries and after sale service. If required, Micro Irrigation installing Company may also be asked to provide a Toll Free number.

17 Violations & Penalties

- 17.1 The Central & State Governments, micro irrigation suppliers/manufacturers and other stake holders are putting in a lot of efforts for effective operations of micro irrigation systems. Any wrong operations could lead to system failure & financial loss to the beneficiary apart from loss of faith in the technology. It is, therefore, important to have well defined measures / terms for violation of norms by the stake-holders. Any violation to the quality, maintenance and other parameters need be viewed seriously. The list of violations mentioned below is not exhaustive and any other deviations, which affect the implementation of the scheme adversely may be considered by the DMIC/SLC as deemed fit for smooth functioning of the same.
- 17.2 A due process, where show cause is issued and adequate time is allowed for response, shall be followed and the MI companies as well as the beneficiary shall be adequately heard and natural justice provided.
- 17.3 In case of violations in respect of failure in quality control & quality assurance and to provide maintenance & after sales service, following penalties shall be imposed:
- i. First time in a year, a warning letter may be issued to the manufacturer instructing to rectify the short coming immediately.
 - ii. Second time in same year, a warning letter may be issued to the manufacturer instructing to rectify the shortcoming immediately with a penalty of 10% of invoice value.
 - iii. Third time in same year, a penalty of 25% of invoice value may be charged.
 - iv. Fourth time in same year, a show cause notice may be issued to the company and the case may be refer to SLSC for de-listing the company for a period of one year or more as decided by SLSC.
- 17.4 The violations with regard to submission of bills without installation/partial installation, wrong invoicing, variations in component specifications, submission of wrong documents with reference to pump/system discharge, improper installation, quoting higher price than approved, deviations from prescribed material specifications etc. may be dealt with by the SLSC suitably apart from initiating suitable action under the relevant sections of Indian penal code and other relevant/ appropriate statutory enactments.
- 17.5 In case of sale of the MI system to other farmers before expiry of average life of the system, for which subsidy has been claimed by the beneficiary, legal proceedings against the beneficiary as per applicable law may be initiated and the beneficiary may be blacklisted from availing any government assistance in future.

18 Quality Control

- 18.1 Crucial aspect of supply of micro irrigation systems is the quality of hardware which is delivered to the farmer. It needs to be ensured that quality components having BIS marking (wherever applicable) are installed in the beneficiary field. Poor quality has an adverse impact on performance of the system which may affect yield of the crop, quantity of water applied, quantity of fertilizer delivered to the plant etc. It may also increase energy consumption. In fact, sub-standard system will not only adversely impact performance, but could also reduce the durability and the life of the components and/or system.
- 18.2 The SLSC shall form joint inspection teams for field inspection and frequent surveillance by inspection teams will be a regular feature under the Scheme. They will draw random samples periodically from the field, within a period of three years from the date of installation of the system. At the time of inspection, the system should be fully functional. The report should be submitted to the competent authority under SLSC for further action.
- 18.3 While one surveillance visit per operative year shall be kept as the general norm, more or less inspections may be planned depending on the performance or specific guidelines issued by SLSC.
- 18.4 Samples for testing should be collected jointly by the joint inspection team, state nodal official and the company representatives in triplicate and properly labelled, sealed and signed. The samples are collected for all major system components, especially pipes & tubing. One set of samples should be sent to CIPET/BIS or any other approved product testing laboratory for testing as the SLSC may deem fit, another set is to be preserved in the custody of nodal officer and the third one is to be with the manufacturer. After collection of samples at random, they should be coded as per BIS guidelines for the purpose of security and further reference.
- 18.5 Collection of samples with batch number is mandatory. The samples may be collected from the beneficiaries' fields as well as the supply chain of the manufacturer after the product has been dispatched from the manufacturing unit.
- 18.6 The quantity of material required for conducting the test is as detailed below:

Sl. No.	Test	Test samples required
Laterals as per IS : 12786 & Emitting Pipes as per IS : 13488		
1	Identification & composition analysis	15 meters for laterals. 50 meters for emitting pipe.
2	Thickness	
3	Pressure Test	
4	Dimensions	

HDPE Pipes IS: 17425:2020		
1	Identification & composition analysis	1 mts
2	Thickness	
3	Pressure Test	
4	Dimensions	
UPVC Pipes IS: 4985		
1	Identification & composition analysis	1 mts
2	Thickness	
3	Pressure Test	
4	Dimensions	
Emitters / drippers as per IS : 13487		
1	Identification & composition analysis	50 Nos
2	Flow Rate	

18.7 The expenditure towards the testing charges shall be met from the administrative charges under the scheme.

18.8 The state nodal officer will do proper scrutiny of the test report provided by the testing laboratory and draw conclusion from the findings regarding conformity or otherwise of the samples under the test. After scrutiny, the details of test report and results of conformity/non-conformity shall be placed before SLSC for consideration. In case of non-conformity, SLSC may take action against the company/its authorised dealers as per penalty clause mentioned in the scheme guidelines. The SLSC shall follow principle of natural justice and the company as well as the beneficiary shall be heard before taking a final action in the matter.

19 Human Resource Development and Media

19.1 Human resource development is an important component of the scheme. Under the programme training of farmers, entrepreneurs, field level workers, officers, micro irrigation technician and farm pond lining technician and trainers' training may be taken up.

19.2 The financial provisions for the same would be as under:

a) Training of stake holders		
i) Within the State	Rs. 1000/day per farmer including transport	100% of the cost.
ii) Outside the State	Project based as per actual	100% of the cost.
b) Exposure visit of stake holders		
i) Outside the State	Project based as per actual	100% of the cost.

ii) Outside India	Rs. 4.00 lakh/ participants	Project Based 100% of air/rail travel. Course fee cost to be funded under Mission Management
c) Study tour of technical staff/ field functionaries		
i) Within the State	Rs. 300/day per participant plus TA/ DA as admissible	100% of the cost.
ii) Study tour to progressive States/units (group of minimum 5 participants)	Rs. 800/day per participant plus TA/ DA as admissible	100% of the cost
iii) Outside India	Rs. 4.00 lakh per participant	100% of air/rail travel and course fee cost to be funded under Mission Management

- 19.3 For organization of a workshop/conference or participation in an international event the financial provision is given below. However, prior approval of DA & FW will be required for participation in international events.

International level event	Rs. 7.50 lakh per event.	100% of the cost per event of 4 days, on pro rata basis.
National level event	Rs. 5.00 lakh per event.	100% of the cost per event of two days.
State level event	Rs. 3.00 lakh per event	100% of the cost per event of two days.
District level event	Rs. 2.00 lakh per event	100% of the cost per event of two days.

- 19.4 Area wise/District wise Awareness/Publicity creation - awareness creation and publicity of the micro irrigation technology will be undertaken through print and electronic media and other methods. The publicity campaigns at block/ district/state level need be undertaken by the state nodal agencies.

- 19.5 The expenses for above Human Resource Development activities and awareness programmes etc. will be met from the administrative expenses earmarked under the scheme.

20 Pattern of Assistance & funding pattern

- 20.1 The total financial assistance available to the beneficiary under the micro irrigation scheme from both Central and State Governments would be 55% for small & marginal farmers & 45% for other farmers. The unit cost would be

limited to the Indicative costs mentioned in the guidelines for various technologies and areas as given at **Annexure Nos. IV to IX**. For the purpose of calculating subsidy the unit cost shall include the applicable GST.

- 20.2 Funding of financial assistance - under PDMC the subsidy amount payable to the beneficiary will be shared in the ratio of 60:40 between the Central & State Governments for all states except North Eastern & Himalayan states, where the sharing will be in the ratio of 90:10. In the case of Union Territories, the scheme will be funded 100% by the Central Government.

21 Monitoring and Evaluation

- 21.1 Government of India has been emphasizing the use of IT such as online monitoring and information system. All Implementing Agencies/ SPVs of the States/UTs should develop a dedicated portal for the implementation of the scheme. States should ensure transparency and information should be accessible to all the stake holders as well as the public. The State portals should be integrated with the National portal or information to be made accessible through API for seamless flow of information. The State portal should be operational round the year for acceptance of farmers applications and also enabling registration facility at remote places. The State Portal should have online work flow mapping all levels of implementation to ensure effective monitoring. The State portal should also have information like scheme guidelines, application forms, procedures, policies etc. for easy access and facilitation to beneficiary and other stakeholders
- 21.2 Periodic review meeting of the scheme would be conducted under Chairmanship of Additional Secretary/ Joint Secretary of DA&FW with all the States. The physical & financial progress must be uploaded on web-portal on monthly basis by 5th of every month for the preceding month.
- 21.3 It may also be ensured that each micro irrigation installation will be given a unique digital QR code and the same will appear on the web portal of the scheme. The physical/ financial progress report is to be submitted by 5th of next month as per the format at Annexure-III-a and III-b. Biometric registration of beneficiary & geo tagging/referencing should be made compulsory. Krishi Mapper/Mobile App developed by DA&FW shall be used for Geo Tagging/Geo Fencing of farmers' field. The data captured by the App will automatically link with the State MIS portal through API.
- 21.4 Geo-tagged photograph of the installation and the beneficiary acknowledgement will be mandatory for every installation covered under the scheme and shall be made available in the State Portal.
- 21.5 National Committee on Precision Agriculture and Horticulture (NCPAH) will be involved in monitoring and reviewing the progress of scheme at the National

level. NCPAH secretariat will provide necessary logistic support to the Ministry for this purpose and maintain statistical data base/information on various aspects of the Micro Irrigation.

- 21.6 DA&FW will evolve suitable mechanism for concurrent evaluation of implementation of PDMC. DA&FW may also engage suitable agency for conducting state specific/pan-India/ implementation monitoring and/or mid-term/end-term evaluation of the scheme. Defined number of projects/cases selected on scientific sampling basis shall have to be compulsorily taken up for third party monitoring and evaluation by the implementing States. Such study should be carried by establishing accurate baseline data. In general parameters such as water use efficiency, change in use of fertilizer, soil health, change in income of farmers etc. shall be evaluated.
- 21.7 Action plan for monitoring and evaluation will be decided by SLSC at the beginning of every year based on project cost, importance of the project and other parameters, preferably covering all sectors. The State Government will be free to choose any reputed agencies for conducting the monitoring and evaluation work in their states. Requisite fees/cost towards monitoring & evaluation will be met by the state government from the provision of administrative expenses of the scheme. The performance of the states will be reflected in the Outcome Budget document of the respective Ministry/Department.
- 21.8 In order to have cross learnings, the entire thematic activities and outcomes may be documented with the help of ICAR, SAUs for the benefit of stakeholders. Best practices if any, be documented which can be showcased across the States/UTs.

22 Release of Funds

- 22.1 60% of fund will be released as first installment to the States/UTs upon receipt of proposal in the prescribed format along with specified documents including Annual Action Plan approved by State Level Sanctioning Committee (SLSC) along with minutes of SLSC meeting approving the Annual Action Plan of the State. Suggestive formats for Annual Action Plan are enclosed at **Annexure-II**. The State will submit the utilisation certificate, corresponding physical and financial progress report along with requisite information to the DA&FW regularly.
- 22.2 The guidelines issued by the Ministry of Finance, Government of India regarding procedure for release of funds under Centrally Sponsored Schemes shall be followed for release of installments during the financial year.
- 22.3 If a State fails to submit proposal for release of funds with specified documents within reasonable period of time, the balance funds may be re-allocated to better performing States.

23 Administrative Expenses and Contingencies

Administrative expenses may be met on pro-rata basis from the programme following the general guidelines of RKVY at each level to strengthen coordination, scientific planning and technical support for effective implementation. Administrative expenditure for functioning of coordinating agency/Institutions responsible for implementing the scheme, engagement of contractual staff for monitoring and operating the MI System, payments to consultants, outsourcing of specific activities, recurring expenses of various kinds, procurement of android driven smart phones/tablets for uploading of App for geo tagging, staff costs etc. are admissible. However, no permanent employment can be created, nor vehicles can be purchased. States may supplement any administrative expenditure in excess of the provisions of RKVY Guidelines from their own resources.

Recommended norms for use of treated sewage quality for specified activities at point of use

S.N	Parameter	Toilet flushing	Fire Protection	Vehicle Exterior washing	Non-contact impoundments	Landscaping, Horticulture & Agriculture			
						Horticulture, Golf course	Crops		
							Non edible Crops	Crops which are eaten	
								Raw	Cooked
1	Turbidity (NTU)	<2	<2	<2	<2	<2	AA	<2	AA
2	SS	nil	Nil	Nil	Nil	nil	30	nil	30
3	TDS	2100							
4	pH	6.5 to 8.3							
5	Temperature °C	Ambient							
6	Oil & Grease	10	nil	Nil	Nil	10	10	nil	nil
7	Minimum Residual Chlorine	1	1	1	0.5	0	Nil	nil	nil
8	Total Kjeldahl Nitrogen as N	10	10	10	10	10	10	10	10
9	BOD	10	10	10	10	10	20	10	20
10	COD	AA	AA	AA	AA	AA	30	AA	30
11	Dissolved Phosphorous as P	1	1	1	1	2	5	2	5
12	Nitrate Nitrogen as N	10	10	10	5	10	10	10	10
13	Faecal Coliform in 100 ml	nil	Nil	Nil	Nil	nil	230	nil	230
14	Helminthic Eggs/ litre	AA	AA	AA	AA	AA	<1	<1	<1
15	Colour	Colourless	Colourless	Colourless	Colourless	Colourless	AA	Colourless	Colourless
16	Odour	Aseptic which means not septic and no foul odour							

All units in mg/l unless specified; AA-as arising when other parameters are satisfied;
A tolerance of plus 5% is allowable when yearly average values are considered.

Format for Annual Action Plan– Per Drop More Crop (PDMC)

A) Micro Irrigation:

(i) District wise details:

Sr. No.	District (Ensure to cover all Aspirational Districts, and Namami Gange Districts)	Drip irrigation						Sprinkler irrigation						Total		
		Field Crops			Horticultural Crops			Field Crops			Horticultural Crops					
		Area	Farmers to be benefitted	Cost	Area	Farmers to be benefitted	Cost	Area	Farmers to be benefitted	Cost	Area	Farmers to be benefitted	Cost	Area	Farmers to be benefitted	Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=3+6+9+12	16=4+7+10+13	17=5+8+11+14
						Note: Major Crop wise details of both field & horticultural crops may be mentioned										

(ii) State Summery (MI):

Rs. in Lakh								
S No	Activity	Area (ha)	No of Farmers to be benefitted	Subsidy			Farmers Contribution	Total Cost
				GOI Share	Matching State Share	Total		
1	Drip Irrigation system							
2	Sprinkler Irrigation system							
Total A								
Administrative cost- B								
Total A+B								
% MI cost to total AAP			%					

B) Other Interventions (Optional)- Linked with Micro irrigation

(i) District wise details:

Rs. in lakh

SN	District	Activity1				Activity2.....
		Quantity	Unit	Unit rate(Rs.)	cost	

(ii) State Summary (OI):

Rs. in Lakh

S N	Activity	Quantity	Unit	Unit rate	No of Farmers to be benefitted	Subsidy			Farmers contribution	Total Cost
						GOI Share	Matching State Share	Total		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Total A										
Administrative cost- B										
Total A+B										
% OI cost to total AAP						%				

Format for Physical Progress Monitoring Report for Per Drop More Crop (Micro Irrigation)

	Name of the State:					Period of the report:								
	<i>Area in hectare:</i>													
Name of District	Physical Target				Total Physical Target	Physical Achievement				Total Physical Achievement	% Achievement			
	Horticulture		Agriculture			Horticulture		Agriculture						
	Drip	Sprinkler	Drip	Sprinkler		Drip	Sprinkler	Drip	Sprinkler					

Annexure-III b

Format for Financial Progress Monitoring Report for Per Drop More Crop (Micro Irrigation)

Name of District	Name of the State:								Period of the report:									
	Rs. in Lakh																	
	Financial Target								Financial Achievement									% Achieveme nt
	Horticulture		Agriculture		Trainin g	Seminar / Exhibiti on	Schem e Admin . Cost	Total Financi al Target	Horticulture		Agriculture		Trainin g	Seminar / Exhibiti on	Schem e Admin . Cost	Total Financial Achieveme nt		
	Dri p	Sprinkl er	Dri p	Sprinkl er					Dri p	Sprinkl er	Dri p	Sprinkl er						

Annexure- IV a

Drip Irrigation Technology - Indicative Bill of Quantities for 0.2 ha at farmer's field

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5x0.6	1.2x0.6
Control Unit																	
1	Screen filter 10 m ³ /hr/ Disc filter	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
2	Ventury& manifold (1 1/2")	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
3	Air release Valve 1"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
4	Non Return Valve - 1.5"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly - 1.5"x1.5"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
Field Unit																	
6	PVC Pipe 50 mm, class-III; 6 kg/cm ²	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48
7	Lateral 12 mm, Class II ; 2.5 kg/ cm ²	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010	1347	20	27	32	40
8	Emitting Pipe 12 mm; Class II: (0.6 m x 1 to 4lph)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	808	1122	1347	1683
9	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020	907	0	0	0	0
10	Control Valve 50 mm	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
11	Flush Valve 50 mm	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
12	Throttle Valve - 1.5"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
13	Fittings/installation & Accessories @5%	set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Annexure- IV b

Drip Irrigation Technology - Indicative Bill of Quantities for 0.4 ha at farmer's field

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12 X 12	10 X 10	9 x 9	8 X 8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X 3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X 0.6	1.5 X 0.6	1.2 X 0.6
Control Unit																	
1	Screen filter 10 m ³ /hr/ Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ventury& manifold (1 1/2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Air release Valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Non Return Valve - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly - 1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Field Unit																	
6	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/ cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0
7	PVC Pipe 50 mm, class-III; 6 kg/ cm ²	m	96	96	96	96	96	96	96	96	66	66	66	96	96	96	96
8	Lateral 12mm, Class II; 2.5 kg/ cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	1616	2020	2693	38	53	64	79
9	Emitting Pipe 12 mm; Class II: (0.6 m x 1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1616	2245	2693	3367
10	Lateral 12 mm, Class II ; 2.5 kg/ cm ²	m	339	406	452	508	677	813	1016	1355	0	0	0	0	0	0	0
11	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	113	163	201	255	453	653	510	907	1293	2010	1796	0	0	0	0
12	Control Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
13	Control Valve 50 mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Flush Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
15	Flush Valve 50 mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Throttle Valve - 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17	Throttle Valve - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
18	Fittings/Installation& Accessories @5%	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Annexure- IV c

Drip Irrigation Technology - Indicative Bill of Quantities for 1.0 ha at farmer's field

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12 X 12	10 X 10	9 x 9	8 X 8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X 3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X 0.6	1.5 X 0.6	1.2 X 0.6
Control Unit																	
1	Screen filter 20 / 25 m ³ / hr/ Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ventury & manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Air release Valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Non Return Valve - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly - 1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Field Unit																	
6	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/ cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	54	54	54	54	54	54	54	54
7	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/ cm ²	m	0	0	0	0	54	156	156	102	102	102	102	102	102	102	102
8	PVC Pipe 50 mm, class-III; 6 kg/ cm ²	m	156	156	156	156	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/ cm ²	m	833	1000	1111	1250	1667	2000	2500	3333	4000	5000	6667	60	83	100	125
10	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.6 m x 1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4040	5611	6733	8417
11	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	278	400	494	625	1111	1600	1275	2267	3232	5050	4489	0	0	0	0
12	Control Valve 75 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
13	Control Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
14	Control Valve 50 mm	No.	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2	2
15	Flush Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2
16	Flush Valve 50 mm	No.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Throttle Valve - 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Fittings/Instalation& Accessories @5%	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Annexure- IV d

Drip Irrigation Technology - Indicative Bill of Quantities for 2.0 ha at farmer's field

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12 X 12	10 X 10	9 x 9	8 X 8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X 0.6	1.5 X 0.6	1.2 X 0.6
Control Unit																	
1	Screen filter 20 / 25 m ³ / hr/ Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ventury& manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Air release Valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Non Return Valve - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly - 1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Field Unit																	
6	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/ cm ²	m	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
7	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/ cm ²	m	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
8	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/ cm ²	m	1850	2130	2350	2600	3500	4200	5200	6900	8250	11000	14000	120	150	170	200
9	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.6 m x 1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	11500	13600	17000
10	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	600	800	1000	1300	2300	3300	2600	4800	6600	10400	9000	0	0	0	0
11	Control Valve 75 mm	No.	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1
12	Control Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
13	Flush Valve 63 mm	No.	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Throttle Valve - 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Fittings/Instalation& Accessories @5%	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Drip Irrigation Technology - Indicative Bill of Quantities for 3.0 ha at farmer's field

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12 X 12	10 X 10	9 x 9	8 X 8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X 3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X 0.6	1.5 X 0.6	1.2 X 0.6
Control Unit																	
1	Screen filter 30 m ³ / hr/ Disc filter	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
2	Screen filter 20 / 25 m ³ / hr/ Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
3	Ventury& manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Air release Valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Non Return Valve - 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
6	Non Return Valve – 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	By-pass Assembly - 2"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Field Unit																	
8	PVC Pipe 90 mm, class-II; 4 kg/ cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90	90	90
9	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/ cm ²	m	0	0	0	0	216	216	216	216	132	132	132	132	132	132	132
10	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/ cm ²	m	216	216	216	216	336	336	336	336	174	174	174	174	174	174	174
11	PVC Pipe 50 mm, class-III; 6 kg/ cm ²	m	336	336	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/ cm ²	m	2500	3000	3333	3750	5000	6000	7500	10000	12120	15150	20200	156	217	260	325
13	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.6 m x 1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12120	16833	20200	25250
14	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	833	1200	1481	1875	3333	2400	3750	6667	9696	15150	13467	0	0	0	0
15	Control Valve 90 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
16	Control Valve 75 mm	No.	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2
17	Control Valve 63 mm	No.	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	Control Valve 50 mm	No.	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Flush Valve 75 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
20	Flush Valve 63 mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Throttle Valve - 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
22	Throttle Valve – 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
23	Fittings/Installation& Accessories @5%	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Drip Irrigation Technology - Indicative Bill of Quantities for 4.0 ha at farmer's field

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12 X12	10 X 10	9 x 9	8 X 8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X 3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X0.6	1.5 X 0.6	1.2 X 0.6
Control Unit																	
1	Screen filter 30 m ³ / hr/ Disc filter	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
2	Screen filter 20/ 25 m ³ /hr/ Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
3	Ventury& manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Air release Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Non Return Valve - 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
6	Non Return Valve – 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	By-pass Assembly - 2"x1.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
8	By-pass Assembly – 1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
Field Unit																	
9	PVC Pipe 90 mm, class-II; 4 kg/ cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138	138	138	138	138
10	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/ cm ²	m	222	222	222	222	222	222	222	222	276	276	276	276	276	276	276
11	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/ cm ²	m	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
12	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/ cm ²	m	3400	4080	4533	5100	6800	8160	10200	13600	16160	20200	26933	180	250	300	375
13	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.6 m x 1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	22000	26950	33100
15	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	1133	1632	2015	2550	4533	4896	7700	9244	12800	20000	17800	0	0	0	0
16	Control Valve 90 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
17	Control Valve 75 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
18	Control Valve 63 mm	No.	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
19	Flush Valve 75 mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Flush Valve 63 mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Throttle Valve - 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
22	Throttle Valve – 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
23	Fittings/Installation& Accessories @5%	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Drip Irrigation Technology- Indicative Bill of Quantities 5.0 ha at farmer's field

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12 X 12	10 X 10	9 x 9	8 X 8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X0.6	1.5 X 0.6	1.2 X 0.6
Control Unit																	
1	Screen filter 30 m ³ / hr/ Disc filter	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
2	Screen filter 20/ 25 m ³ /hr/ Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
3	Ventury& manifold (2 1/2")	No.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Ventury& manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Air release Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Non Return Valve – 2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
7	Non Return Valve – 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	By-pass Assembly – 2.5"x2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	By-pass Assembly - 2"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Field Unit																	
10	PVC Pipe 90 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	114	114	114	114	114	114	114	114	168	168	168	168	168	168	168
11	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	168	168	168	168	168	168	168	168	342	342	342	342	342	342	342
12	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	450	450	450	450	450	450	450	450	456	456	456	456	456	456	456
13	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/cm ²	m	4250	5100	5667	6375	8500	10200	12750	17000	20200	25250	33667	268	373	447	559
14	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.6 m x 1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	28056	33667	42083
15	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	1417	2040	2519	3188	5667	8160	6500	11556	16160	25250	22444	0	0	0	0
16	Control Valve 90 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
17	Control Valve 75 mm	No.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	Control Valve 63 mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	Flush Valve 75 mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Flush Valve 63 mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Throttle Valve – 2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
22	Throttle Valve – 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
23	Fittings/Installation& Accessories @5%	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Annexure- IV h

NEH States-Drip Irrigation Technology - Indicative Bill of Quantities for 0.2 ha at farmer's field

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5x0.6	1.2x0.6
	Control Unit																
1	Screen filter 10 m ³ /hr/ Disc filter	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
2	Ventury& manifold (1 1/2")	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
3	Air release Valve 1"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
4	Non Return Valve - 1.5"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly - 1.5"x1.5"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
6	Field Unit																
7	HDPE Pipe 50 mm; 4 kg/cm ²	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	54	54	54	54
8	Lateral 12 mm, Class II ; 2.5 kg/cm ²	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010	1347	20	27	32	40
9	Emitting Pipe 12 mm; Class II:(0.2-0.3 m x 1 to 2-4 lph)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	808	1122	1347	1683
10	Pressure regulating Emitter/ Dripper 2/ 4/ 8 lph	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020	907	0	0	0	0
11	Control Valve 50 mm	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
12	Control Valve 63 mm	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0	0	0	0
13	Flush Valve 50 mm	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	2	2
14	Throttle Valve - 1.5"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
15	Fittings/Installation& Accessories @5%	set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Annexure- IV i

NEH States- Drip Irrigation Technology- Indicative Bill of Quantities for 0.4 ha at farmer's field

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12 X 12	10 X 10	9x9	8X8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X 3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X 0.6	1.5 X 0.6	1.2 X 0.6
	Control Unit																
1	HDPE Pipe 50 mm; 4 kg/cm ²	m	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
2	HDPE Pipe 63 mm; 4 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0
3	Lateral 12 mm, Class II ; 2.5 kg/cm ²	m	339	406	452	508	677	813	1016	1355	0	0	0	0	0	0	0
4	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	1616	2020	2693	38	53	64	79
5	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.2-0.3 m x 1 to 2-4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1616	2245	2693	3367
6	Pressure regulating Emitter/ Dripper 2/ 4/ 8 lph	No.	113	163	201	255	453	490	765	1360	1306	2010	3627	0	0	0	0
7	Control Valve 50 mm	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	4	4
8	Control Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
9	Flush Valve 50 mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4
10	Air release Valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
11	Non Return Valve - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
12	Throttle Valve - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
13	Screen filter 10 m ³ / hr/ Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	By-pass Assembly - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Ventury& manifold - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Fittings/Installation& Accessories	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Annexure- IV j

NEH States - Drip Irrigation Technology- Indicative Bill of Quantities for 1.0 ha at farmer's field

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12 X 12	10 X10	9x9	8X8	6 X 6	5 X5	4 X 4	3 X3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5X 1.5	2.5X0.6	1.8X0.6	1.5 X 0.6	1.2X0.6
	Control Unit																
1	HDPE Pipe 40 mm; 6 kg/cm ²	m	172	172	172	172	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	HDPE Pipe 50 mm; 4 kg/cm ²	m	0	0	0	0	60	172	172	172	172	172	172	0	0	0	0
3	HDPE Pipe 63 mm; 4 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	60	60	60	60	118	118	118	118
4	HDPE Pipe 75 mm; 4 kg/cm ²	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62	62	62	62
5	Lateral 12 mm, Class II ; 2.5 kg/cm ²	m	980	1150	1300	1400	1800	2000	2500	3333	0	0	0	0	0	0	0
6	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	4040	5050	6733	60	83	100	125
7	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.2-0.3 m x 1 to 2-4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4040	5611	6733	8717
8	Pressure regulating Emitter/ Dripper 2/ 4/ 8 lph	No.	350	440	540	650	1150	1224	1913	3400	3232	5050	9067	0	0	0	0
9	Control Valve 40 mm	No.	10	10	10	10	0	0	0	0	7	7	7	0	0	0	0
10	Control Valve 50 mm	No.	0	0	0	0	10	10	10	0	3	3	3	4	4	4	4
11	Control Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	1	1	1
12	Control Valve 75 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
13	Flush Valve 50 mm	No.	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	4	4	4	4
14	Flush Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1
15	Air release Valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Non Return Valve - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Throttle Valve - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Screen filter 10 m3/ hr/ Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
19	By-pass Assembly - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Ventury& manifold - 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Fittings/Installation& Accessories	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Annexure- IV k

NEH States-Drip Irrigation Technology - Indicative Bill of Quantities for 2.0 ha at farmer's field

SN	Component Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5 X 0.6	1.2x0.6
1	HDPE Pipe 50 mm; 4 kg/cm ²	m	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	165	120	120	120	120
2	HDPE Pipe 63mm; 4 kg/cm ²	m	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	80	80	80	80
3	HDPE Pipe 75mm; 4 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90
4	Lateral 12 mm, Class II ; 2.5 kg/cm ²	m	1850	2130	2350	2600	3500	4200	5200	6900	0	0	0	0	0	0	0
5	Lateral 16 mm Class II, 2.5 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	8400	11400	14600	120	150	170	200
6	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.2-0.3 m x 1 to 2-4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	11500	13600	17000
7	Pressure regulating Emitter/ Dripper 2/ 4/ 8 lph	No.	600	800	1000	1300	2300	2448	3825	6800	6600	10400	18133	0	0	0	0
8	Control Valve 50 mm	No.	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	8	8	8	8
9	Control Valve 63 mm	No.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4
10	Control Valve 75 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
11	Flush Valve 50 mm	No.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	8	8	8
12	Flush Valve 63 mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	4	4	4	4
13	Air Release Valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Non Return Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Throttle Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
16	Throttle Valve 2"	No.	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
17	Screen Filter 10 m ³ /hr/ Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
18	Screen Filter 30 m ³ /hr/ Disc filter	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
19	By-pass Assembly-1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Venturi & Manifold 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
21	Fittings/Installation& Accessories	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

NEH States- Drip Irrigation Technology- Indicative Bill of Quantities 3.0 ha at farmer's field

SN	Component Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5 X 0.6	1.2x0.6
1	HDPE Pipe 90mm; 4 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	105	105	105	0	0	0	0
2	HDPE Pipe 75mm; 4 kg/cm ²	m	0	0	0	0	240	240	240	240	144	144	144	105	105	105	105
3	HDPE Pipe 63mm; 4 kg/cm ²	m	240	240	240	240	380	380	380	380	190	190	190	150	150	150	150
4	HDPE Pipe 50 mm; 4 kg/cm ²	m	380	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	200	200	200	200
5	Lateral 16 mm Class II, 2.5 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	12120	15150	20200	156	217	260	325
6	Lateral 12 mm, Class II ; 2.5 kg/cm ²	m	2500	3000	3333	3750	5000	6000	7500	10000	0	0	0	0	0	0	0
7	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.2-0.3 m x 1 to 2-4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12120	16833	20200	25250
8	Pressure regulating Emitter/ Driller 2/ 4/ 8 lph	No.	833	1200	1481	1875	3333	3672	5738	10200	9696	15150	26933	0	0	0	0
9	Control Valve 90 mm	No	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
10	Control Valve 75 mm	No	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	1	1	1	1
11	Control Valve 63 mm	No.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	2	2	2	2
12	Control Valve 50 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8
13	Flush Valve 75mm	No.	3	3	3	3	3	3	3	3	5	5	5	0	0	0	0
14	Flush Valve 63mm	No.	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	1	1	1	1
15	Flush Valve 50mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4
16	Air Release Valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Non Return Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
18	Non Return Valve 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
19	Throttle Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
20	Throttle Valve 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
21	Screen Filter 30 m ³ /hr/ Disc filter	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
22	Screen Filter 20/25 m ³ /hr/ Disc filter	No.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
23	Screen Filter 10 m ³ /hr/ Disc filter	No.	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
24	By-pass Assembly-2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
25	Venturi & Manifold 2 "	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
26	Fittings/Installation & Accessories	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

NEH States- Drip Irrigation Technology- Indicative Bill of Quantities 4.0 ha at farmer's field

SN.	Component Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5 X 0.6	1.2x0.6
1	HDPE Pipe 90mm; 4 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	160	160	160	150	150	150	150
2	HDPE Pipe 75mm; 4 kg/cm ²	m	245	245	245	245	245	245	245	245	300	300	300	300	300	300	300
3	HDPE Pipe 63mm; 4 kg/cm ²	m	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275
4	HDPE Pipe 50 mm; 4 kg/cm ²	m	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167
5	Lateral 16 mm Class II, 2.5 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	16160	20200	26933	180	250	300	375
6	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.2-0.3 m x 1 to 2-4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	22000	26670	33100
7	Lateral 12 mm, Class II ; 2.5 kg/cm ²	m	3400	4080	4533	5100	6800	8160	10200	13600	0	0	0	0	0	0	0
8	Pressure regulating Emitter/ Driller 2/ 4/ 8 lph	No.	1133	1632	2015	2550	4533	4896	7700	13600	12800	20000	35911	0	0	0	0
9	Control Valve 90 mm	No.	0	2	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2	2
10	Control Valve 75 mm	No.	0	0	0	0	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
11	Control Valve 63mm	No.	5	5	5	5	3	3	3	3	8	8	8	5	5	5	5
12	Control Valve 50mm	No.	3	3	3	3	2	2	2	2	4	4	4	3	3	3	3
13	Flush Valve 75mm	No.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	1	1	1
14	Flush Valve 63mm	No.	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
15	Flush Valve 50mm	No.	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	2
16	Air Release Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Non Return Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
18	Non Return Valve 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
19	Non Return Valve 2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
20	Throttle Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Throttle Valve 2"	No.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
22	Throttle Valve 2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
23	Screen Filter 30 m ³ /hr/ Disc filter	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
24	Screen Filter 20/25 m ³ /hr/ Disc filter	No.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
25	Screen Filter 10 m ³ /hr/ Disc filter	No.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	By-pass Assembly-2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
27	By-pass Assembly-1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
28	Venturi & Manifold 2 "	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
29	Fittings/Installation & Accessories	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

NEH States- Drip Irrigation Technology- Indicative Bill of Quantities 5.0 ha at farmer's field

SN	Component Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5 X 0.6	1.2x0.6
1	HDPE Pipe 90mm; 4 kg/cm ²	m	124	124	124	124	124	124	124	124	180	180	180	180	180	180	180
2	HDPE Pipe 75mm; 4 kg/cm ²	m	180	180	180	180	180	180	180	180	372	372	372	375	375	375	375
3	HDPE Pipe 63mm; 4 kg/cm ²	m	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	310	310	310	310
4	HDPE Pipe 50 mm; 4 kg/cm ²	m	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	212	200	200	200	200
5	Lateral 16 mm Class II, 2.5 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	25250	33667	268	373	447	559
6	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.2-0.3 m x 1 to 2-4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	28056	33667	42083
7	Lateral 12 mm, Class II ; 2.5 kg/cm ²	m	4250	5100	5667	6375	8500	10200	12750	17000	0	0	0	0	0	0	0
8	Pressure regulating Emitter/ Dripper 2/ 4/ 8 lph	No.	1417	2040	2519	3188	5667	6120	9563	17000	16610	25250	44889	0	0	0	0
9	Control Valve 90 mm	No.	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
10	Control Valve 75 mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2
11	Control Valve 63 mm	No.	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12	Control Valve 50 mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
13	Flush Valve 75 mm	No.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
14	Flush Valve 63 mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
15	Flush Valve 50 mm	No.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
16	Air Release Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
17	Non Return Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
18	Non Return Valve 2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
19	Throttle Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Throttle Valve 2"	No.	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
21	Throttle Valve 2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
22	Screen Filter 30m ³ /hr/ Disc filter	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
23	Screen Filter 20/25 m ³ /hr/ Disc filter	No.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
24	Screen Filter 10 m ³ /hr/ Disc filter	No.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	By-pass Assembly-2.5"	No.	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
26	By-pass Assembly-2"	No.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Venturi & Manifold 2 "	No.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Fittings/Installation & Accessories	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Portable Sprinkler Irrigation System

Using 63 mm coupler								
SN	Components/ Area (Ha)	Unit	0.4	1	2	3	4	5
1	HDPE Pipes with Quick coupled (Pipe of Class II; 3.2 kg/cm ² IS:17425:2020 63 mm diameter & 6m long)	No	18	30	41	NA	NA	NA
2	Quick coupled HDPE 63mm Foot batten Assembly ;	No	3	5	9	NA	NA	NA
3	GI/PP/ PVC Riser Pipe 3/4" diameter x 75 cm long	No	3	5	9	NA	NA	NA
4	Sprinkler Nozzles (1.7 to 2.8 kg/cm ²) ;IS 12232 Part I Brass/Plastic	No	3	5	9	NA	NA	NA
5	Quick coupled HDPE Bend with Coupler 90 ⁰ (63/50 mm) ;	No	1	1	1	NA	NA	NA
6	Quick coupled HDPE Pump Connecting Nipple 63 mm;	No	1	1	1	NA	NA	NA
7	Quick coupled HDPE End Plug (63 mm) ;	No	1	2	2	NA	NA	NA
8	Quick coupled HDPE Tee with Coupler (63mm) ;	No	1	1	1	NA	NA	NA
Using 75 mm coupler								
SN	Components/ Area (Ha)	Unit	0.4	1	2	3	4	5
1	HDPE Pipes with Quick coupled (Pipe of Class I; 2.5 kg/cm ² IS:17425:2020, 75 mm diameter & 6m long)	No	NA	30	41	NA	NA	NA
2	Quick coupled HDPE 75mm Foot batten Assembly;	No	NA	5	9	NA	NA	NA
3	GI/PP/ PVC Riser Pipe 3/4" diameter x 75 cm long	No	NA	5	9	NA	NA	NA
4	Sprinkler Nozzles (1.7 to 2.8 kg/cm ²) ;IS 12232 Part I Brass/Plastic	No	NA	5	9	NA	NA	NA
5	Quick coupled HDPE Bend with Coupler 90 ⁰ (75 mm) ;	No	NA	1	1	NA	NA	NA
6	Quick coupled HDPE Pump Connecting Nipple , 75 mm;	No	NA	1	1	NA	NA	NA
7	Quick coupled HDPE End Plug (75 mm) ;	No	NA	2	2	NA	NA	NA
8	Quick coupled HDPE Tee with Coupler (75 mm);	No	NA	1	1	NA	NA	NA
Using 90 mm coupler								
SN	Components/ Area (Ha)	Unit	0.4	1	2	3	4	5
1	HDPE Pipes with Quick coupled (Pipe of Class I; 2.5 kg/cm ² ; IS:17425:2020, 90 mm diameter & 6m long)	No	NA	NA	NA	41	52	58
2	Quick coupled HDPE 90mm Foot batten Assembly ;	No	NA	NA	NA	11	14	16
3	GI/PP/ PVC Riser Pipe 3/4" diameter x 75 cm long	No	NA	NA	NA	11	14	16
4	Sprinkler Nozzles (1.7 to 2.8 kg/cm ²) ;IS 12232 Part I Brass/Plastic	No	NA	NA	NA	11	14	16
5	Quick coupled HDPE Bend with Coupler 90 ⁰ (90 mm) ;	No	NA	NA	NA	2	2	4
6	Quick coupled HDPE Pump Connecting Nipple, 90 mm;	No	NA	NA	NA	1	1	1
7	Quick coupled HDPE End Plug (90 mm) ;	No	NA	NA	NA	2	2	2
8	Quick coupled HDPE Tee with Coupler (90 mm);	No	NA	NA	NA	1	1	2

Note: In the cases of area up to 2 ha, the beneficiary may be allowed for using higher dia HDPE pipe as per his choice. However, financial assistance may be allowed as per the indicative Unit cost for 75 mm dia HDPE pipe.

Annexure-VI

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Micro Sprinkler Irrigation System

SN	Components/ Area (Ha)	5mx5m						3m x 3m						
		Unit	0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
1	PVC Pipe 90 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	160	0	0	0	0	0	150
2	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	30	54	80	100	252	600	30	54	100	140	220	520
3	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	66	102	150	180	402	0	66	102	150	180	380	0
4	20 mm LLDPE plain laterals, Class II; 2.5 kg/cm ²	m	0	2000	4000	6000	8000	10000	0	3350	6660	10000	13330	16600
5	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/cm ²	m	800	0	0	0	0	0	1336	0	0	0	0	0
6	Micro sprinkler Set	No.	160	400	800	1200	1600	2000	444	1111	2222	3333	4444	5556
7	Control Valve 90 mm	No.	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	1
8	Control Valve 75 mm	No.	1	1	1	1	4	4	1	1	1	1	4	4
9	Control Valve 63 mm	No.	1	1	4	4	0	0	1	1	4	4	0	0
10	Flush Valve 75 mm	No.	0	0	0	0	4	6	0	0	0	0	4	4
11	Flush Valve 63 mm	No.	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0
12	Flush Valve 50 mm	No.	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Air release Valve - 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Non Return Valve - 2"	No.	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
15	Non Return Valve - 2.5"	No.	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
16	Throttle Valve - 2"	No.	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
17	Throttle Valve - 2 .5"	No.	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
18	Screen filter 30 m ³ / hr	No.	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
19	Screen filter 20/25 m ³ / hr	No.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
20	By-pass Assembly - 2 .5"x2"	No.	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	By-pass Assembly - 2"x1,5"	No.	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
22	Venturi & manifold - 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
23	Fittings/Installation & Accessories		5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Annexure-VII

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Mini Sprinkler Irrigation System

SN	Components/ Area (Ha)	Unit	10x10						8x8					
			0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0
1	PVC Pipe 90 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	0	0	80	210	235	310	0	0	80	210	235	310
2	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	30	60	150	320	420	480	30	60	150	320	420	480
3	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	66	110	0	0	0	0	66	110	0	0	0	0
4	25/32 mm LLDPE plain laterals, 2.5 kg/cm ² -Class II	m	400	1000	2000	3000	4000	5000	500	1250	2500	3750	5000	6250
5	Mini Sprinkler Head/ Nozzle	No.	40	100	220	300	400	500	63	156	312	470	625	780
6	Riser Assembly (MS/Plastic)	No.	40	100	220	300	400	500	63	156	313	470	625	781
7	Control Valve 90 mm	No.	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
8	Control Valve 75 mm	No.	0	1	1	1	4	4	0	1	2	4	4	4
9	Control Valve 63 mm	No.	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0
10	Control Valve 32 mm	No.	0	20	34	52	68	84	0	24	36	54	72	90
11	Flush Valve 75 mm	No.	0	0	1	4	4	4	0	1	2	4	4	4
12	Flush Valve 63 mm	No.	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13	Air release Valve - 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Non Return Valve - 2.5"	No.	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
15	Non Return Valve - 2"	No.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
16	Throttle Valve 3"	No.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
17	Throttle Valve - 2.5"	No.	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0
18	Throttle Valve - 2"	No.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
19	Screen filter 30 m ³ / hr	No.	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1
20	Screen filter 20/25 m ³ /hr	No.	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
21	By-pass Assembly - 2"x1.5"	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
22	By-pass Assembly - 1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0
23	Venturi & manifold - 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
24	Fittings/Installation & Accessories	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: Installation of PVC or HDPE pipes for main/sub mains may be the choice of beneficiary. However, financial assistance will be limited to the PVC pipe and differential amount to be borne by beneficiary.

Annexure-VIII

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Semi Permanent Sprinkler Irrigation System

SN	Particulars/ ha area	0.4	1	2	3	4	5
1	PVC Pipe 90 mm, class-II; 4 kg/cm ²	0	0	0	0	0	173
2	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/cm ²	0	0	110	135	156	0
3	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/cm ²	96	154	273	340	395	440
4	PVC Pipe 25 mm Class-V; 10 Kg/cm ²	350	950	1904	0	0	0
5	32 mm LLDPE plain laterals, 2.5 kg/cm ² - Class II	0	0	0	3006	4000	5014
6	Control Valve 63 mm	1	1	2	2	2	2
7	By-pass Assembly - 2 .5" x 2"	1	1	1	1	1	1
8	Control Valve 25 mm	12	20	42	51	80	88
9	Sprinkler Nozzles (1.7 to 2.8 kg/cm ²) ;IS 12232 Part I Brass/Plastic	12	12	12	12	12	12
10	Screen filter 20/25 m ³ /hr	1	1	1	1	1	1
11	Fittings/Installation & Accessories	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Annexure-IX

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Rain-gun Sprinkler Irrigation System

Using 63 mm coupler						
SN	Components/ Area (ha)	1	2	3	4	5
1	HDPE Pipes with Quick coupled (Pipe of Class 3; 4 kg/cm ² IS:17425:2020 63 mm diameter & 6m long)	30	NA	NA	NA	NA
2	Raingun Sprinkler 1.25" female threaded connection	1	N.A	N.A	N.A	N.A
3	Tripod Stand with adapter to feeder line 1.25"x1.5 m	1	N.A	N.A	N.A	N.A
4	Quick coupled HDPE Bend with Coupler 90° (63/50 mm) ;	1	N.A	N.A	N.A	N.A
5	Quick coupled HDPE Pump Connecting Nipple 63 mm;	1	N.A	N.A	N.A	N.A
6	Quick coupled HDPE End Plug (63 mm) ;	1	N.A	N.A	N.A	N.A
7	Quick coupled HDPE Tee with Coupler (63mm) ;	1	N.A	N.A	N.A	N.A
8	Screen filter 20/25 m3/hr	1	N.A	N.A	N.A	N.A
9	By-pass Assembly - 2"x1,5"	1	N.A	N.A	N.A	N.A
Using 75 mm coupler						
SN	Components/ Area (ha)	1	2	3	4	5
1	HDPE Pipes with Quick coupled (Pipe of Class 3; 4 kg/cm ² IS:17425:2020 75 mm diameter & 6m long)	30	42	NA	NA	NA
2	Raingun Sprinkler 1.25" female threaded connection	1	1	N.A	N.A	N.A
3	Tripod Stand with adapter to feeder line 1.25"x1.5 m	1	1	N.A	N.A	N.A
4	Quick coupled HDPE Bend with Coupler 90° (75 mm) ;	1	1	N.A	N.A	N.A
5	Quick coupled HDPE Pump Connecting Nipple , 75 mm;	1	1	N.A	N.A	N.A
6	Quick coupled HDPE End Plug (75 mm) ;	1	1	N.A	N.A	N.A
7	Quick coupled HDPE Tee with Coupler (75 mm);	1	1	N.A	N.A	N.A
8	Screen filter 20/25 m3/hr	1	1	N.A	N.A	N.A
9	By-pass Assembly - 2"x1,5"	1	1	N.A	N.A	N.A
Using 90 mm coupler						
SN	Components/ Area (ha)	1	2	3	4	5
1	HDPE Pipes with Quick coupled (Pipe of Class 3; 4 kg/cm ² IS:17425:2020 90 mm diameter & 6m long)	NA	NA	45	52	60
2	Raingun Sprinkler 1.5" female threaded connection	N.A	N.A	1	1	1
3	Tripod Stand with adapter to feeder line 1.5"x1.5 m	N.A	N.A	1	1	1
4	Quick coupled HDPE Bend with Coupler 90° (90 mm);	N.A	N.A	1	1	1
5	Quick coupled HDPE Pump Connecting Nipple, 90 mm;	N.A	N.A	1	1	1
6	Quick coupled HDPE End Plug (90 mm) ;	N.A	N.A	1	1	1
7	Quick coupled HDPE Tee with Coupler (90 mm);	N.A	N.A	1	1	1
8	Screen filter 30 m3/ hr	N.A	N.A	0	1	1
9	Screen filter 20/25 m3/hr	N.A	N.A	1	0	0
10	By-pass Assembly - 2"x1,5"	N.A	N.A	1	0	0
11	By-pass Assembly - 2 .5"x2"	N.A	N.A	0	1	1

Note: The above items/components are indicative for calculation of subsidy. Deviation if any, from the above items/components is subject to ceiling of cost and differential amount to be borne by the beneficiary.

Annexure X

Water Quality Criteria in Relation to Clogging

The criteria for water quality for conventional irrigation is different from the one meant for irrigating through drip. The clogging hazard with different water qualities are presented below:

Extent of Clogging on the Basis of Quality of Irrigation Water

Quality of Water	Clogging Hazard		
	Slight	Moderate	Severe
Suspended Solids (ppm)	<50	50-100	>100
pH	<7.0	7.0-8.0	>8.0
TDS (ppm)	<500	500-2000	>2000
Manganese (ppm)	<0.1	0.1-1.5	>1.5
Iron (ppm)	<0.1	0.1-1.5	>1.5
Calcium and Magnesium (ppm)	<20	20-40	>40
Hydrogen sulphide (ppm)	<0.5	0.5-2.0	>2.0
Bacterial population (No./ml)	<10000	10000-50000	>50000

Source: Dasberg and Dani, 1999

Guidelines for Selection of Filter

Water Quality	Type of Filter	Remarks
Good without any physical and biological impurities.	Screen	Screen filters shall be suggested only if the physical impurity do not call for cleaning of filter element more than once a day
Water sources with heavy physical and biological impurities.	Only screen filter will not be sufficient	Additional filter is required depending upon the type of water impurity
Water sources with sand and other heavier particles.	Hydro cyclone Separator or Hydro cyclone of matching flow capacity.	Disc/Screen Filter shall be provided after hydro cyclone
Water sources with heavy of Biological impurities such as Algae, trash and other debris.	Media / sand filter	Disc/screen filter should be provided after Media filter
Water sources with heavy sand and other biological impurities such as Algae and trash.	Combination of Hydro Cyclone followed by a Sand Filter	Screen/disc filter should be after sand filter

Indicative Price of Optional Components

SN	Optional Component	Appr. Price (Rs)
1	Sand Filter with back wash assembly IS 14606	
a	10 m ³ /hr x 1.5"	9775
b	20 m ³ /hr x 2"	13225
c	25 m ³ /hr x 2"	16100
d	30 m ³ /hr x 2.5"	18400
2	Hydro cyclone Filter IS 14743	
a	20 m ³ /hr x 2"	4025
b	25 m ³ /hr x 2"	4600
c	30 m ³ /hr x 2.5"	6325
3	Fertilizer Tank with Assembly IS 14483 - Part III	
a	30 litres	3220
b	60 litres	5750
4	Winder	
	Drip Line Winder	2000

Annexure- XIII

Other Interventions to be provided as optional, if and only if a farmer opted to install micro-irrigation System in his/her field

SN	Activities	Cost Norms
1	Water harvesting system for individuals	50% of cost (Construction cost - Rs. 125 for plain/ Rs. 150 per cum for hilly areas) limited to Rs. 75000 for plain areas and Rs. 90000 for hilly areas including lining. For smaller size of the ponds/ dug wells, cost admissible on pro rata basis. Cost for non-lined ponds/tanks will be 30% less.
2	Construction of Tube wells / Bore wells (Shallow / Medium) only in areas which are not categorized under over-exploited, critical & semi- critical zones by Central Ground Water Board.	50% of the total cost of installation limited to Rs. 25,000 / - per unit
3	Restoration / Renovation of small tank	50% of the cost of renovation limited to Rs. 15,000 / - per unit
4	Recharge of defunct bore well	50% of the cost of recharging limited to Rs. 5000 / - per unit
5	Pipe/pre-cast distribution system	50% of the cost of system limited to Rs. 10,000 / - per ha
6	Water Lifting Devices (Electric, Diesel, wind / Solar)	50% of the cost of installation limited to Rs. 15,000/ - per electric / diesel unit and Rs. 50,000/- per solar / wind unit
7	Petrol Irrigation Pumps- up to 15 hp	Rs. 10000/unit or 50% of the cost of the system (including installation) whichever is less.

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 803]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2017/फाल्गुन 30, 1938

No. 803]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2017/PHALGUNA 30, 1938

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2017

का.आ. 893(अ).— सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुत दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और जबकि भारत सरकार में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (जिसे इसमें इसके पश्चात मंत्रालय कहा गया है) अनुमोदित वित्त पोषण पद्धति के अनुसार राज्य सरकार अथवा मंच राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन नोडल विभागों (जिसे इसमें इसके पश्चात विभाग कहा गया है) को अनुदान सहायता प्रदान करके केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई स्कीम (पीएमकेएसवाई) (जिसे इसमें इसके पश्चात स्कीम कहा गया है) के "प्रति बूंद अधिक फसल घटक" का कार्यान्वयन कर रहा है।

और जबकि स्कीम के अधीन दी जा रही अनुदान सहायता राज्य नोडल अभिकरणों अथवा रजिस्ट्रीकृत अथवा पैनलीकृत कम्पनियों (जिसे इसमें इसके पश्चात कार्यान्वयन अभिकरण कहा गया है) के माध्यम से किसानों (जिसे इसमें इसके पश्चात लाभार्थी कहा गया है) को सहायता प्राप्त सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियां तथा अन्य फायदे अथवा अन्य सेवाएं प्रदान करने के लिए है।

और जबकि स्कीम के अधीन प्रदान किए गए फायदों में भारत की संचित निधि से उपगत पूर्ण अथवा आंशिक आवर्ती व्यय अंतर्बलित है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करती हैं, अर्थात्:-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे अथवा आधार अधिप्रमाणन करवाए।

(2) इस स्कीम के अधीन फायदे प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति, जिसके पास आधार संख्या नहीं है अथवा जिसने आधार के लिए नामांकन नहीं करवाया है, परंतु वह इस स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने का इच्छुक है, के लिए 31.12.2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना आवश्यक है परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार आधार अधिप्राप्त करने का हकदार हो और ऐसा व्यक्ति आधार के लिए नामांकन करवाने के लिए किसी भी आधार नामांकन केंद्र (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध सूची) पर जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार कार्यान्वयन अभिकरणों राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक संबंधित विभाग, जो किसी व्यक्ति से आधार प्रस्तुत करने की अपेक्षा करता है, से अपेक्षा की जाती है कि वह उन फायदाग्राहियों को आधार नामांकन सुविधा प्रदान करे जिन्होंने आधार के लिए अभी तक नामांकित नहीं किया है और यदि संबद्ध ब्लॉक अथवा तालुका अथवा तहसील में कोई भी आधार नामांकन केंद्र स्थित नहीं है तो राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों में स्कीम के कार्यान्वयन से संबंधित भारसाधक विभाग कार्यान्वयन अभिकरण के माध्यम से अपेक्षित है कि वह भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के वर्तमान रजिस्ट्रार के सहयोग से अथवा स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बनकर सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं प्रदान करे।

परन्तु यह कि उस व्यक्ति को आधार समनुदेशित किए जाने के समय तक उक्त स्कीम के अधीन फायदा निम्नलिखित पहचान दस्तावेज प्रस्तुत करने के अधीन रहते हुए ऐसे व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा, अर्थात:-

(क) (i) आधार नामांकन पर्ची, यदि हिताधिकारी ने आधार के लिए नामांकन दिया है;

अथवा

(ii) हिताधिकारी द्वारा पैरा-2 के उप पैरा (ख) में यथा विनिर्दिष्ट आधार नामांकन के लिए किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) (i) मतदाता पहचान पत्र; अथवा (ii) स्थाई खाता संख्यांक (पैन) कार्ड; अथवा (iii) पासपोर्ट; अथवा (iv) राशन कार्ड; अथवा (v) सरकारी कर्मचारी का आईडी कार्ड; अथवा (vi) बैंक/पोस्ट ऑफिस पासबुक फोटो के साथ; (vii) मनरेगा कार्ड; अथवा (viii) किसान फोटो पासबुक; अथवा (ix) मोटर अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अंतर्गत अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; अथवा (x) सरकारी लैटर हैड पर किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा तहसीलदार द्वारा जारी ऐसे सदस्य की फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र; अथवा (xi) राज्य सरकार अथवा संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अन्य कोई दस्तावेज;

परन्तु यह और कि इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा उपयुक्त दस्तावेज की जांच की जाएगी।

2. इस स्कीम के अधीन हिताधिकारियों को सुविधाजनक व बाधामुक्त फायदे प्रदान करने के लिए अभिकरणों राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन का भारसाधक संबंधित विभाग सभी आवश्यक व्यवस्थाएं, जिनमें निम्नलिखित भी हैं, करेंगे अर्थात:

(क) इस स्कीम के अधीन आधार की आवश्यकता के बारे में हिताधिकारियों को जागरूक बनाने के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से मीडिया व्यष्टिक सूचना के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि आवेदक ने नामांकन नहीं

करवाया है तो उन्हें 31.12.2017 तक अपने क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर नामांकन करवाने की सलाह दी जाए और उन्हें स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केंद्रों (www.uidai.gov.in पर सूची उपलब्ध) की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) यदि निकट आसपड़ोस जैसे ब्लॉक अथवा तहसील अथवा तालुका में नामांकन केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण इस स्कीम के अधीन हिताधिकारी आधार के लिए नामांकन करवा पाने में समर्थ नहीं है, कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन में स्कीम के कार्यान्वयन के भारसाधक संबंधित विभाग से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं सृजित करना अपेक्षित है और इस उद्देश्य के लिए कार्यान्वयन अभिकरणों अथवा वेब-पोर्टल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को अपना नाम, पता व मोबाइल नंबर और पैरा 1 के उप पैरा (3) के परंतुक में यथाविनिर्दिष्ट अन्य ब्यौरा देकर आधार नामांकन के लिए रजिस्ट्रीकरण करवाने का हिताधिकारियों से अनुरोध किया जाये।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 19-59/2016-आरएफएम-III]

आर. बी. सिन्हा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
(Department of Agriculture Cooperation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th March, 2017

S.O. 893(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare (hereinafter referred to as Ministry) in the Government of India is implementing the "Per Drop More Crop" component of the Prime Minister Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) (hereinafter referred to as the Scheme) as a Centrally Sponsored Scheme by providing Grant-in-Aid to the concerned nodal Departments (hereinafter referred to as Department) under the State Government or Union territory Administration, as per the approved funding pattern;

And whereas, the Grant-in-Aid given under the Scheme is meant for providing subsidized Micro-Irrigation System and other benefits or services (hereinafter referred to as the benefits) to the farmers (hereinafter referred to as beneficiaries) through the State Nodal Agencies or Registered or Empanelled Companies (hereinafter referred to as Implementing Agencies);

And whereas, the benefits offered under the Scheme involve full or partial recurring expenditures incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An Individual eligible to receive the benefits under the Scheme is hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any Individual entitled to receive the benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or, has not yet enrolled for Aadhaar, but desirous of availing the benefits under the Scheme, is hereby required to make application for Aadhaar enrollment by 31.12.2017, provided she or he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the said Act and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.
- (3) As per regulation 12 of Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the States or Union territories through its Implementing Agencies, which requires an individual to furnish Aadhaar, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar, and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in

the respective Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the States or Union territories through its Implementing Agencies is required to provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming UIDAI Registrar themselves;

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individuals subject to the production of the following identification documents, namely:-

- (a) (i) if she or he has enrolled, her or his Aadhaar Enrolment ID slip; or
- (ii) a copy of her or his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (b) of paragraph 2 below; and
- (b) (i) Voter Identity Card; or (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or (iii) Passport; or (iv) Ration Card; or (v) Employee Government ID Card; or (vi) Bank / Post office Passbook with Photo (vii) MGNREGS card; or (viii) Kisan Photo passbook; or (ix) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or (x) Certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (xi) Any other document as specified by the State Government or Union territory Administration;

Provided further that the above documents shall be checked by an officer specifically designated by State Government or Union territory Administration for that purpose.

2. In order to provide convenient and hassle free benefits under the Scheme to the beneficiaries, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in the State Government or Union territory Administration, shall make all the required arrangements including the following, namely:-

(a) Wide publicity through media and individual notices through shall be given through its Implementing Agencies to the beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar under the Scheme and they may be advised to get themselves enrolled at the nearest Aadhaar enrolment centres available in their areas by 31.12.2017, in case they are not already enrolled and the list of locally available enrolment centres (list available at www.uidai.gov.in) shall be made available to them.

(b) In case, the beneficiaries under the Scheme are not able to enroll for Aadhaar due to non-availability of enrolment centres in the near vicinity such as in the Block or Taluka or Tehsil, the concerned Department in charge of implementation of the Scheme in State Government or Union territory Administration through its Implementing Agencies is required to create Aadhaar enrolment facilities at convenient locations, and the beneficiaries may be requested to register their requests for Aadhaar enrolment by giving their names, addresses, mobile numbers and other details as specified in the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 1, with the concerned official of the Implementing Agencies or through the web portal provided for the purpose.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette in all States and Union territories except the States of Assam, Meghalaya and Jammu and Kashmir.

[F. No. 19-59/2016-RFS-III]

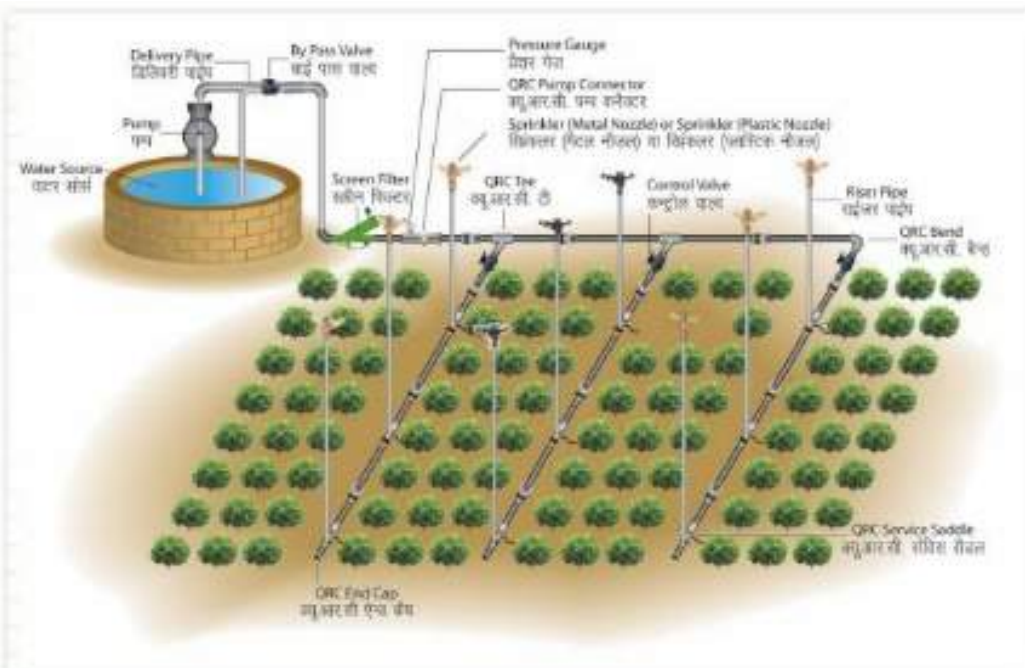
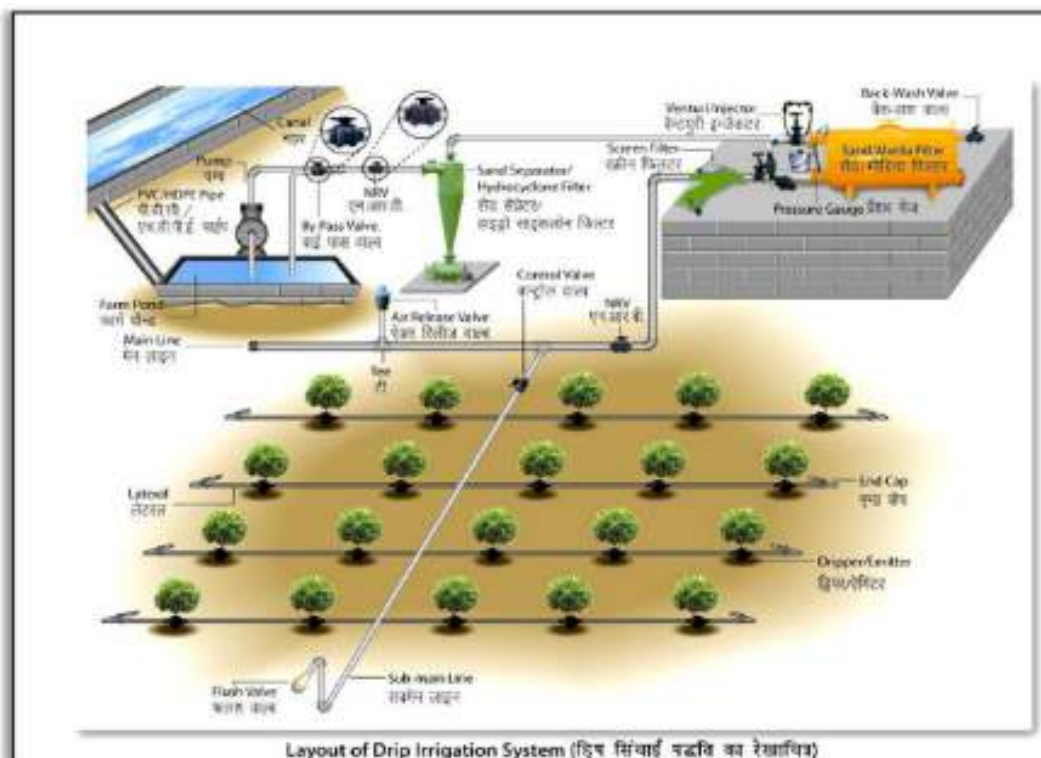
R. B. SINHA, Jt. Secy.

List of BIS Standards

SN	Component Description	BIS
1	Polyethylene pipes for Irrigation- Laterals with amendment number 6	IS 12786: 1989 (reaffirmed 2009)
2	Irrigation Equipment-Emitters- Specification	IS 13487: 1992 (reaffirmed 2009)
3	Irrigation Equipment-Emitting pipes system- Specification (first revision)	IS 13488: 2008 (reaffirmed 2014)
4	Irrigation Equipment-Strainer type filters Specification (first revision)	IS 12785: 1994 (reaffirmed 2011)
5	Irrigation equipment rotating sprinkler Part I, Design and Operational requirements (1st revision)	IS 12232 (Part I) -1996 (reaffirmed 2011)
6	Irrigation equipment rotating sprinkler Part 2, Test method for uniformity of distribution (1st revision)	IS 12232 (Part 2) -1995 (reaffirmed 2011)
7	Fertilizer and Chemicals Injection system Part I Venturi Injector	IS 14483 (Part 1) 1997 (reaffirmed 2009)
8	Irrigation Equipment-Media Filters- Specification	IS 14606: 2022
9	Irrigation Equipment-Hydro cyclone filter-Specification	IS 14743: 1999 (reaffirmed 2009)
10	Unplasticized PVC pipes for agriculture - Specifications	IS 4985 – 2021 TYPE B
11	Irrigation Equipment –Quick Coupled Polyethylene Pipes and Fittings for Sprinkler Irrigation Systems.	IS 17425:2020
12	High Density Polyethylene Pipes for water supply- Specification (fourth revision)	IS 4984 : 2016
13	Fertilizer & Chemical Injector System- Part 2 Water Driven Chemical Injector Pump	IS:14483 Part 2 – 2002
14	Fertilizer & Chemical Injector System- Part 3 Fertilizer Tank	IS:14483 Part 3 – 2018
15	Irrigation equipments- Micro sprayers-Specifications	IS:14605:1998
16	Agricultural Irrigation equipment- Manually operated serviceable plastic valves- Specifications	IS: 18286 :2023
17	Injection Moulded PVC Socket Fittings with solvent Cement Joints	IS:7834:1987 (Part1 to Part7)
18	Fabricated PVC-U fittings	IS:10124:2009 (Part1 to Part13)
19	Injection moulded/machined polyethylene fittings	IS:8008:2022
20	Fabricated Polyethylene fittings	IS:8360:2022

Source: Online catalogue of Bureau of Indian Standards

LAYOUT DESIGN OF DRIP & SPRINKLER IRRIGATION SYSTEMS



राजस्थान सरकार
उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdh.ext.hort@rajasthan.gov.in)

क्रमांक: प.5 (22)आउ / Ext/ PDMC-MI/Fert./GL / 2024-25 /

दिनांक: .09.2024

उप निदेशक उद्यान, समस्त।

विषय:- वर्ष 2024-25 के दौरान ऑटोमेशन, फर्टीगेशन एवं समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश एवं जिलेवार लक्ष्य बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उद्यानिकी गतिविधियों में नवाचार एवं अत्याधुनिकतम तकनीकों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत वर्ष 2024-25 के दौरान ऑटोमेशन, फर्टीगेशन एवं समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान परियोजना का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाना है। इस क्रम में योजना के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2024-25 हेतु क्रियान्वयन दिशानिर्देश संलग्न कर लेख है कि योजना का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष के दौरान प्रभावी मॉनिटरिंग के साथ किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(जय सिंह)
आयुक्त उद्यानिकी

क्रमांक: प.5 (22)आउ / Ext/ PDMC-MI/Fert./GL / 2024-25 /

दिनांक: : .09.2024

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक उद्यान, मुख्यालय/सीएसएस/नर्सरी/अनुसंधान/विस्तार/कीट/सीओई, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड कोटा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, जालौर, सीकर, श्रीगंगानगर, भीलवाड़ा, बीकानेर।
6. उप निदेशक उद्यान शस्य/एनएचएम/नर्सरी/सांख्यिकी/विस्तार, उद्यान आयुक्तालय जयपुर।
7. आहरण वितरण अधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
8. समस्त उप निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद-----
9. मुख्य लेखाधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।

आयुक्त उद्यानिकी

Document certified by JAI SINGH
<jaising001@gmail.com>

Digitally Signed by Jai Singh
Designation : Director
Date :02-09-2024 06:50:16

क्रियान्वयन दिशा-निर्देश

ऑटोमेशन, समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान एवं फर्टीगेशन सपोर्ट

परियोजना 2024-25

1. भूमिका

सूक्ष्म सिंचाई ऑटोमेशन (Micro Irrigation Automation)

1. कृषि आदानों की लागत में निरन्तर वृद्धि तथा प्रति इकाई क्षेत्र में कृषक आमदनी में कमी के कारण नई पीढ़ी का रूख कृषि क्षेत्र से निरन्तर विमुख होता जा रहा है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आज विज्ञान का वर्चस्व है। कृषि क्षेत्र में भी दिन-प्रतिदिन नवीन तकनीक के प्रादुर्भाव व नवाचारों के फलस्वरूप उत्पादन व उत्पादन गुणवत्ता में वृद्धि के साथ-साथ नई पीढ़ी को भी इस क्षेत्र में आकर्षित किया जाना संभव है।
2. राज्य में सीमित जल संसाधन के दक्षतम उपयोग के मध्यनजर राज्य सरकार द्वारा बूंद-बूंद सिंचाई संयंत्रों व संरक्षित खेती के प्रोत्साहन पर अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया है।
3. विभिन्न स्टेकहोल्डर्स में जागरूकता तथा तकनीक प्रोत्साहन पर अनुदान राशि का प्रावधान किया जाकर उक्त तकनीक के प्रति कृषकों का रुझान व्यापक रूप से बढ़ाया जाना लक्षित है।
4. राज्य में **ड्रिप सिंचाई पद्धति की** उत्तरोत्तर वृद्धि, कृषक रुझान, उच्च तकनीक उद्यानिकी की माँग तथा ड्रिप पद्धति पर आदर्श उत्पादकता एवं गुणवत्ता प्राप्त करने के मध्यनजर इस **तकनीक का स्वचालन (ऑटोमेशन)** की महती आवश्यकता है। उच्च उद्यानिकी तकनीक अपनाए जाने के दृष्टिगत ऑटोमेशन तकनीक को अपनाया जाना अवश्यम्भावी है।
5. विगत वर्षों के दौरान ड्रिप सिंचाई तकनीक अपनाए जाने के प्रति बढ़े हुए रुझान के कारण इस तकनीक के तहत राज्य में करीब 4 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में कृषक ड्रिप सिंचाई तकनीक के माध्यम से सफलतापूर्वक उच्च गुणवत्ता का उत्पादन प्राप्त कर रहे हैं। संरक्षित खेती के तहत पॉलीहॉउसिंग तथा शैडनेट हॉउसिंग में भी कृषकों का रुझान बढ़ा है।
6. ड्रिप सिंचाई तकनीक का वास्तविक लाभ छोटे-छोटे अन्तराल पर प्रभावी जड़ क्षेत्र में जल मांग व पौषक तत्वों की मांग के अनुसार सिंचाई व फर्टीगेशन से ही प्राप्त होता है। संरक्षित खेती में भी तापक्रम व आद्रता का नियंत्रण प्रभावी रूप से किया जाना अतिआवश्यक है। परन्तु न्यून अन्तराल पर इन गतिविधियों का बारम्बार संचालन मैन्यूअली किया जाना न तो संभव है तथा न ही त्रुटिरहित क्रियान्वयन संभव है। अतः उक्त तकनीक का वांछित लाभ प्राप्त करने के दृष्टिगत ऑटोमेशन तकनीक ही सर्वोत्तम विकल्प है।

7. उन्नत कृषि एवं उद्यानिकी तकनीक को मूर्त रूप देने के मध्यनजर ड्रिप, फर्टीगेशन, फोगर, फिल्टर्स, वाल्वस व अन्य तकनीकी युक्तियों का स्वचालन (ऑटोमेशन) आवश्यक है।
8. इस तकनीक में कंट्रोलर, सेन्सर, सोलोनाइड वॉल्व, फिल्टर्स व अन्य युक्तियों के माध्यम से ड्रिप सिंचाई संयंत्रों का स्वचालन किया जाता है।
9. स्वचालन से श्रम की प्रभावी बचत के साथ-साथ पानी व पौषक तत्वों की इच्छित (Accurate) मात्रा इच्छित समय पर पौधों को प्राप्त होती है। जिससे उत्पादन मात्रा एवं गुणवत्ता में प्रभावी इजाफा होता है।

समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान (Community Based Artificial Intelligence Solutions)

10. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समाधान का सदुपयोग विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर किये जाने की सम्भावना के मद्देनजर कृषि क्षेत्र में भी इसकी प्रभावी शुरुआत किया जाना समय की आवश्यकता है।
11. विभिन्न सॉफ्टवेयर तथा मोबाइल ऐप्लीकेशन के माध्यम से विभिन्न कृषक समूहों तक मौसम, जल प्रबंधन, जल मांग, पोषक तत्व मांग आदि की सटीक जानकारी, सलाह/एडवाइजरी प्रदान की जा सकती है।
12. इस क्षेत्र में कार्यशील विशेषज्ञ फर्मस की सेवाएँ ली जाकर सामुदायिक आधार पर विभिन्न कृषक जिनके पास एन्ड्रॉयड फोन की सुविधा हो उन्हें इस नवाचारी तकनीक से जोड़ा जाकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समाधान वृहत स्तर पर प्रदान किये जा सकते हैं।

फर्टीगेशन (Fertigation)

13. फर्टीगेशन तकनीक में फसल को वांछित पोषक तत्वों की आपूर्ति ड्रिप सिंचाई प्रणाली के माध्यम से सिंचाई के साथ ही जल विलेयक उर्वरक/तरल उर्वरक द्वारा सीधे ही प्रभावी जड़ क्षेत्र में की जा सकती है।
14. राज्य में ड्रिप सिंचाई पद्धति की उत्तरोत्तर वृद्धि, कृषक रुझान, उच्च उद्यानिकी मांग तथा ड्रिप पद्धति पर आदर्श उत्पादकता एवं गुणवत्ता प्राप्त करने के मध्येनजर फसलों को जल विलयक उर्वरक ड्रिप के माध्यम से दिये जाने (फर्टीगेशन) की महती आवश्यकता है।
15. इस तकनीक से उर्वरक उपयोग दक्षता में प्रभावी इजाफा तथा फसल की विभिन्न अवस्थाओं में आवश्यकतानुसार पोषक तत्वों की आपूर्ति सम्भव है।
16. फर्टीगेशन तकनीक, ड्रिप सिंचाई पद्धति के फायदे में सहक्रियाशीलता (Synergetic) की भूमिका का निर्वहन करता है। उच्च उद्यानिकी तकनीकी अपनाये जाने के दृष्टिगत फर्टीगेशन तकनीक को अपनाया जाना आवश्यकम्भावी है।

बजट प्रावधान

17. यह परियोजना केंद्रीय प्रवर्तित योजना/राज्य योजना/निधि/मद व अटल भू-जल योजना की प्रोत्साहन राशि से क्रियान्वित की जावेगी।
18. प्रारंभिक तौर पर ऑटोमेशन तकनीक के सञ्चालन हेतु केन्द्रियांश, राज्यांश व अतिरिक्त अनुदान राशि PDMC MI से प्रावधित किया जाना प्रस्तावित है। फर्टिगेशन तकनीक के संचालन हेतु सम्पूर्ण राशि ऑटोमेशन के राज्य मद से प्रावधित किया जाना प्रस्तावित है। समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान तकनीक के संचालन हेतु सम्पूर्ण राशि अटल भूजल योजना की प्रोत्साहन राशि मद से प्रावधित किया जाना प्रस्तावित है।

क्र. स.	योजना	बजट प्रावधान	बजट मद
1	ऑटोमेशन	केन्द्रियांश, राज्यांश व अतिरिक्त अनुदान राशि PDMC MI से (SNA/ SPARSH Account & IFMS)	2401-00-119-26-00 2401-00-789-02-05 2401-00-796-51-04 2401-00-119-47-01 2401-00-789-15-01 2401-00-796-81-01
2	समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान	सम्पूर्ण राशि अटल भूजल योजना की प्रोत्साहन राशि मद से (CNA Account)	GIA General/ Equipment & System 26.01.01.12.07
3	फर्टिगेशन	सम्पूर्ण राशि ऑटोमेशन के राज्य मद से (IFMS)	2401-00-119-37-00 2401-00-789-02-13 2401-00-796-51-12

परियोजना का क्रियान्वयन स्वरूप इस प्रकार है –

2. कृषक पात्रता के मापदण्ड

कृषक चयन निम्न पात्रता के आधार पर किया जाना है:—

1. कृषक के पास भू-स्वामित्व/ भू-लीज (न्यूनतम 10 वर्ष एवं सक्षम स्तर से पंजीकृत) हो।
2. फर्टिगेशन हेतु कृषक के यहां ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित हो। ऑटोमेशन व समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान के प्रकरणों में ड्रिप/माइक्रो/मिनी स्प्रिंकलर या फव्वारा सिंचाई संयंत्र स्थापित हो।
3. कृषक के पास स्थायी रूप से सिंचाई का साधन हो।
4. कृषक द्वारा हाईटेक उद्यानिकी के तहत सब्जी/ फूल/ फल-बगीचे/ अन्य फसल ड्रिप संयंत्र पर ली जा रही हो।
5. कृषक परियोजना के तहत विभागीय निर्देशों एवं सिफारिश के अनुसार फर्टिगेशन शिड्यूल अपनाने हेतु सहमत हो।
6. फर्टिगेशन का अनुदान संस्तुतित फसलों पर ही देय होगा।
7. सूक्ष्म सिंचाई ऑटोमेशन पर अनुदान संरक्षित खेती व खुली खेती, दोनों ही प्रकरणों में देय होगा।

3. अनुदान पत्रावलियों के साथ लगाये जाने वाले दस्तावेज—

1. जनाधार आधारित ऑनलाईन (Rajkisan Saathi Portal) आवेदन
2. भूमि की जमाबंदी या पासबुक की प्रतिलिपि (भू-स्वामित्व) या रजिस्टर्ड लीज की प्रति / ऑनलाईन भू-स्वामित्व
3. बिजली का बिल/पम्प सैट क्रय बिल/दस्तावेज (सिंचाई स्रोत)
4. मृदा एवं जल परीक्षण रिपोर्ट
5. सूचीबद्ध निर्माता/अधिकृत आपूर्तिकर्ता का बिल/प्रफोर्मा इनवाइस/ कॉटेशन
6. आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक द्वारा उगाई जा रही फसलों पर फर्टीगेशन का तकनीकी सिफारिश सिड्यूल व ड्रिप से फसल उगाने का प्रमाण-पत्र (उत्पादन)
7. ट्राई-पार्टी अनुबन्ध (संलग्नक-1)

4. परियोजना संचालन प्रक्रिया

1. परियोजना हेतु इच्छुक पात्र कृषकों से **ऑनलाईन** आवेदन-पत्र निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किये जाने हैं। ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति के लिए राजकिसान साथी पोर्टल के स्तर पर नया आवेदन फॉर्मेट अपडेट/निर्माण कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त फॉर्मेट समय पर न डवलप होने की स्थिति में ऑफलाईन पत्रावली प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया जा सकेगा।
2. कृषि/उद्यान विभाग कार्मिक द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि सम्बन्धित आवेदक द्वारा अमुक फसल ड्रिप पर उगाई जा रही है।
3. जिलों में लक्ष्यों की सीमा तक आवेदन प्राप्त कर, उनका निस्तारण वरिष्ठता के आधार पर **“पहले आओ पहले पाओ”** के आधार पर किया जाना है।
4. आयुक्तालय स्तर से समय-समय पर विभिन्न फसलों हेतु फर्टीगेशन किट (संलग्न अनुसार) की सिफारिश की जावेगी। उक्त फर्टीगेशन किट में फसल विशेष की विभिन्न अवस्थाओं में प्रति इकाई क्षेत्र हेतु आवश्यक समस्त प्रकार के उर्वरक / पौध वृद्धि रसायनों का समावेश होगा। प्रत्येक फसल व क्षेत्र हेतु अलग-अलग फर्टी किट होंगे।
5. आयुक्तालय स्तर या खंड स्तर अधिकारी या पर इस कार्य हेतु ट्राई-पार्टी/सलाहकार परियोजना के क्रियान्वयन, तकनीकी सलाह, फर्टीगेशन शेड्यूल अपग्रेडेशन तथा तकनीकी व उत्पादन प्रभावों की मॉनिटरिंग/सम्पादन करेंगे।
6. खंड स्तर अधिकारी या ट्राई-पार्टी/सलाहकार द्वारा समय-समय पर फर्टी किट आपूर्ति तथा कार्यक्रम संचालन का रेण्डम आधार पर निरीक्षण किया जायेगा।

5. देय राज-सहायता

1. फर्टिगेशन हेतु आपूर्तित उर्वरक /रसायन तथा ऑटोमेशन इकाई पर विभाग द्वारा अनुमोदित दर का 75 प्रतिशत अनुदान कृषक संस्तुति पर सम्बन्धित कार्यदायी फर्म को देय होगा।
2. समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान तकनीक के संचालन हेतु सम्पूर्ण राशि का वहन परियोजना से किया जायेगा।
3. तकनीकी सपोर्ट के तहत देय 100 प्रतिशत अनुदान की पूर्ण राशि का भुगतान सीधे ही सम्बन्धित फर्म/ संस्थान को किया जायेगा।

क्र. सं.	योजना	अनुदान	वि. वि.
1	ऑटोमेशन	75 प्रतिशत	तकनीकी सपोर्ट के तहत शत प्रतिशत अनुदान
2	समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान	100 प्रतिशत	
3	फर्टिगेशन	75 प्रतिशत	तकनीकी सपोर्ट के तहत शत प्रतिशत अनुदान

6. अनुदान प्रक्रिया –

1. कृषक द्वारा निर्धारित आवेदन पत्र मय वांछित दस्तावेज सम्बन्धित क्षेत्र के कृषि/ उद्यान विभाग के कार्यालय में स्वयं/ कृषि पर्यवेक्षक/ सहायक कृषि अधिकारी/ बैंक/ आपूर्तिकर्ता डीलर/ निर्माता के माध्यम से **ऑनलाईन** प्रेषित किया जावे।
2. पात्र आवेदनों पर सम्बन्धित जिला कार्यालय द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जावे।

ऑटोमेशन

3. ऑटोमेशन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रकरणों में आपूर्तिकर्ता द्वारा तकनीकी सर्वे व कृषक हिस्सा राशि संग्रहण पश्चात् संयंत्र आपूर्ति एवं स्थापन का कार्य सम्पन्न करेंगे।
4. ऑटोमेशन स्थापन का भौतिक सत्यापन कृषि अधिकारी या इसके समकक्ष या उच्च अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
5. कार्यदायी फर्म द्वारा ऑटोमेशन इकाई की आपूर्ति/स्थापन प्रशासनिक स्वीकृति/ कृषक हिस्सा राशि प्राप्ति के 20 दिवस में आवश्यक रूप से की जानी होगी। आपूर्ति में विलम्ब की स्थिति में सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम के तहत शास्ती के प्रावधान (2.5, 5.0, 7.5 व 10 प्रतिशत) लागू होंगे।

फर्टीगेशन

6. प्रशासनिक स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि आवेदक द्वारा आवेदित फसल जो फर्टीगेशन हेतु अनुशंसित है एवं उसके खेत में ड्रिप पर ली जा रही है।
7. प्रशासनिक स्वीकृति पश्चात सम्बन्धित सूचीबद्ध निर्माता द्वारा सम्बन्धित जिला इकाई को सूचित करते हुये लाभार्थी को स्वीकृत फसल /क्षेत्र के अनुसार अनुशंसित फर्टी किट/माल आपूर्ति की जावेगी। जिसका सत्यापन जिला अधिकारियों द्वारा किया जायेगा।
8. फर्टी किट आपूर्ति जिला मुख्यालय या जिला स्तर पर अनुशंसित अन्य स्थान (यथा सम्भव सहायक कृषि अधिकारी मुख्यालय) पर प्रत्येक सप्ताह को नियत दिवस में सम्बन्धित फिल्ड कार्मिकों के समक्ष किया जावें, जिसका मौके पर ही भौतिक सत्यापन सम्बन्धित द्वारा किया जावेगा।
9. सम्बन्धित जिला ईकाई स्तर से फर्टीकिट आपूर्ति शेड्यूल प्रपत्र के अनुसार निर्धारित किया जावेगा। उक्त शेड्यूल का समुचित प्रचार प्रसार अपेक्षित है।
10. सम्बन्धित क्षेत्र के कृषि अधिकारी /कृषि अनुसंधान अधिकारी /सहायक कृषि अधिकारी /कृषि पर्यवेक्षक द्वारा आपूर्तित उर्वरक/ रसायन का तत् दिवस भौतिक सत्यापन किया जायेगा। जिला स्तर अधिकारी से उक्त दिवस को आपूर्ति स्थलों पर रेण्डम आधार पर आपूर्ति निरीक्षण किया जायेगा।

अन्य

11. जिला स्तर /आयुक्तालयस्तर के अधिकारियों द्वारा फिल्ड भ्रमण के दौरान रेण्डम आधार पर लाभार्थियों से आपूर्तित फर्टीकिट/ऑटोमेशन इकाई व इसके उपयोग से होने वाले लाभ का फीड बैक लिया जावेगा।
12. आयुक्तालय स्तर के अधिकारियों या इस प्रयोजन हेतु नामित ट्राई-पार्टी एजेन्सी/विशेषज्ञ सलाहकारों द्वारा भी समय-समय पर वांछानुसार फर्टीकिट आपूर्ति/ऑटोमेशन इकाई का निरीक्षण रेण्डम आधार पर किया जावेगा।
13. आपूर्तित फर्टी किट की आपूर्तिकर्तावार तथा फसलवार सूचना साप्ताहिक रूप से आयुक्तालय को निर्धारित प्रपत्र में उपलब्ध कराई जावेगी।
14. सम्बन्धित कार्यदायी फर्म के स्तर से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार कलस्टर आधार पर प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

अनुदान भुगतान—

15. ऑटोमेशन व फर्टीगेशन के प्रकरणों में अनुदान का भुगतान सम्बन्धित निर्माता फर्म को 3 चरणों में किया जावेगा—
 - (अ) प्रशासनिक स्वीकृति पर कृषक द्वारा 25 प्रतिशत कृषक हिस्सा राशि का भुगतान सीधे ही सम्बन्धित फर्म को किया जायेगा।
 - (ब) वांछित माल आपूर्ति पर 55 प्रतिशत
 - (स) निर्धारित मापदण्डानुसार आपूर्ति तथा प्रशिक्षण कार्य सम्पन्न करने पर/फसल समाप्ति पर शेष 20 प्रतिशत या शेष रहा पूर्ण भुगतान।
16. समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान के प्रकरणों में अनुदान भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा—

- (अ) प्रारम्भिक योजना, ओरियनटेशन, प्रशिक्षण, इन्सपेक्शन रिपोर्ट व लाभार्थियों को वांछित सॉफ्टवेयर पर जोड़े जाने पर 30 प्रतिशत (कृषक हिस्सा राशि का भुगतान सीधे ही सम्बन्धित फर्म को किया जायेगा)।
- (ब) 8 माह तक सफलतापूर्वक एडवाइजरी प्रदान करने पर 50 प्रतिशत
- (स) 1 वर्ष तक कार्यक्रम के सफल सम्पादन पर शेष 20 प्रतिशत या शेष रहा पूर्ण भुगतान।

17. प्रशासनिक / सपोर्ट मद से भुगतान

- (अ) तकनीकी सपोर्ट / प्रशिक्षण के कार्य को सन्तोषजनक रूप से सम्पादित करने पर इस हेतु देय राशि का पूर्ण भुगतान सम्बन्धित फर्म को किया जावेगा।
- (ब) ट्राई-पार्टी / सलाहकार तथा अनुसंधान प्रदर्शन हेतु देय राशि का भुगतान जिला इकाई/ आयुक्तालय स्तर से सीधे ही सम्बन्धित फर्म / संस्थान को प्रशासनिक मद से किया जायेगा।

7. गुणवत्ता नियन्त्रण

1. गुणवत्ता नियन्त्रण के मध्यनजर आपूर्तिकर्ता के नमूने/लोट का परीक्षण सम्बन्धित खण्डीय उद्यान अधिकारी द्वारा कृषि विभाग से समन्वय स्थापित कर करवाया जावे तथा अमानक आपूर्ति स्थिति में भुगतान नहीं किया जावे।
2. खण्डीय स्तरीय उद्यान अधिकारी की देख-रेख में जिला स्तरीय उद्यान अधिकारी/प्रतिनिधि, क्षेत्र के कृषि विज्ञान केन्द्र/एटीसी/सी.ओ.ई./कृषि अनुसंधान केन्द्र तथा आपूर्तिकर्ता प्रतिनिधि के तीन सदस्यों की स्टैंडिंग कमेटी द्वारा लगभग 5 प्रतिशत प्रकरणों में फर्टीगेशन के फसलों पर प्रभाव तथा आपूर्तिकर्ता द्वारा दिये जा रहे तकनीकी सपोर्ट का निरंतर आकलन किया जावे।
3. आपूर्तिकर्ता के तकनीकी प्रतिनिधि द्वारा किसानों को दिये जाने वाले तकनीकी सपोर्ट के विवरण का रिकॉर्ड संधारित किया जावे।
4. आपूर्तिकर्ता द्वारा छिड़काव में अडजूवेंट/स्टीकर के उपयोग आवश्यक रूप से करवाया जावे।
5. यथा संभव कार्यक्रम क्लस्टर आधार पर क्रियान्वयन किया जावे।

8. आपूर्तिकर्ता / कार्यदायी फर्म

परियोजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष के दौरान न्यूनतम दर पर कार्य करने हेतु सहमत आपूर्तिकर्ता फर्मस् सूचीबद्धता सूची अलग से जारी की जा रही है।

9. सूचीबद्ध निर्माताओं/ आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारी

1. विभिन्न फसलों एवं इनके वृद्धि स्तर हेतु फर्टिगेशन शिड्यूल/ ऑटोमेशन से संबंधित साहित्य कृषकों को उपलब्ध कराया जावे।
2. परियोजना हेतु की गयी आपूर्ति फर्टिलाइजर कन्ट्रोल आर्डर के तहत हो।
3. फर्टीकट के प्रत्येक पैकेट पर “ राजस्थान फर्टीगेशन सपोर्ट परियोजना 2024–25 राजस्थान” अंकित किया जायेगा।
4. आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि लाभान्वित ने आपूर्तित उर्वरक किट का उपयोग योजनान्तर्गत चयनित फसल/भूमि पर ही किया है। दुरुपयोग की स्थिति में सम्बन्धित कृषक की जानकारी तुरन्त जिला इकाई एवं आयुक्तालय को सूचित करते हुए देनी होगी।
5. कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान आपूर्तित उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण के मध्यनजर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आउटसोर्सिंग, पोर्ट एनालिसिस रिपोर्ट इत्यादि आयुक्तालय को आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावे।
6. आपूर्ति की सूचना संबंधित जिले के संयुक्त निदेशक कृषि को समय-समय पर प्रस्तुत की जावे, ताकि आवश्यकतानुसार रेण्डम आधार पर सैम्पल लिये जाकर नियमानुसार जांच करायी जा सके।
7. तकनीकी सपोर्ट सेवा के तहत प्रत्येक आपूर्तिकर्ता को सीजन में कम से कम दो बार प्रशिक्षण आयोजित करवाने होंगे जिसमें विभागीय कार्मिकों की उपस्थिति आवश्यक होगी। प्रशिक्षण के दौरान कृषकों को तकनीकी साहित्य उपलब्ध करवाना होगा। तकनीकी कर्मियों का नाम, योग्यता एवं दूरभाष नम्बर संबंधित जिले एवं आयुक्तालयको प्रस्तुत करते हुये साप्ताहिक कार्य का विवरण संबंधित जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

10. कृषक के दायित्व

1. आवेदन पत्र प्रस्तुत करना, आपूर्तिकर्ता फर्म का चयन तथा कृषक हिस्सा राशि जमा करवाना।
2. कृषक द्वारा आपूर्तित किट/ऑटोमेशन इकाई का उपयोग अपनी चयनित भूमि/फसल में ही करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुदान सहायता वापस वसूल कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही जिला इकाई स्तर से की जावेगी।

3. फर्टीकट/माल आपूर्ति, भौतिक सत्यापन व अन्य निरीक्षण के समय लाभार्थी यथासम्भव स्वयं या अन्य परिवार के जिम्मेदार सदस्य की उपस्थिति सुनिश्चित करेगा।
4. फर्टीकट/ ऑटोमेशन का हस्तांतरण या बेचान नहीं किया जायेगा।
5. संयंत्र का उचित रखरखाव तथा सिफारिश अनुसार उर्वरकीकरण कार्य सम्पन्न करना।
6. ट्राई-पार्टीअनुबन्ध।

11. वार्षिक कार्य योजना / लक्ष्य 2024.25

ऑटोमेशन की कार्ययोजना 2024.25 केंद्रीय प्रवर्तित योजना पर ड्राप मोर क्रॉप के साथ जारी की जा चुकी है। कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य से 25 गावों को ऑटोमेशन के तहत लाने की अपेक्षा की गयी है। अतः प्रत्येक जिले द्वारा अधिसक्रिय आधार पर व्यक्तिगत ऑटोमेशन यूनिट स्थापित करने के साथ साथ सम्पूर्ण ग्राम ऑटोमेशन की संकल्पना पर कार्य करने हेतु ऐसे गावों का चयन कर योजना का क्रियान्वयन किया जाना है।

फर्टिगेशन व समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान के लक्ष्य/ कार्य योजना अलग से सूचित किये जायेंगे। जिला विशेष में मॉग आधार पर लक्ष्यों का आहरण/ अतिरिक्त आवंटन किया जा सकेगा।

संलग्नक-1

राज्य योजनान्तर्गत फर्टीगेशन / ऑटोमेशन परियोजना हेतु अनुबंध

(100 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल शपथ-पत्र पर) (कृषक द्वारा वहन किया जावे)

प्रपत्र
ट्राई-पार्टी अनुबंध

अनुबंध डीड का क्रियान्वयन आज दिनांक 2024 / 2025, स्थान.....
....., जिला....., को जिला इकाई(प्रतिनिधि श्री),
कृषक श्री/श्रीमती....., गाँव.....तहसील.....जिला.....
राजस्थान एवं फर्टीगेशन / ऑटोमेशन कार्यदायी फर्म मेंसर्स(प्रतिनिधि
श्री), के बीच सम्पन्न किया गया जिसमें निम्न शर्तें संबंधित
पार्टी द्वारा स्वीकार की जाती है ।

1. कृषक अनुदान पर फर्टीगेशन / ऑटोमेशन परियोजना का लाभ लेने का इच्छुक है तथा उसके द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज लगाये गये हैं। अनुदान राशि का भुगतान संयंत्र आपूर्तिकर्ता को करने के लिये कृषक सहमत है।
2. आपूर्तिकर्ता द्वारा कृषक की मॉग पर खेत का तकनीकी सर्वेक्षण, मृदा-जल का परीक्षण तथा फर्टीगेशन संयंत्र का अवलोकन कर लिया गया है। कृषक की आवश्यकता तथा निर्धारित फसल/क्षेत्र के आधार पर निर्माता द्वारा लागत अनुमान तैयार किये गये हैं।
3. कृषक वांछित क्षेत्र व फसल जिस पर फर्टीगेशन / ऑटोमेशन कार्य किया जाना है निश्चित समयावधि में पूर्ण / तैयार करने हेतु सहमत हैं।
4. आपूर्तिकर्ता द्वारा प्रफोर्मा इनवाइस प्रस्तुत करने, प्रशासनिक स्वीकृति व त्रिपक्षीय अनुबंध सम्पन्न होने के पश्चात कृषक / जिला इकाई द्वारा 25 प्रतिशत अग्रिम भुगतान किया जावेगा।
5. आपूर्तिकर्ता कम्पनी प्रशासनिक स्वीकृति जारी होने / अग्रिम राशि प्राप्त होने के 20 दिवस में माल / फर्टीकिट / ऑटोमेशन इकाई की सुपुर्दगी सुनिश्चित करेगी।
6. कृषक द्वारा अपने स्तर पर फर्टीगेशन / ऑटोमेशन संयंत्र व समुचित पॉवर की व्यवस्था की जावेगी।
7. जिला इकाई द्वारा भौतिक सत्यापन एवं प्रयोगिक परीक्षण के दौरान कृषक अपनी संतुष्टी के लिये वहां उपस्थित रहेगा।
8. भौतिक सत्यापन के उपरांत कार्यदायी फर्म फर्टीकिट / ऑटोमेशन इकाई कृषक के सुपुर्दगी कर देगा उसके लिये कृषक द्वारा निर्धारित प्रपत्र में प्राप्ती रसीद देनी होगी।
9. आयुक्तालय द्वारा अनुमोदित फर्टीगेशन कार्यदायी फर्म एक माह के भीतर फर्टीकिट / ऑटोमेशन इकाई आपूर्ति नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में कृषक के

अन्य सप्लायर के चुनने की स्वतंत्रा होगी, विलम्ब की तिथि त्रिपक्षिय अनुबन्ध की तिथि से गिना जावेगा।

10. कार्यदायी फर्म द्वारा कृषक द्वारा जारी कार्यपूर्ण प्रमाण-पत्र, अनुदान दावा (क्लेम) प्रपत्र तथा भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन के साथ अंतिम भुगतान बिल प्रस्तुत किया जावेगा। जिला इकाई द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की जाकर फर्टीगेशन/ फोलियर उर्वरकीकरण/ ऑटोमेशन कार्यदायी फर्म को शेष रही राशि का भुगतान किया जावेगा।
11. उद्यान विभाग या कार्यदायी फर्म कृषक की त्रुटि से संयंत्र/फसल के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगी।
12. कृषक द्वारा आपूर्तित किट/ ऑटोमेशन इकाई का उपयोग अपनी चयनित भूमि/फसल में ही करना अनिवार्य होगा अन्यथा अनुदान सहायता वापस वसूल कर आवश्यक कानूनी कार्यवाही जिला इकाई स्तर से की जावेगी।
13. कार्यदायी फर्म द्वारा परियोजना हेतु की गयी आपूर्ति फर्टिलाइजर कन्ट्रोल आर्डर के तहत हो।
14. फर्टीकिट के प्रत्येक पैकेट पर "फर्टीगेशन सपोर्ट परियोजना 2024-25 राजस्थान" अंकित किया जायेगा।
15. आपूर्तिकर्ता द्वारा यह सुनिश्चित किया जावेगा कि लाभान्वित ने आपूर्तित उर्वरक किट का उपयोग योजनान्तर्गत चयनित फसल/भूमि पर ही किया है। दुरुपयोग की स्थिति में सम्बन्धित कृषक की जानकारी तुरन्त जिला इकाई व आयुक्तालय को सूचित करते हुए देनी होगी।
16. कार्यक्रम क्रियान्वयन के दौरान आपूर्तित उर्वरकों की गुणवत्ता नियंत्रण के मध्यनजर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आउटसोर्सिंग, पोर्ट एनालिसिस रिपोर्ट इत्यादि आयुक्तालय को आवश्यक रूप से प्रस्तुत की जावें।
17. आपूर्ति की सूचना संबंधित जिले के उप निदेशक कृषि को समय-समय पर प्रस्तुत की जावें, ताकि आवश्यकतानुसार रेण्डम आधार पर सैम्पल लिये जाकर नियमानुसार जांच करायी जा सके।
18. कार्यदायी फर्म कृषक को सिंचाई अवधि, उर्वरक देने की अवधि, तकनीकी व आर्थिक विश्लेषण की रिपोर्ट (फसल वार) संयंत्र के रख रखाव संबंधी जानकारी का साहित्य भी उपलब्ध कराया जावेगा।
19. कार्यदायी फर्म फसल बुआई के समय से पूर्व तथा फसल कटाई से पूर्व सीजन में दो बार प्रशिक्षण आयोजन की व्यवस्था करेगा।
20. प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान कार्यदायी फर्म द्वारा जिला इकाई प्रभारी अन्य विशेषज्ञ मुख्यालय से/तथा विश्वविधालय से प्रशिक्षण कार्य हेतु बुलाये जावेंगे।

जिला इकाई प्रतिनिधि
 फर्टीगेशन/ ऑटोमेशन कार्यदायी फर्म
 कृषक
 गवाह

राजस्थान सरकार
उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdh.ext.hort@rajasthan.gov.in)

क्रमांक: प.5 (22)आउ / Ext/ PDMC-MI/Fert./GL / 2024-25 /

दिनांक: .12.2024

**उप निदेशक उद्यान,
समस्त।**

विषय:- वर्ष 2024-25 के दौरान **ऑटोमेशन** परियोजना के क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश बाबत।

प्रसंग:- आयुक्तालय के पूर्व पत्रांक 10164643 दिनांक 02.09.2024 द्वारा **ऑटोमेशन**, फर्टीगेशन एवं समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान परियोजना के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र द्वारा उद्यानिकी गतिविधियों में नवाचार एवं अत्याधुनिकतम तकनीकों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत वर्ष 2024-25 के दौरान ऑटोमेशन, फर्टीगेशन एवं समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।

ऑटोमेशन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संबंधित आपूर्तिकर्ताओं के चयन हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर विभिन्न कम्पोनेन्ट्स का दर अनुमोदन कर आपूर्तिकर्ताओं से दर-अनुबंध किये जा चुके हैं। भारत सरकार द्वारा जारी **‘पर ड्रॉप मोर क्रॉप’** योजना के तहत ऑटोमेशन कार्यक्रम हेतु जारी दिशा-निर्देशानुसार ऑटोमेशन कम्पोनेंट हेतु कृषकों को **1 हेक्टेयर हेतु राशि रुपये 40,000 देय** है। विभाग द्वारा जारी प्रासांगिक निर्देशों में लाभार्थी को अनुमोदित लागत का **75 प्रतिशत अनुदान** दिये जाने का प्रावधान किया गया है। **ऑटोमेशन** कार्यक्रम के विभिन्न कम्पोनेन्ट्स की अनुमोदित दरें संलग्न कर पूर्व में जारी दिशा निर्देशों के तहत कार्यक्रम के प्रभावी सञ्चालन एवं क्रियान्वयन के संशय दूर करने के क्रम में निम्न स्पष्टीकरण जारी किये जाते हैं:

1. ऑटोमेशन एक नयी तकनीक है जिसका वृहत स्तर पर प्रचार प्रसार कर अधिकाधिक कृषकों को इसे अपनाये जाने हेतु प्रेरित / प्रोत्साहित किया जाना है जिससे राज्य में जल बचत व प्रिसिजन फार्मिंग की अवधारणा फील्ड स्तर पर स्थापित की जा सके।
2. भारत सरकार द्वारा जारी PDMC दिशानिर्देशानुसार **ऑटोमेशन** हेतु प्रति हेक्टेयर रु. 40,000 केंद्रीय प्रवर्तित योजना (CSS) के तहत देय है जो की अधिकतम 5 हेक्टेयर हेतु रु. 2,00,000 देय होंगे तथा 1 हेक्टेयर से कम क्षेत्र हेतु राशि की गणना prorata आधार पर की जावे।
3. ऑटोमेशन कार्यक्रम के तहत कृषक अपने फील्ड या सरक्षित खेती हेतु सम्पूर्ण ऑटोमेशन (यथा कंट्रोलर , सलोनोइड वाल्व्स, वायर/ वॉयरलेस युक्तियाँ आदि) अथवा आंशिक ऑटोमेशन (यथा ऑटोमेटेड फिल्टर्स) का विकल्प ले सकते हैं।
4. सूक्ष्म सिंचाई योजना के प्रचलित प्रावधान के अनुसार ऑटोमेशन हेतु भी 0.2 से 5.0 हेक्टेयर क्षेत्र सीमा में अनुदान देय होगा।
5. कृषि एवं कृषि कल्याण मंत्रालय के पात्र दिनांक 16 अप्रैल 2024 के अनुसार राजस्थान राज्य के किसानों में सम्पूर्ण सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों पर ऑटोमेशन की अपेक्षा की गयी है। अतः

**RajKaj Ref
12428896**



Signature Not Verified

Digitally signed by **Surash Kumar**
Date: 2024.12.17 18:29:56 IST
Reason: Approved

द्वारा अपने क्षेत्र के कम से कम 3 गांवों का चयन कर इस अत्यधुनिक तकनीक का क्रियान्वयन पायलट आधार पर प्राथमिकता से केंद्रित किया जाना है। चयनित प्रत्येक गांव एक दर अनुबंधित फर्म को समर्पित (dedicated) आधार पर प्रदान किया जावे। सम्बंधित फर्म भी इस आशय का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं।

6. संरक्षित खेती के पाली हाउसेस व शेडनेट हाउसेस पर यथासंभव सम्पूर्ण ऑटोमेशन करवाया जावे।
7. राज्य के अन्य क्षेत्र के सूक्ष्म सिंचाई धारक कृषकों को भी आवेदन के आधार पर अनुदान देय होगा।
8. दर अनुबंध बिना टैक्स की दरों के साथ किया गया है जिस पर समय समय पर जारी टैक्स प्रावधान के अनुसार (उदाहरणार्थ 12%) टैक्स की राशि जुड़ने के पश्चात लागत पर अनुदान की गणना की जानी है।
9. लाभार्थी को केन्द्रीय प्रवर्तित योजना 'पर ड्रॉप मोर क्रॉप' से प्रति हैक्टेयर राशि रुपये 40,000 या अनुमोदित दर का 75 प्रतिशत जो भी कम हो देय होगा तथा शेष देय अतिरिक्त अनुदान बजट मद से देय होगा।
10. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाना उचित होगा कि इस कार्यक्रम के तहत कृषकों द्वारा एक या एक से अधिक कम्पोनेन्ट्स अनुदान हेतु आवेदित किया जाना संभव है जिसकी अनुमोदित लागत मय जीएसटी को प्रति हैक्टेयर राशि रुपये 40,000 की सीमा तक (कैन्द्रीय+राज्यांश) कैन्द्रीय प्रवर्तित योजना से किया जायेगा तथा इस सीमा से ऊपर की राशि अतिरिक्त अनुदान बजट मद (सामान्य 2401-00-119-47-01, अजजा. 2401-00-789-15-01 एवं अजा. 2401-00-796-81-01) से किया जावेगा।
11. उदाहरणार्थ, परिशिष्ट-1

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(सुरेश कुमार ओला)
आयुक्त उद्यानिकी

क्रमांक: प.5 (22)आउ / Ext/ PDMC-MI/Fert./GL / 2024-25 /

दिनांक: .12.2024

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि एवं उद्यानिकी शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. वरिष्ठ निजी सहायक, आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर
3. अतिरिक्त निदेशक उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक उद्यान, मुख्यालय/सीएसएस/नर्सरी/अनुसंधान/विस्तार/कीट/सीओई, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
5. संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड कोटा, जयपुर, जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर, जालौर, सीकर, श्रीगंगानगर, भीलवाडा, बीकानेर।
6. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि (वि.) जिला परिषद
7. उप निदेशक उद्यान शस्य/एनएचएम/नर्सरी/सांख्यिकी/विस्तार, उद्यान आयुक्तालय जयपुर।
8. आहरण वितरण अधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर
9. मुख्य लेखाधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।

आयुक्त उद्यानिकी

RajKaj Ref
12428896

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.17 18:29:56 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट-1												
Subsidy calculation for the Automation Program: An illustration												
राशि रुपये में												
क्र.सं.	कम्पोनेट क्रमांक	कम्पोनेट नाम	क्षेत्रफल (हे)	ईकाइ	संख्या	अनुमोदित ईकाइ लागत	कुल ईकाइ लागत	जीएसटी राशि @ 12%	कुल ईकाइ लागत मय जीएसटी	कुल देय अनुदान		
										CA+S	Add i. Top-Up	Total Subsidy @75%
1	1.48	2.5" Automatic Screen Filter (30m3/hr) with 220 Ac Unit	1	No.	1	4392.00	4392.00	5270.40	49190.00	36893.0	0.0	36893.0
2	1.02	Time based Irrigation & Fertigation Controller (4 Stations) with inbuilt rain sensor, Flow Detection Sensor, with minimum 2 program, inbuilt battery back Up (Suitable to Indian Conditions Erratic Electric Condition)	1	No.	1	1345.00	1345.00	1614.00	15064.00	40000.0	13214.0	53214.0
	1.08	2" Solenoid Valve with ON/OFF Manual Bleed (operating voltage 24 VAC for wired system)		No.	2	2990.00	5980.00	717.60	6697.60			
	1.48	2.5" Automatic Screen Filter (30m3/hr) with 220 Ac Unit		No.	1	4392.00	4392.00	5270.40	49190.00			
Total Unit Cost for 1.00 Ha									70952.00			
3	1.03	Irrigation Controller with (1-12 Station) Time Based with In Built Rain Sensor Port (220V Input & 24VAC Output) [Note: If the controller have the additional features viz. fertigation output and inbuilt rain sensor with over and above the minimum required features, it will be accepted for supply.]	1	No.	1	2910.00	2910.00	3492.00	32592.00	40000.0	170496.0	210496.0
	1.08	2" Solenoid Valve with ON/OFF Manual Bleed (operating voltage 24 VAC for wired system)		No.	6	2990.00	17940.00	2152.80	20092.80			
	1.71	Four Injector Fertilizer Unit		No.	1	197050.00	197050.00	23646.00	220696.00			
	1.28	1.5 Sqmm Copper Flexible wire Single Core (Live Wire)		Mtr	400	16.25	6500.00	780.00	7280.00			
Total Unit Cost for 1.00 Ha									280661.00			
4	1.03	Irrigation Controller with (1-12 Station) Time Based with In Built Rain Sensor Port (220V Input & 24VAC Output) [Note: If the controller have the additional features viz. fertigation output and inbuilt rain sensor with over and above the minimum required features, it will be accepted for supply.]	2	No.	1	2910.00	2910.00	3492.00	32592.00	77658.0	0.0	77658.0
	1.08	2" Solenoid Valve with ON/OFF Manual Bleed (operating voltage 24 VAC for wired system)		No.	10	2990.00	29900.00	3588.00	33488.00			
	1.18	Base Unit 12 Station with Suitable Communication Antenna with Ac Adopter		No.	1	1850.00	1850.00	2220.00	20720.00			
	1.44	Wireless Remote Unit- minimum 4 Stations-DC Type with Antenna, suitable Solar Panel and Rechargeable battery (With GI Pole of minimum 1.5" dia and 10 ft height) Suitable for all Irrigation Controller		No.	1	1495.00	1495.00	1794.00	16744.00			
Total Unit Cost for 2.00 Ha									103544.00			
5	1.03	Irrigation Controller with (1-12 Station) Time Based with In Built Rain Sensor Port (220V Input & 24VAC Output) [Note: If the controller have the additional features viz. fertigation output and inbuilt rain sensor with over and above the minimum required features, it will be accepted for supply.]	2	No.	1	2910.00	2910.00	3492.00	32592.00	80000.0	248400.0	328400.0
	1.08	2" Solenoid Valve with ON/OFF Manual Bleed (operating voltage 24 VAC for wired system)		No.	10	2990.00	29900.00	3588.00	33488.00			
	1.71	Four Injector Fertilizer Unit		No.	1	197050.00	197050.00	23646.00	220696.00			
	1.72	Automatic Fertilizer Mixing Unit (upto Four Injector) with Blower/ Agitator Unit and Piping Network		No.	1	9500.00	9500.00	1140.00	10640.00			
	1.7	Plastic Fertilizer Tank (500ltrs)		No.	4	6745.00	26980.00	3237.60	30217.60			

RajKaj Ref 12428896

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh K Ola

Designation : Commissioner

RajKaj Ref
12428896

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.17 18:29:56 IST
Reason: Approved

परिशिष्ट-1

Subsidy calculation for the Automation Program: An illustration												
राशि रुपये में												
क्र.सं.	कम्पोनेट क्रमांक	कम्पोनेन्ट नाम	क्षेत्रफल (हे)	ईकाइ	संख्या	अनुमोदित ईकाइ लागत	कुल ईकाइ लागत	जीएसटी राशि @ 12%	कुल ईकाइ लागत मय जीएसटी	कुल देय अनुदान		
										CA+S	Addi. Top-Up	Total Subsidy @75%
	3			o.		00	0.00	60	.60			
	1.28	1.5 Sqmm Copper Flexible wire Single Core (Live Wire)		Mtr	800	16.25	13000.00	1560.00	14560.00			
Total Unit Cost for 2.00 Ha									437954			

RajKaj Ref
12428896

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.12.17 18:29:56 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdih.ext.hort@rajasthan.gov.in)

क्रमांक: प.5 (22)आउ / Ext/ PDMC-MI/Fert./GL / 2024-25 /

दिनांक: .03.2025

उप निदेशक उद्यान, जयपुर व दौसा।

विषय:- वर्ष 2024-25 के दौरान ऑटोमेशन, फर्टीगेशन एवं समुदाय आधारित कृत्रिम बुद्धिमत्ता समाधान परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ऑफलाईन स्वीकृति एवं दिशा निर्देश बाबत।

प्रसंग:- आयुक्तालय के पत्र क्रमांक 10164643 दिनांक 02.09.2024 द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं लक्ष्यों के आवंटन के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत उद्यानिकी गतिविधियों में नवाचार एवं अत्याधुनिकतम तकनीकों को बढ़ावा देने के दृष्टिगत वर्ष 2024-25 के दौरान ऑटोमेशन फर्टीगेशन कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रसांगिक पत्र द्वारा योजना के दिशा-निर्देश एवं लक्ष्य जारी किये गये हैं। इस क्रम में फर्टीगेशन एवं ऑटोमेशन कार्यक्रम हेतु निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर आपूर्तिकर्ताओं के चयन पश्चात दर संविदा कार्यालय आदेश जारी किये जा चुके हैं।

चूंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है अतः फर्टीगेशन कार्यक्रम के कम्पोनेन्ट बायोफर्टीलाइजर की ऑनलाईन प्रक्रिया विकसित न होने के मध्यनजर इसके सफल क्रियान्वयन हेतु पत्रावलियों की प्राप्ति से लेकर भुगतान तक की पूर्ण प्रक्रिया ऑफलाईन की जा सकेगी ताकि वित्तीय वर्ष की कार्ययोजना अनुसार कार्य सम्पादित किया जा सकें। हालांकि राजकिसान साथी पोर्टल पर ऑनलाईन सुविधा विकसित होते ही पत्रावलियों का निस्तारण ऑनलाईन ही किया जावे।

इसी क्रम में बायोफर्टीलाइजर कम्पोनेन्ट के क्रियान्वयन हेतु प्रति हैक्टेयर दी जाने वाली मात्रा की गणना वर्ष 2024-25 में जारी लक्ष्यों एवं जारी की गई निविदा में अंकित बायोफर्टीलाइजर्स की मात्रा के आधार पर निम्नानुसार देय है:-

FERTIGATION PROGRAM (Bio Fertilizers)							
S.No.	Crop	Indicative Requirement (Litre or kg)					
		Liquid Consortia		Mycorrhizal Biofertilizer		Zinc Solubilizing Biofertilizers (ZSB) Liquid	
		Per 0.4 ha	Per ha	Per 0.4 ha	Per ha	Per 0.4 ha	Per ha
1	Vegetables	10.00	25.00	10.00	25.00	3.00	7.50
2	Fruits	5.00	12.50	5.00	12.50	2.00	5.00
3	Field crops & others	8.00	20.00	5.00	12.50	2.00	5.00

अतः तदनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(सुरेश कुमार ओला)
आयुक्त उद्यानिकी

क्रमांक: प.5 (22)आउ / Ext/ PDMC-MI/Fert./GL / 2024-25 /

दिनांक: 03.2025

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. संयुक्त निदेशक उद्यान, खण्ड जयपुर।

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Designation : Commissioner
Date: 2025.03.18 19:05:53 IST
Reason: Approved





COMMISSIONERATE OF HORTICULTURE
PANT KRISHI BHAWAN, JAIPUR-302005

(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jd.h.ext.hort@rajasthan.gov.in)



No. F5(7) CH/ PDMC-MI/Reg./2023-24/

Dated: .06.2023

OFFICE ORDER

The Terms & Conditions for Registration of Micro Irrigation System manufacturing companies under PDMC-MI for 03 year (2023-24 to 2025-26) are enclosed herewith for registration of manufacturers to execute PDMC-MI scheme in the State of Rajasthan.

All departmental officers, Micro Irrigation System manufacturing companies & authorized dealers are advised to strictly follow the terms & conditions for efficient and timely execution of scheme in the State with coordination among all stake holders.

Terms & Conditions for registration of Micro Irrigation System manufacturing companies under PDMC-MI for 03 year (2023-24 to 2025-26) are also available on web site of horticulture department (<https://horticulture.rajasthan.gov.in>) & SPPP (<https://sppp.rajasthan.gov.in>) also.

Enclosed-As above.

(Laxman Singh Kuri)
Commissioner Horticulture

No. F5(7) CH/ PDMC-MI/Reg./2023-24/

Dated: .06.2023

Copy to:

1. PS to Secretary, Agri & Hort., Govt. of Rajasthan, Jaipur.
2. PS to Commissioner, Agri. Govt. of Rajasthan, Jaipur.
3. PS to Commissioner Hort., Govt. of Rajasthan, Jaipur.
4. CAO, Commissionerate of Horticulture, Jaipur.
5. Joint Director, Horticulture, Division.....
6. Deputy Director, Horticulture, District.....
7. All Micro Irrigation System manufacturing companies.....

(Laxman Singh Kuri)
Commissioner Horticulture

Signature Not Verified

Digitally Signed by Laxman
Singh Kuri
Designation : Commissioner
Date :06-06-2023 11:41:02

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
COMMISSIONERATE OF HORTICULTURE, RAJASTHAN, JAIPUR
(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdih.ext.hort@rajasthan.gov.in)

**Registration of Micro Irrigation System manufacturing companies Under
Per Drop More Crop-PDMC (Micro Irrigation-MI) for the Year 2023-24 to
2025-26**

[Operational Guidelines of Per Drop More Crop-PDMC (Micro Irrigation-MI) Component of RKVY 2021]

Offers are invited for online registration from Micro Irrigation Manufacturers for supply/installation of BIS marked Drip / Sprinkler sets to the cultivators/farmers of Rajasthan at their fields under Per Drop More Crop-PDMC (Micro Irrigation-MI) for the year 2023-24 to 2025-26. It may be noted that this is not a government purchase.

1.0 Registration Application Procedure

- 1.1. Online application needs to be submitted by the authorized person of the manufacturing firm at RajKisanSathiPortal/ Application (<http://rajkisan.rajasthan.gov.in>). Registration application fees of Rs. 1000/- is to be deposited online at the time of online application which is non-refundable.
- 1.2. Registration will be made for two categories, viz. drip and sprinkler irrigation system. Drip category will cover the micro/ mini sprinklers as well as online and inline drip irrigation system while the sprinkler category will cover the portable sprinklers and large volume sprinklers (rain guns).
- 1.3. Separate registration applications for Sprinkler and Drip manufacturer needs to be submitted. The manufacturers, manufacturing both drip and sprinkler irrigation systems, needs to apply separately for both the systems.
- 1.4. One manufacturing unit will be registered for one brand only; however, the additional brand, on the logical with valid documents, request of the firm and after the satisfaction of the department may be registered with additional fees (same applicable for new registration).

Registration time, Validity and Renewal

- 1.5. The registration will be open round the year and a company can apply at any time to enable maximum flexibility and open participation. Any update/ variation in PDMC-MI Operational Guidelines/ policy of state/ central government will be applicable as and when required.
- 1.6. Registration of micro irrigation system manufacturers will be done with the approval of Department of Horticulture, Rajasthan/ SLSC for a period of three years. However, policy change at the level of central/ state government during the course of time may extend or reduce the period of registration.

- 1.7. The company once registered will be valid from the date of registration to year 2025-26 (Subject to any update in PDMC-MI Operational Guidelines which will supersede these terms conditions pertaining to validity period in terms of shorter or longer) although, the firm will have to be renewed in the beginning of every financial year.
- 1.8. The license validity renewal cases will be disposed by the registering authority once in the last week of every month. The manufacturer is supposed to submit the renewed BIS license within a grace period of 2 month after the expiry of validity.

Dealer/ Agentnetwork

- 1.9. The firm may either work directly with the farmers or through their dealer/ agent network or with both the options. In all cases, the manufacturer should authenticate the invoices.
- 1.10. The registration seeking firm needs to fill the details of the dealers/ agent in the state.
- 1.11. The deletion and addition of the dealer/ agent during the registration period will be made only on the basis of logical proposal by the registered firm.

Performance

- 1.12. The registration will be subject to the satisfactory performance of the company as assessed by the state implementing agency and repeated failures will lead to the de-registration by Department of Horticulture/ SLSC.

2.0 Registration Fees and Performance Security

- 2.1 The firm will submit a onetime registration fee of Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousand) for 3 years (2023-24to 2025-26). This is subject to the any change in Operational Guidelines ofPDMC-MI which may further reduce/ increase the period.
- 2.2 Separate Registration fee will be applicable for drip and sprinkler systems. If any firm is applying for registration of both sprinkler and drip irrigation system,separate registration fee will be applicable.
- 2.3 The fees will be deposited online as per the option provided in the registration application/ portal. However, option in the form of demand draft/ e-GRAS (e-Challan)willkept to deposit the fees if online system is not working. The demand draft will be payable to Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society and Commissioner Horticulture Rajasthan, Jaipur.
- 2.4 The registration fee is non-refundable.
- 2.5 The manufacturer shall have to submit a Bank Guarantee for due performance of contract and supplies.
- 2.6 The Bank guarantee of Rs. 5,00,000/- (Rs. Five Laonly) for Sprinkler & Rs. 10,00,000/- (Rs. Tenlaconly) for Drip needs to be submitted with a validity period up to 31st March, 2026 duly pledged in favour of Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society and Commissioner Horticulture Rajasthan, Jaipur.Provision of DD/ e-GRAS will also be allowed for performance security.
- 2.7 The validity of the Bank Guarantee needsto be extended (one year) every year at the time of registration renewal to cover the warrantee/ performance period of at least 3 years.

3.0 Eligibility

3.1 Manufacturing Facilities

- 3.1.1 Only those manufacturing companies, which have all the facilities to ensure supply of quality product as per BIS standards and can provide prompt after sales services will be registered.
- 3.1.2 The firm should either manufacture all the major MI components within their factory or in collaboration with specialized manufacturers.
- 3.1.3 The companies willing to participate in the scheme should be manufacturing below mentioned components and own BIS in their name.
 - 3.1.3.1 In the case of Drip irrigation System, company must manufacture at least laterals and emitting devices as specified conforming to BIS standards. For online drip irrigation systems, the company should be manufacturer of lateral tubing as well as drippers as per BIS and for inline drip irrigation systems, the company should be manufacturer of inline emitting pipe. In the case of Mini, Microsprinkler systems, the company should manufacture either of HDPE/ PVC/ PE pipes/ nozzles and should possess respective BIS.
 - 3.1.3.2 In the case of Sprinkler Irrigation System, the company should manufacture coupled HDPE pipes or sprinklers and should possess respective BIS.
- 3.1.4 The manufacturers seeking registration should declare the technical details of components proposed to be manufactured and supplied.
- 3.1.5 They must provide guarantee of quality assurance of other components which are not manufactured by them.

3.2 Experience and technical team

- 3.2.1 The firm/ company should have at least an experience of 5 years in the field of micro irrigation. Although, new entrepreneurs applying for registration need to establish the facts that their technical team is capable to implement the micro irrigation program successfully.
- 3.2.2 The firm/ company should have a strong technical team including Agronomists and Engineers to successfully implement the micro irrigation program.
- 3.2.3 The firm/ company should have strong dealer/ agent network in the state of Rajasthan.
- 3.2.4 The firm/ company should have sufficient service centres in the state to provide the services to the beneficiary farmers. In district where company is working, there should be at least one service centre to provide timely after sale service to farmers.

4.0 BIS License

- 4.1 The company will supply only BIS marked material. The list of relevant BIS components are given as:
- 4.1.1 Polyethylene pipes for Irrigation- Laterals with amendment number 6 IS 12786: 1989 (reaffirmed 2009)
 - 4.1.2 Irrigation Equipment-Emitters- Specification IS 13487: 1992 (reaffirmed 2009)
 - 4.1.3 Irrigation Equipment-Emitting pipes system Specification (first revision) IS 13488: 2008 (reaffirmed 2014)
 - 4.1.4 Irrigation Equipment-Strainer type filters Specification (first revision) IS 12785: 1994 (reaffirmed 2011)
 - 4.1.5 Irrigation equipment rotating sprinkler Part I, Design and Operational requirements (1st revision) IS 12232 (Part I) -1996 (reaffirmed 2011)
 - 4.1.6 Irrigation equipment rotating sprinkler Part 2, Test method for uniformity of distribution (1st revision) S 12232 (Part 2) -1995 (reaffirmed 2011)
 - 4.1.7 Fertilizer and Chemicals Injection system Part I Venturi Injector IS 14483 (Part 1) 1997 (reaffirmed 2009)
 - 4.1.8 Irrigation Equipment-Media Filters- Specification IS 14606: 1998 (reaffirmed 2009)
 - 4.1.9 Irrigation Equipment-Hydro cyclone filter-Specification IS 14743: 1999 (reaffirmed 2009)
 - 4.1.10 Unplasticized PVC pipes for portable water supplies Specification (third revision) IS 4985 – 2000
 - 4.1.11 Irrigation equipment- Sprinkler pipes -Specifications Quick coupled Polyethylene pipes & fittings IS 17425:2020.
 - 4.1.12 High Density Polyethylene Pipes for water supply Specification (fourth revision) IS 4984 : 1995 (reaffirmed 2002)
 - 4.1.13 Fertilizer & Chemical Injector System- Part 3 Fertilizer Tank IS:14483 Part 3 - 2016
- 4.2 In case the company intends to supply imported components, it should obtain prior approval of DAC&FW subject to indigenize the manufacturing of component within a period of two years.
- 4.3 In case of imported equipment, the techno- economic analysis report will be provided by NCPAH after proper examination and verification and submit report to DAC&FW for consideration.

5.0 Documents:

The following documents shall be uploaded for registration along with duly filled prescribed formats: -

- 5.1 Manufacturers should upload certified copy of valid BIS License in the name of applicant for the required components: -

Drip

i)	IS 4984: 1995	{HDPE Pipes}
ii)	IS 4985: 1999	{PVC Pipes for Water Supply}
iii)	IS 12785: 1994	{Strainer type Filters}
iv)	IS 12786: 1989	{PE Pipes for Irrigation Laterals with amendment No.5}
v)	IS 13487: 1992	{Emitters}
vi)	IS 13488: 2008	{Emitting Pipes Systems}
vii)	IS 17425:2020	{Polyethylene Pipes}
viii)	IS 14482: 1997	{PE Micro Tube for Drip Irrigation}
ix)	IS 14483 Pt 1: 1997	{Fertilizer and Chemicals Injector Systems Pt. 1 Ventury}
x)	IS 14605: 1998	{Micro Sprayers}
xi)	IS 14606: 1998	{Media Filter}
xii)	IS 14743: 1999	{Hydro Cyclone Separators}
xiii)	IS 14791: 2000	{P & T of blockage problems in DIS}
xiv)	IS 11624: 1986	{Quality of Irrigation Water}
xv)	IS 10805: 1986	{PVC Foot Valve & NRV}
xvi)	IS 10799: 1999	{Design, Inst. & Field evaluation of MIS}
xvii)	IS 10124: 1988	{Fabricated PVC Fittings}
xviii)	IS 8360: 1977	{PE Fabricated Fittings}
xix)	IS 7834: 1987	{Moulded PVC Fittings}
xx)	IS 1879: 1987	{GI & MS Fittings/ GI Pipes}
xxi)	IS 808: 2003	{PE Moulded Fittings}
xxii)	IS 780: 1984	{Sluice Valves}
xxiii)	IS 778: 1984	{GM Valves/ CI NRV}

Sprinkler

i)	IS 7092 Pt. 1/92 & Pt.2/87:	{Aluminium Alloy Tube for Irrigation Purpose Pt.1: Welded Tubes/ Pt.2: Extruded Tubes}
ii)	IS 17425:2020	{Polyethylene Pipes}
iii)	IS 17425:2020	{Quick-Coupled PE Pipes}
iv)	IS 12232 Pt.I: 1996	{Rotating Sprinkler/Nozzle: Design & OR}
v)	IS 12232 Pt.II: 1995	{Rotating Sprinkler/Nozzle: Test Method for UD}

5.2 In case any component is obtained from another manufacturer the offer should be accompanied with the authority letter & BIS License of manufacturer for this component.

5.3 A certified copy of application / registration of trademark from the competent authority in support of the brand for which the offer has been submitted.

5.4 The firms will have to give the following Undertakings on Rs.500/- Non Judicial Stamp paper:

"Whereby undertake to provide education to the farmers for agronomic practices to be followed for irrigation the crop with drip / sprinkler system, system's maintenance and warranty, inclusive of replacement of complete defective parts free of cost, for one year from date of installation on the farmer field for the sets supplied / installed by us to the farmers of Rajasthan under the scheme for subsidy.

The firm will set up service centers for providing technological and agronomic support at the grass root level & address of the same will be submitted for registration. Firm will provide free after sales service for three years after installation. Firm/Dealer will provide operating manual and eight after sales service coupons for three years to the farmers within a month of installation of the Drip/Sprinkler sets.

The firm undertakes to provide guarantee of quality assurance of all BIS/ Non BIS components, either manufactured by our self or outsourced from other company, our company will supply the BIS marked material only as per illustrated in list of BIS standard at annexure of DAC-GOI guideline of PDMC-MI. We will remain abide from quality control provision mentioned in GOI guideline & provide/use proper design in drip installation duly ensuring effective root zone wetting. In case of any complaint regarding quality aspect of any component/designing, we will fully responsible for the same & ready for replacement of component as well as rectification of design, if required, within 15 days of complaint and also suspected departmental action."

- 5.5 The firm will submit a one time for registration fee of Rs. 50,000/- (Rs. Fifty Thousandonly) in the form of demand draft (separately for Drip and Sprinkler) payable to Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society, Rajasthan, Jaipur. This registration fee is non-refundable.
- 5.6 The manufacturer shall have to submit a Bank Guarantee of Rs. 5,00,000/- (Rs. Five Laconly) for Sprinkler & Rs. 10,00,000/- (Rs. Ten lac only) for Drip valid up to 31st March, 2026 duly pledged in favour of Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society and Commissioner Horticulture, Rajasthan, Jaipur for due performance of contract and supplies.
- 5.7 The manufacturers have to produce their internal Quality Assurance and Quality Control (QAQC) plan, details of manufacturing process and manufacturing process and manufacturing plant & machinery, testing procedures of inputs & manufacturing process, Quality audit system and internal Quality Assurance and Quality Control Manual & Quality Report of Samples drawn earlier.
- 5.8 The manufacturing units have to produce the ISO 9000/9001 Certificate. The units, which do not have the same, must get and submit the certificate within 6 month of registration.
- 5.9 The firm will have to furnish the latest copies of GST/ IncomeTax Clearance Certificate / Registration Certificate.
- 5.10 The firm will have to provide detailed information comprising of name, address, mob..no., aadhar no., residence proof, office/shop proof of authorized dealers separately

with the application from which will be examined and sent to the district officers after approval from Commissionerate of Horticulture.

- 5.11 The firm will have to submit the details of all Executive, Administrative and technical officers working in the state of Rajasthan with photo affixed on the form along with, residence ID proof and aadhar no.

6.0 Supplies and pricing system

- 6.1 The material should be supplied directly by the manufacturer or their authorized distributors/dealers. In all cases, the manufacturer should authenticate the invoices.
- 6.2 Each company may have its own pricing system. However, the company would be required to submit the same to the Registering Authority/SLSC at the beginning of the year and as and when the prices are revised by the company.

7.0 After sales services, technical services& campaigns

- 7.1 The manufacturers should have network for providing after sales service in their areas of operation. Operation and maintenance of the system, though simple, requires training for maintenance, fertigation, chemigation, automation etc. in the initial stage. Therefore the manufacturers, should provide detailed operational and maintenance manuals in the vernacular language at the time of installation of the system. The beneficiaries should be advised to follow the instructions provided by the manufacturers for the operation and maintenance of the drip/ sprinkler irrigation systems.
- 7.2 Service Centers and / or Offices of drip / sprinkler system manufacturers should have facilities to provide technical guidance on agronomic practices, system maintenance schedules, supply spare parts and ensure satisfactory performance of the system during the warranty period. List of service centers / offices with full address / telephone number / e-mail should be widely published.
- 7.3 Free after sales service should be provided by the manufacturer / authorized distributor at least for three years from the date of installation. If any system manufacturer fails to provide such free service, the same shall be brought to the notice of DMIC and DAC / EC for taking appropriate action against the manufacturing company.
- 7.4 Operation and Maintenance of the system requires adequate training of beneficiaries for system operation etc. The manufacturers should have required network for providing training and after sales service in their areas of operation. The manufacturers should provide detailed operational and maintenance manual in the local vernacular language at the time of installation of the system. The beneficiaries should be advised to follow the instructions provided by the manufacturers for the operation and maintenance of drip/sprinkler irrigation systems.
- 7.5 Service centres and / or offices of drip / sprinklersystem manufacturers / authorized distributors should have facilities to provide technical guidance on system maintenance schedules, supply spare parts and ensure satisfactory performance of the system during the warranty period. The manufacturer should also operate a free customer care number where beneficiaries can register their complaints. List of service centres/offices/offices

- of authorized distributors with full address/telephone numbers/e-mail should be widely published.
- 7.6 After sales service should be provided by the manufacturer/authorized distributor, free of cost for at least a period of three years. The company shall repair or replace any components/instruments of the MI system free of cost within warranty period, if they are found to have manufacturing defects or workmanship defects.
 - 7.7 Due to normal wear and tear, if any parts/components require repairing/replacement, the company shall supply the same and recover the cost from the beneficiary after the free period is over. The company or its authorized representatives shall provide acid/chlorine treatment to drip system once during the first year of operation of the system.
 - 7.8 If any system manufacturer fails to provide such service, the same should be brought to the notice of district level committee and SLSC. The manufacturer would be responsible for any dispute arising from the supply of their product/component directly or through their authorized distributors/dealers. The Implementing Agency/ SLSC of each State shall evolve a process and modus operandi to redress the disputes, if any. In cases where product quality related complaints from beneficiaries are received due sampling process mentioned in the guidelines shall be followed.
 - 7.9 The SLSC may take measures against erring companies or their authorized dealers, as well as their own staff after due hearing in order to safeguard the interests of farmers/beneficiaries and to ensure effective utilization of public funds. However, before initiating any action, principle of natural justice should be followed.
 - 7.10 The manufacturer should submit the details of the authorized dealers/ agents/ distributors along with their jurisdiction. The manufacturer should take the responsibility for any disputes arising from the supply of their product through their distributors or dealers.
 - 7.11 The SMIC / IAs are free to take strong punitive measures against erring companies as well as against their own staff, in order to safeguard the interests of farmer's and to ensure effective utilization of public funds.
 - 7.12 There could be extension campaigns by the MI companies at a centralized location having area nodal officials, farmers & other related officials. Various aspects of system maintenance, acid treatment, fertigation, automation etc. could be covered.
 - 7.13 The campaigns by companies should cover all beneficiaries under warranty period & could be as under:

More than 5000 ha area coverage in the state 6 campaigns

1000-5000 ha area coverage in the state 4 campaigns

Less than 1000 ha area coverage in the state 2 campaigns

8.0 Quality Control

- 8.1 The company must provide guarantee of quality assurance of other components which are not manufactured by them in various technologies covered under the scheme.
- 8.2 The crucial aspect of supply of micro irrigation system is the quality of the hardware delivered to the farmer. Poor quality has an adverse impact on performance of the

system which may affect yield of the crop, quantity of water applied, quantity of fertilizer delivered to the plant etc. It may also increase energy consumption. In fact, sub standard system will not only adversely impact performance, but could also reduce the durability and the life of the components and / or system.

- 8.3 Frequent surveillance by inspection teams comprising officials from Horticulture Department/ NCPAH / PFDC/CIPET, Irrigation Association of India (IAI), BIS and TSG will be regular feature under the Scheme. They will draw random samples periodically from the field, within a period of three years from the date of installation of the system. At the time of inspection, the system should be fully functional.
- 8.4 Periodic inspections and sampling from the manufacturing unit by the Horticulture Departmental Officials. Adverse report for any manufacturing unit will be liable for show cause notice or suspension or rejection of the registration depending on the gravity of the case.
- 8.5 One surveillance visit per operative year shall be kept as the general norm, more or less inspections may be planned depending on the performance or specific guidelines issued.
- 8.6 Samples for testing should be collected jointly by the joint inspection team, state nodal official and the company representatives in triplicate and properly labelled, sealed and signed. The samples are collected for all major system components, especially pipes & tubing. One set of samples should be sent to CIPET/BIS or any other approved product testing laboratory for testing as the SLSC may deem fit, another set is to be preserved in the custody of nodal officer and the third one is to be with the manufacturer. After collection of samples at random, they should be coded as per BIS guidelines for the purpose of security and further reference.
- 8.7 Collection of samples with batch number is mandatory. The samples may be collected from the beneficiaries' fields as well as the supply chain of the manufacturer after the product has been dispatched from the manufacturing unit.
- 8.8 The quantity of material required for conducting the test is as detailed below:

Sl. No.	Test	Test samples required
Laterals as per IS : 12786 & Emitting Pipes as per IS : 13488		
1	Identification & composition analysis	15 meters for laterals. 50 meters for emitting pipe
2	Thickness	
3	Pressure Test	
4	Dimensions	
HDPE Pipes IS: 4984 /IS:17485 UPVC Pipes IS: 4985		
1	Identification & composition analysis	1 mts
2	Thickness	
3	Pressure Test	
4	Dimensions	
Emitters / drippers as per IS : 13487		
1	Identification & composition analysis	50 Nos
2	Flow Rate	

- 8.9 The expenditure towards the testing charges shall be met from the administrative charges under the scheme.
- 8.10 The state nodal officer will do proper scrutiny of the test report provided by the testing laboratory and draw conclusion from the findings regarding conformity or otherwise of the samples under the test. After scrutiny, the details of test report and results of conformity/non-conformity shall be placed before SLSC for consideration. In case of non-conformity, SLSC may take action against the company/its authorized dealers as per penalty clause mentioned in the scheme guidelines. The SLSC shall follow principle of natural justice and the company as well as the beneficiary shall be heard before taking a final action in the matter.
- 8.11 The firm will have to replace all the components of drip and sprinkler system taken as sample immediately after interception of sample so that the system may work uninterruptedly.

9.0 Violations & Penalties

- 9.1 In case of detection of failures for supply of poor sub-standard quality material, the concerned manufacturer will be issued warning for the first offence. In case of subsequent offence, the Company will be deregistered and restricted from participating in the PDMC –MI Scheme throughout the country in addition to invoking of bank guarantee.
- 9.2 The Central & State Governments, micro irrigation suppliers/manufacturers and other stake holders are putting in a lot of efforts for effective operations of micro irrigation systems. Any wrong operations could lead to system failure & financial loss to the beneficiary apart from loss of faith in the technology. It is, therefore, important to have well defined measures / terms for violation of norms by the stake-holders. Any violation to the quality, maintenance and other parameters need be viewed seriously. The list of violations mentioned below is not exhaustive and any other deviations, which affect the implementation of the scheme adversely may be considered by the DMIC/SLC as deemed fit for smooth functioning of the same.
- 9.3 A due process, where show cause is issued and adequate time is allowed for response, shall be followed and the MI companies as well as the beneficiary shall be adequately heard and natural justice provided.
- 9.4 In case of violations in respect of failure in quality control & quality assurance and to provide maintenance & after sales service, following penalties shall be imposed:
- First time in a year, a warning letter may be issued to the manufacturer instructing to rectify the shortcoming immediately.
 - Second time in same year, a warning letter may be issued to the manufacturer instructing to rectify the shortcoming immediately with a penalty of 10% of invoice value.
 - Third time in same year, a penalty of 25% of invoice value may be charged.

- Fourth time in same year, a show cause notice may be issued to the company and the case may be refer to SLSC for de-listing the company for a period of one year or more as decided by SLSC.
- 9.5 The violations with regard to submission of bills without installation/partial installation, wrong invoicing, variations in component specifications, submission of wrong documents with reference to pump/system discharge, improper installation, quoting higher price than approved, deviations from prescribed material specifications etc. may be dealt with by the SLSC suitably apart from initiating suitable action under the relevant sections of Indian penal code and other relevant/ appropriate statutory enactments.
- 9.6 In case of sale of the MI system to other farmers before expiry of average life of the system, for which subsidy has been claimed by the beneficiary, legal proceedings against the beneficiary as per applicable law may be initiated and the beneficiary may be blacklisted from availing any government assistance in future.

10.0 Other Terms & Conditions for Registration:

- 10.1 The manufacturers are required to prepare an estimate of cost and submit to the concerned office duly within one month indicating the time frame by when the system will be supplied and installed in the farmer's field.
- 10.2 The manufacturer Firm must provide free after sales service to the farmers at least for three years. Moreover, they should set up service centers for providing technological and agronomic support at the grass root level. In event, if any system manufacturer fails to abide by his commitments, appropriate action will be taken. Firm / Dealer will have to provide operating manual and eight after sales service coupons for three years to the farmers within a month installation of the Drip / Sprinkler sets. Firm / Dealer will have to submit annual service statement also to the concerned district officers up to 30th April mentioning the name of farmers, date of installation and number of service provided etc.
- 10.3 The material should be supplied directly by the manufactures only or their authorized distributor / dealer. In all cases the manufactures should authenticate the invoices and invoice no. of manufacturer with date should be mention on dealers invoice.
- 10.4 The manufacturers will have compulsorily engrave / emboss Batch No., Class, Brand, O.D., CML No., on the pipes supplied under subsidy scheme.
- 10.5 Manufacturing unit (factory) may be inspected before approval or as and when Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society, feels necessary to ensure the performance and quality of the product. Any official nominated by the Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society, will do inspection. Authorizes distributors / dealers may also be inspected as and when required.
- 10.6 A random sampling from the manufacturing unit or go-down or authorized distributor / dealer will as and when required, be performed to ascertain the quality of supplies. Provision of third party inspection from any authentic agency will also be kept so as to

- take samples of any manufacturer fail, the registration of the same will be withdrawn for rest of the financial year.
- 10.7 In the event of any complaint regarding after sales service or supply of defective / sub standard material is received, the registered firm shall have to rectify the defects within a period of 15 days. If the firm fails to comply, the bank guarantee shall be liable to be forfeited in part or as a whole on merits. The approved firm will also be liable to be blacklisted and they will not be registered in future for a period of three years.
- 10.8 In case of detection of failures or supply of poor sub standard quality material; the concerned manufacturer will be issued warning for first offence. In case subsequent offences, the company will be deregistered and debarred from participating in the MI Scheme throughout the country in addition to invoking of bank guarantee furnished by their dealers.
- 10.9 In order to ensure supply of BIS quality materials to the farmers the manufacturers who are registered to participate in Micro Irrigation Scheme should manufacture only such system component, which has BIS Certification.
- 10.10 The manufacturer should take the responsibility in case of any dispute arising from the supply of their product through their distributor or dealer.
- 10.11 The SMIC /IAs are free to evolve strong punitive measure against erring companies as well as against their own staff, in order to safeguard the interests of farmers and in order to ensure qualitative utilization of public funds.
- 10.12 Manufacturers should send details of quarterly statement of stock with each authorized agent to the head of respective District Horticulture Development Society.
- 10.13 Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society, Rajasthan, Jaipur reserves the right to reject / cancel the registration of the offers of manufacturers at any time if he is satisfied that it is desirable to do so in farmer interest, after giving an opportunity of hearing to such an applicant. The decision of Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society, Rajasthan, Jaipur shall be final and binding.
- 10.14 Registration will be subject to any other conditions from time to time, which the Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society, Rajasthan, Jaipur may feel necessary to safeguard the interest of farmers.
- 10.15 Registered firm will have to execute an agreement for due performance of obligations to the farmer as per terms and conditions fixed by the Commissioner Horticulture/ Mission Director, Rajasthan Horticulture Development Society, Rajasthan, Jaipur.

Commissioner Horticulture

Agreement

1. An agreement signed on dated.....202.....between M/s.....Herein called the approved/ Registered supplier which expression shall where the context so admits, be deemed to include his heirs successors executors and administration of the one part and the Govt. of the State of Rajasthan through Commissioner Horticulture, Department of Horticulture, Rajasthan Hereinafter called the Govt. which expression shall where the context so admits be deemed to include his successor in office and assigns of the other part.
2. Whereas approved supplier has agreed with the Govt./ Department of Horticulture/ RHDS to supply the sprinklers/drips to the farmers of the State of Rajasthan in the manner set forth in the terms & conditions of the registration context appended herewith.
3. Whereas the approved supplier has agreed not supply to any institutions/Government Department within or outside the state at lower rates than what he has offered to the Horticulture Department of Govt. of Rajasthan. If it is found that the firm is supplying sprinkler/drip sets at rates lower than quoted with Horticulture Dept. then the firm will have to pay back the excess money charged from the cultivators to the Horticulture Department.
4. Third party inspection certificate ISO certificate (if not submitted earlier) will be submitted within the stipulated period as per the terms and conditions of the registration.
5. The Department will have the right to invoke the B.G. furnished by the suppliers as and when required to do so.
6. If the approved supplier violets any of the terms & conditions of this agreement the Department will be free to invoke the B.G. in whole or in part thereof.
7. The supplier agrees to send initial available Stock with each dealer in every district. Subsequently monthly statement of sets transferred to each such dealer shall be sent to each district. This information will regularly be sent to the Dy. Directors of each district and to the Director of Horticulture, Jaipur. the supplier further agrees that failure to comply with this requirement shall be penal action as deemed appropriate by the Govt.
8. All disputed arising out of this agreement and all question relating to the interpretation of meeting and break of the terms and conditions of the contract, the parties shall refer to the matter to the Mission Director, R.H.D.S./ commissioner Horticulture, Jaipur whose decision will be final.
9. All legal proceeding if necessary shall have to be lodged at Jaipur only.

Signature of the approved Supplier

**Signature for and on behalf of
theGovernor**

Date.....

Date.....

Witness No. 1

Witness No. 1

Witness No. 2

Witness No. 2

राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, राजस्थान जयपुर

क्रमांक एफ 5(56) आ.उ./प्रशिक्षण/2023-24/

दिनांक:- .09.2024

उप निदेशक उद्यान,
समस्त.....।

विषय:- पी.डी.एम.सी. (सूक्ष्म सिंचाई योजना) योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 के तहत कृषक दम्पति प्रशिक्षण आयोजन के लक्ष्य आवंटन एवं दिशानिर्देश जारी करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राज्य में पी.डी.एम.सी.(सूक्ष्म सिंचाई योजना) योजनान्तर्गत वर्ष 2024-25 के तहत उद्यान विभाग के जिला कार्यालयों द्वारा **एक दिवसीय कृषक दम्पति प्रशिक्षणों** के आयोजन हेतु निम्न दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं।

- 1 कृषक दम्पति स्वयं प्रशिक्षण स्थल के नजदीक कृषि भूमि का स्वामी हो।
- 2 कृषक दम्पति द्वारा उद्यानिकी गतिविधियाँ क्रियान्वित की जा रही हों।
- 3 कृषकों का प्रशिक्षण विश्वविद्यालय/केवीके/विभागीय एटीसी एवं अन्य भारत सरकार के कृषि संस्थानों में आयोजित कराये जावें।
- 4 प्रशिक्षणों में तकनीकी व्याख्यान विश्वविद्यालय/केवीके/विभागीय एटीसी एवं अन्य भारत सरकार के कृषि संस्थानों में कार्यरत तकनीकी कृषि वैज्ञानिकों/अधिकारियों द्वारा ही करवाया जावे।
- 5 प्रशिक्षणों में सूक्ष्म सिंचाई की उन्नत तकनीक यथा आटोमेशन, फर्टिगेशन की तकनीकी जानकारी कृषकों को दी जावे।
- 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम में उप निदेशक उद्यान/सहायक निदेशक उद्यान के साथ खण्डीय अधिकारी की उपस्थिति वांछनीय है।
- 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम के विवरण संबंधी एक बैनर लगाकर ग्रुप फोटो लेकर प्रगति सहित आयुक्तालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
- 8 प्रशिक्षण समाप्ति उपरान्त प्रतिभागी कृषकों के साथ प्रशिक्षण संबंधी प्रश्नोत्तरी का आयोजन कराया जावे। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पाने वाले कृषकों को क्रमशः 1000 रुपये, 600 रुपये एवं 400 रुपये तक की कृषि/उद्यानिकी कार्यों में उपयोग आने वाली सामग्री पुरस्कार के रूप में दी जावे।
- 9 प्रशिक्षण हेतु मदवार विवरण:-

अ. प्रशिक्षणार्थियों की संख्या- 50 (25 कृषक दम्पति)

ब. बजट प्रावधान:- 50,000/-रुपये प्रति प्रशिक्षण

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar
Ola
Designation : Commissioner
Date: 2024.09.10 15:21:01 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन, जयपुर
(Ph. +91 141 2227606 e-mail: jdh.ext.hort@rajasthan.gov.in)

क्रमांक: एफ.5 (6)आ.उ./PDMC-MI /गु.नि./ 2023-24 /

दिनांक:

1.संयुक्त निदेशक उद्यान खण्ड.....

2.उप निदेशक उद्यान, जिला.....।

विषय:- "राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई मिशन" PDMC-MI योजना के तहत कृषक खेतों पर स्थापित किये गये ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई संयंत्रों की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु वर्ष 2023-24 हेतु नमूने आहरित करने के लिये आवश्यक दिशा-निर्देश एवं लक्ष्य भिजवाने बाबत।

राज्य में सूक्ष्म सिंचाई योजना के प्रभावी परिणाम प्राप्त करने के दृष्टिगत कृषकों को उच्च गुणवत्ता के सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना नितान्त आवश्यक है। इस हेतु समय-समय पर सिंचाई संयंत्रों के मुख्य कम्पोनेंटस के विभिन्न स्टेक होल्डर्स से रेण्डम आधार पर नमूने आहरित कर प्रयोगशाला परीक्षण करवाया जाना आवश्यक है।

गुणवत्ता नियंत्रण लक्ष्य

गत 02 वर्षों में स्थापित तथा वर्तमान में स्थापित किये गये ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई संयंत्रों के **परिशिष्ट-अ** में जिलों के सामने अंकित कम्पोनेंटस के नमूनों का आहरण किया जाकर जाँच हेतु सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET) एसपी-1298, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र फेज-3, टॉक रोड, जयपुर को भिजवाया जाना है। तालिका में अंकित कम्पोनेंटस में एक नमूने के लक्ष्य की स्थिति में नमूना कृषक खेत से लिया जाना है तथा एक से अधिक नमूनों की संख्या होने पर एक नमूना संयंत्र निर्माता अथवा डीलर के स्टॉक से लिया जाना सुनिश्चित करावें।

गुण नियंत्रण कार्यवाही के दिशा-निर्देश/प्रक्रिया

कृषक खेतों से ड्रिप अथवा फव्वारा सिंचाई संयंत्रों के स्थापित पूर्ण सेट से ही समस्त कम्पोनेंटस के नमूनों का आहरण करावें ताकि निर्माता कम्पनी द्वारा स्थापित किये गये एक पूर्ण संयंत्र की गुणवत्ता की जाँच की जा सके। नमूनों के आहरण हेतु **नमूने का कम्पोनेंटवार आकार अथवा संख्या** का विवरण **परिशिष्ट-ब** पर उपलब्ध है। नमूना आहरण प्रक्रिया का विवरण निम्नानुसार है-

1. जिला स्तर पर निरीक्षण एवं नमूना लेने हेतु अधिकारियों की टीम निम्नानुसार गठित की जाती है:-

निरीक्षण एवं नमूना टीम	कार्यक्षेत्र
1. खण्डीय संयुक्त निदेशक उद्यान	स्वयं का कार्य क्षेत्र
1. उप/सहायक निदेशक उद्यान (संबंधित जिले का) 2. कृषि अधिकारी उद्यान	संबंधित जिला

2.

नमूना लेने के लिए विभिन्न अवयवों की निर्धारित मात्रा परिशिष्ट-अ में निर्धारित लक्ष्यानुसार लेनी होगी।

RajKaj Ref
4980081

3. नमूनों को कपड़े/टांट में पैक कर सील बंद किया जायेगा। जिस पर नमूनों का कोड न., बैच नम्बर निर्माता, दिनांक लिखकर हस्ताक्षर कर सील बंद किया जायेगा।
4. नमूना निर्माता, डीलर, किसान के अथवा उसके प्रतिनिधि के समक्ष लिया जायेगा एवं प्रपत्रों पर निर्माता/डीलर, किसान, टीम सदस्यों के हस्ताक्षर करवाये जायेंगे।
5. नमूना दो प्रतियों में लिया जायेगा। एक प्रति पत्र के साथ में सीपेट को टेस्टिंग हेतु भिजवाई जायेगी एवं एक प्रति संबंधित कार्यालय में सुरक्षित रखी जायेगी।
6. निरीक्षण एवं नमूना हेतु निर्धारित प्रपत्र भरे जायेंगे एवं एक प्रति निर्माता कम्पनी/डीलर/किसान को दी जायेगी एवं एक प्रति मय पत्र आयुक्तालय को भिजवायी जायेगी।
7. नमूना हेतु ली गई सामग्री के बिल की प्रति संबंधित कृषक/फर्म से प्राप्त की जावेगी जिसका भुगतान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के **विविध मद** (2401-00-119-26-28) में आवंटित बजट से किया जावेगा।
8. राज्य के विभिन्न जिलों में स्थापित सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र निर्माताओं के निर्माण परिसर से संबंधित जिले के अधिकारियों द्वारा रेण्डम आधार पर नमूने आवश्यक रूप से लिये जाकर परीक्षण हेतु प्रयोगशाला में भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावे।
9. सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र निर्माताओं के निर्माण परिसर/अधिकृत डीलर का निरीक्षण, नमूनों का आहरण एवं कृषकों के खेत से लिये गये नमूनों का मासिक पर्यवेक्षण संबंधित खण्डीय संयुक्त निदेशक उद्यान द्वारा किया जाकर प्रगति से आयुक्तालय को प्रति माह अवगत कराया जाना है।
10. समय-समय पर उद्यान आयुक्तालयों के अधिकारियों द्वारा भी सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र निर्माताओं के निर्माण परिसर/अधिकृत डीलर का निरीक्षण, नमूनों का आहरण कार्य करने हेतु खण्डीय संयुक्त निदेशक उद्यान द्वारा अधीनस्थ कार्य क्षेत्र के जिलों से चर्चा कर मासिक कलैण्डर तैयार किया जावे जिसकी सूचना उद्यान आयुक्तालय को प्रेषित की जावे ताकि इस कार्य हेतु उद्यान आयुक्तालयों के अधिकारियों का मनोनयन किया जा सके।

तालिका में अंकित नमूनों का जिलेवार आवंटित लक्ष्यों के अनुरूप संलग्न प्रपत्रानुसार शीघ्र आहरण कर **सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET) एसपी-1298, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-III, टोंक रोड़, जयपुर-22** को जाँच हेतु भिजवाना सुनिश्चित करावे।

उल्लेखनीय है कि सूक्ष्म सिंचाई संयंत्रों की गुणवत्ता सुनिश्चित किया जाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। गुण नियंत्रण के लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं किये जाने की स्थिति में इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारी के वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल टिप्पणी अंकित की जावेगी।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(लक्ष्मण सिंह कुड़ी)

आयुक्त उद्यानिकी

दिनांक:

क्रमांक: एफ.5 (6)आ.उ./PDMC-MI /गु.नि./2023-24 /

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी, शासन सचिवालय राज., जयपुर।
2. निदेशक, सेन्ट्रल इन्स्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजिनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी (CIPET)

एसपी-1298, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, फेज-III, टोंक रोड़ जयपुर-22।

कम्पोनेन्टवार ड्रिप एवं फव्वारा सिंचाई संयंत्रों के नमूनों का आकार

Drip Irrigatin system		
Sr. No.	Name of Product/ Standards	Size of Sample
1	Irrigation Laterals As per IS:12786-1989	05Mtrs.
2	Emitters as per IS:13487-1992 with Amendment No.1	30 Nos.
3	Emitting pipe systems as per IS:13488-2008	Pipe consisting 30 Nos.of Emitting units +Connector
4	The un-plasticized PVC Pipe for portable water supply (with socket End) as per IS:4985-2000 with latest amendment.	03 Nos.of 1 mtr.each (Included Socket Ended Two nos.)
5	Irrigation equipment-strainer Type Filters As per IS:12785-1994	01 Nos.
Sprinkler Irrigation System		
6 (a)	Irrigation Equipment-Sprinkler Pipes-(Quick Coupled) Polyethylene Pipes As per IS:17425	3x1 mtr. Two Plain Ended & One with Socketed male and female with holding attachment and Rubber Rings.
(b)	IS:17425:2008 with amendment No.1 & 2	
7	Irrigation Equipment Rotating Sprinkler as per IS:12232-PT-1:1996	03 Nos.

RajKaj Ref
4980081

Signature Not Verified
Digitally Signed by Laxman
Singh Kuri
Designation : Commissioner
Date :19-12-2023 12:16:30

Computation of Annual Action plan 2025-26 (Physical Targets Ha.)

Sr.No	District	Drip (Close Specing)				Drip (wide Spacing)				Mini/ micro Sprinkler				Sprinkler/ Raingun				G. Total			
		Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total
1	Ajmer	1419	89	9	1517	222	35	9	266	292	29	20	341	3066	511	205	3782	4999	664	243	5906
2	Alwar	154	46	109	309	31	8	7	46	2180	121	484	2785	1105	158	252	1515	3470	333	852	4655
3	Balotara	395	63	16	474	2368	158	20	2546	109	11	4	124	812	81	25	918	3684	313	65	4062
4	Banswara	45	5	202	252	10	0	5	15	172	34	1345	1551	69	14	1432	1515	296	53	2984	3333
5	Baran	230	22	93	345	69	13	35	117	1081	99	786	1966	2796	140	979	3915	4176	274	1893	6343
6	Barmer	4582	458	115	5155	573	115	28	716	5411	291	42	5744	5986	599	119	6704	16552	1463	304	18319
7	Beawar	100	13	4	117	21	4	0	25	10	0	0	10	817	91	26	934	948	108	30	1086
8	Bharatpur	99	7	12	118	82	6	9	97	61	2	7	70	150	9	15	174	392	24	43	459
9	Bhilwara	1439	252	107	1798	57	14	8	79	163	43	25	231	4728	941	705	6374	6387	1250	845	8482
10	Bikaner	201	40	4	245	56	16	4	76	567	57	11	635	5941	1782	60	7783	6765	1895	79	8739
11	Bundi	300	238	612	1150	38	25	75	138	1039	445	1485	2969	627	157	939	1723	2004	865	3111	5980
12	Chittorgarh	146	14	8	168	88	15	7	110	325	28	14	367	6723	1233	560	8516	7282	1290	589	9161
13	Churu	491	62	31	584	31	12	3	46	858	71	36	965	5318	945	118	6381	6698	1090	188	7976
14	Dausa	46	13	66	125	54	27	151	232	343	69	458	870	861	377	2690	3928	1304	486	3365	5155
15	Deeg	61	4	6	71	38	5	4	47	49	1	2	52	71	4	5	80	219	14	17	250
16	Dholpur	0	0	0	0	23	8	14	45	21	7	14	42	218	78	139	435	262	93	167	522
17	Didwana Kuchaman	470	94	0	564	19	9	0	28	1007	155	0	1162	2647	318	53	3018	4143	576	53	4772
18	Dungarpur	15	1	9	25	5	0	4	9	10	0	51	61	71	5	490	566	101	6	554	661
19	Ganganagar	52	6	0	58	210	10	0	220	83	9	0	92	4433	886	0	5319	4778	911	0	5689
20	Hanumangarh	133	14	6	153	167	13	7	187	147	15	7	169	8239	1177	23	9439	8686	1219	43	9948
21	Jaipur	6795	480	1055	8330	59	12	29	100	6008	447	1607	8062	5068	456	642	6166	17930	1395	3333	22658
22	Jaisalmer	63	8	0	71	48	8	0	56	50	17	-1	66	2099	840	420	3359	2260	873	419	3552
23	Jalore	11287	757	151	12195	1226	237	51	1514	10164	593	225	10982	3310	231	93	3634	25987	1818	520	28325
24	Jhalawar	986	494	370	1850	987	493	370	1850	6657	2663	3328	12648	1917	767	894	3578	10547	4417	4962	19926
25	Jhunjhunu	459	17	17	493	85	9	8	102	998	60	40	1098	4303	287	72	4662	5845	373	137	6355
26	Jodhpur	226	21	8	255	106	18	3	127	7911	1187	63	9161	4686	750	47	5483	12929	1976	121	15026
27	Karauli	1	0	3	4	6	1	5	12	30	5	41	76	291	74	359	724	328	80	408	816
28	Khairthal Tijara	191	19	9	219	19	5	2	26	7271	291	97	7659	1104	92	46	1242	8585	407	154	9146
29	Kota	81	8	21	110	81	7	23	111	494	33	132	659	2620	175	698	3493	3276	223	874	4373
30	Kotputli Behror	1404	149	99	1652	42	4	4	50	10857	388	387	11632	852	122	121	1095	13155	663	611	14429
31	Nagaur	3324	207	4	3535	41	17	0	58	612	129	0	741	3347	413	0	3760	7324	766	4	8094
32	Pali	108	21	15	144	72	22	14	108	29	7	74	110	1370	274	182	1826	1579	324	285	2188
33	Phalodi	120	15	6	141	90	18	3	111	2002	858	28	2888	3587	646	36	4269	5799	1537	73	7409
34	Pratapgarh	56	11	56	123	67	6	56	129	410	273	341	1024	1118	335	2235	3688	1651	625	2688	4964
35	Rajsamand	169	9	4	182	61	6	5	72	49	3	1	53	632	158	126	916	911	176	136	1223
36	S. Madhpur	227	90	136	453	680	454	907	2041	1405	351	2109	3865	378	189	505	1072	2690	1084	3657	7431
37	Salumber	2	0	1	3	3	1	2	6	3	0	1	4	26	9	42	77	34	10	46	90
38	Sikar	2149	143	48	2340	143	19	10	172	7426	437	73	7936	7989	1524	263	9776	17707	2123	394	20224
39	Sirohi	177	36	37	250	153	29	29	211	1846	481	262	2589	1448	220	280	1948	3624	766	608	4998
40	Tonk	149	37	74	260	74	15	37	126	250	83	166	499	2545	848	1696	5089	3018	983	1973	5974
41	Udaipur	59	4	40	103	20	4	8	32	28	4	10	42	563	56	507	1126	670	68	565	1303
Total		38411	3967	3563	45941	8225	1878	1956	12059	78428	9797	13775	102000	103931	17972	18099	140002	228995	33614	37393	300002

Computation of Annual Action plan 2025-26 (CA in lac Rs.)

Sr.No	District	Drip (Close Spacing)				Drip (wide Spacing)				Mini/ micro Sprinkler				Sprinkler/ Raingun				G. Total			
		Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total
		39398	39398	39398		12834	12834	12834		32097	32097	32097		7476	7476	7476					
1	Ajmer	559.06	35.06	3.55	597.67	28.49	4.49	1.16	34.14	93.72	9.31	6.42	109.45	229.21	38.20	15.33	282.74	910.48	87.06	26.46	1024.00
2	Alwar	60.67	18.12	42.94	121.73	3.98	1.03	0.90	5.91	699.71	38.84	155.35	893.90	82.61	11.81	18.84	113.26	846.97	69.80	218.03	1134.80
3	Balotara	155.62	24.82	6.30	186.74	303.91	20.28	2.57	326.76	34.99	3.53	1.28	39.80	60.71	6.06	1.87	68.64	555.23	54.69	12.02	621.94
4	Banswara	17.73	1.97	79.58	99.28	1.28	0.00	0.64	1.92	55.21	10.91	431.70	497.82	5.16	1.05	107.06	113.27	79.38	13.93	618.98	712.29
5	Baran	90.62	8.67	36.64	135.93	8.86	1.67	4.49	15.02	346.97	31.78	252.28	631.03	209.03	10.47	73.19	292.69	655.48	52.59	366.60	1074.67
6	Barmer	1805.22	180.44	45.31	2030.97	73.54	14.76	3.59	91.89	1736.77	93.40	13.48	1843.65	447.51	44.78	8.90	501.19	4063.04	333.38	71.28	4467.70
7	Beawar	39.40	5.12	1.58	46.10	2.70	0.51	0.00	3.21	3.21	0.00	0.00	3.21	61.08	6.80	1.94	69.82	106.39	12.43	3.52	122.34
8	Bharatpur	39.00	2.76	4.73	46.49	10.52	0.77	1.16	12.45	19.58	0.64	2.25	22.47	11.21	0.67	1.12	13.00	80.31	4.84	9.26	94.41
9	Bhilwara	566.94	99.28	42.16	708.38	7.32	1.80	1.03	10.15	52.32	13.80	8.02	74.14	353.47	70.35	52.71	476.53	980.05	185.23	103.92	1269.20
10	Bikaner	79.19	15.76	1.58	96.53	7.19	2.05	0.51	9.75	181.99	18.30	3.53	203.82	444.15	133.22	4.49	581.86	712.52	169.33	10.11	891.96
11	Bundi	118.19	93.77	241.12	453.08	4.88	3.21	9.63	17.72	333.49	142.83	476.64	952.96	46.87	11.74	70.20	128.81	503.43	251.55	797.59	1552.57
12	Chittorgarh	57.52	5.52	3.15	66.19	11.29	1.93	0.90	14.12	104.32	8.99	4.49	117.80	502.61	92.18	41.87	636.66	675.74	108.62	50.41	834.77
13	Churu	193.44	24.43	12.21	230.08	3.98	1.54	0.39	5.91	275.39	22.79	11.55	309.73	397.57	70.65	8.82	477.04	870.38	119.41	32.97	1022.76
14	Dausa	18.12	5.12	26.00	49.24	6.93	3.47	19.38	29.78	110.09	22.15	147.00	279.24	64.37	28.18	201.10	293.65	199.51	58.92	393.48	651.91
15	Deeg	24.03	1.58	2.36	27.97	4.88	0.64	0.51	6.03	15.73	0.32	0.64	16.69	5.31	0.30	0.37	5.98	49.95	2.84	3.88	56.67
16	Dholpur	0.00	0.00	0.00	0.00	2.95	1.03	1.80	5.78	6.74	2.25	4.49	13.48	16.30	5.83	10.39	32.52	25.99	9.11	16.68	51.78
17	Didwana Kuchaman	185.17	37.03	0.00	222.20	2.44	1.16	0.00	3.60	323.22	49.75	0.00	372.97	197.89	23.77	3.96	225.62	708.72	111.71	3.96	824.39
18	Dungarpur	5.91	0.39	3.55	9.85	0.64	0.00	0.51	1.15	3.21	0.00	16.37	19.58	5.31	0.37	36.63	42.31	15.07	0.76	57.06	72.89
19	Ganganagar	20.49	2.36	0.00	22.85	26.95	1.28	0.00	28.23	26.64	2.89	0.00	29.53	331.41	66.24	0.00	397.65	405.49	72.77	0.00	478.26
20	Hanumangarh	52.40	5.52	2.36	60.28	21.43	1.67	0.90	24.00	47.18	4.81	2.25	54.24	615.95	87.99	1.72	705.66	736.96	99.99	7.23	844.18
21	Jaipur	2677.09	189.11	415.65	3281.85	7.57	1.54	3.72	12.83	1928.39	143.47	515.80	2587.66	378.88	34.09	48.00	460.97	4991.93	368.21	983.17	6343.31
22	Jaisalmer	24.82	3.15	0.00	27.97	6.16	1.03	0.00	7.19	16.05	5.46	-0.32	21.19	156.92	62.80	31.40	251.12	203.95	72.44	31.08	307.47
23	Jalore	4446.85	298.24	59.49	4804.58	157.34	30.42	6.55	194.31	3262.34	190.34	72.22	3524.90	247.46	17.27	6.95	271.68	8113.99	536.27	145.21	8795.47
24	Jhalawar	388.46	194.63	145.77	728.86	126.67	63.27	47.49	237.43	2136.70	854.74	1068.19	4059.63	143.31	57.34	66.84	267.49	2795.14	1169.98	1328.29	5293.41
25	Jhunjhunu	180.84	6.70	6.70	194.24	10.91	1.16	1.03	13.10	320.33	19.26	12.84	352.43	321.69	21.46	5.38	348.53	833.77	48.58	25.95	908.30
26	Jodhpur	89.04	8.27	3.15	100.46	13.60	2.31	0.39	16.30	2539.19	380.99	20.22	2940.40	350.33	56.07	3.51	409.91	2992.16	447.64	27.27	3467.07
27	Karauli	0.39	0.00	1.18	1.57	0.77	0.13	0.64	1.54	9.63	1.60	13.16	24.39	21.76	5.53	26.84	54.13	32.55	7.26	41.82	81.63
28	Khairthal Tijara	75.25	7.49	3.55	86.29	2.44	0.64	0.26	3.34	2333.77	93.40	31.13	2458.30	82.54	6.88	3.44	92.86	2494.00	108.41	38.38	2640.79
29	Kota	31.91	3.15	8.27	43.33	10.40	0.90	2.95	14.25	158.56	10.59	42.37	211.52	195.87	13.08	52.18	261.13	396.74	27.72	105.77	530.23
30	Kotputli Behror	553.15	58.70	39.00	650.85	5.39	0.51	0.51	6.41	3484.77	124.54	124.22	3733.53	63.70	9.12	9.05	81.87	4107.01	192.87	172.78	4472.66
31	Nagaur	1309.59	81.55	1.58	1392.72	5.26	2.18	0.00	7.44	196.43	41.41	0.00	237.84	250.22	30.88	0.00	281.10	1761.50	156.02	1.58	1919.10
32	Pali	42.55	8.27	5.91	56.73	9.24	2.82	1.80	13.86	9.31	2.25	23.75	35.31	102.42	20.48	13.61	136.51	163.52	33.82	45.07	242.41
33	Phalodi	47.28	5.91	2.36	55.55	11.55	2.31	0.39	14.25	642.58	275.39	8.99	926.96	268.16	48.29	2.69	319.14	969.57	331.90	14.43	1315.90
34	Pratapgarh	22.06	4.33	22.06	48.45	8.60	0.77	7.19	16.56	131.60	87.62	109.45	328.67	83.58	25.04	167.09	275.71	245.84	117.76	305.79	669.39
35	Rajsamand	66.58	3.55	1.58	71.71	7.83	0.77	0.64	9.24	15.73	0.96	0.32	17.01	47.25	11.81	9.42	68.48	137.39	17.09	11.96	166.44
36	S. Madhpur	89.43	35.46	53.58	178.47	87.27	58.27	116.40	261.94	450.96	112.66	676.93	1240.55	28.26	14.13	37.75	80.14	655.92	220.52	884.66	1761.10
37	Salumber	0.79	0.00	0.39	1.18	0.39	0.13	0.26	0.78	0.96	0.00	0.32	1.28	1.94	0.67	3.14	5.75	4.08	0.80	4.11	8.99
38	Sikar	846.66	56.34	18.91	921.91	18.35	2.44	1.28	22.07	2383.52	140.26	23.43	2547.21	597.26	113.93	19.66	730.85	3845.79	312.97	63.28	4222.04
39	Sirohi	69.73	14.18	14.58	98.49	19.64	3.72	3.72	27.08	592.51	154.39	84.09	830.99	108.25	16.45	20.93	145.63	790.13	188.74	123.32	1102.19
40	Tonk	58.70	14.58	29.15	102.43	9.50	1.93	4.75	16.18	80.24	26.64	53.28	160.16	190.26	63.40	126.79	380.45	338.70	106.55	213.97	659.22
41	Udaipur	23.24	1.58	15.76	40.58	2.57	0.51	1.03	4.11	8.99	1.28	3.21	13.48	42.09	4.19	37.90	84.18	76.89	7.56	57.90	142.35
	Total	15133.13	1562.91	1403.74	18099.78	1055.61	241.05	251.07	1547.73	25173.04	3144.54	4421.34	32738.92	7769.88	1343.57	1353.08	10466.53	49131.66	6292.07	7429.23	62852.96

Computation of Annual Action plan 2025-26 (SS in lac Rs..)

Sr.No	District	Drip (Close Specing)				Drip (wide Spacing)				Mini/ micro Sprinkler				Sprinkler/ Raingun				G. Total			
		Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total
		26265	26265	26265		8556	8556	8556		21398	21398	21398		4984	4984	4984					
1	Ajmer	372.70	23.38	2.36	398.44	18.99	2.99	0.77	22.75	62.48	6.21	4.28	72.97	152.81	25.47	10.22	188.50	606.98	58.05	17.63	682.66
2	Alwar	40.45	12.08	28.63	81.16	2.65	0.68	0.60	3.93	466.48	25.89	103.57	595.94	55.07	7.87	12.56	75.50	564.65	46.52	145.36	756.53
3	Balotara	103.75	16.55	4.20	124.50	202.61	13.52	1.71	217.84	23.32	2.35	0.86	26.53	40.47	4.04	1.25	45.76	370.15	36.46	8.02	414.63
4	Banswara	11.82	1.31	53.06	66.19	0.86	0.00	0.43	1.29	36.80	7.28	287.80	331.88	3.44	0.70	71.37	75.51	52.92	9.29	412.66	474.87
5	Baran	60.41	5.78	24.43	90.62	5.90	1.11	2.99	10.00	231.31	21.18	168.19	420.68	139.35	6.98	48.79	195.12	436.97	35.05	244.40	716.42
6	Barmer	1203.46	120.29	30.20	1353.95	49.03	9.84	2.40	61.27	1157.85	62.27	8.99	1229.11	298.34	29.85	5.93	334.12	2708.68	222.25	47.52	2978.45
7	Beawar	26.27	3.41	1.05	30.73	1.80	0.34	0.00	2.14	2.14	0.00	0.00	2.14	40.72	4.54	1.30	46.56	70.93	8.29	2.35	81.57
8	Bharatpur	26.00	1.84	3.15	30.99	7.02	0.51	0.77	8.30	13.05	0.43	1.50	14.98	7.48	0.45	0.75	8.68	53.55	3.23	6.17	62.95
9	Bhilwara	377.95	66.19	28.10	472.24	4.88	1.20	0.68	6.76	34.88	9.20	5.35	49.43	235.64	46.90	35.14	317.68	653.35	123.49	69.27	846.11
10	Bikaner	52.79	10.51	1.05	64.35	4.79	1.37	0.34	6.50	121.33	12.20	2.35	135.88	296.10	88.81	2.99	387.90	475.01	112.89	6.73	594.63
11	Bundi	78.80	62.51	160.74	302.05	3.25	2.14	6.42	11.81	222.33	95.22	317.76	635.31	31.25	7.82	46.80	85.87	335.63	167.69	531.72	1035.04
12	Chittorgarh	38.35	3.68	2.10	44.13	7.53	1.28	0.60	9.41	69.54	5.99	3.00	78.53	335.07	61.45	27.91	424.43	450.49	72.40	33.61	556.50
13	Churu	128.96	16.28	8.14	153.38	2.65	1.03	0.26	3.94	183.59	15.19	7.70	206.48	265.05	47.10	5.88	318.03	580.25	79.60	21.98	681.83
14	Dausa	12.08	3.41	17.33	32.82	4.62	2.31	12.92	19.85	73.40	14.76	98.00	186.16	42.91	18.79	134.07	195.77	133.01	39.27	262.32	434.60
15	Deeg	16.02	1.05	1.58	18.65	3.25	0.43	0.34	4.02	10.49	0.21	0.43	11.13	3.54	0.20	0.25	3.99	33.30	1.89	2.60	37.79
16	Dholpur	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	0.68	1.20	3.85	4.49	1.50	3.00	8.99	10.87	3.89	6.93	21.69	17.33	6.07	11.13	34.53
17	Didwana Kuchaman	123.45	24.69	0.00	148.14	1.63	0.77	0.00	2.40	215.48	33.17	0.00	248.65	131.93	15.85	2.64	150.42	472.49	74.48	2.64	549.61
18	Dungarpur	3.94	0.26	2.36	6.56	0.43	0.00	0.34	0.77	2.14	0.00	10.91	13.05	3.54	0.25	24.42	28.21	10.05	0.51	38.03	48.59
19	Ganganagar	13.66	1.58	0.00	15.24	17.97	0.86	0.00	18.83	17.76	1.93	0.00	19.69	220.94	44.16	0.00	265.10	270.33	48.53	0.00	318.86
20	Hanumangarh	34.93	3.68	1.58	40.19	14.29	1.11	0.60	16.00	31.46	3.21	1.50	36.17	410.63	58.66	1.15	470.44	491.31	66.66	4.83	562.80
21	Jaipur	1784.71	126.07	277.10	2187.88	5.05	1.03	2.48	8.56	1285.59	95.65	343.87	1725.11	252.59	22.73	32.00	307.32	3327.94	245.48	655.45	4228.87
22	Jaisalmer	16.55	2.10	0.00	18.65	4.11	0.68	0.00	4.79	10.70	3.64	-0.21	14.13	104.61	41.87	20.93	167.41	135.97	48.29	20.72	204.98
23	Jalore	2964.53	198.83	39.66	3203.02	104.90	20.28	4.36	129.54	2174.89	126.89	48.15	2349.93	164.97	11.51	4.64	181.12	5409.29	357.51	96.81	5863.61
24	Jhalawar	258.97	129.75	97.18	485.90	84.45	42.18	31.66	158.29	1424.46	569.83	712.13	2706.42	95.54	38.23	44.56	178.33	1863.42	779.99	885.53	3528.94
25	Jhunjhunu	120.56	4.47	4.47	129.50	7.27	0.77	0.68	8.72	213.55	12.84	8.56	234.95	214.46	14.30	3.59	232.35	555.84	32.38	17.30	605.52
26	Jodhpur	59.36	5.52	2.10	66.98	9.07	1.54	0.26	10.87	1692.80	253.99	13.48	1960.27	233.55	37.38	2.34	273.27	1994.78	298.43	18.18	2311.39
27	Karauli	0.26	0.00	0.79	1.05	0.51	0.09	0.43	1.03	6.42	1.07	8.77	16.26	14.50	3.69	17.89	36.08	21.69	4.85	27.88	54.42
28	Khairthal Tijara	50.17	4.99	2.36	57.52	1.63	0.43	0.17	2.23	1555.85	62.27	20.76	1638.88	55.02	4.59	2.29	61.90	1662.67	72.28	25.58	1760.53
29	Kota	21.27	2.10	5.52	28.89	6.93	0.60	1.97	9.50	105.71	7.06	28.25	141.02	130.58	8.72	34.79	174.09	264.49	18.48	70.53	353.50
30	Kotputli Behror	368.76	39.13	26.00	433.89	3.59	0.34	0.34	4.27	2323.18	83.02	82.81	2489.01	42.46	6.08	6.03	54.57	2737.99	128.57	115.18	2981.74
31	Nagaur	873.05	54.37	1.05	928.47	3.51	1.45	0.00	4.96	130.96	27.60	0.00	158.56	166.81	20.58	0.00	187.39	1174.33	104.00	1.05	1279.38
32	Pali	28.37	5.52	3.94	37.83	6.16	1.88	1.20	9.24	6.21	1.50	15.83	23.54	68.28	13.66	9.07	91.01	109.02	22.56	30.04	161.62
33	Phalodi	31.52	3.94	1.58	37.04	7.70	1.54	0.26	9.50	428.39	183.59	5.99	617.97	178.78	32.20	1.79	212.77	646.39	221.27	9.62	877.28
34	Pratapgarh	14.71	2.89	14.71	32.31	5.73	0.51	4.79	11.03	87.73	58.42	72.97	219.12	55.72	16.70	111.39	183.81	163.89	78.52	203.86	446.27
35	Rajsamand	44.39	2.36	1.05	47.80	5.22	0.51	0.43	6.16	10.49	0.64	0.21	11.34	31.50	7.87	6.28	45.65	91.60	11.38	7.97	110.95
36	S. Madhpur	59.62	23.64	35.72	118.98	58.18	38.84	77.60	174.62	300.64	75.11	451.28	827.03	18.84	9.42	25.17	53.43	437.28	147.01	589.77	1174.06
37	Salumber	0.53	0.00	0.26	0.79	0.26	0.09	0.17	0.52	0.64	0.00	0.21	0.85	1.30	0.45	2.09	3.84	2.73	0.54	2.73	6.00
38	Sikar	564.43	37.56	12.61	614.60	12.24	1.63	0.86	14.73	1589.02	93.51	15.62	1698.15	398.17	75.96	13.11	487.24	2563.86	208.66	42.20	2814.72
39	Sirohi	46.49	9.46	9.72	65.67	13.09	2.48	2.48	18.05	395.01	102.92	56.06	553.99	72.17	10.96	13.96	97.09	526.76	125.82	82.22	734.80
40	Tonk	39.13	9.72	19.44	68.29	6.33	1.28	3.17	10.78	53.50	17.76	35.52	106.78	126.84	42.26	84.53	253.63	225.80	71.02	142.66	439.48
41	Udaipur	15.50	1.05	10.51	27.06	1.71	0.34	0.68	2.73	5.99	0.86	2.14	8.99	28.06	2.79	25.27	56.12	51.26	5.04	38.60	94.90
	Total	10088.67	1041.95	935.83	12066.45	703.76	160.66	167.36	1031.78	16782.05	2096.36	2947.59	21826	5179.9	895.73	902.07	6977.7	32754.38	4194.7	4952.85	41901.93

Computation of Annual Action plan 2025-26 (Addl subsidy in lac Rs.)

Sr.No	District	Drip (Close Spacing)				Drip (wide Spacing)				Mini/ micro Sprinkler				Sprinkler/ Raingun				G. Total			
		Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total
		28050	28050	28050		9137	9137	9137		22852	22852	22852		5323	5323	5323					
1	Ajmer	398.03	24.96	2.52	425.51	20.28	3.20	0.82	24.30	66.73	6.63	4.57	77.93	163.20	27.20	10.91	201.31	648.24	61.99	18.82	729.05
2	Alwar	43.20	12.90	30.57	86.67	2.83	0.73	0.64	4.20	498.17	27.65	110.60	636.42	58.82	8.41	13.41	80.64	603.02	49.69	155.22	807.93
3	Balotara	110.80	17.67	4.49	132.96	216.36	14.44	1.83	232.63	24.91	2.51	0.91	28.33	43.22	4.31	1.33	48.86	395.29	38.93	8.56	442.78
4	Banswara	12.62	1.40	56.66	70.68	0.91	0.00	0.46	1.37	39.31	7.77	307.36	354.44	3.67	0.75	76.23	80.65	56.51	9.92	440.71	507.14
5	Baran	64.52	6.17	26.09	96.78	6.30	1.19	3.20	10.69	247.03	22.62	179.62	449.27	148.83	7.45	52.11	208.39	466.68	37.43	261.02	765.13
6	Barmer	1285.25	128.47	32.26	1445.98	52.36	10.51	2.56	65.43	1236.52	66.50	9.60	1312.62	318.63	31.88	6.33	356.84	2892.76	237.36	50.75	3180.87
7	Beawar	28.05	3.65	1.12	32.82	1.92	0.37	0.00	2.29	2.29	0.00	0.00	2.29	43.49	4.84	1.38	49.71	75.75	8.86	2.50	87.11
8	Bharatpur	27.77	1.96	3.37	33.10	7.49	0.55	0.82	8.86	13.94	0.46	1.60	16.00	7.98	0.48	0.80	9.26	57.18	3.45	6.59	67.22
9	Bhilwara	403.64	70.69	30.01	504.34	5.21	1.28	0.73	7.22	37.25	9.83	5.71	52.79	251.67	50.09	37.53	339.29	697.77	131.89	73.98	903.64
10	Bikaner	56.38	11.22	1.12	68.72	5.12	1.46	0.37	6.95	129.57	13.03	2.51	145.11	316.24	94.86	3.19	414.29	507.31	120.57	7.19	635.07
11	Bundi	84.15	66.76	171.67	322.58	3.47	2.28	6.85	12.60	237.43	101.69	339.35	678.47	33.38	8.36	49.98	91.72	358.43	179.09	567.85	1105.37
12	Chittorgarh	40.95	3.93	2.24	47.12	8.04	1.37	0.64	10.05	74.27	6.40	3.20	83.87	357.87	65.63	29.81	453.31	481.13	77.33	35.89	594.35
13	Churu	137.73	17.39	8.70	163.82	2.83	1.10	0.27	4.20	196.07	16.22	8.23	220.52	283.08	50.30	6.28	339.66	619.71	85.01	23.48	728.20
14	Dausa	12.90	3.65	18.51	35.06	4.93	2.47	13.80	21.20	78.38	15.77	104.66	198.81	45.83	20.07	143.19	209.09	142.04	41.96	280.16	464.16
15	Deeg	17.11	1.12	1.68	19.91	3.47	0.46	0.37	4.30	11.20	0.23	0.46	11.89	3.78	0.21	0.27	4.26	35.56	2.02	2.78	40.36
16	Dholpur	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10	0.73	1.28	4.11	4.80	1.60	3.20	9.60	11.60	4.15	7.40	23.15	18.50	6.48	11.88	36.86
17	Didwana Kuchaman	131.84	26.37	0.00	158.21	1.74	0.82	0.00	2.56	230.12	35.42	0.00	265.54	140.90	16.93	2.82	160.65	504.60	79.54	2.82	586.96
18	Dungarpur	4.21	0.28	2.52	7.01	0.46	0.00	0.37	0.83	2.29	0.00	11.65	13.94	3.78	0.27	26.08	30.13	10.74	0.55	40.62	51.91
19	Ganganagar	14.59	1.68	0.00	16.27	19.19	0.91	0.00	20.10	18.97	2.06	0.00	21.03	235.97	47.16	0.00	283.13	288.72	51.81	0.00	340.53
20	Hanumangarh	37.31	3.93	1.68	42.92	15.26	1.19	0.64	17.09	33.59	3.43	1.60	38.62	438.56	62.65	1.22	502.43	524.72	71.20	5.14	601.06
21	Jaipur	1906.00	134.64	295.93	2336.57	5.39	1.10	2.65	9.14	1372.95	102.15	367.23	1842.33	269.77	24.27	34.17	328.21	3554.11	262.16	699.98	4516.25
22	Jaisalmer	17.67	2.24	0.00	19.91	4.39	0.73	0.00	5.12	11.43	3.88	-0.23	15.08	111.73	44.71	22.36	178.80	145.22	51.56	22.13	218.91
23	Jalore	3166.00	212.34	42.36	3420.70	112.02	21.65	4.66	138.33	2322.68	135.51	51.42	2509.61	176.19	12.30	4.95	193.44	5776.89	381.80	103.39	6262.08
24	Jhalawar	276.57	138.57	103.79	518.93	90.18	45.05	33.81	169.04	1521.26	608.55	760.51	2890.32	102.04	40.83	47.59	190.46	1990.05	833.00	945.70	3768.75
25	Jhunjhunu	128.75	4.77	4.77	138.29	7.77	0.82	0.73	9.32	228.06	13.71	9.14	250.91	229.05	15.28	3.83	248.16	593.63	34.58	18.47	646.68
26	Jodhpur	63.39	5.89	2.24	71.52	9.69	1.64	0.27	11.60	1807.82	271.25	14.40	2093.47	249.44	39.92	2.50	291.86	2130.34	318.70	19.41	2468.45
27	Karauli	0.28	0.00	0.84	1.12	0.55	0.09	0.46	1.10	6.86	1.14	9.37	17.37	15.49	3.94	19.11	38.54	23.18	5.17	29.78	58.13
28	Khairthal Tijara	53.58	5.33	2.52	61.43	1.74	0.46	0.18	2.38	1661.57	66.50	22.17	1750.24	58.77	4.90	2.45	66.12	1775.66	77.19	27.32	1880.17
29	Kota	22.72	2.24	5.89	30.85	7.40	0.64	2.10	10.14	112.89	7.54	30.16	150.59	139.46	9.32	37.15	185.93	282.47	19.74	75.30	377.51
30	Kotputli Behror	393.82	41.79	27.77	463.38	3.84	0.37	0.37	4.58	2481.04	88.67	88.44	2658.15	45.35	6.49	6.44	58.28	2924.05	137.32	123.02	3184.39
31	Nagaur	932.38	58.06	1.12	991.56	3.75	1.55	0.00	5.30	139.85	29.48	0.00	169.33	178.16	21.98	0.00	200.14	1254.14	111.07	1.12	1366.33
32	Pali	30.29	5.89	4.21	40.39	6.58	2.01	1.28	9.87	6.63	1.60	16.91	25.14	72.93	14.59	9.69	97.21	116.43	24.09	32.09	172.61
33	Phalodi	33.66	4.21	1.68	39.55	8.22	1.64	0.27	10.13	457.50	196.07	6.40	659.97	190.94	34.39	1.92	227.25	690.32	236.31	10.27	936.90
34	Pratapgarh	15.71	3.09	15.71	34.51	6.12	0.55	5.12	11.79	93.69	62.39	77.93	234.01	59.51	17.83	118.97	196.31	175.03	83.86	217.73	476.62
35	Rajsamand	47.40	2.52	1.12	51.04	5.57	0.55	0.46	6.58	11.20	0.69	0.23	12.12	33.64	8.41	6.71	48.76	97.81	12.17	8.52	118.50
36	S. Madhpur	63.67	25.25	38.15	127.07	62.13	41.48	82.87	186.48	321.07	80.21	481.95	883.23	20.12	10.06	26.88	57.06	466.99	157.00	629.85	1253.84
37	Salumber	0.56	0.00	0.28	0.84	0.27	0.09	0.18	0.54	0.69	0.00	0.23	0.92	1.38	0.48	2.24	4.10	2.90	0.57	2.93	6.40
38	Sikar	602.79	40.11	13.46	656.36	13.07	1.74	0.91	15.72	1696.99	99.86	16.68	1813.53	425.25	81.12	14.00	520.37	2738.10	222.83	45.05	3005.98
39	Sirohi	49.65	10.10	10.38	70.13	13.98	2.65	2.65	19.28	421.85	109.92	59.87	591.64	77.08	11.71	14.90	103.69	562.56	134.38	87.80	784.74
40	Tonk	41.79	10.38	20.76	72.93	6.76	1.37	3.38	11.51	57.13	18.97	37.93	114.03	135.47	45.14	90.28	270.89	241.15	75.86	152.35	469.36
41	Udaipur	16.55	1.12	11.22	28.89	1.83	0.37	0.73	2.93	6.40	0.91	2.29	9.60	29.97	2.98	26.99	59.94	54.75	5.38	41.23	101.36
	Total	10774.28	1112.74	999.41	12886.43	751.52	171.61	178.73	1101.86	17922.4	2238.82	3147.86	23309.08	5532.24	956.65	963.4	7452.29	34980.44	4479.82	5289.4	44749.66

Computation of Annual Action plan 2025-26 (Total subsidy in lac Rs.)

Sr.No	District	Drip (Close Spacing)				Drip (wide Spacing)				Mini/ micro Sprinkler				Sprinkler/ Raingun				G. Total			
		Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total	Gen	SCP	TSP	Total
1	Ajmer	1329.79	83.40	8.43	1421.62	67.76	10.68	2.75	81.19	222.93	22.15	15.27	260.35	545.22	90.87	36.46	672.55	2165.70	207.10	62.91	2435.71
2	Alwar	144.32	43.10	102.14	289.56	9.46	2.44	2.14	14.04	1664.36	92.38	369.52	2126.26	196.50	28.09	44.81	269.40	2014.64	166.01	518.61	2699.26
3	Balotara	370.17	59.04	14.99	444.20	722.88	48.24	6.11	777.23	83.22	8.39	3.05	94.66	144.40	14.41	4.45	163.26	1320.67	130.08	28.60	1479.35
4	Banswara	42.17	4.68	189.30	236.15	3.05	0.00	1.53	4.58	131.32	25.96	1026.86	1184.14	12.27	2.50	254.66	269.43	188.81	33.14	1472.35	1694.30
5	Baran	215.55	20.62	87.16	323.33	21.06	3.97	10.68	35.71	825.31	75.58	600.09	1500.98	497.21	24.90	174.09	696.20	1559.13	125.07	872.02	2556.22
6	Barmer	4293.93	429.20	107.77	4830.90	174.93	35.11	8.55	218.59	4131.14	222.17	32.07	4385.38	1064.48	106.51	21.16	1192.15	9664.48	792.99	169.55	10627.02
7	Beawar	93.72	12.18	3.75	109.65	6.42	1.22	0.00	7.64	7.64	0.00	0.00	7.64	145.29	16.18	4.62	166.09	253.07	29.58	8.37	291.02
8	Bharatpur	92.77	6.56	11.25	110.58	25.03	1.83	2.75	29.61	46.57	1.53	5.35	53.45	26.67	1.60	2.67	30.94	191.04	11.52	22.02	224.58
9	Bhilwara	1348.53	236.16	100.27	1684.96	17.41	4.28	2.44	24.13	124.45	32.83	19.08	176.36	840.78	167.34	125.38	1133.50	2331.17	440.61	247.17	3018.95
10	Bikaner	188.36	37.49	3.75	229.60	17.10	4.88	1.22	23.20	432.89	43.53	8.39	484.81	1056.49	316.89	10.67	1384.05	1694.84	402.79	24.03	2121.66
11	Bundi	281.14	223.04	573.53	1077.71	11.60	7.63	22.90	42.13	793.25	339.74	1133.75	2266.74	111.50	27.92	166.98	306.40	1197.49	598.33	1897.16	3692.98
12	Chittorgarh	136.82	13.13	7.49	157.44	26.86	4.58	2.14	33.58	248.13	21.38	10.69	280.20	1195.55	219.26	99.59	1514.40	1607.36	258.35	119.91	1985.62
13	Churu	460.13	58.10	29.05	547.28	9.46	3.67	0.92	14.05	655.05	54.20	27.48	736.73	945.70	168.05	20.98	1134.73	2070.34	284.02	78.43	2432.79
14	Dausa	43.10	12.18	61.84	117.12	16.48	8.25	46.10	70.83	261.87	52.68	349.66	664.21	153.11	67.04	478.36	698.51	474.56	140.15	935.96	1550.67
15	Deeg	57.16	3.75	5.62	66.53	11.60	1.53	1.22	14.35	37.42	0.76	1.53	39.71	12.63	0.71	0.89	14.23	118.81	6.75	9.26	134.82
16	Dholpur	0.00	0.00	0.00	0.00	7.02	2.44	4.28	13.74	16.03	5.35	10.69	32.07	38.77	13.87	24.72	77.36	61.82	21.66	39.69	123.17
17	Didwana Kuchaman	440.46	88.09	0.00	528.55	5.81	2.75	0.00	8.56	768.82	118.34	0.00	887.16	470.72	56.55	9.42	536.69	1685.81	265.73	9.42	1960.96
18	Dungarpur	14.06	0.93	8.43	23.42	1.53	0.00	1.22	2.75	7.64	0.00	38.93	46.57	12.63	0.89	87.13	100.65	35.86	1.82	135.71	173.39
19	Ganganagar	48.74	5.62	0.00	54.36	64.11	3.05	0.00	67.16	63.37	6.88	0.00	70.25	788.32	157.56	0.00	945.88	964.54	173.11	0.00	1137.65
20	Hanumangarh	124.64	13.13	5.62	143.39	50.98	3.97	2.14	57.09	112.23	11.45	5.35	129.03	1465.14	209.30	4.09	1678.53	1752.99	237.85	17.20	2008.04
21	Jaipur	6367.80	449.82	988.68	7806.30	18.01	3.67	8.85	30.53	4586.93	341.27	1226.90	6155.10	901.24	81.09	114.17	1096.50	11873.98	875.85	2338.60	15088.43
22	Jaisalmer	59.04	7.49	0.00	66.53	14.66	2.44	0.00	17.10	38.18	12.98	-0.76	50.40	373.26	149.38	74.69	597.33	485.14	172.29	73.93	731.36
23	Jalore	10577.38	709.41	141.51	11428.30	374.26	72.35	15.57	462.18	7759.91	452.74	171.79	8384.44	588.62	41.08	16.54	646.24	19300.17	1275.58	345.41	20921.16
24	Jhalawar	924.00	462.95	346.74	1733.69	301.30	150.50	112.96	564.76	5082.42	2033.12	2540.83	9656.37	340.89	136.40	158.99	636.28	6648.61	2782.97	3159.52	12591.10
25	Jhunjhunu	430.15	15.94	15.94	462.03	25.95	2.75	2.44	31.14	761.94	45.81	30.54	838.29	765.20	51.04	12.80	829.04	1983.24	115.54	61.72	2160.50
26	Jodhpur	211.79	19.68	7.49	238.96	32.36	5.49	0.92	38.77	6039.81	906.23	48.10	6994.14	833.32	133.37	8.35	975.04	7117.28	1064.77	64.86	8246.91
27	Karauli	0.93	0.00	2.81	3.74	1.83	0.31	1.53	3.67	22.91	3.81	31.30	58.02	51.75	13.16	63.84	128.75	77.42	17.28	99.48	194.18
28	Khairthal Tijara	179.00	17.81	8.43	205.24	5.81	1.53	0.61	7.95	5551.19	222.17	74.06	5847.42	196.33	16.37	8.18	220.88	5932.33	257.88	91.28	6281.49
29	Kota	75.90	7.49	19.68	103.07	24.73	2.14	7.02	33.89	377.16	25.19	100.78	503.13	465.91	31.12	124.12	621.15	943.70	65.94	251.60	1261.24
30	Kotputli Behror	1315.73	139.62	92.77	1548.12	12.82	1.22	1.22	15.26	8288.99	296.23	295.47	8880.69	151.51	21.69	21.52	194.72	9769.05	458.76	410.98	10638.79
31	Nagaur	3115.02	193.98	3.75	3312.75	12.52	5.18	0.00	17.70	467.24	98.49	0.00	565.73	595.19	73.44	0.00	668.63	4189.97	371.09	3.75	4564.81
32	Pali	101.21	19.68	14.06	134.95	21.98	6.71	4.28	32.97	22.15	5.35	56.49	83.99	243.63	48.73	32.37	324.73	388.97	80.47	107.20	576.64
33	Phalodi	112.46	14.06	5.62	132.14	27.47	5.49	0.92	33.88	1528.47	655.05	21.38	2204.90	637.88	114.88	6.40	759.16	2306.28	789.48	34.32	3130.08
34	Pratapgarh	52.48	10.31	52.48	115.27	20.45	1.83	17.10	39.38	313.02	208.43	260.35	781.80	198.81	59.57	397.45	655.83	584.76	280.14	727.38	1592.28
35	Rajsamand	158.37	8.43	3.75	170.55	18.62	1.83	1.53	21.98	37.42	2.29	0.76	40.47	112.39	28.09	22.41	162.89	326.80	40.64	28.45	395.89
36	S. Madhpur	212.72	84.35	127.45	424.52	207.58	138.59	276.87	623.04	1072.67	267.98	1610.16	2950.81	67.22	33.61	89.80	190.63	1560.19	524.53	2104.28	4189.00
37	Salumber	1.88	0.00	0.93	2.81	0.92	0.31	0.61	1.84	2.29	0.00	0.76	3.05	4.62	1.60	7.47	13.69	9.71	1.91	9.77	21.39
38	Sikar	2013.88	134.01	44.98	2192.87	43.66	5.81	3.05	52.52	5669.53	333.63	55.73	6058.89	1420.68	271.01	46.77	1738.46	9147.75	744.46	150.53	10042.74
39	Sirohi	165.87	33.74	34.68	234.29	46.71	8.85	8.85	64.41	1409.37	367.23	200.02	1976.62	257.50	39.12	49.79	346.41	1879.45	448.94	293.34	2621.73
40	Tonk	139.62	34.68	69.35	243.65	22.59	4.58	11.30	38.47	190.87	63.37	126.73	380.97	452.57	150.80	301.60	904.97	805.65	253.43	508.98	1568.06
41	Udaipur	55.29	3.75	37.49	96.53	6.11	1.22	2.44	9.77	21.38	3.05	7.64	32.07	100.12	9.96	90.16	200.24	182.90	17.98	137.73	338.61
Total		35996.08	3717.60	3338.98	43052.66	2510.89	573.32	597.16	3681.37	59877.49	7479.72	10516.79	77874.00	18482.02	3195.95	3218.55	24896.52	116866.48	14966.59	17671.48	149504.55

PDMC: Automation Annual Action plan 2025-26

Sr.No	District	Physical Target (ha.)				Financial Target (Rs. In lac)															
		Gen	SCP	TSP	Total	Gen				SCP				TSP				GT			
		Gen	SCP	TSP	Total	CA	SS	Addl	Total	CA	SS	Addl	Total	CA	SS	Addl	Total	CA	SS	Addl	Total
1	Ajmer	25	3	2	30	6.00	4.00	8.75	18.75	0.72	0.48	1.05	2.25	0.48	0.32	0.70	1.50	7.20	4.80	10.50	22.50
2	Alwar	13	1	3	17	3.12	2.08	4.55	9.75	0.24	0.16	0.35	0.75	0.72	0.48	1.05	2.25	4.08	2.72	5.95	12.75
3	Balotara	5	0	0	5	1.20	0.80	1.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.80	1.75	3.75
4	Banswara	5	0	5	10	1.20	0.80	1.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.80	1.75	3.75	2.40	1.60	3.50	7.50
5	Baran	33	2	14	49	7.92	5.28	11.55	24.75	0.48	0.32	0.70	1.50	3.36	2.24	4.90	10.50	11.76	7.84	17.15	36.75
6	Barmer	5	0	0	5	1.20	0.80	1.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.80	1.75	3.75
7	Beawar	2	1	1	4	0.48	0.32	0.70	1.50	0.24	0.16	0.35	0.75	0.24	0.16	0.35	0.75	0.96	0.64	1.40	3.00
8	Bharatpur	1	0	0	1	0.24	0.16	0.35	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.16	0.35	0.75
9	Bhilwara	30	10	10	50	7.20	4.80	10.50	22.50	2.40	1.60	3.50	7.50	2.40	1.60	3.50	7.50	12.00	8.00	17.50	37.50
10	Bikaner	10	2	0	12	2.40	1.60	3.50	7.50	0.48	0.32	0.70	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2.88	1.92	4.20	9.00
11	Bundi	4	2	4	10	0.96	0.64	1.40	3.00	0.48	0.32	0.70	1.50	0.96	0.64	1.40	3.00	2.40	1.60	3.50	7.50
12	Chittorgarh	30	10	10	50	7.20	4.80	10.50	22.50	2.40	1.60	3.50	7.50	2.40	1.60	3.50	7.50	12.00	8.00	17.50	37.50
13	Churu	5	0	0	5	1.20	0.80	1.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.80	1.75	3.75
14	Dausa	9	3	12	24	2.16	1.44	3.15	6.75	0.72	0.48	1.05	2.25	2.88	1.92	4.20	9.00	5.76	3.84	8.40	18.00
15	Deeg	1	0	0	1	0.24	0.16	0.35	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.16	0.35	0.75
16	Dholpur	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Didwana Kuchaman	25	5	0	30	6.00	4.00	8.75	18.75	1.20	0.80	1.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	4.80	10.50	22.50
18	Dungarpur	5	0	2	7	1.20	0.80	1.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.32	0.70	1.50	1.68	1.12	2.45	5.25
19	Ganganagar	5	0	0	5	1.20	0.80	1.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.80	1.75	3.75
20	Hanumangarh	20	1	0	21	4.80	3.20	7.00	15.00	0.24	0.16	0.35	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	5.04	3.36	7.35	15.75
21	Jaipur	54	9	9	72	12.96	8.64	18.90	40.50	2.16	1.44	3.15	6.75	2.16	1.44	3.15	6.75	17.28	11.52	25.20	54.00
22	Jaisalmer	5	0	0	5	1.20	0.80	1.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.80	1.75	3.75
23	Jalore	5	0	0	5	1.20	0.80	1.75	3.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.80	1.75	3.75
24	Jhalawar	20	5	5	30	4.80	3.20	7.00	15.00	1.20	0.80	1.75	3.75	1.20	0.80	1.75	3.75	7.20	4.80	10.50	22.50
25	Jhunjhunu	8	1	1	10	1.92	1.28	2.80	6.00	0.24	0.16	0.35	0.75	0.24	0.16	0.35	0.75	2.40	1.60	3.50	7.50
26	Jodhpur	150	20	5	175	36.00	24.00	52.50	112.50	4.80	3.20	7.00	15.00	1.20	0.80	1.75	3.75	42.00	28.00	61.25	131.25
27	Karauli	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	Khairthal Tijara	84	4	2	90	20.16	13.44	29.40	63.00	0.96	0.64	1.40	3.00	0.48	0.32	0.70	1.50	21.60	14.40	31.50	67.50
29	Kota	9	2	4	15	2.16	1.44	3.15	6.75	0.48	0.32	0.70	1.50	0.96	0.64	1.40	3.00	3.60	2.40	5.25	11.25
30	Kotputli Behror	8	1	1	10	1.92	1.28	2.80	6.00	0.24	0.16	0.35	0.75	0.24	0.16	0.35	0.75	2.40	1.60	3.50	7.50
31	Nagaur	20	2	0	22	4.80	3.20	7.00	15.00	0.48	0.32	0.70	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5.28	3.52	7.70	16.50
32	Pali	10	3	2	15	2.40	1.60	3.50	7.50	0.72	0.48	1.05	2.25	0.48	0.32	0.70	1.50	3.60	2.40	5.25	11.25
33	Phalodi	50	10	2	62	12.00	8.00	17.50	37.50	2.40	1.60	3.50	7.50	0.48	0.32	0.70	1.50	14.88	9.92	21.70	46.50
34	Pratapgarh	2	0	0	2	0.48	0.32	0.70	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.32	0.70	1.50
35	Rajsamand	2	0	0	2	0.48	0.32	0.70	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.32	0.70	1.50
36	S. Madhpur	3	1	2	6	0.72	0.48	1.05	2.25	0.24	0.16	0.35	0.75	0.48	0.32	0.70	1.50	1.44	0.96	2.10	4.50
37	Salumber	1	0	0	1	0.24	0.16	0.35	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.16	0.35	0.75
38	Sikar	40	5	3	48	9.60	6.40	14.00	30.00	1.20	0.80	1.75	3.75	0.72	0.48	1.05	2.25	11.52	7.68	16.80	36.00
39	Sirohi	35	5	5	45	8.40	5.60	12.25	26.25	1.20	0.80	1.75	3.75	1.20	0.80	1.75	3.75	10.80	7.20	15.75	33.75
40	Tonk	30	5	10	45	7.20	4.80	10.50	22.50	1.20	0.80	1.75	3.75	2.40	1.60	3.50	7.50	10.80	7.20	15.75	33.75
41	Udaipur	5	1	2	8	1.20	0.80	1.75	3.75	0.24	0.16	0.35	0.75	0.48	0.32	0.70	1.50	1.92	1.28	2.80	6.00
Total		774	114	116	1004	185.76	123.84	270.90	580.50	27.36	18.24	39.90	85.50	27.84	18.56	40.60	87.00	240.96	160.64	351.40	753.00